



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
31 मार्च 2024 के लिए समाप्त वर्ष हेतु

संघ सरकार  
वित्त एवं संचार  
वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 5  
(अनुपालन लेखापरीक्षा)



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
31 मार्च 2024 के लिए समाप्त वर्ष हेतु

संघ सरकार  
वित्त एवं संचार  
वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 5  
(अनुपालन लेखापरीक्षा)



## विषय-वस्तु

विवरण	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v
<b>अध्याय I: प्रस्तावना</b>		
लेखापरीक्षा प्राधिकार	1.1	1
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.2	1
लेखापरीक्षा कवरेज	1.3	2
लेखापरीक्षित इकाइयों की संक्षिप्त रूपरेखा	1.4	2
लेखापरीक्षा अवलोकन	1.5	14
<b>खंड क</b>		
<b>अध्याय II: डाक विभाग</b>		
डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी धारकों से संग्रहित विलंब शुल्क पर ₹78.92 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर का न लगाया जाना	2.1	17
पर्याप्त नियंत्रण के अभाव के कारण ई-कॉमर्स बिलर को ₹1.05 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया	2.2	19
<b>अध्याय III: दूरसंचार विभाग</b>		
क्रियान्वयन में विलंब और सार्वभौमिक सेवा प्रदाता से ₹8.49 करोड़ के जुर्माने की गैर-वसूली	3.1	22
दूरसंचार विभाग द्वारा ₹107.07 करोड़ के ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र जुर्माने की गैर-वसूली	3.2	23
<b>अध्याय IV: व्यय विभाग</b>		
केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना	4.1	25
<b>अध्याय V: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		
कौशल विकास पहल पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा	5.1	30
सामान्य सेवा केंद्र 2.0 परियोजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा	5.2	48

विवरण	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
<b>खंड ख</b>		
<b>अध्याय VI: संचार मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा	6.1	71
भारत संचार निगम लिमिटेड में टावर संपत्तियों के प्रबंधन पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा	6.2	86
<b>परिशिष्ट और अनुलग्नक</b>		
परिशिष्ट		101
अनुलग्नक		127
शब्दावली		167

## प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन - संचार मंत्रालय के अंतर्गत विभागों, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2023-24 की अवधि में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए परन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। जहाँ भी प्रासंगिक पाया गया है, वहाँ वर्ष 2023-24 के पश्चात की अवधि से संबंधित मामलों को भी समाविष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



---

---

## कार्यकारी सार

---

---



## कार्यकारी सार

### प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इसमें छः अध्याय सम्मिलित हैं। **अध्याय I** लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों / विभागों की रूपरेखा और लेखापरीक्षा का संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है। **अध्याय II, III, IV और V** क्रमशः संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग (डी ओ पी) और दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग (डी ओ ई) एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) की अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों / टिप्पणियों से संबंधित हैं। संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के लेखापरीक्षा निष्कर्ष **अध्याय VI** में दर्शाए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा ₹411.92 करोड़ की वसूली को इंगित किया गया। इसमें से, लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹257.73 करोड़ की वसूली स्वीकार की और ₹83.95 करोड़ की वसूली वास्तविक रूप से की गयी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों पर निष्कर्षों के साथ-साथ सिफारिशों की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं:

### अध्याय II: डाक विभाग:

**क. डाक जीवन बीमा (पी एल आई) / ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) पॉलिसी धारकों से संग्रहित विलंब शुल्क पर ₹78.92 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर का न लगाया जाना:** डाक विभाग केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी जी एस टी) अधिनियम 2017 के खण्डों का पालन नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2017 से दिसम्बर 2023 की अवधि के लिये पॉलिसी धारकों द्वारा पी एल आई / आर पी एल आई प्रीमियम के विलंबित शुल्क पर ₹78.92 करोड़ की राशि के जी एस टी का गैर अधिरोपण और गैर संग्रहण हुआ। (पैरा 2.1)

**ख. पर्याप्त नियंत्रण के अभाव के कारण ई-कॉमर्स बिलर को ₹1.05 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया:** डाक विभाग [कोलकाता रेल डाक सेवा (आर एम एस प्रभाग)] ने 11 जुलाई 2016 को मैसर्स नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक ई-कॉमर्स बिलर, के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए बिलर द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं की बुकिंग, प्रेषण और वितरण हेतु करार किया था। इन करारों में कैश ऑन डिलीवरी (सी ओ डी) सुविधा भी शामिल थी। सिस्टम, एप्लिकेशन और डेटा प्रोसेसिंग में उत्पाद (एस ए पी) में निवारक नियंत्रणों की कमी और सी ओ डी भुगतानों

की प्रक्रिया में मौजूदा मैनुअल जाँच न करने के कारण विभाग ने बिलर को ₹1.05 करोड़ का अधिक भुगतान कर दिया। (पैरा 2.2)

### अध्याय III: दूरसंचार विभाग:

क. क्रियान्वयन में विलंब और सार्वभौमिक सेवा प्रदाता से ₹8.49 करोड़ के जुर्माने की गैर-वसूली: डिजिटल भारत निधि (डी बी एन) ने दिसंबर 2017 में भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ असम और सिक्किम में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए एक करार किया था, जिसके तहत सभी साइटों को जून 2019 तक चालू किया जाना था। कार्यान्वयन अवधि को आगे अक्टूबर 2020 तक विस्तारित किया गया। अप्रैल 2021 तक, स्वीकृत 756 साइट में से केवल 431 ही चालू हो पाई थीं। अंततः, डी बी एन ने लक्ष्य को संशोधित करके 562 साइट कर दिया, लेकिन 124 साइट जो अभी भी चालू नहीं हो पाई (अप्रैल 2025), उन पर ₹19.47 करोड़ की परिनिर्धारित हानि (एल डी) और गैर-निष्पादन जुर्माना (एन पी पी) लगाया गया। इसमें से, डी बी एन ने केवल ₹10.98 करोड़ वसूल किए, जबकि कार्यान्वयन अवधि समाप्त होने के चार वर्ष बाद भी ₹8.49 करोड़ बकाया हैं। दीर्घकालीन विलंब और लंबित वसूली कमजोर अनुबंध प्रवर्तन को दर्शाती है। डी बी एन को लंबित साइट को चालू करने में शीघ्रता करनी चाहिए और भारती एयरटेल लिमिटेड से बकाया एल डी और एन पी पी की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

(पैरा 3.1)

ख. दूरसंचार विभाग द्वारा ₹107.07 करोड़ के ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र जुर्माने की गैर-वसूली: एकीकृत लाइसेंस (यू एल) करार के तहत, दूरसंचार लाइसेंसधारियों के लिये यह अनिवार्य है कि वे मोबाइल सेवाओं को सक्रिय करने से पहले प्रत्येक ग्राहक का पूरी तरह से सत्यापन करें। इस प्रक्रिया की निगरानी ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र (सी ए एफ) के साथ दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एल एस ए) कार्यालय के माध्यम से की जाती है, जो कि मासिक लेखापरीक्षा करने के लिये उत्तरदायी हैं ताकि दूरसंचार विभाग के सत्यापन मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। दूरसंचार विभाग के 2008 के आदेशों के आधार पर, एल एस ए को 0.1 प्रतिशत ग्राहक की सी ए एफ लेखापरीक्षा मासिक रूप से करनी होती है और संचालक की समग्र सत्यापन अनुपालन दर के आधार पर, प्रत्येक गैर-अनुपालन सी ए एफ पर ₹1,000 से ₹50,000 तक का वित्तीय जुर्माना लगाया जाना है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान ग्राहक सत्यापन में कमियों के लिए लगाए गए ₹143.09 करोड़ के जुर्माने में से केवल ₹36.02 करोड़ (25 प्रतिशत) की वसूली हो सकी, जबकि ₹107.07 करोड़ (75 प्रतिशत) अभी भी (मार्च 2025) लंबित हैं। उच्च अप्राप्य बकाया राशि का बने रहना दंड ढांचे के निवारक प्रभाव को कमजोर करता है तथा वसूली में भी प्रवर्तन अंतराल का संकेत देता है। (पैरा 3.2)

#### अध्याय IV: व्यय विभाग:

केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सी जी ई जी आई एस) के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना: सी जी ई जी आई एस 1982 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कम मूल्य पर और पूरी तरह से अंशदान और स्व-वित्तपोषण के आधार पर, सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की सहायता के लिए बीमा का लाभ प्रदान करने तथा सेवानिवृत्ति पर उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए एकमुश्त भुगतान के दोहरे लाभ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी।

लेखापरीक्षा में योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन न करने के निम्नलिखित मामले देखे गए:

- i. बीमा निधि में ब्याज को शामिल न करना।
- ii. बचत निधि शेष पर तिमाही चक्रवृद्धि के बजाय वार्षिक साधारण ब्याज।
- iii. कुल सी जी ई जी आई एस निधि शेष में कमी।
- iv. योजना की निर्धारित समयावधि पर समीक्षा न करना।

योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने को ध्यान में रखते हुए, योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। (पैरा 4.1)

#### अध्याय V: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय:

क. एम ई आई टी वाई में कौशल विकास पहल पर विषय-विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा:

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास (ई एस डी एम-1 एवं II), आकांक्षी जिलों में युवाओं का कौशल विकास (एस डी वाई ए डी) तथा फ्यूचर स्किल्स प्राइम (एफ एस पी) जैसी योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलें लागू करता है। लेखापरीक्षा में इन योजनाओं के 2018-19 से 2022-23 की अवधि के प्रदर्शन की समीक्षा की गई, जिसमें कार्यान्वयन, निगरानी, निधि उपयोग तथा अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति, विशेष रूप से प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगार-योग्यता के संदर्भ में, पर ध्यान केंद्रित किया गया। (पैरा 5.1)

ई एस डी एम योजनाओं में, जबकि समग्र नामांकन और प्रमाणन की संख्या उल्लेखनीय थी, समान जनसांख्यिकीय विवरण वाले अभ्यर्थियों के एकाधिक पंजीकरण के उदाहरणों के कारण लाभार्थियों की विशिष्टता बनाए रखने में समस्याएँ देखी गईं। योजना का संचालन कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी एम यू) द्वारा संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (टी पी) के माध्यम से किया गया। यह देखा गया कि 40 प्रशिक्षण भागीदारों में से 33 द्वारा पंजीकरण-सह-प्रमाणन शुल्क एकत्र नहीं किया गया। मूल्यांकन के संचालन तथा प्रमाणपत्र जारी करने में देरी देखी गई, जिससे लाभार्थियों की समयबद्ध प्रगति प्रभावित हुई। प्लेसमेंट का स्तर सीमित रहा और 'प्लेस एंड ट्रेन' मॉडल के विलंबित कार्यान्वयन के कारण पहले से

प्रमाणित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध प्लेसमेंट सहायता सीमित हो गई। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षुओं की ट्रेकिंग एक वर्ष के स्थान पर केवल तीन महीने तक की गई और प्रशिक्षण भागीदारों के प्रतिपूर्ति दावे विस्तारित अवधि तक लंबित रहे, जो प्रसंस्करण और निपटान में देरी को दर्शाता है। निधि जारी करने और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतिकरण में भी देरी देखी गई। (पैरा 5.1.7)

एस डी वाई ए डी योजना में, कई जिलों में प्रशिक्षण भागीदारों को नियुक्त नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप इन जिलों में किसी भी अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं हुआ। पंजीकरण पोर्टल में सहायक दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान नहीं था, जिससे डेटा सत्यापन में कमियाँ उत्पन्न हुईं, जिनमें एकाधिक पंजीकरण और अमान्य प्रविष्टियाँ शामिल थीं। प्रशिक्षित और प्रमाणित अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में प्लेसमेंट परिणाम कम रहे। यह भी देखा गया कि प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा इनवाँइस का प्रसंस्करण दिशानिर्देशों में निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करने के बजाय मैनुअल रूप से किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष के अंत में निधि जारी करना और उसके बाद अप्रयुक्त राशि शेष रह जाना निधि आवश्यकता के अवास्तविक आकलन को दर्शाता है। (पैरा 5.1.8)

एफ एस पी कार्यक्रम में, डीप स्किलिंग सशुल्क पाठ्यक्रमों में डीप स्किलिंग निःशुल्क पाठ्यक्रमों की तुलना में नामांकन दर कम रही; तथापि इनकी पूर्णता दर उल्लेखनीय रूप से अधिक रही। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाणन को उद्योग द्वारा सीमित मान्यता मिलना शिक्षार्थियों की प्रेरणा को प्रभावित करने वाला एक पहलू पाया गया। (पैरा 5.1.9)

समग्र रूप से, यद्यपि इन योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त पहुँच और प्रशिक्षण कवरेज प्राप्त हुआ, तथापि कार्यान्वयन, निगरानी और निधि प्रबंधन से संबंधित कुछ समस्याओं के कारण अपेक्षित लाभों की पूर्ण प्राप्ति, विशेष रूप से समय पर प्रमाणन और रोजगार-योग्यता में वृद्धि के संदर्भ में, प्रभावित हुई। (पैरा 5.1.7, पैरा 5.1.8 और पैरा 5.1.9)

### सिफारिशें:

#### मंत्रालय

- i. लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण / ई-के वाई सी प्रक्रिया / पोर्टल की कार्यक्षमता को मजबूत कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे।
- ii. मूल्यांकन और प्रमाणन में देरी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों और प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों (के आई ए) की अधिक सक्रिय निगरानी सुनिश्चित कर सकता है।
- iii. प्रशिक्षुओं की ट्रेकिंग के संबंध में सामान्य मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।
- iv. यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रशिक्षण भागीदार (टी पी) प्रशिक्षण शुल्क के लिए इनवाँइस ऑनलाइन पोर्टल से तैयार करने संबंधी योजना दिशानिर्देशों का पालन करें।

v. योजनाओं में परिकल्पित रोजगार-योग्यता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकता है।

ख. सामान्य सेवा केंद्र 2.0 परियोजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा:

सामान्य सेवा केंद्र (सी एस सी) योजना को भारत सरकार द्वारा सितंबर 2006 में पहली बार अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य एक लाख सेवा वितरण केंद्र स्थापित करना था, अर्थात् लगभग हर छह गांवों के लिए एक केंद्र। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर नागरिकों को सुविधाजनक पहुंच के साथ ई-सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराना था, जिससे डिजिटल विभाजन को कम किया जा सके और शासन को मजबूत किया जा सके। (पैरा 5.2.1)

प्रारंभिक रूपरेखा के आधार पर, सरकार ने अगस्त 2015 में ₹475.11 करोड़ के समग्र परिव्यय के साथ सी एस सी 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सी एस सी स्थापित करके डिजिटल सेवा वितरण की पहुंच का विस्तार करना था, जिसके तहत चार वर्षों के भीतर देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर किया जाना था। इस विस्तार रणनीति में पहले चरण के तहत पहले से ही कार्यरत एक लाख सी एस सी को सुदृढ़ और एकीकृत करना और साथ ही 1.5 लाख अतिरिक्त केंद्र जोड़ना भी शामिल था। (पैरा 5.2.1)

सी एस सी 2.0 परियोजना ने ग्रामीण भारत में सी एस सी की पहुंच और लेनदेन का विस्तार करके डिजिटल समावेशन को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। वर्ष 2018-2024 के दौरान लेन-देन की संख्या में 291 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लेन-देन के मूल्य में 322 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनौपचारिक कार्यबल के लिए 16.57 करोड़ ई-श्रम पंजीकरण के कारण लेन-देन की संख्या वर्ष 2021-22 में चरम पर थी। हालांकि, राज्य की ई-सेवाओं का अपूर्ण एकीकरण, ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वी एल ई) की कमजोर वित्तीय स्थिरता, निष्क्रिय सी एस सी की अधिक घटनाएँ और बिना मंजूरी के प्रशिक्षण शुल्क लगाए जाने के कारण इसकी प्रभावशीलता बाधित हुई है। राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की सीमित भागीदारी, निगरानी और भौतिक सत्यापन में कमियाँ, असंगत ब्रांडिंग, महिलाओं की कम भागीदारी और शिकायत निवारण में देरी, सेवा वितरण को और भी कमजोर करती हैं। सी एस सी के लिए राज्य की भागीदारी को मजबूत करना, ग्राम स्तरीय उद्यमियों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना, निगरानी में सुधार करना और शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है ताकि वह सुलभ और स्थाई अंतिम-मील ई-गवर्नेंस के अपने वादे को पूरा कर सके। (पैरा 5.2.1, 5.2.3 तथा 5.2.4)

**सिफारिशें:**

मंत्रालय / सी एस सी-एस पी वी

- i. सफल 4,913 वी एल ई से सीख लेने पर विचार करे तथा इन वी एल ई को उनके जिलों व उसके आसपास में प्रशिक्षण / जागरूकता कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध करे।
- ii. राजस्व साझेदारी मॉडल की समीक्षा करे तथा सफल वी एल ई को आदर्श मॉडल के रूप में बढ़ावा देने के साथ-साथ वी एल ई की स्थिरता को मजबूत करने के लिये नियमित प्रशिक्षण प्रदान करे।
- iii. सक्रिय रूप से निष्क्रिय सी एस सी की पहचान करे और उनकी कार्यशीलता बहाल करने में सहयोग करे।
- iv. वी एल ई के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाये।
- v. सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की ई-सेवाओं का डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ एकीकरण सुनिश्चित करे।
- vi. निगरानी तथा सेवा वितरण में सुधार के लिये सी एस सी का भौतिक सत्यापन समय पर पूर्ण करे।
- vii. वी एल ई चयन, सी एस सी के स्थान निर्धारण और अवसंरचना समर्थन में जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी तथा स्थानीय प्रशासन को शामिल करे।
- viii. वी एल ई पर पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण शुल्क की समीक्षा करे और इसे बंद करे।
- ix. स्पेक्टा तथा सेवा वितरण की नियमित निगरानी के माध्यम से सी एस सी निगरानी को मजबूत करे।

अध्याय VI: संचार मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

क. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई पी पी बी) द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा: यह लेखापरीक्षा कई ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालती है जो भारत में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित, कम बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले और कम सुविधायें प्राप्त करने वाले समाज के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के आई पी पी बी के प्राथमिक दायित्व को प्रभावित करते हैं। हमारी लेखापरीक्षा से ज्ञात होता है कि आई पी पी बी ने अपने नेटवर्क का विस्तार करने और ग्राहकों को जोड़ने में प्रगति की है, लेकिन महत्वपूर्ण परिचालन, नियामक और प्रणालीगत कठिनाइयों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता को बाधित किया है। (पैरा 6.1.1)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यक्तिगत व्यवसाय अभिकर्ता (आई बी सी) की अपर्याप्त तैनाती के कारण ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच को बाधित किया है। आई पी पी बी के मौजूदा ग्राहक खातों में व्यापक निष्क्रियता और कामकाज में कमी पाई गई। इसके अलावा, आई पी पी बी की एकीकृत भुगतान

इंटरफेस (यू पी आई) सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में लेनदेन अस्वीकृत पाए गए, जिससे ग्राहकों का विश्वास कम हुआ। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों से पता चला है कि आई पी पी बी की यू पी आई लेन-देन में तकनीकी गिरावट की दर काफी अधिक थी - वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3.29 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.82 प्रतिशत, जो आर बी आई के 1 प्रतिशत से कम के लक्ष्य से काफी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, आई पी पी बी की यू पी आई सेवाओं में 362 घंटे तक व्यवधान रहा, जो फिनो (19 घंटे), एयरटेल (52 घंटे) और पे टी एम बैंक (शून्य घंटे) की तुलना में काफी अधिक है। (पैरा 6.1.5)

इसके अतिरिक्त, मोबाइल नंबरों को सत्यापित किये बिना खाते खोले गए और एक ही मोबाइल नंबर से एकाधिक ग्राहक सूचना फाइलें सम्बद्ध की गईं। आई पी पी बी की घर-घर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग सीमित पाया गया, जिसमें कई अनुरोधों में देरी हुई, उन्हें रद्द कर दिया गया या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई पी पी बी खातों को डाकघर बचत बैंक खातों से सम्बद्ध न करने और वित्तीय साक्षरता शिविरों के लिए नाबार्ड की सहायता का उपयोग न करने के कारण लेनदेन विफल रहे। इसके अतिरिक्त, आई पी पी बी संचालन के लिए माइक्रो-ए टी एम उपकरणों के उपयोग से संबंधित सुरक्षा जांच में कमियां पाई गईं। (पैरा 6.1.5)

### सिफारिशें :

#### **आई पी पी बी**

- i. आई बी सी की तैनाती की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र स्थापित करे तथा कठिन या कम संभावनाओं वाले क्षेत्रों में आई बी सी को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन संरचना लागू करे।*
- ii. निष्क्रिय खातों के वास्तविक समय में निगरानी, आकांक्षी जिलों में लक्षित पुनर्सक्रियण तथा ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना सरल पुनर्सक्रियण की व्यवस्था के साथ एक सक्रिय निष्क्रियता प्रबंधन ढाँचा अपनाए।*
- iii. ग्राहकों के विश्वास की रक्षा के लिए यू पी आई लेन-देन से संबंधित निर्धारित मानकों को निरंतर पूरा करने हेतु सुदृढ़ निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र लागू करे।*
- iv. अवैध या डुप्लीकेट लिंक को समाप्त करने तथा खाता खोलने के दौरान सत्यापन में मौजूद कमियों की पहचान करने के लिए व्यापक डेटा शुद्धिकरण करे, जिससे आई टी प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सके।*
- v. ग्राहक घर-घर अनुरोध प्रबंधन प्रणाली में ट्रेकिंग तंत्र को सुदृढ़ करे तथा सेवा प्रदाय में सुधार करते हुए घर-घर बैंकिंग सेवाओं की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करे।*

- vi. विशेष रूप से उच्च शेष राशि तथा डी बी टी से जुड़े खातों के लिए डाकघर बचत खातों के साथ सक्रिय लिंकिंग को बढ़ावा देने हेतु लक्षित अभियान और प्रणालीगत संकेत प्रारंभ करे।
- vii. आई पी पी बी सर्किलों और नाबार्ड के राज्य कार्यालयों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करे, स्वीकृत और आयोजित शिविरों की निगरानी को बेहतर बनायें तथा निधियों के उपयोग को सीमित करने वाली मनमानी आंतरिक सीमाओं को समाप्त करे।

ख. भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) में टावर संपत्तियों के प्रबंधन पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा:

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए बी एस एन एल की टावर अवसंरचना की लेखापरीक्षा में परिसंपत्ति प्रबंधन, उनके उपयोग और राजस्व प्राप्ति में अनियमितताएं पाई गईं। चयनित सर्किलों में जिन भू-खंडों पर दूरसंचार टावर लगाए गए थे, उनमें से 36 प्रतिशत भू-खंडों के संबंध में स्वामित्व विलेख बी एस एन एल के नाम पर पंजीकृत नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 27 प्रतिशत पट्टाधारित टावर स्थल ऐसे करारों के आधार पर संचालित पाए गए जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। समाप्त हो चुके पट्टा करारों के अंतर्गत टावरों का निरंतर संचालन करने से बी एस एन एल को कानूनी जोखिमों तथा संभावित वित्तीय दायित्वों का सामना करना पड़ सकता है। सर्किलों और निगमित कार्यालय द्वारा संरक्षित किये गए टावर डेटा में लगातार विसंगतियां पाई गई हैं। बी एस एन एल ने ओडिशा सर्किल में अपने स्वामित्व वाले टावर होने के बावजूद, सात टावर निजी विक्रेताओं से किराए पर लिए थे।

(पैरा 6.2.2, पैरा 6.2.3)

₹59.77 करोड़ मूल्य की भारी मात्रा में टावर सामग्री अप्रयुक्त पड़ी रही, जिसके परिणामस्वरूप धनराशि अवरुद्ध हो गई और सामग्री खराब हो गई। तीन सर्किलों में ₹11.13 करोड़ मूल्य के 81 स्थापित टावर, स्थापना के पश्चात तीन से सात वर्षों की अवधि तक निष्क्रिय बने रहे। इसके अतिरिक्त, ओडिशा सर्किल में 84 टावरों के मामले में टावर स्थापना एवं बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी टी एस) की स्थापना के बीच विलंब के कारण टावरों के उपयोग में देरी हुई, जिससे अनुमानित ₹6.22 करोड़ की राजस्व की हानि हुई। बी एस एन एल ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1,092 साइट सौंपने में भी देरी की, जिससे ₹10.87 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 6.2.3)

इसके अतिरिक्त, 1,740 टावर साइट लंबे समय तक (16 वर्षों तक) निष्क्रिय रहीं, जिसके परिणामस्वरूप पट्टे पर दिये जाने या पुनर्नियोजन के माध्यम से राजस्व अर्जन का अवसर चूक गया। कमजोर आंतरिक नियंत्रणों के कारण विलंब शुल्क (₹7.24 करोड़) नहीं लगाया गया, भूमि किराया शुल्क (₹2.33 करोड़) का बिल जारी नहीं किया गया तथा अवसंरचना प्रावधान शुल्क (₹0.55 करोड़) भी टी एस पी से वसूल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि की वसूली नहीं हो सकी।

(पैरा 6.2.3)

**सिफारिशें :**

**बी एस एन एल**

- i. सभी टावर-संबंधी डेटा की निगरानी, सत्यापन और प्रबंधन के लिए एक मजबूत, वास्तविक-समय प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करे, जिसमें कार्यक्षमता की स्थिति, साइट का उपयोग, पट्टे की व्यवस्था और बिलिंग चक्र शामिल हों।*
- ii. परिचालन निरंतरता में बाधा उत्पन्न करने वाली संभावित कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए भूमि स्वामित्व से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करे तथा समाप्त हो चुके पट्टे समझौतों का नवीनीकरण करे।*
- iii. निष्क्रिय और गैर-कार्यशील टावरों के उपयोग को अनुकूल बनाने के लिए उनकी नियमित समीक्षा करे तथा पुनः उपयोग एवं पुनर्स्थापन या पट्टे पर देने के संबंध में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे।*
- iv. मास्टर सेवा समझौतों के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से राजस्व की सटीक और समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत बिलिंग और वसूली तंत्र लागू करे।*



<b>अध्याय</b>	<b>परिचय</b>
<b>I</b>	

### 1.1 लेखापरीक्षा प्राधिकार

केंद्र और राज्यों, सरकारी कंपनियों और निगमों, निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा संबंधी अधिदेश, संविधान तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी पी सी) अधिनियम, 1971 से प्राप्त होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी हैं जिन्हें संघ और राज्यों के लेखों की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 13 (धारा 17 के साथ पठित) और धारा 16 के तहत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह कर्तव्य है कि वे संघ, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश सरकार के सभी व्यय, सभी प्राप्तियों और अन्य लेन-देन की लेखापरीक्षा करें। संविधान के तहत और अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखापरीक्षा को भी सम्मिलित करता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद अथवा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी नीतियां एवं निर्देश तैयार करने में सहायता मिलने की उम्मीद है, जिनसे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान मिलेगा।

यह प्रतिवेदन संचार, वित्त एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों / विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और दायरे की व्याख्या के साथ-साथ संचार, वित्त एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों / विभागों के व्यय और उनके वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। अध्याय II से आगे संचार, वित्त एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों / विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों के साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी पी एस ई) की अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष / अवलोकन प्रस्तुत किए गए हैं।

### 1.2 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित लेन-देन की जांच करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों तथा लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, और साथ ही इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावशीलता का भी निर्धारण करना है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के दौरान, अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन सामयिकता, महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता आदि मापदंडों के अतिरिक्त, जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन, साथ ही पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पाए गए निष्कर्ष शामिल हैं।

लेखापरीक्षा के पश्चात, इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, अनुपालन प्रदर्शित होने पर, जहाँ आवश्यक हो, लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों का निपटान किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्राप्त हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जिनका अनुपालन लंबित है, को प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए मसौदा पैराग्राफ के रूप में अलग से जारी किए जाते हैं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए संसाधित किए जाते हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

### 1.3 लेखापरीक्षा कवरेज

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों और उनकी इकाइयों को शामिल किया गया है, जिनमें सी पी एस ई भी सम्मिलित है:

- 1) संचार मंत्रालय
  - क) डाक विभाग
  - ख) दूरसंचार विभाग
- 2) वित्त मंत्रालय
  - क) आर्थिक कार्य विभाग
  - ख) व्यय विभाग
- 3) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- 4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

### 1.4 लेखापरीक्षित इकाइयों की संक्षिप्त रूपरेखा

लेखापरीक्षित इकाइयों की संक्षिप्त रूपरेखा के बारे में अगले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 1.4.1 संचार मंत्रालय

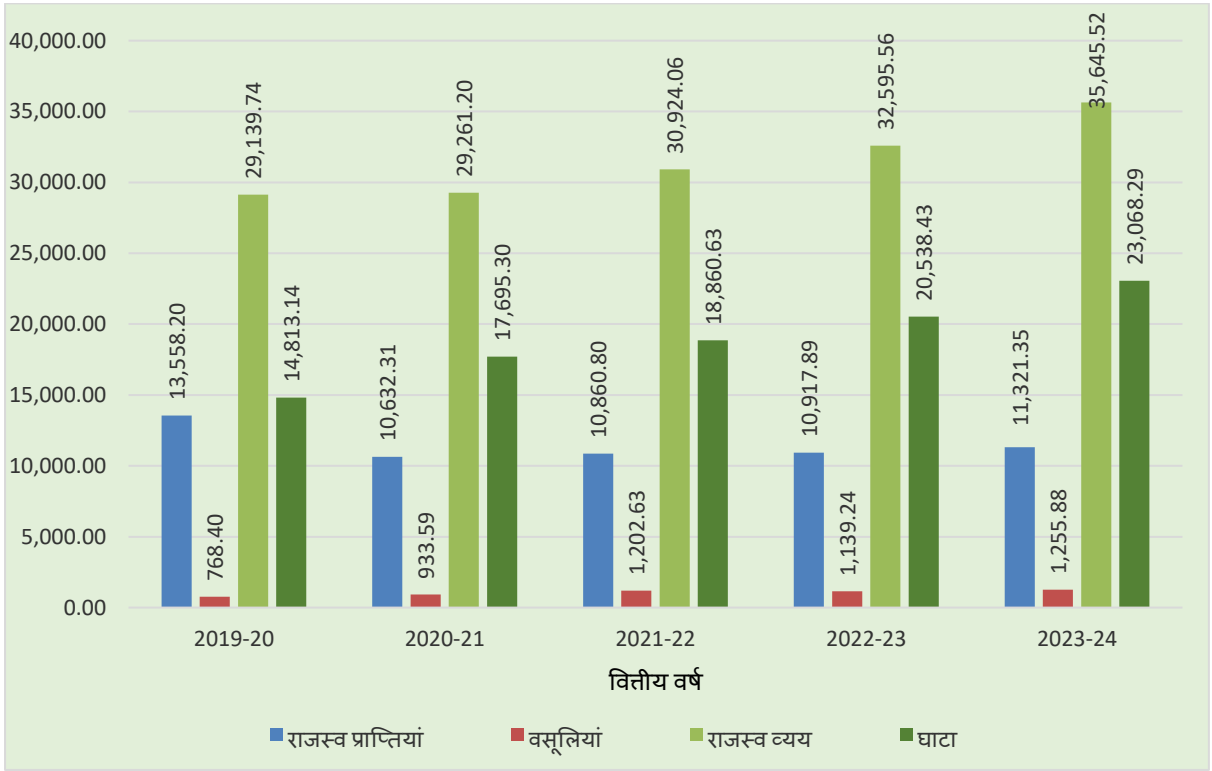
भारत सरकार के अंतर्गत संचार मंत्रालय (एम ओ सी) में दो विभाग हैं, जिनमें दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और डाक विभाग (डी ओ पी) सम्मिलित हैं। भारत में दूरसंचार विभाग दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है और डाक विभाग डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

### 1.4.1.1 डाक विभाग

भारत का डाक नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है, जिसमें 1.64 लाख से अधिक डाकघर हैं, जिनमें से 91 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। यह देश के सुदूरतम कोनों तक अपनी सेवाएं पहुंचाता है। जबकि डाक विभाग की मुख्य गतिविधि डाक का प्रसंस्करण, प्रेषण और वितरण है, यह धन प्रेषण, बैंकिंग, बीमा, पासपोर्ट सेवाएं और आधार नामांकन एवं अद्यतन सेवाओं सहित विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं भी प्रदान करता है। डाक विभाग को केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सामाजिक लाभ भुगतानों के संवितरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

चित्र 1.1: डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डी ओ पी के विनियोग लेखे

राजस्व प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹10,917.89 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹11,321.35 करोड़ हो गई। हालांकि, राजस्व व्यय में लगातार वृद्धि के कारण घाटा बढ़ता रहा। राजस्व व्यय में वृद्धि का कारण वेतन और भत्ते, आकस्मिक व्यय, बोनस, पेंशन शुल्क आदि जैसे खर्चों में हुई बढ़ोतरी है।

डाक विभाग का केवल एक ही पी एस यू है, जिसका नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, जिसकी स्थापना अगस्त 2016 में हुई थी और 31 मार्च 2024 तक इसमें ₹2,105.00 करोड़ का पूंजी निवेश

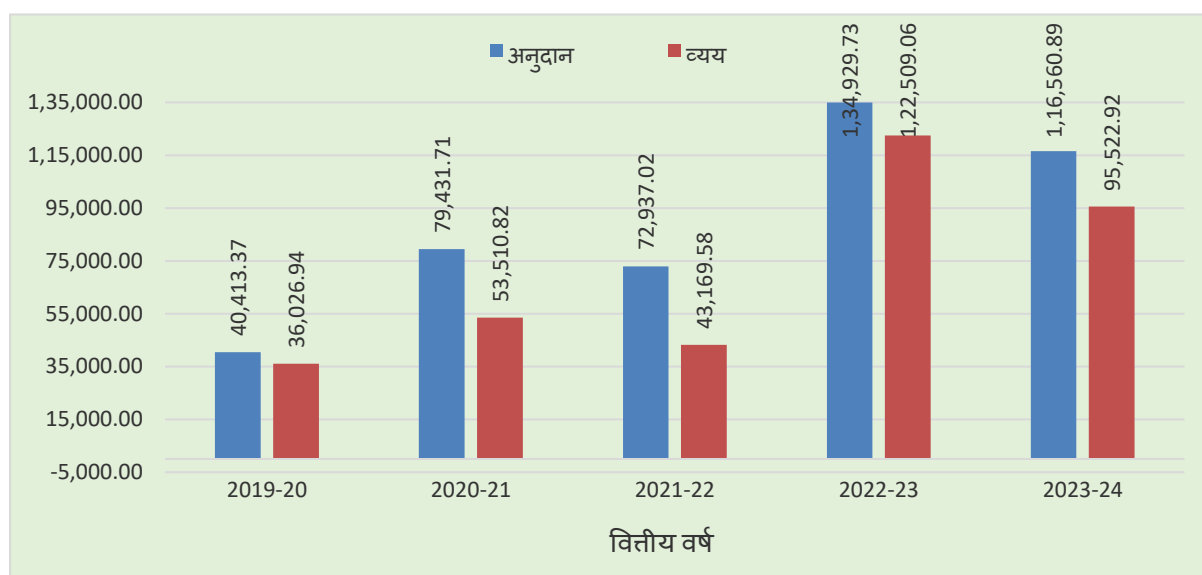
था (विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है)। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

#### 1.4.1.2 दूरसंचार विभाग

संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) देश की दूरसंचार सेवाओं के प्रबंधन और विनियमन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम प्रबंधन भी सम्मिलित हैं। यह देश के सभी उपयोगकर्ताओं के बेतार सम्प्रेषण की निगरानी करके बेतार नियामक उपायों को भी लागू करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दूरसंचार विभाग के अनुदान और व्यय का विवरण चित्र 1.2 में दिया गया है।

चित्र 1.2: दूरसंचार विभाग का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दूरसंचार विभाग के विनियोग लेखे

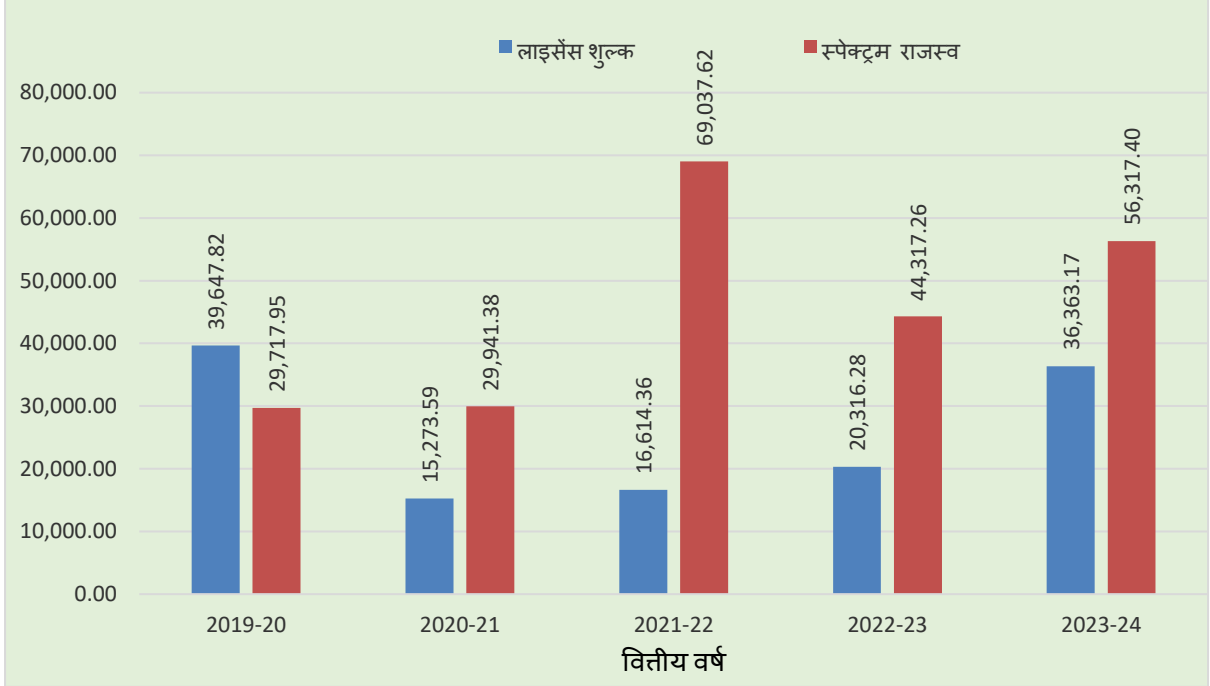
वर्ष 2022-23 की तुलना में, वर्ष 2023-24 में अनुदान में 14 प्रतिशत की कमी आई, जबकि व्यय में 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2023-24 में व्यय में हुई इस गिरावट का मुख्य कारण, वर्ष 2022-23 में ₹53,500 करोड़ के हस्तांतरण के सापेक्ष डिजिटल भारत निधि [यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन (यू एस ओ) फंड] में ₹2,000 करोड़ का हस्तांतरण है। व्यय में यह गिरावट आंशिक रूप से इसलिए संतुलित हो गई क्योंकि वर्ष 2022-23 में बी एस एन एल में पूंजी निवेश (₹26,386.44 करोड़) वर्ष 2023-24 (₹56,785.04 करोड़) की तुलना में कम था। यू एस ओ एफ के बारे में विस्तृत जानकारी पैरा 1.4.1.2 क में दी गई है।

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व हैं। लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस धारकों द्वारा अर्जित राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत होता है। स्पेक्ट्रम राजस्व के मुख्य घटक स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त राशि और टी एस पी द्वारा

भुगतान किए गए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व का विवरण चित्र 1.3 में दिया गया है।

**चित्र 1.3: वित्तीय 2019-20 से वित्तीय 2023-24 के दौरान लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का विवरण**

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लाइसेंस शुल्क के संग्रह में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम राजस्व के संग्रह में भी 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

#### 1.4.1.2 क दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आरक्षित निधि: डिजिटल भारत निधि (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि)

ग्रामीण टेलीफोनी को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 2002 से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) की स्थापना की। दूरसंचार अधिनियम, 2023 में यू एस ओ एफ का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि (डी बी एन) कर दिया गया है। डी बी एन (यू एस ओ एफ) का प्राथमिक उद्देश्य वंचित ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और वितरण को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करना है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ एफ) को पूरा करने के लिए विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत सभी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व के एक प्रतिशत के रूप में सार्वभौमिक पहुंच शुल्क (यू ए एल) के माध्यम से संसाधन जुटाए जाने थे। दूरसंचार अधिनियम, 2023 के पैरा 25 के अनुसार, डी बी एन के लिए प्राप्त धनराशि को पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और केंद्र सरकार समय-समय पर बजट में विनियोजन के माध्यम से इस धनराशि को निर्धारित उपयोगों के लिए कोष में जमा कर

सकती है। यू एस ओ एफ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में भारत नेट परियोजना, 4 जी सचुरेशन योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना आदि शामिल हैं।

विगत पांच वर्षों में निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण चित्र 1.4 के अनुसार है।

चित्र 1.4: डी बी एन से होने वाली प्राप्तियों और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां (सार्वभौमिक पहुँच शुल्क)	निधि में वास्तविक हस्तांतरण	वास्तविक प्राप्तियों के संदर्भ में लघु हस्तांतरण	संचयी लघु हस्तांतरण	निधि से वास्तविक संवितरण	यू जी एफ ए के अनुसार निधि में शेष
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6)	(7) = विगत वर्ष की निधि में शेष + (3)-(6)
वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में अथ शेष				50,550.04	-	0.00
2019-20	7,961.53	2,926.00	5,035.53	55,585.57	2,926.00	0.00
2020-21	9,471.23	7,200.00	2,271.23	57,856.80	7,200.00	0.00
2021-22	10,376.23	8,300.00	2,076.23	59,933.03	8,300.00	0.00
2022-23	12,692.68	53,500.00	(40,807.32)	19,125.71	3,500.00	50,000.00
2023-24	22,722.41	2,000.00	20,722.41	39,848.12	8,380.50	43,619.50

स्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखे (यू जी एफ ए)

लोक लेखा समिति (15वीं लोकसभा के 14वें और 49वें प्रतिवेदन) ने सिफारिश की थी कि सरकार को सार्वभौमिक सेवा शुल्क के रूप में एकत्रित पूरी राशि को यू एस ओ निधि में जमा करना चाहिए, विशेषकर तब जब इस निधि की आय का उपयोग विशेष रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाना है। हस्तांतरण के लिए लंबित बड़ी शेष राशि और उपयोग की अपेक्षाकृत कम दर को देखते हुए, पी ए सी की सिफारिशों के अनुपालन में मंत्रालय अधिक प्रभावी हस्तांतरण सुनिश्चित करने और सार्वभौमिक पहुंच शुल्क के उपयोग के लिए कदम उठा सकता है।

#### 1.4.1.2 ख दूरसंचार क्षेत्र का विनियामक ढांचा

##### क. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1997 से प्रभावी हुई, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है। ट्राई के उद्देश्यों में सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संबद्धता की शर्तों और नियमों को निर्धारित करना और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संबद्धता सुनिश्चित करना भी शामिल है। यह दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त राजस्व के बंटवारे के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था को भी विनियमित करता है। ट्राई

उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओ एस) के मानकों को भी निर्धारित और लागू करता है।

ट्राई पूरी तरह से सरकारी अनुदानों से वित्त पोषित है। ट्राई ने वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त ₹375 करोड़ के अनुदान में से ₹250.39 करोड़ की राशि का उपयोग किया।

## ख. दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण

दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टी डी एस ए टी) की स्थापना 24 जनवरी 2000 को ट्राई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से की गई थी, जिसका उद्देश्य लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारी के बीच, दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच, या किसी सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी भी विवाद का निपटान करना और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई एवं निपटान करना है। अपने गठन के बाद से, टी डी एस ए टी ने अपने समक्ष दायर<sup>1</sup> कुल 16,593 मामलों में से 11,227 मामलों का निपटान किया है।

### 1.4.1.2 ग दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

दूरसंचार विभाग के अंतर्गत 10 पी एस यू हैं। 31 मार्च 2024 तक इन पी एस यू में सरकार द्वारा निवेश की गई कुल पूंजी ₹87,131.85 करोड़ थी (विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है)। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रमुख पी एस यू का संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है:

## क. भारत संचार निगम लिमिटेड

अक्टूबर 2000 में घटित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल), दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बी एस एन एल विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं, मोबाइल संचार हेतु वैश्विक प्रणाली (जी एस एम), ब्रॉडबैंड इंटरनेट, एन्टरप्राइज डेटा सेवाएं और लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा शामिल हैं।

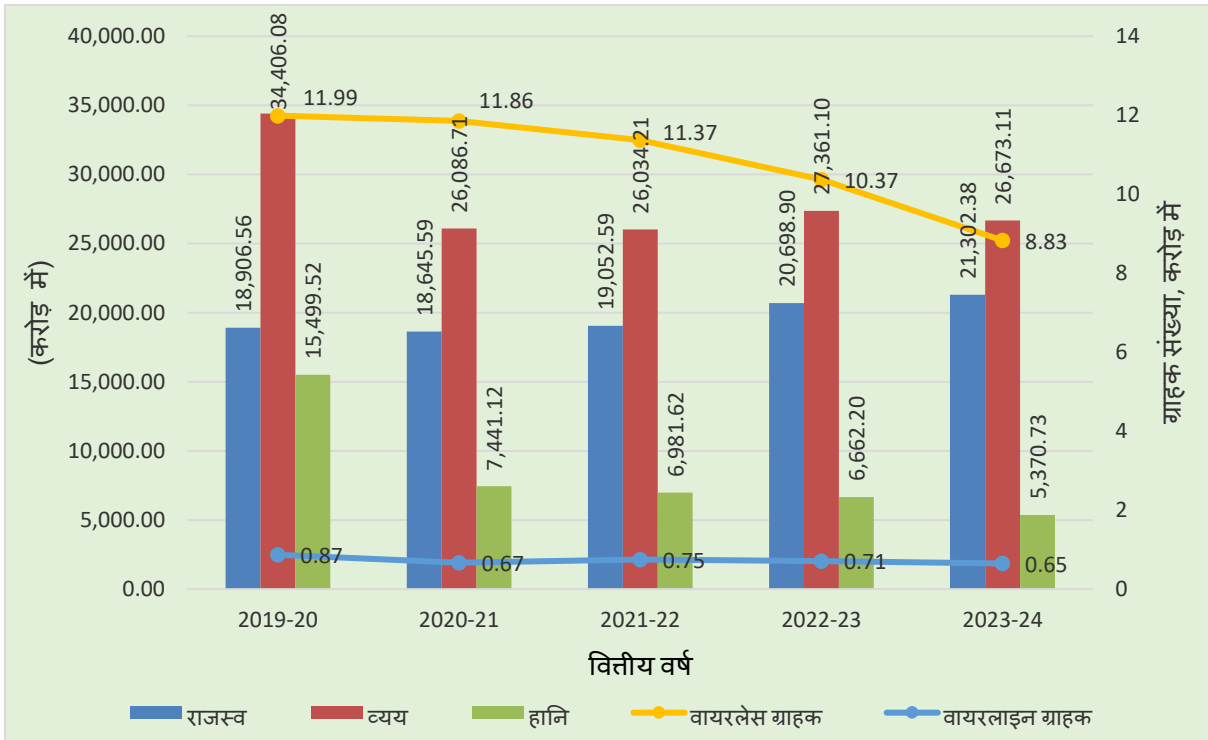
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी 27.07.2022 की बैठक में बी एस एन एल के पुनरुद्धार को मंजूरी दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, बी एस एन एल सेवाओं के उन्नयन हेतु कंपनी में नई पूंजी का निवेश, ए जी आर बकाया का निपटान तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के प्रावधान जैसे उपाय शामिल हैं। पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में ₹26,386.44 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में ₹46,380.38 करोड़ का इक्विटी निवेश किया गया। यह वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 75.77 प्रतिशत की वृद्धि है। मार्च 2024 के अंत तक, बी एस एन एल में सरकारी निवेश ₹85,266.82 करोड़ था।

<sup>1</sup> दूरसंचार विभाग के वर्ष 2023-24 के प्रतिवेदन के अनुसार

बी एस एन एल डी बी एन (यू एस ओ एफ) के माध्यम से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जैसे कि भारत नेट परियोजना, 4 जी मोबाइल सेवाओं का सचुरेशन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैंडविड्थ का संवर्धन आदि।

विगत पांच वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन चित्र 1.5 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित कुल राजस्व और कुल हानि क्रमशः ₹21,302.38 करोड़ और ₹5,370.73 करोड़ थी।

चित्र 1.5: विगत पांच वर्षों के दौरान बी एस एन एल का प्रदर्शन



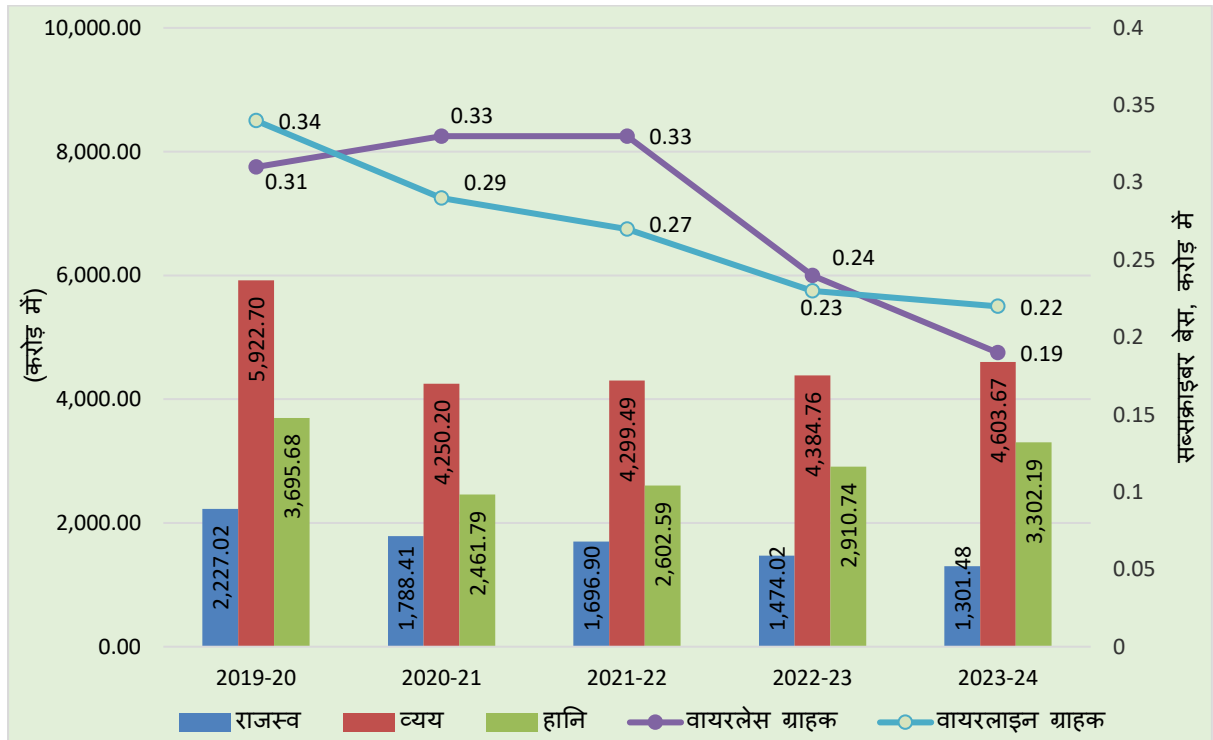
स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बी एस एन एल के वार्षिक प्रतिवेदन और ट्राई के प्रदर्शन संकेतक

कंपनी के राजस्व के मुख्य स्रोत सेलुलर, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज डेटा सेवाएं थीं। चित्र 1.5 दर्शाता है कि विगत पांच वर्षों में वायरलेस और वायरलाइन दोनों ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, हालांकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लीड्स लाइन, फाइबर टू द होम (एफ टी टी एच) और फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग जैसी सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण हुई है। विगत पांच वर्षों में, कंपनी का राजस्व वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹18,906.56 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹21,302.38 करोड़ हो गया, जो 12.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

**ख. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड**

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) की स्थापना 1986 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी और यह दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के लिए उत्तरदायी है। एम टी एन एल इन दोनों महानगरों में फिक्स्ड लाइन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रही है। एम टी एन एल एक सूचीबद्ध कंपनी है और मार्च 2024 के अंत में, ₹354.38 करोड़ मूल्य के 56.25 प्रतिशत शेयर सरकार के पास और शेष अन्य शेयरधारकों के पास हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,301.48 करोड़ था और इसे ₹3,302.19 करोड़ की हानि हुई। विगत पांच वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन चित्र 1.6 में दिया गया है।

**चित्र 1.6 : विगत पांच वर्षों के दौरान एम टी एन एल का प्रदर्शन**



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एम टी एन एल के वार्षिक प्रतिवेदन और ट्राई के प्रदर्शन संकेतक

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वायरलेस और वायरलाइन, दोनों प्रकार के ग्राहकों की संख्या में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के राजस्व में लगातार गिरावट हो रही है।

एम टी एन एल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) भी है, जिसका उद्देश्य सबमरीन केबल परियोजनाएं स्थापित करना और आई टी समाधान प्रदान करना है।

दूरसंचार विभाग के अंतर्गत शेष पी एस यू की रूपरेखा परिशिष्ट II में दी गई है।

## 1.4.2 वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजारों, केंद्र और राज्य के वित्त तथा केंद्रीय बजट से संबंधित है। मंत्रालय में छह विभाग शामिल हैं, नामतः व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग।

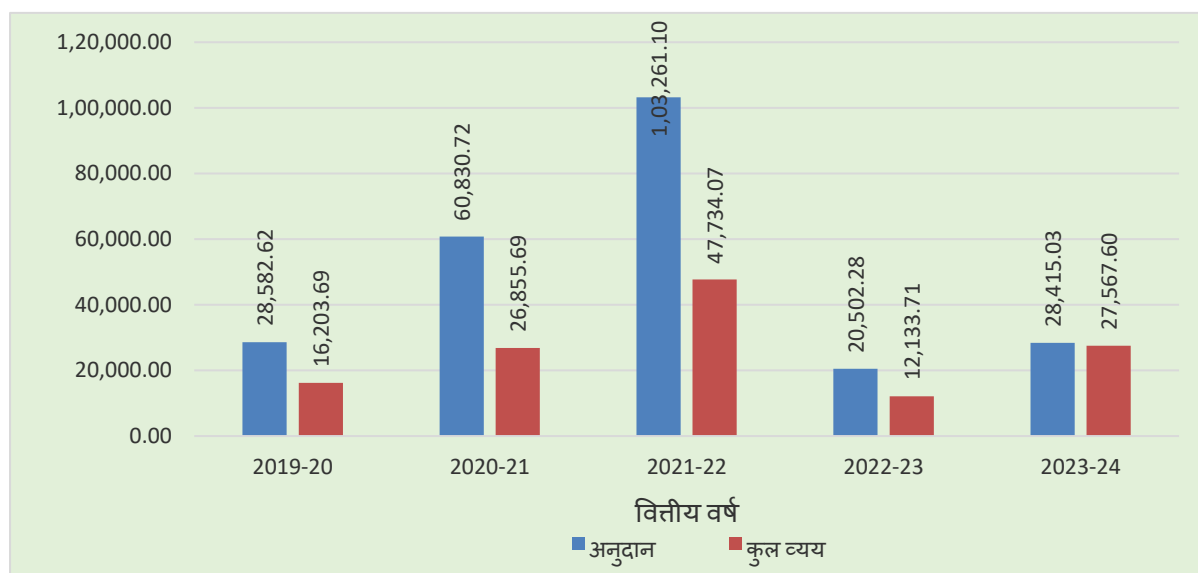
इस प्रतिवेदन में आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए) और व्यय विभाग (डी ओ ई) को शामिल किया गया है।

### 1.4.2.1 आर्थिक कार्य विभाग

डी ई ए भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक और बाह्य पहलुओं को प्रभावित करने वाले आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के साथ साथ मुद्रास्फीति, मूल्य नियंत्रण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आधिकारिक विकास सहायता और केंद्रीय बजट की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों के लिए उत्तरदायी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान डी ई ए के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.7 में दी गई है।

चित्र 1.7: डी ई ए का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डी ई ए के विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, डी ई ए का कुल अनुदान ₹28,415.03 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में डी ई ए का व्यय ₹27,567.6 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में 127 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के उपलब्ध होने के कारण बजट आवंटन में बचत हुई।

डी ई ए के प्रशासनिक नियंत्रण में चार पी एस यू हैं। 31 मार्च 2024 की समाप्ति तक सरकार द्वारा इन पी एस यू में निवेश की गई कुल पूंजी ₹3,587.52 करोड़ थी (विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है)। इन पी एस यू की संक्षिप्त रूपरेखा परिशिष्ट II में दी गई है।

#### 1.4.2.1 क वित्त क्षेत्र (डी ई ए) का विनियामक ढांचा

##### क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) एक वैधानिक नियामक निकाय है जिसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 को भारतीय पूंजी और प्रतिभूति बाजार की निगरानी और विनियमन करने के साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने, नियमों और दिशानिर्देशों को तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी।

##### ख. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आई एफ एस सी ए) की स्थापना एक एकीकृत नियामक के रूप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत की गई है।

आई एफ एस सी ए का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक संबंध विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ पूरे क्षेत्र और समग्र रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में कार्य करना है।

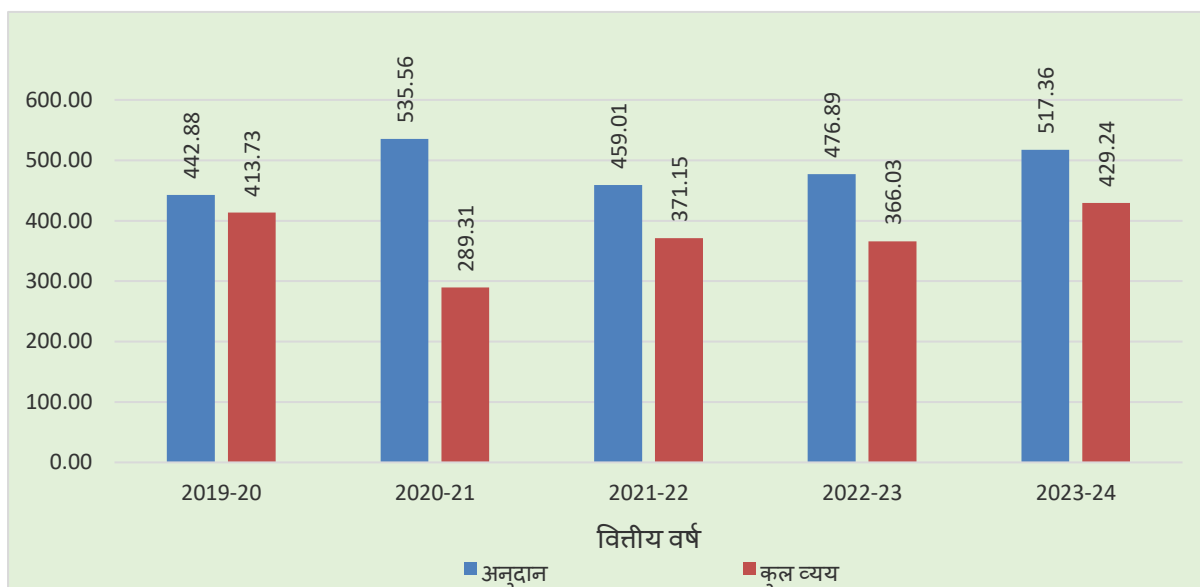
#### 1.4.2.2 व्यय विभाग

व्यय विभाग (डी ओ ई) केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की देखरेख करने वाला नोडल विभाग है। यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों / अवलोकनों की निगरानी और केंद्र सरकार के लेखों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को सार्वजनिक सेवाओं की लागत और कीमतों को नियंत्रित करने, सार्वजनिक व्यय के परिणामों और निष्कर्षों को अनुकूलित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में भी सहायता करता है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों में वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों में व्यय प्रबंधन की निगरानी, वित्तीय नियमों / विनियमों / आदेशों का प्रशासन, प्रमुख योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व मूल्यांकन, तथा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले केंद्रीय बजटीय संसाधनों के बड़े हिस्से का प्रबंधन करना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय विभाग के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.8 में दी गई है।

चित्र 1.8: डी ओ ई का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डी ओ ई के विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान ₹476.89 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान ₹517.36 करोड़ था, वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के व्यय ₹366.03 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय ₹429.24 करोड़ था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई बचत मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने, मिशन कर्मयोगी लैब के निर्माण कार्य के पूरा न होने, कार्यालय सामग्री की खरीद न होने / कम होने, आई टी संबंधी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद पूरी न होने एवं मशीनरी और उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर आदि की कम खरीद के कारण हुई।

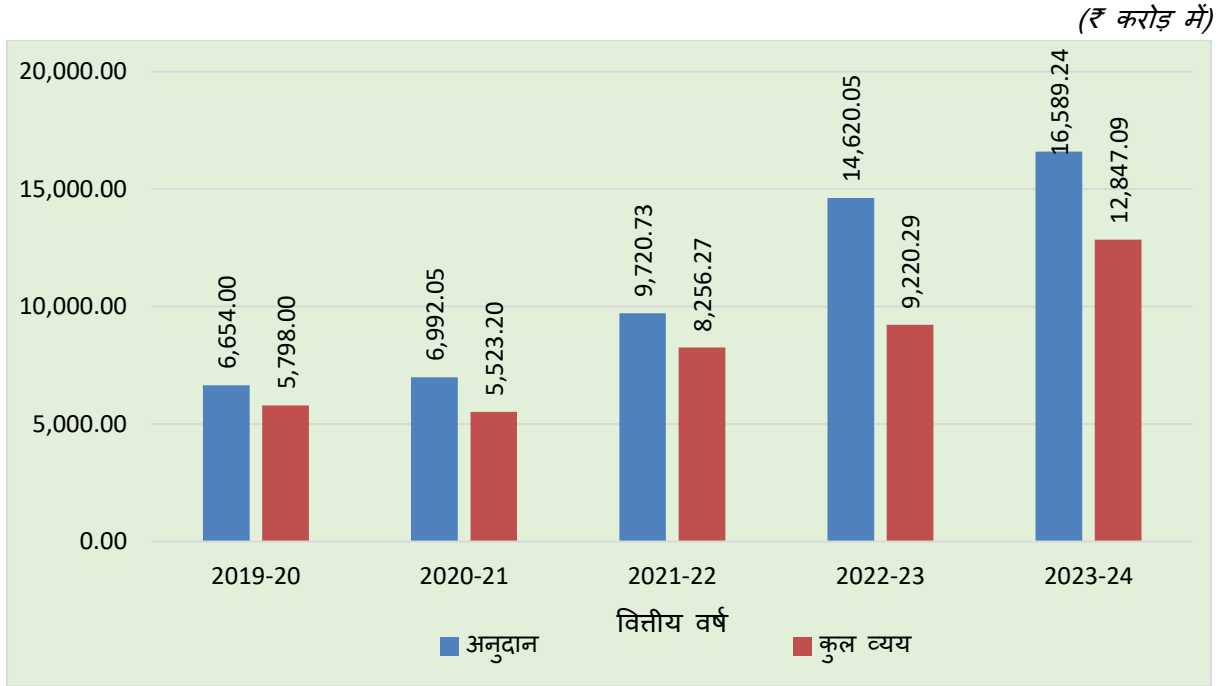
### 1.4.3 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंसिंग के अलावा अन्य सभी मामलों) में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

एम ई आई टी वाई भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुंच, डिजिटल विभाजन को कम करने, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण को सुनिश्चित करके भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में परिवर्तित करना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि के दौरान एम ई आई टी वाई द्वारा प्राप्त अनुदान तथा किए गए व्यय का विवरण चित्र 1.9 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.9: अनुदान और व्यय



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एम ई आई टी वाई के विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, एम ई आई टी वाई का कुल अनुदान ₹16,589.24 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में एम ई आई टी वाई का व्यय ₹12,847.09 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है।

इसके अतिरिक्त, बजटीय आवंटनों में बचत हुई, जो सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले निर्माण के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कम उपयोग, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कम उपयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में कार्यों के निष्पादन न होने, साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के अंतर्गत कम उपयोग, तथा आई टी एवं आई टी ई एस उद्योगों के संवर्धन के अंतर्गत प्रोत्साहनों के प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं कम वितरण के कारण हुई।

एम ई आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण में पाँच पी एस यू हैं। 31 मार्च 2024 के अंत तक, इन पी एस यू में कुल ₹2.00 करोड़ का निवेश किया गया था (विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है)। मंत्रालय के अधीन संलग्न कार्यालयों और पी एस यू की संक्षिप्त रूपरेखा परिशिष्ट II में दी गई है।

#### 1.4.4 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

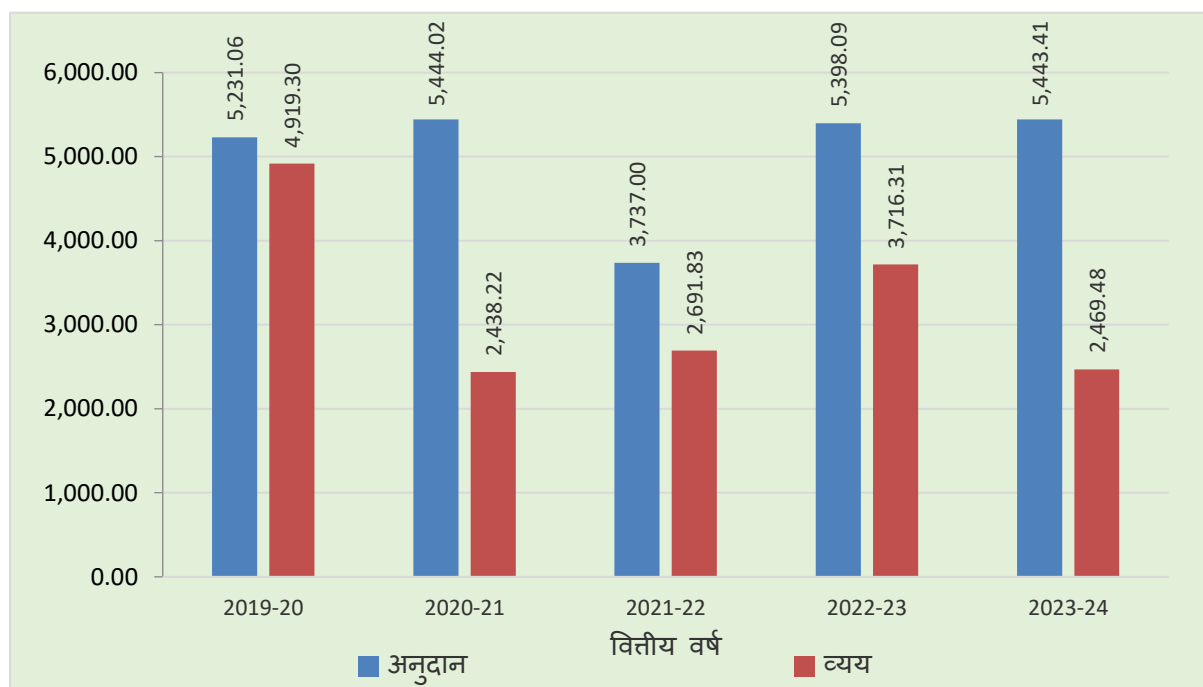
सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद 1999 में यह मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमूनाकरण विधियों पर आधारित हैं। मंत्रालय के दो विंग हैं - सांख्यिकी विंग (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) और कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग। इन दोनों विंग के अलावा, भारत सरकार (एम ओ एस पी आई) के एक प्रस्ताव

द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और एक स्वायत्त संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एम ओ एस पी आई का अनुदान और व्यय चित्र 1.10 में दिया गया है।

चित्र 1.10: एम ओ एस पी आई का अनुदान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एम ओ एस पी आई के विनियोग लेखे

उपरोक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान ₹5,398.09 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान 5,443.41 करोड़ रुपये था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के व्यय ₹3,716.31 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यय ₹2,469.48 करोड़ था।

बचत मुख्यतः एम पी एल ए डी योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों / कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धन के कम उपयोग, अनुमानित संख्या से कम आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, तथा मुकदमेबाजी के कारण राष्ट्रीय एकीकृत सूचना परियोजना के पूर्ण न हो पाने के कारण हुई।

## 1.5 लेखापरीक्षा अवलोकन

### 1.5.1 लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर वसूलियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल सभी मंत्रालयों / विभागों और सी पी एस ई में निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा ₹411.92 करोड़ की वसूली को इंगित किया गया। इसमें से, लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹257.73 करोड़ की वसूली स्वीकार की और ₹83.95 करोड़ की वसूली वास्तविक रूप से की गयी।

### 1.5.2 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों / विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पी ए सी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित मसौदा पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रिया पैराग्राफों की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, मसौदा पैराग्राफ संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिवों को भेजा जाता है, ताकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके और उनसे निर्धारित समय के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जा सके।

सभी पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों / विभागों की प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है और उसे प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

### 1.5.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

#### क. सिविल विभाग:

लोक लेखा समिति की सिफारिश पर, लेखा महानियंत्रक कार्यालय ने वर्ष 2011 में ऑडिट पैरा मोनिटरिंग सिस्टम (ए पी एम एस) पोर्टल शुरू किया है, जो कि एक वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सी ए जी के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) की प्रस्तुति (सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा परीक्षित पैराग्राफों को छोड़कर), पी ए सी की टिप्पणियों / सिफारिशों पर कार्रवाई प्रतिवेदन (ए टी आर) तथा ₹100 करोड़ या उससे अधिक की अधिक व्यय अथवा बचत से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों (ई एन) की प्रभावी निगरानी करना है।

संघ सरकार (वित्त एवं संचार) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों पर 31 अगस्त 2025 तक प्राप्त ए टी एन की स्थिति की समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि संचार मंत्रालय, एम ई आई टी वाई और वित्त मंत्रालय से संबंधित 145 अनुच्छेदों के संबंध में विभिन्न चरणों में ए टी एन लंबित थे। वर्षवार विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है।

#### ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पी एस यू के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे गए लेखों और अभिलेखों की गहन जांच प्रक्रिया का अंतिम परिणाम प्रस्तुत करते हैं। अतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल निष्कर्षों पर कार्यपालिका से उचित और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करना आवश्यक है।

सचिवों की समिति की बैठक में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पैराग्राफों और सी ओ पी यू की सिफारिशों पर लंबित ए टी एन / ए टी आर को अगले तीन महीनों के भीतर निपटाने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्णय (जून 2010 में) लिया गया। इस निर्णय (जुलाई 2010), को संप्रेषित करते हुए वित्त मंत्रालय ने भविष्य में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

अगस्त 2025 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल एम ओ सी, एम ई आई टी वाई और एम ओ एफ के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 61 पैराग्राफों (बी एस एन एल के 48 पैराग्राफों सहित) के संबंध में ए टी एन लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट IV** में उल्लेखित किया गया है।

#### 1.5.4 एम ओ सी / एम ई आई टी वाई / एम ओ एफ के केंद्रीय स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की स्थिति

जी एफ आर (सामान्य वित्त नियम), 2017 के नियम 237 के अनुसार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सी ए बी) के वार्षिक लेखों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने, जिसके परिणामस्वरूप सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर संसद में प्रस्तुत करने के लिए नोडल मंत्रालय को प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	समय सीमा
(i) स्वायत्त निकाय द्वारा संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालय को अनुमोदित और प्रमाणित वार्षिक लेखे उपलब्ध कराना तथा वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की शुरुआत	30 जून
(ii) संबंधित स्वायत्त निकाय / सरकार को लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र सहित अंतिम एस ए आर का अंग्रेजी संस्करण जारी करना।	31 अक्टूबर
(iii) वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखों को नोडल मंत्रालय को प्रस्तुत करना ताकि इसे संसद के पटल पर रखा जा सके।	31 दिसंबर

वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत पी एस यू के लेखाओं के प्रमाणीकरण की स्थिति तथा सी ए बी के संबंध में लेखा प्रस्तुत करने, प्रमाणीकरण करने और संसद को प्रस्तुत करने की स्थिति का विवरण **परिशिष्ट V** में दिया गया है।

#### 1.5.5 प्रमाणन लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2023-24 के लिए पी एस यू के वार्षिक लेखों के प्रमाणीकरण के दौरान, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत टिप्पणियाँ संबंधित पी एस यू को जारी की गईं। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सी ए बी) का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) संसद में प्रस्तुत प्रमाणित अंतिम लेखों के साथ संलग्न किये गए। उल्लेखित प्रमुख टिप्पणियाँ **परिशिष्ट-VI** में संलग्न हैं।

---

---

खंड - क

---

---



## अध्याय

II

## डाक विभाग (डी ओ पी)

2.1 डाक जीवन बीमा (पी एल आई) / ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) पॉलिसी धारकों से संग्रहित विलंब शुल्क पर ₹78.92 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) का न लगाया जाना

डाक विभाग (डी ओ पी) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी जी एस टी) अधिनियम 2017 के खण्डों का पालन नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2017 से दिसम्बर 2023 की अवधि के लिए पॉलिसी धारकों द्वारा पी एल आई / आर पी एल आई प्रीमियम के विलंबित शुल्क पर 78.92 करोड़ रूपए की राशि के जी एस टी का गैर अधिरोपण और गैर संग्रहण हुआ।

डाक विभाग, संचार मंत्रालय अपने प्रधान डाकघरों (एच ओ) / उप डाकघरों (एस ओ) और शाखा डाकघरों (बी ओ) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भारत के नागरिकों को डाक जीवन बीमा (पी एल आई) / ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) सेवाएं प्रदान करता है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी जी एस टी) अधिनियम, 2017 की धारा 15(1) और 15(2) में यह प्रावधान है कि वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य लेनदेन मूल्य होगा, जो वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत है और इसमें किसी भी आपूर्ति के लिए किसी भी प्रतिफल के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना शामिल है। डाक वित्तीय पुस्तिका खंड-II, 2022 का नियम 84(घ), सी जी एस टी अधिनियम, 2017 में निर्धारित उपरोक्त प्रावधान को दोहराता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अधिभार और शुल्क के विलंबित भुगतान पर जी एस टी प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण<sup>2</sup> (अगस्त 2022) जारी किया। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई सुविधा के रूप में ब्याज या विलंबित भुगतान शुल्क, जुर्माना या दंड के साथ विलंबित भुगतान की स्वीकृति स्वतः ही मुख्य आपूर्ति के साथ होगी।

मई 2023 से फरवरी 2024 के दौरान प्रधान डाकघरों में पी एल आई / आर पी एल आई प्रीमियम प्राप्तियों की नमूना जांच और डाक परिमंडलो<sup>3</sup> में निदेशक लेखा (डाक) के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत ई-लेखा अभिलेखों के आधार पर पता चला कि जुलाई 2017 से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान, लागू दर<sup>4</sup> पर जी एस टी सिर्फ प्रीमियम राशि पर लगाया गया था, न कि पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसी धारकों द्वारा प्रीमियम के विलंबित भुगतान पर वसूले गए विलंब शुल्क पर। सभी 23 पोस्टल परिमंडलो से पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसी धारकों से विलंब शुल्क के तौर पर

<sup>2</sup> परिपत्र संख्या 178/10/2022-जी एस टी दिनांक 3.08.2022 (पैरा 9)

<sup>3</sup> आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

<sup>4</sup> पी एल आई/आर पी एल आई प्रीमियम पर जी एस टी 2.25 प्रतिशत की दर पर है और डिफॉल्ट शुल्क 18 प्रतिशत की दर पर है।

कुल ₹438.43 करोड़ वसूले गए, जिस पर ₹78.92 करोड़ का जी एस टी नहीं लगाया गया (अनुलग्नक-2.1)।

इंगित किये जाने पर, डाक इकाइयों द्वारा यह उत्तर दिया गया (जून 2023-मार्च 2024) कि डाक निदेशालय ने डिफॉल्ट शुल्क पर जी एस टी लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है और मैककैमिश सॉफ्टवेयर<sup>5</sup> में डिफॉल्ट शुल्क पर जी एस टी लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है।

डाक इकाइयों का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी एस टी के उपरोक्त प्रावधानों को 2017 में अधिसूचित किया गया था और डाक विभाग द्वारा स्वयं डाक वित्तीय पुस्तिका खंड-II, 2022 (मार्च 2022 तक शामिल) के नियम 84(घ) के तहत इसे दोहराया गया था।

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर, पी एल आई निदेशालय ने सभी परिमंडलो को देय जी एस टी राशि का मिलान करने और जुलाई 2017 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए बिना किसी देरी के विलंब शुल्क पर 18 प्रतिशत की दर से जी एस टी का भुगतान करने का निर्देश (दिसंबर 2023, जनवरी 2024 और मार्च 2024) दिया ताकि ब्याज और जुर्माने के संचय से बचा जा सके। जनवरी 2024 से विलंब शुल्क पर जी एस टी का शुल्क मैनुअल रूप से लेना शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने जवाब दिया (मार्च 2025) कि जुलाई 2017 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के दौरान पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसी धारकों से विलंब शुल्क के रूप में कुल ₹438.43 करोड़ वसूले गए, जिस पर ₹78.92 करोड़ का जी एस टी देय था और डाक विभाग ने जी एस टी प्राधिकरण को ₹80.08<sup>6</sup> करोड़ का जी एस टी भुगतान किया है। यह भी बताया कि विलंब शुल्क पर जी एस टी की स्वतः कटौती की कार्यक्षमता को मैककैमिश सॉफ्टवेयर में शामिल कर लिया गया है। अंत में, निर्णय लिया गया है कि जुलाई 2017 से दिसंबर 2023 तक की अवधि से संबंधित पॉलिसी धारकों द्वारा प्रीमियम भुगतान के साथ विलंब शुल्क पर जी एस टी राशि की वसूली के लिए मैककैमिश सॉफ्टवेयर में प्रावधान को शामिल किया जायेगा।

सी जी ए सटी अधिनियम, 2017 के खण्डों का पालन न करने के कारण जुलाई 2017 से दिसंबर 2023 की अवधि के लिए पॉलिसी धारकों से जी एस टी के गैर अधिरोपण और गैर-संग्रहण के परिणामस्वरूप, विलंब शुल्क पर जी एस टी प्रभार वहन करने का दायित्व डाक विभाग को स्थानांतरित हो गया है।

<sup>5</sup> पी एल आई / आर पी एल आई के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला सॉफ्टवेयर।

<sup>6</sup> 14 परिमंडलो ने देय से अधिक जी एस टी का भुगतान किया और 9 परिमंडलो ने देय से कम जी एस टी का भुगतान किया।

## 2.2 पर्याप्त नियंत्रण के अभाव के कारण ई-कॉमर्स बिलर को ₹1.05 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया

डाक विभाग ने एस ए पी में निवारक नियंत्रण की कमी और कैश-ऑन-डिलीवरी (सी ओ डी) भुगतान की प्रक्रिया को करने के लिए मौजूदा मैनुअल चेक का पालन न करने के कारण एक ई-कॉमर्स बिलर को ₹1.05 करोड़ का ज़्यादा भुगतान कर दिया।

डाक विभाग [(कोलकाता रेल डाक सेवा (आर एम एस प्रभाग)] ने 11 जुलाई 2016 को ई-कॉमर्स बिलर<sup>7</sup> (हुगली में निर्मित वस्तुओं के लिए) के साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए दो करार किए जो कि बिलर द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं की बुकिंग, संचारण और वितरण के लिए क्रमशः बिजनेस पार्सल प्रेषण और एक्सप्रेस पार्सल प्रेषण के रूप में थे। इस समझौते में बिलर की आवश्यकतानुसार कैश ऑन डिलीवरी (सी ओ डी) सुविधा भी शामिल थी।

कैश ऑन डिलीवरी सुविधा के अंतर्गत, विभाग माल की डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता से राशि एकत्र करता है और ई-भुगतान के माध्यम से प्रेषक / ई-कॉमर्स बिलर<sup>7</sup> को राशि प्रेषित करता है। विभाग द्वारा ई-भुगतान सिस्टम, एप्लीकेशन और डेटा प्रोसेसिंग में उत्पाद (एस ए पी) प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है। वस्तु की डिलीवरी के बाद, एस ए पी के अंतर्गत डिलीवरी पोस्टमैन प्रबंधन प्रणाली (डी पी एम एस) में प्रविष्टियाँ अद्यतन की जाती हैं। एकत्रित नकदी नोडल भुगतान डाकघर में अंतरित कर दी जाती है, जहाँ एस ए पी में एक देयता दस्तावेज़ तैयार किया जाता है। भुगतान प्रक्रिया से पहले दोहरी सी ओ डी देनदारियों का पता लगाने के लिए एक प्रश्न-आधारित जाँच मौजूद है, हालाँकि, इसके लिए मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

कोलकाता आर एम एस डिवीजन ने मैसर्स नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल डिलीवरी के लिए क्रमशः दो बिलर आई डी- ई पी सी ओ डी<sup>8</sup> - 7052 और बी पी सी ओ डी<sup>9</sup> -7055 बनाए (सितंबर 2016), और डिलीवरी डाकघरों से सी ओ डी राशि एकत्र करने और चेक द्वारा बिलर को राशि भेजने के लिए पार्क स्ट्रीट प्रधान डाकघर (एच पी ओ), कोलकाता को नोडल भुगतान डाकघर के रूप में नामित किया (अक्टूबर 2016)।

पार्क स्ट्रीट एच पी ओ से संबंधित एस ए पी डेटा के विश्लेषण और एस ए पी में नियंत्रण की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018 के लिए निम्नलिखित अवलोकन किया:

- एस ए पी में एक ही डिलीवरी असाइनमेंट के लिए कई देयता दस्तावेज़ों और कई भुगतानों के निर्माण को रोकने के लिए कोई अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रण मौजूद नहीं था। अगस्त-दिसंबर 2018 के दौरान, पार्क स्ट्रीट एच पी ओ द्वारा एक ही डिलीवरी असाइनमेंट के लिए कई देयता

<sup>7</sup> मैसर्स नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड

<sup>8</sup> एक्सप्रेस पार्सल कैश ऑन डिलीवरी

<sup>9</sup> बिजनेस पार्सल कैश ऑन डिलीवरी

दस्तावेजों के निर्माण हेतु मैनुअल जाँच भी नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप एक ही असाइनमेंट के लिए कई भुगतान संसाधित किए गए। नीचे दी गई तालिका एस ए पी प्रणाली में एक ही डिलीवरी असाइनमेंट के लिए कई देयता के निर्माण और कई भुगतानों के कुछ उदाहरण दर्शाती है।

### तालिका-2.1

बिलर आई डी (ई पी सी ओ डी-7052) के लिए एक ही असाइनमेंट के लिए कई भुगतानों के उदाहरण

असाइनमेंट संख्या	देयता दस्तावेज संख्या	पोस्ट करने की तारीख	मात्रा (₹ में)	भुगतान दस्तावेज संख्या	भुगतान तिथि
YB024909039IN	3302421804	12-09-2018	1,940.00	4118159992	13-09-2018
	3303014743	19-09-2018	1,940.00	4119223114	20-09-2018
YB024928024IN	3302119726	23-08-2018	940.00	4115979191	25-08-2018
	3302466633	14-09-2018	940.00	4118524585	15-09-2018
	3302914573	19-09-2018	940.00	4119223114	20-09-2018
YB024969077IN	3302160568	26-08-2018	940.00	4116336926	28-08-2018
	3302542736	14-09-2018	940.00	4118524585	15-09-2018
YB060222821IN	3302287445	04-09-2018	4,099.00	4117639826	07-09-2018
	3302543574	14-09-2018	4,099.00	4118524585	15-09-2018
YB060222897IN	3302261982	01-09-2018	2,339.00	4117189495	04-09-2018
	3302541163	14-09-2018	2,339.00	4118524585	15-09-2018

स्रोत: पार्क स्ट्रीट प्रधान डाकघर, कोलकाता का एस ए पी डेटा

- अगस्त-दिसंबर 2018 के दौरान एक ही वस्तु के वितरण असाइनमेंट के लिए कई भुगतानों के परिणामस्वरूप मैसर्स नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड को ₹1.05 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया जो विभाग द्वारा वास्तविक सी ओ डी संग्रह से अधिक था, जैसा की नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है:

तालिका-2.2

डाक विभाग द्वारा मैसर्स नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड को किये गये अधिक भुगतान का विवरण

बिलर आई डी ई पी सी ओ डी-7052				बिलर आई डी बी पी सी ओ डी-7055			
एक ही असाइनमेंट के लिए की गई भुगतान की संख्या	ऐसे असाइनमेंट की संख्या	भुगतान हेतु देय राशि (₹ में)	भुगतान की गई कुल राशि (₹ में)	एक ही असाइनमेंट के लिए की गई भुगतान की संख्या	ऐसे असाइनमेंट की संख्या	भुगतान हेतु देय राशि (₹ में)	भुगतान की गई कुल राशि (₹ में)
2	1,720	27,09,173	54,18,346	2	834	18,57,727	37,15,454
3	898	12,79,779	38,39,337	3	307	6,49,222	19,47,666
4	14	21,015	84,060	4	313	6,69,988	26,79,952
6	1	940	5,640				
<b>कुल योग</b>	<b>2,633</b>	<b>40,10,907</b>	<b>93,47,383</b>	<b>कुल योग</b>	<b>1,454</b>	<b>31,76,937</b>	<b>83,43,072</b>
<b>कुल किया गया अधिक भुगतान (क)</b>			<b>53,36,476</b>	<b>कुल किया गया अधिक भुगतान (ख)</b>			<b>51,66,135</b>
<b>मैसर्स नापतोल (क+ख) को किए गए अधिक भुगतान का कुल योग</b>				<b>₹1,05,02,611</b>			

स्रोत: पार्क स्ट्रीट प्रधान डाकघर, कोलकाता का एस ए पी डेटा

अपने जवाब में, पार्क स्ट्रीट एच पी ओ, कोलकाता ने इससे सहमति जताई और सूचित किया (नवंबर 2024) कि उसने ₹1.05 करोड़ के अधिक भुगतान की वापसी के लिए मैसर्स नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड को संदर्भ दिया था। कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल ने अपने जवाब (जनवरी 2025) में, इस मामले के संबंध में जांच रिपोर्ट भेजी, जिससे अगस्त-दिसंबर 2018 के दौरान एक ही वस्तु के असाइनमेंट के प्रति कई भुगतानों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि हुई, जिसके परिणामस्वरूप मैसर्स नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड को अधिक भुगतान हुआ। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि दोहरी जांच प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था, जिससे कई भुगतान हुए।

मंत्रालय ने (जून 2025) लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए पुष्टि की कि एस ए पी प्रणाली में स्वचालित डुप्लिकेट पहचान की कमी है, और आश्वासन दिया कि 2025 में शुरू होने वाली आगामी आई टी प्रणाली इस कमी को पूरा करेगी। मंत्रालय ने आगे बताया कि मैसर्स नापतोल द्वारा अधिक भुगतान की वापसी अभी बाकी है।

एस ए पी प्रणाली में पर्याप्त निवारक नियंत्रण के अभाव और प्रक्रियात्मक स्तर पर निर्धारित मैनुअल जांच न करने के कारण ई-कॉमर्स बिलर को ₹1.05 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जिसका अनुबंध 2019 में समाप्त हो गया था।

अध्याय	दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)
III	

### 3.1 क्रियान्वयन में विलंब और सार्वभौमिक सेवा प्रदाता से ₹8.49 करोड़ के जुर्माने की गैर-वसूली

पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ डिजिटल भारत निधि के समझौते में लंबी देरी हुई, कई साइटों का निर्माण, करार की समय सीमा से काफी बाद में शुरू हुआ। लक्ष्यों में संशोधन के बाद भी, 124 साइटें शुरू नहीं हो पाईं और ₹8.49 करोड़ का जुर्माना क्रियान्वयन अवधि समाप्त होने के चार साल बाद भी वसूल नहीं हो पाया।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ<sup>10</sup>), जिसका नाम अब डिजिटल भारत निधि (डी बी एन<sup>11</sup>) रखा गया है, ग्रामीण, दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में किफायती मोबाइल और डिजिटल सेवाओं को बेहतर करने के लिए बनाया गया था। बाद में इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार वंचित शहरी क्षेत्रों और अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) को बढ़ावा देने के लिए किया गया। दिसंबर 2017 में, डी बी एन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की असम-ए<sup>12</sup>, असम-बी, असम-सी, असम-डी और सिक्किम इकाइयों में चिन्हित वंचित गाँवों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (बी ए एल) के साथ एक करार किया।

करार के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा प्रदाता (यू एस पी) यानी बी ए एल को नौ महीने के भीतर सर्वेक्षण पूरा करना था और करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने के भीतर सभी साइटों को चालू करना था (जून 2019 तक)। करार में संशोधन के माध्यम से क्रियान्वयन अवधि को अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। करार के खंड 6.6.2 में नवंबर 2020 (क्रियान्वयन अवधि की समाप्ति के 30 दिन बाद) से परे शुरुआत में देरी के लिए प्रति माह प्रति साइट श्रेणी-विशिष्ट प्रदर्शक दर<sup>13</sup> (आर आर) के दो प्रतिशत (अधिकतम 10 प्रतिशत प्रति साइट) पर परिनिर्धारित हर्जाना (एल डी) लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, करार के खंड 7.5.1 में क्रियान्वयन अवधि (30 अप्रैल 2021 तक) की समाप्ति के छह महीने के भीतर शुरुआत नहीं करने वाली साइटों के लिए प्रति साइट पाँच प्रतिशत आर आर का गैर-निष्पादन जुर्माना (एन पी पी) निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2023) कि 30 अप्रैल 2021 तक, स्वीकृत 756 साइटों में से केवल 431 ही चालू की गई थीं, जिससे शेष 325 साइटों के चालू न होने पर एल डी और एन पी पी का शुल्क लगाया जाना आवश्यक हो गया। मंत्रालय ने बाद में (मार्च 2025) स्पष्ट किया कि डी बी एन

<sup>10</sup> यू एस ओ एफ की स्थापना अप्रैल 2002 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में संशोधन करके की गई थी।

<sup>11</sup> दूरसंचार अधिनियम, 2023 द्वारा इसका नाम बदलकर 'डिजिटल भारत निधि' (डी बी एन) कर दिया गया।

<sup>12</sup> असम-ए, असम-बी आदि श्रेणियाँ हैं जो असम के विभिन्न विशिष्ट जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को समूहीकृत करती हैं।

<sup>13</sup> श्रेणी विशिष्ट प्रदर्शक दर, साइट के स्थान और अवसंरचना के प्रकार के आधार पर प्रति साइट देय सब्सिडी की प्रदर्शक दर है।

ने चालू करने के लिए कुल 763 साइटों<sup>14</sup> को मंजूरी दी थी, जिनमें से 201 को छोड़ दिया गया, इस प्रकार लक्ष्य को संशोधित कर 562 साइट कर दिया गया। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि संशोधित लक्ष्य के प्रति, 438 साइटों को चालू किया गया और डी बी एन ने शेष 124 साइटों के चालू न होने पर ₹19.47 करोड़<sup>15</sup> का जुर्माना निर्धारित किया है, जिसमें से ₹9.80 करोड़ की वसूली की गई।

मंत्रालय का उत्तर खुद इस बात की पुष्टि करता है कि 562 साइटों के संशोधित लक्ष्य में से 124 साइटों के चालू होने में काफी देरी हो रही है। इसके अलावा, ₹8.49 करोड़<sup>16</sup> की शेष वसूली अभी भी लंबित है (जैसा कि अप्रैल 2025 में देखा गया है), जबकि क्रियान्वयन अवधि समाप्त होने के बाद से चार वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, जो संविदात्मक प्रावधानों को लागू करने और समय पर वसूली सुनिश्चित करने में कमियों को दर्शाता है। डी बी एन को लंबित साइटों के चालू होने में तेज़ी लानी चाहिए और बी ए एल से बकाया एल डी और एन पी पी की बिना किसी देरी के वसूली करनी चाहिए, साथ ही साइट चयन प्रक्रियाओं और करार निगरानी को मज़बूत करना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न आए।

### 3.2 दूरसंचार विभाग द्वारा ₹107.07 करोड़ के ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र (सी ए एफ) जुर्माने की गैर-वसूली

दूरसंचार विभाग वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान दूरसंचार सेवा प्रदाता से ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र (सी ए एफ) जुर्माने के तहत लगाए गए कुल जुर्माने का केवल 25 प्रतिशत ही वसूल कर सका। उच्च अप्राप्य बकाया राशि का बने रहना दंड ढांचे के निवारक प्रभाव को कमजोर करता है तथा वसूली में भी प्रवर्तन अंतराल का संकेत देता है।

एकीकृत लाइसेंस (यू एल) करार के तहत, दूरसंचार लाइसेंसधारियों को मोबाइल सेवाओं के सक्रियण से पहले प्रत्येक ग्राहक का पूर्ण सत्यापन करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया की निगरानी ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र (सी ए एफ) के माध्यम से की जाती है, और दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एल एस ए) कार्यालय, दूरसंचार विभाग के सत्यापन मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मासिक लेखापरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। दूरसंचार विभाग के 2008 के आदेशों के आधार पर, एल एस ए को ग्राहक आधार के 0.1 प्रतिशत का मासिक सी ए एफ लेखापरीक्षा करना है, और संचालक की समग्र सत्यापन अनुपालन दर (अप्रैल 2009 से प्रभावी) के आधार पर, प्रत्येक गैर-अनुपालन सी ए एफ पर ₹1,000 से ₹50,000 तक का वित्तीय जुर्माना लगाया जाना है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 15 मार्च 2025 तक, 2022-23 से 2024-25 के दौरान ग्राहक सत्यापन में कमियों के लिए 22 एल एस ए में ₹143.09 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) से केवल ₹36.02 करोड़ (अर्थात लगाए गए कुल जुर्माने

<sup>14</sup> अप्रैल 2024 में सात स्थलों को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<sup>15</sup> एल डी के लिए ₹12.98 करोड़ और एन पी पी के लिए ₹6.49 करोड़।

<sup>16</sup> लेखापरीक्षा संवीक्षा के अनुसार 25.03.2025 तक ₹10.98 करोड़ वसूल किए गए हैं।

का 25 प्रतिशत) वसूल किया गया, जिससे ₹107.07 करोड़ (अर्थात 75 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण बकाया राशि शेष रह गई। इसमें से ₹86.31 करोड़ दिवालियापन के अधीन टी एस पी से संबंधित हैं, ₹8.33 करोड़ मुकदमेबाजी के अधीन हैं, ₹0.08 करोड़ विवाद के अधीन हैं, और ₹12.35 करोड़ निर्विवाद वसूली योग्य बकाया राशि को दर्शाते हैं, जिसमें पूर्व अवधि की अंतरित राशियां भी शामिल हैं।

मंत्रालय ने (जुलाई 2025) वसूली योग्य राशि की स्थिति बताते हुए बताया कि ₹94.64 करोड़ मुकदमेबाजी / दिवालियापन / परिसमापन प्रक्रिया के अधीन हैं और बी एस एन एल / एम टी एन एल से ₹12.32 करोड़ की राशि वसूल नहीं हो पाई है। मंत्रालय ने आगे बताया कि दूरसंचार विभाग और एल एस ए बकाया राशि की वसूली के लिए बी एस एन एल के साथ इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं।

मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बी एस एन एल के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों (वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25) में देखा गया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा मांगा गया सी ए एफ जुर्माना देयता के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसे विवादित मानते हुए आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, उच्च अप्राप्य बकाया राशि का बने रहना दंड ढाँचे के निवारक प्रभाव को कमजोर करता है। विभाग सेवा प्रदाताओं द्वारा बार-बार की जाने वाली कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए, एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) स्थापित करके विभिन्न एल एस ए कार्यालयों में सत्यापन मानदंडों की एक समान व्याख्या और दंड की गणना के लिए एक तंत्र को मजबूत करने पर विचार कर सकता है।

अध्याय	<b>व्यय विभाग (डी ओ ई)</b>
IV	

**4.1 केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सी जी ई जी आई एस) दिशानिर्देशों का अनुपालन करना**

केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सी जी ई जी आई एस) 1 जनवरी 1982 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कम मूल्य पर और पूरी तरह से अंशदान और स्व-वित्तपोषण के आधार पर, सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की सहायता के लिए बीमा का लाभ प्रदान करने तथा सेवानिवृत्ति पर उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए एकमुश्त भुगतान के दोहरे लाभ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। योजना के लिए सदस्यों का अंशदान हर महीने उनके वेतन से वसूला जाता है और इसे 70:30 के अनुपात में दो निधि, अर्थात् बचत निधि और बीमा निधि में बांटा जाता है। 01.01.1982 के बाद से वर्ग वार सी जी ई जी आई एस अंशदान की दर तालिका 4.1 में दी गई हैं:

**तालिका 4.1: वर्ग वार सी जी ई जी आई एस अंशदान की दर**

वर्ग	31.12.1989 तक		01.01.1990 से प्रभावी	
	अंशदान की दर (₹ प्रति माह)	बीमा राशि (₹)	अंशदान की दर (₹ प्रति माह)	बीमा राशि (₹)
क	80	80,000	120	1,20,000
ख	40	40,000	60	60,000
ग	20	20,000	30	30,000
घ	10	10,000	15*	15,000

\*पूर्ववर्ती वर्ग 'घ' कर्मचारी जिन्हें पे बैंड-1 में ₹1800 ग्रेड पे के साथ रखा गया था, उन्हें वर्ग 'ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 01.01.2011 से ₹30 प्रति माह की दर से सी जी ई जी आई एस प्रीमियम वसूला जाना है। (ओ.एम. संख्या 7(1)/ई.वी./2008, दिनांक:10.09.2010)

व्यय विभाग (डी ओ ई), वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के तहत कई कार्यालयों के पास इस योजना से जुड़ी परिभाषित भूमिकाएँ हैं। कार्मिक एवं स्थापना प्रभाग के तहत स्थापना-V अनुभाग इस योजना के प्रशासन और समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। सी जी ए कार्यालय का वित्त लेखा अनुभाग, डी ए एम ए (डेटा विश्लेषण और मासिक लेखे) अनुभाग, और सी सी ए (मुख्य लेखानियन्त्रक - वित्त) कार्यालय के तहत वेतन एवं लेखा कार्यालय-आंतरिक ऋण एवं लेखा (पी ए ओ-आई डी ए), इस योजना के ब्याज गणना एवं लेखांकन से सम्बंधित कार्यों में शामिल हैं।

योजना की विस्तृत जांच करने पर हमने पाया कि:

#### 4.1.1 बीमा निधि में ब्याज को शामिल न करना

वित्त मंत्रालय के दिनांक 15 मई 1989 के कार्यालय ज्ञापन (सी जी ई जी आई एस दिशानिर्देश) के पैरा 7.2 के अनुसार, बीमा निधि के अंतर्गत धनात्मक और ऋणात्मक शेष को, जैसा भी मामला हो, डाकघर बचत बैंक (पी ओ एस बी) जमा पर प्रचलित ब्याज दर पर गणना की गई ब्याज राशि के साथ क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बीमा निधि शेष पर ब्याज को बीमा निधि से डेबिट या क्रेडिट नहीं किया गया था। पी ओ एस बी के लिए ब्याज दर 2016-17 से 4 प्रतिशत वार्षिक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई बीमा निधि के वर्ष-वार अथ शेष व अंत शेष और उस पर मिलने वाले ब्याज का विवरण तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.2: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार और लेखापरीक्षा द्वारा गणना किए गए ब्याज सहित बीमा निधि के वर्षवार शेष**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मंत्रालय के अनुसार				लेखापरीक्षा के अनुसार			
	अथ शेष	प्राप्ति	भुगतान	अंत शेष	अथ शेष	अंत शेष	(6) पर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज	अंत शेष (ब्याज सहित)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) + (2) - (3)	(7)	(8) = (6) + (7)
2016-17	-291.82	51.96	48.01	-287.87	-291.82	-287.87	-11.51	-299.38
2017-18	-287.87	54.62	38.66	-271.92	-299.38	-283.42	-11.34	-294.76
2018-19	-271.92	49.02	43.90	-266.79	-294.76	-289.64	-11.59	-301.23
2019-20	-266.79	84.73	57.50	-239.56	-301.23	-274.00	-10.96	-284.96
2020-21	-239.56	53.11	69.17	-255.64	-284.96	-301.02	-12.04	-313.06
2021-22	-255.64	42.27	94.58	-307.95	-313.06	-365.37	-14.61	-379.98
2022-23	-307.95	29.43	66.34	-344.86	-379.98	-416.89	-16.68	-433.57
2023-24	-344.86	74.97	65.05	-334.94	-433.57	-423.65	-16.95	-440.60

उपर दी गई तालिका 4.2 दर्शाती है कि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में ₹(334.94) करोड़ का ऋणात्मक अंत शेष बताया। अगर ब्याज को भी शामिल किया जाता, तो ऋणात्मक अंत शेष ₹(440.60) करोड़ होता। इस तरह, बीमा निधि पर ब्याज का क्रेडिट / डेबिट न होने से योजना की स्व-वित्तपोषण क्षमता में कमी आई और सार्वजनिक खजाने पर बोझ बढ़ गया। मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि वे विश्लेषण करेंगे और तदनुसार इसे शामिल करेंगे।

#### 4.1.2 बचत निधि शेष पर तिमाही चक्रवृद्धि के बजाय वार्षिक साधारण ब्याज

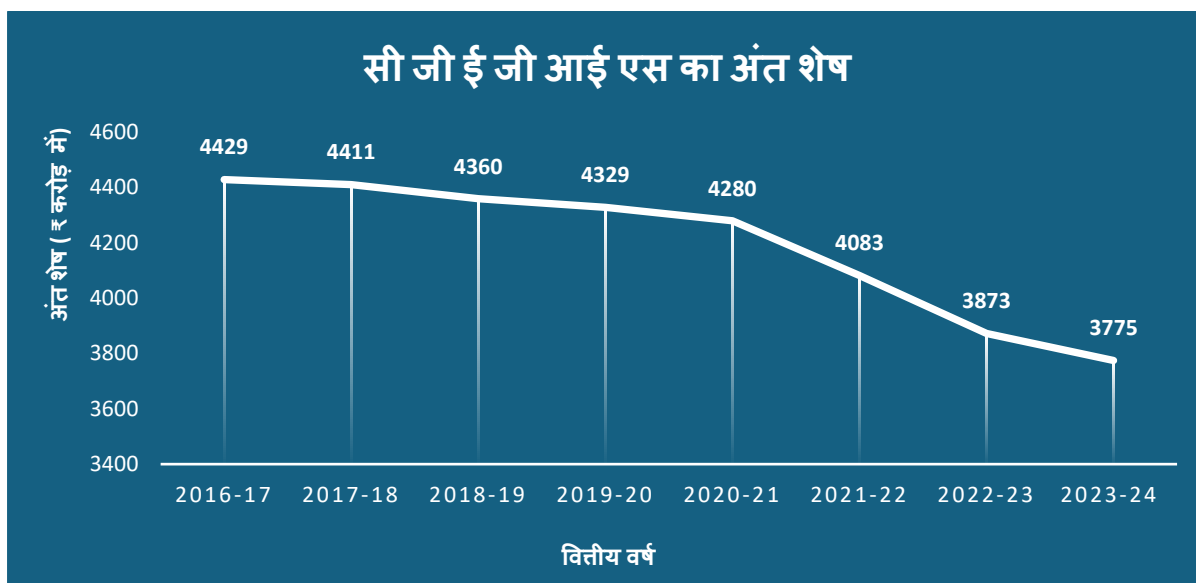
योजना दिशानिर्देशों के पैरा 8.2 के अनुसार, कर्मचारियों को बचत निधि से वास्तविक लाभ के लिए, ब्याज हर तीन महीने में संयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पैरा 8.5 में यह तय किया गया है कि बचत निधि शेष पर ब्याज भी आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर तय की गई दरों पर तिमाही संयोजित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, हालांकि पैरा 8.2 की शर्तों का पालन किया जा रहा है, लेकिन मंत्रालय पैरा 8.5 का पालन नहीं कर रहा है। बचत निधि शेष पर ब्याज तिमाही के बजाय वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, जिससे बचत निधि पर ब्याज कम जमा हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नमूना जांच के आधार पर बचत निधि पर कम जमा ब्याज की गणना ₹7.51 करोड़ आई (विवरण **अनुलग्नक 4.1** में है)। यह मानते हुए कि तिमाही संयोजन का उपयोग योजना शुरू होने के बाद से नहीं किया गया है, कुल कम जमा काफी हो सकता है, जिससे बचत निधि व कुल सी जी ई जी आई एस निधि दोनों के शेष पर काफी असर पड़ सकता है। लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत होते हुए, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2025) कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज संयोजित किया है।

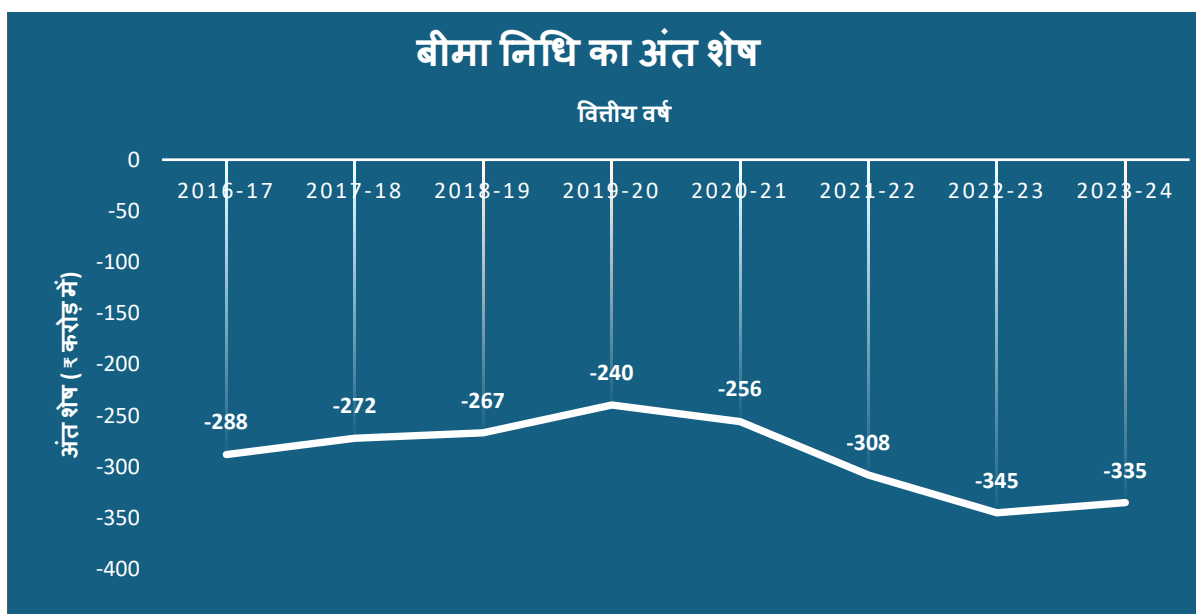
#### 4.1.3 कुल सी जी ई जी आई एस शेष में कमी

सम्बंधित वर्षों के संघ सरकार वित्त लेखे (यू जी एफ ए) के विवरण सं. 14 के अनुसार (**अनुलग्नक 4.2**) सी जी ई जी आई एस निधि में शेष राशि के विवरण से हमने देखा कि 2017-18 से, निधि से संवितरण, निधि में वृद्धियों से अधिक थे। 2016-17 के दौरान संवितरण और वृद्धि का अनुपात 0.96 था और यह अनुपात 2023-24 के दौरान बढ़कर 1.23 हो गया है। यह दर्शाता है कि वार्षिक भुगतान हर वर्ष आगे बढ़ाए जा रहे शेष को कम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि (**चित्र 4.1**), मार्च 2017 में ₹4,429 करोड़ से मार्च 2024 में ₹3,775 करोड़ तक धीरे-धीरे कम हो रही है। यह चिंता का विषय है क्योंकि आगे चलकर शेष राशि प्रतिकूल हो सकती है। बीमा निधि में यह पहले ही ऋणात्मक हो चुका है और ऋणात्मक निधि 2016-17 में ₹288 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹335 करोड़ हो गया है (**चित्र 4.2**)। इससे संघ सरकार की देनदारियां बढ़ जाएंगी क्योंकि सी जी ई जी आई एस ग्राहकों के लाभ के वित्त पोषण के लिए और अधिक संसाधन लगाने होंगे।

चित्र 4.1: पिछले आठ वित्तीय वर्ष के लिए सी जी ई जी आई एस निधि में अंत शेष



चित्र 4.2: पिछले आठ वित्तीय वर्ष के लिए बीमा निधि का अंत शेष



मंत्रालय ने (मार्च 2025) संघ सरकार वित्त लेखे (यू जी एफ ए) के विवरणों के अनुसार सी जी ई जी आई एस की शेष राशि की जानकारी की पुष्टि की, लेकिन सी जी ई जी आई एस निधि शेष में कमी होने पर कोई टिप्पणी नहीं की।

#### 4.1.4 योजना की निर्धारित समयावधि पर समीक्षा न करना

इसके अलावा, योजना के निर्देशों में यह भी कहा गया है कि योजना के काम करने के तरीके पर हर तीन वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना स्व-वित्तपोषित व स्व-सहायक बनी रहे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना शुरू होने के समय (01.01.1982), अंशदान को बीमा निधि में 31.25 प्रतिशत और बचत निधि में 68.75 प्रतिशत बांटा गया था। इसके बाद, 01.01.1988 से, अंशदान का बंटवारा बदलकर बीमा निधि में 30 प्रतिशत और बचत निधि में 70 प्रतिशत कर दिया गया। यह बदलाव ग्राहकों की मृत्यु दर में बदलाव के आधार पर किया गया था, जो 1982 में 3.75 प्रति हजार (1988) से बढ़कर 3.60 प्रति हजार (1988) हो गई थी। व्यय विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) को (अक्टूबर 2023) मृत्यु दर में बढ़ोतरी के बारे में बताए जाने के बावजूद, तब से निधि विभाजन अनुपात को बदला नहीं गया है।

इस बारे में व्यय विभाग ने कहा (नवंबर 2024) कि वे विभाजन अनुपात में बदलाव के लिए डी ओ पी टी से बातचीत कर रहे हैं।

#### 4.1.5 निष्कर्ष

शेष निधि पर ब्याज क्रेडिट / डेबिट करने में योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करने और सी जी ई जी आई एस निधि में शेष राशि के कम होने पर, यह सिफारिश की जाती है कि योजना की समीक्षा जल्द से जल्द की जाए।

अध्याय	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
V	(एम ई आई टी वाई)

## 5.1 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कौशल विकास पहल पर विषय-विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा

### 5.1.1 परिचय

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) आई टी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नीतियाँ बनाकर और उनकी समीक्षा करके भारत की प्रौद्योगिकी प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय की कौशल विकास गतिविधियाँ इसके मानव संसाधन विकास (एच आर डी) प्रभाग द्वारा मुख्य रूप से दो स्वायत्त समितियों, अर्थात् राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी) और प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) के माध्यम से, और एम ई आई टी वाई के अन्य संबद्ध संगठनों, जैसे भारतीय शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क (ई आर एन ई टी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी), इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र (सी-एम ई टी), आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

इस विषय-विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) में मानव संसाधन विकास (एच आर डी) प्रभाग, एम ई आई टी वाई द्वारा लागू की गई तीन मुख्य स्कीम शामिल थीं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- i. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास (ई एस डी एम-I और ई एस डी एम-II)
- ii. आकांक्षी जिलों में सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी (आई ई सी टी) के क्षेत्र में युवाओं [अनुसूचित जाति (एस सी), अनुसूचित जनजाति (एस टी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस) (महिलाएं)] का कौशल विकास, जिससे रोजगार क्षमता में वृद्धि हो (एस डी वाई ए डी)
- iii. भविष्य कौशल प्राइम - रोजगार क्षमता के लिए आईटी जनशक्ति के पुनः कौशल / कौशल उन्नयन का कार्यक्रम (एफ एस पी)

### 5.1.2 लक्ष्य बनाम उपलब्धि

लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि (मार्च 2024 तक) तथा योजनाओं का बजट एवं व्यय नीचे दिया गया है:

तालिका 5.1: लक्ष्य एवं उपलब्धि (अभ्यर्थियों की संख्या)

योजना	ई एस डी एम I (अक्टूबर 2013)	ई एस डी एम II (दिसंबर 2014)	एस डी वाई ए डी (फरवरी 2020)	एफ एस पी (दिसंबर 2019)					
				डीप स्किलिंग (डी एस) (सदस्यता)	डीप स्किलिंग डी एस (निःशुल्क)	फाउंडेशन कोर्स (एफ सी)	ब्रिज कोर्स (बी सी)	सरकारी अधिकारी प्रशिक्षण (जी ओ टी)	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी)
लक्ष्य	90,000	3,28,000	21,600 18,209 (संशोधित)	2,50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	2,000
नामांकित	1,08,625	3,85,303	16,516	30,045	3,43,593	1,06,520	43,660	11,595	2,370
लक्ष्य के सापेक्ष नामांकन	121%	117%	91%	12%	687%	213%	87%	116%	119%
प्रशिक्षित	1,08,438	3,79,950	14,722	23,233	1,46,115	46,471	15,192	11,451	2,367
प्रशिक्षण लक्ष्य के संबंध में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का प्रतिशत	120%	116%	81%	9%	292%	93%	30%	115%	118%
प्रमाणित	82,775	2,57,607	6,821	12,883	24,120	15,492	3,661	10,002	2,041
प्रशिक्षण लक्ष्य के संबंध में प्रमाणित अभ्यर्थियों का प्रतिशत	92%	79%	37%	5%	48%	31%	7%	100%	102%
प्लेसमेंट	36,859	83,615	951	इस योजना का उद्देश्य आईटी पेशेवरों को पुनः कौशल प्रदान करना / उनका कौशल बढ़ाना है।					
प्रमाणित के सापेक्ष प्लेसमेंट	45%	32%	14%						

लक्ष्य बनाम उपलब्धि का विश्लेषण पैरा संख्या 5.1.7.4, पैरा संख्या 5.1.8.3 और पैरा संख्या 5.1.9.1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.2: बजट एवं व्यय (31 मार्च 2024 तक) (₹ करोड़ में)

विवरण	ई एस डी एम-I	ई एस डी एम-II	एस डी वाई ए डी	एफ एस पी
स्वीकृत सहायता अनुदान	₹100.00 करोड़	₹354.85 करोड़	₹29.81 करोड़ (फरवरी 2020) संशोधित ₹32.86 करोड़ (फरवरी 2024)	₹436.87 करोड़
जारी किया (मार्च 2024 तक)	₹76.68 करोड़	₹274.55 करोड़	₹19.17 करोड़	₹154.88 करोड़
कुल व्यय (मार्च 2024 तक)	₹66.71 करोड़ <sup>17</sup>	₹189.01 करोड़	₹16.12 करोड़ <sup>18</sup>	₹156.50 करोड़ <sup>19</sup>

ई एस डी एम योजनाओं में, स्वीकृत सहायता-अनुदान (जी आई ए) का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें पाठ्यक्रम शुल्क, पंजीकरण सह प्रमाणन शुल्क (आर सी सी एफ), ओवरहेड्स और प्लेसमेंट व्यय शामिल हैं, अभ्यर्थियों के प्रमाणन और प्लेसमेंट से जुड़ा था। बजट और व्यय के विश्लेषण से पता चला कि प्रमाणन और प्लेसमेंट लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के परिणामस्वरूप इन घटकों पर कम खर्च हुआ, जिससे स्वीकृत जी आई ए का अपर्याप्त उपयोग हुआ। इसी तरह, एफ एस पी के तहत, स्वीकृत जी आई ए का एक बड़ा हिस्सा प्रोत्साहन भुगतान के लिए निर्धारित किया गया था, जो मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थियों द्वारा प्रोत्साहन का दावा किए जाने पर निर्भर था। हमने देखा कि प्रोत्साहनों के न्यूनतम दावे के कारण प्रोत्साहनों पर व्यय कम हो गया और परिणामस्वरूप स्वीकृत जी आई ए का अपर्याप्त उपयोग हुआ। इसके अलावा, एस डी वाई ए डी योजना में, अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन पर कम व्यय के कारण स्वीकृत जी आई ए का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका। (अनुलग्नक 5.1 में शीर्षवार बजट और व्यय दिया गया है)।

### 5.1.3 लेखापरीक्षा नमूनाकरण

ई एस डी एम के मामले में, कुल 13 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों, ई एस डी एम-I योजना के लिए कर्नाटक, केरल और तेलंगाना तथा ई एस डी एम-II के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति का उपयोग करके नमूने के रूप में लिया गया था। हमने 40 प्रशिक्षण भागीदारों में सर्वेक्षण किया। एस डी वाई ए डी के संबंध में, हमने स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति का उपयोग करके चुने गए पाँच राज्यों, अर्थात् नागालैंड, केरल,

<sup>17</sup> समग्र रूप से, मार्च 2024 तक ई एस डी एम-I के अंतर्गत सहायता-अनुदान (जी आई ए) का 87 प्रतिशत तथा ई एस डी एम-II के अंतर्गत 69 प्रतिशत व्यय किया गया।

<sup>18</sup> एस डी वाई ए डी के अंतर्गत मार्च 2024 तक सहायता-अनुदान (जी आई ए) का 84 प्रतिशत व्यय किया गया।

<sup>19</sup> एफ एस पी के अंतर्गत व्यय स्वीकृत सहायता-अनुदान से अधिक हुआ (101 प्रतिशत)।

जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और बिहार के नो जिलों में लेखापरीक्षा की। एफ एस पी के लिए नमूना संस्थानों के रूप में सी-डैक नोएडा (पी एम यू प्रशासन) और हैदराबाद (पी एम यू प्रौद्योगिकी) को चुना गया।

#### 5.1.4 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि शामिल थी। यह लेखापरीक्षा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों / पी एम यू / पी सी यू में की गई। मंत्रालय के साथ प्रवेश सम्मेलन 27 सितंबर 2023 को और समापन सम्मेलन 28 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पी एम यू, कार्यान्वयन इकाइयों में अभिलेखों / दस्तावेजों की जांच, योजना से संबंधित डेटाबेस का विश्लेषण और एन आई ई एल आई टी / सी-डैक केंद्रों, संबंधित प्रशिक्षण भागीदारों (टी पी) / संसाधन केंद्रों (आर सी) का क्षेत्रीय दौरा शामिल था।

#### 5.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्य यह पता लगाना था:

- क्या कार्यान्वयन संरचना कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकित अभ्यर्थियों के इच्छित कवरेज, प्रशिक्षण, प्रमाणन और प्लेसमेंट के लिए पर्याप्त थी।
- क्या योजनाओं की निगरानी पर्याप्त थी।

#### 5.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानदंड थे:

- इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2012 और 2019, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन ओ एस), जी एफ आर 2017 और वित्त मंत्रालय के संबंधित नियम / विनियम।
- प्रशासनिक अनुमोदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर), दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी), हितधारकों के बीच समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) / समझौते।
- कौशल विकास से संबंधित कैबिनेट द्वारा जारी दिशानिर्देश / मानदंड।
- बैठकों का कार्यवृत्त - परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पी आर एस जी), तकनीकी उप-समिति (टी एस सी), विशेषज्ञ समिति आदि।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एम एस डी ई) द्वारा जारी सामान्य मानदंड तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एन एस क्यू एफ) दिशानिर्देश।

### 5.1.7 इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास (ई एस डी एम-I और ई एस डी एम-II)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई एस डी एम) क्षेत्र में कौशल विकास हेतु ई एस डी एम-I (अक्टूबर 2013) और ई एस डी एम-II (दिसंबर 2014) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ई एस डी एम क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना और देश भर में इसके विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना था। ई एस डी एम-I ने छह राज्यों<sup>20</sup> (बाद में नौ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों<sup>21</sup>), को आवृत्त किया, जबकि ई एस डी एम-II को (दिसंबर 2014 में) देश भर में शुरू किया गया था। दोनों योजनाएँ 31 अगस्त 2025 तक चरणों<sup>22</sup> में बढ़ाई गईं। लक्षित लाभार्थियों में 8वीं / 10वीं पास अभ्यर्थी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) धारक, पॉलिटेक्निक, पूर्वस्नातक और स्नातक अभ्यर्थी शामिल हैं। ई एस डी एम योजना का संचालन और प्रबंधन एन आई ई एल आई टी में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी एम यू) द्वारा किया जाता है, जो एम ई आई टी वाई के तत्वावधान में है, और इसका कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एस आई ए) और प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों (के आई ए), अर्थात् एन आई ई एल आई टी, दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद (टी एस एस सी) और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद (ई एस एस सी आई) के माध्यम से उनके संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (टी पी) द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की पद्धति तथा प्रक्रिया प्रवाह को **अनुलग्नक 5.2** में दर्शाया गया है।

### लेखापरीक्षा अवलोकन

#### 5.1.7.1 पंजीकरण प्रक्रिया

योजना के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान था कि प्रशिक्षण भागीदार (टी पी) को पंजीकरण के समय यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी के पास वैध आधार संख्या हो, ताकि आधार प्रमाणीकरण या ई-के वाई सी प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी की विशिष्टता को बनाए रखा जा सके। यदि आधार उपलब्ध नहीं है, तो टी पी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी आधार के लिए नामांकन कराए और नामांकन संख्या को एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में स्वीकार करे। इसमें यह भी प्रावधान था कि एक अभ्यर्थी इस योजना के तहत केवल एक बार ही लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। एक अभ्यर्थी को क्रमिक स्तरों पर केवल विनिर्माण क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में एक समय में दो पाठ्यक्रम करने की अनुमति थी।

<sup>20</sup> आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, पंजाब और कर्नाटक

<sup>21</sup> बाद में इसे तेलंगाना (सितंबर 2014), उत्तर प्रदेश (सितंबर 2014) और लद्दाख (जनवरी 2021) तक विस्तारित किया गया।

<sup>22</sup> इसे क्रमशः नवंबर 2018 में मार्च 2020 तक, फरवरी 2020 में मार्च 2021 तक, मार्च 2021 में मार्च 2022 तक, दिसंबर 2021 में मार्च 2023 तक, मार्च 2023 में मार्च 2024 तक, अप्रैल 2024 में दिसंबर 2024 तक तथा जुलाई 2025 में अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया।

हमने 4.78 लाख लाभार्थियों (दिसंबर 2023 तक) के डेटाबेस से देखा कि समान जनसांख्यिकीय विवरण (समान नाम और जन्मतिथि) वाले 446 लाभार्थियों<sup>23</sup> को अलग-अलग आई डी के साथ ई एस डी एम पोर्टल में कई बार नामांकित और प्रमाणित किया गया था, जो समान / अलग टी पी के तहत फैले हुए थे, जिससे लाभार्थियों की विशिष्टता के बारे में चिंता उत्पन्न हुई।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने (जुलाई 2024) उत्तर दिया कि वेब पोर्टल पर उपलब्ध शर्तों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को अलग-अलग आधार संख्या / आधार नामांकन संख्या के साथ पंजीकृत किया गया है। लेखापरीक्षा टीम द्वारा साझा किए गए व्यक्तिगत डेटा की जाँच करने पर यह पाया गया कि डेटा केवल अभ्यर्थियों की जन्मतिथि और नाम के आधार पर जांच-परख कर निकाला गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि समान विवरण वाले 100 से अधिक अभ्यर्थियों को अलग-अलग आधार / आधार नामांकन संख्याओं के साथ नामांकित किया गया था और अन्य अभ्यर्थियों के माता-पिता का नाम, फोटो और आधार / आधार नामांकन संख्या भिन्न थी।

उपरोक्त 446 प्रमाणपत्रों में से केवल 14 प्रमाणपत्र ही लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए। हमने पाया कि लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों में न केवल नाम और जन्मतिथि में, बल्कि पिता / माता का नाम, जिला / राज्य, टी पी और फोटोग्राफ जैसे अन्य क्षेत्रों में भी समानताएँ थीं। दो केस स्टडी उपरोक्त असंगति को उजागर करती हैं, जो पंजीकरण में दोहराव का संकेत देती हैं।

### बॉक्स 5.1 केस स्टडीज़

#### केस स्टडी-1

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई अभ्यर्थी सेवा क्षेत्र में एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण नहीं कर सकता है। श्री डी. बी. ने 15 मार्च 2021 को ई एस एस सी आई (इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया) से टी बी एल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड (टी पी) के माध्यम से "फील्ड टेक्नीशियन-नेटवर्किंग एंड स्टोरेज" (एक सेवा क्षेत्र का पाठ्यक्रम) के लिए मोरीगांव जिले, असम में पंजीकरण आई डी "ई एस डी एम-ए एस-एस टी यू-004871" के साथ प्रमाणन प्राप्त किया। पंजीकरण में उनकी मां को सुश्री एच. बी. और उनके पिता को श्री एस. बी. के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 23 अप्रैल 2021 को, श्री डी. बी. को फिर से ई एस एस सी आई द्वारा टी बी एल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड (टी पी) के माध्यम से "इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन-कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स" (एक सेवा क्षेत्र का पाठ्यक्रम) के लिए पंजीकरण आई डी "ई एस डी एम-ए एस-एस टी यू-008974" के साथ प्रमाणित किया गया। इस पंजीकरण में उनकी मां को सुश्री जी. बी. और उनके पिता को श्री एस. बी. के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। दोनों प्रमाणपत्रों में अभ्यर्थी का एक ही

<sup>23</sup> कुल 446 लाभार्थी मामलों में से 369 सेवा क्षेत्र से, 33 विनिर्माण क्षेत्र से तथा 44 सेवा और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों से संबंधित थे। इनमें से 219 मामले एक ही प्रशिक्षण भागीदार के अंतर्गत थे।

फोटोग्राफ है। पहले प्रमाणपत्र में आधार संख्या शामिल है, जबकि दूसरे प्रमाणपत्र में आधार संख्या के लिए "उपलब्ध नहीं" लिखा है।

### केसस्टडी-2

16 सितंबर 2022 को श्री ए. के. को टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल (टी एस एस सी) द्वारा जेनटेक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी (टी पी) के माध्यम से "सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन" (सेवा क्षेत्र का पाठ्यक्रम) के लिए गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण आई डी "ई एस डी एम-यू पी-एस टी यू-016111" के साथ प्रमाणित किया गया। पंजीकरण में उनकी मां को सुश्री जीई. डी. के रूप में और उनके पिता को श्री जे. पी. एस. के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। श्री ए. के. को 29 सितंबर 2022 को टी एस एस सी द्वारा उसी संस्थान से "सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन" के उसी पाठ्यक्रम के लिए गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण आई डी "ई एस डी एम-यू पी-एस टी यू-016344" के साथ फिर से प्रमाणित किया गया। इस पंजीकरण में उनकी मां को सुश्री जी आई. डी. के रूप में और उनके पिता को श्री जे. पी. एस. के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

दोनों प्रमाणपत्रों में अभ्यर्थी का एक ही फोटोग्राफ है। पहले प्रमाणपत्र में आधार संख्या शामिल है, जबकि दूसरे प्रमाणपत्र में आधार संख्या ..... (अर्थात् रिक्त) है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने (मई 2025) उत्तर दिया कि कुल 4.93 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में से यह देखा गया है कि बहुत कम मामलों (0.02 प्रतिशत) में अभ्यर्थी / टी पी द्वारा अपलोड की गई तस्वीरें उचित नहीं हैं या डुप्लिकेट हैं। इस पर ध्यान दिया गया है और के आई ए / टी पी को यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया है कि अपलोड की गई तस्वीरें सभी मामलों में भी अलग-अलग हों।

आधार / नामांकन संख्या / वैध आई डी प्रमाणीकरण के बिना अभ्यर्थियों का पंजीकरण / प्रमाणन पोर्टल की डी-डुप्लीकेशन प्रणाली में कमजोरियों और योजना के अंतर्गत प्रमाणित अभ्यर्थियों की बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्टिंग तथा अतिरिक्त व्यय के जोखिम की ओर इशारा करता है।

### 5.1.7.2 ई एस डी एम योजना में अभ्यर्थियों से पंजीकरण-सह-प्रमाणन शुल्क (आर सी सी एफ) का संग्रह न किया जाना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशिक्षण भागीदारों (टी पी) को नामांकन के समय प्रत्येक अभ्यर्थी से पंजीकरण-सह-प्रमाणन शुल्क (आर सी सी एफ) लेना आवश्यक है, ताकि बैच के प्रारंभ होने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर के आई ए (एन आई ई एल आई टी / ई एस एस सी आई / टी एस एस सी, जैसा भी मामला हो) को जमा किया जा सके। हालाँकि, 40 टी पी में किए गए हमारे सर्वेक्षण से पता चला कि उनमें से 33 नामांकन के समय अभ्यर्थियों से आर सी सी एफ नहीं ले रहे थे। इसके बजाय,

ये टी पी स्वयं लागत वहन कर रहे थे और बाद में उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सफल अभ्यर्थियों के लिए के आई ए से प्रतिपूर्ति का दावा कर रहे थे।

एम ई आई टी वाई ने (दिसंबर 2024) उत्तर दिया कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से अभ्यर्थी आर सी सी एफ राशि जमा करने में असमर्थ थे। वर्तमान में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संबंधित प्रशिक्षण भागीदारों से आर सी सी एफ राशि एकत्र की जाए और उसके बाद, अभ्यर्थियों के के आई ए-आधारित तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रमाणित होने के बाद, यह राशि प्रशिक्षण भागीदारों को वापस कर दी जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा केवल गंभीर और इच्छुक अभ्यर्थियों को ही संगठित और प्रशिक्षित किया जाए।

लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा बताई गई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करती है। हालाँकि, अभ्यर्थियों से आर सी सी एफ की वसूली न करना योजना के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यपद्धति इच्छुक अभ्यर्थियों की वित्तीय प्रतिबद्धताओं के माध्यम से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के इच्छित उद्देश्य को विफल करती है।

### 5.1.7.3 मूल्यांकन और प्रमाणन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने के दो सप्ताह के भीतर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन पूरा हो जाना चाहिए। हमने देखा (मार्च 2024) कि 42,120 अभ्यर्थियों वाले 1,526 बैचों का मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसमें 2019-20 से 8,103 अभ्यर्थियों वाले 320 बैच शामिल थे। इस अवलोकन को 8वें परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पी आर एस जी) द्वारा और बल दिया गया है, जिसने (मई 2024) में उल्लेख किया कि कुल 4,88,388 प्रशिक्षित छात्रों में से 44,940 छात्रों का प्रमाणन मार्च 2024 तक लंबित था।

इसके अलावा, के आई ए को मूल्यांकन किए जाने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर ई एस डी एम पोर्टल पर मूल्यांकन परिणाम अपलोड करने और परिणाम घोषित होने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर पोर्टल पर प्रमाणपत्र अपलोड करने की आवश्यकता है। हमने तीन<sup>24</sup> चयनित राज्यों में के आई ए द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने और अपलोड करने में देरी देखी, जिसमें 279 छात्रों के चार से छह बैचों में 25 से 736 दिनों के बीच की देरी हुई।

एम ई आई टी वाई ने (मई 2025) उत्तर दिया कि मूल्यांकन में देरी मुख्य रूप से प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा के आई ए को आर सी सी एफ भुगतान में देरी और प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को जुटाने तथा तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ताओं के साथ कार्यक्रम समन्वय करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण हुई।

<sup>24</sup> मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र।

मूल्यांकन और प्रमाणन में लंबे समय तक देरी मंत्रालय की कमजोर निगरानी को दर्शाती है, जिससे अभ्यर्थियों की रोजगार पाने की क्षमता प्रभावित होती है और इस प्रकार योजना के रोजगार-योग्यता के उद्देश्य को कमजोर किया जाता है; साथ ही टी पी और अभ्यर्थियों की प्रेरणा तथा सहभागिता भी कम होती है। देरी को दूर करने के लिए टी पी और के आई ए की सक्रिय निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

#### 5.1.7.4 प्लेसमेंट पहल और रोजगार परिणाम

(i) योजना के दिशानिर्देशों<sup>25</sup> के अनुसार, ई एस डी एम योजना की सफलता की माप प्रमाणित अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट के आधार पर की जाती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ई एस डी एम-I और ई एस डी एम-II (मार्च 2024 तक) में 4.88 लाख प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 3.40 लाख अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया (प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का 69.70 प्रतिशत), जिसके परिणामस्वरूप प्रमाणन अंतराल 1.48 लाख रहा, जैसा कि तालिका 5.1 में दर्शाया गया है। जबकि 10 पाठ्यक्रम सफल पाए गए, जिनमें 1,388 अभ्यर्थियों को 100 प्रतिशत प्लेसमेंट मिला, वहीं 43 पाठ्यक्रमों में 6,256 अभ्यर्थियों का नामांकन अनुत्पादक रहा और उन्हें कोई प्लेसमेंट नहीं मिला। इसके अलावा, कुल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से केवल 25 प्रतिशत<sup>26</sup> अभ्यर्थियों को ही अंततः प्लेसमेंट मिल सका।

एम ई आई टी वाई ने (अक्टूबर 2024) कहा कि प्लेसमेंट-केंद्रित मॉडल, जैसे कि 'प्लेस एंड ट्रेन' दृष्टिकोण, जिसे अब लागू किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि नामांकन और प्रशिक्षण भावी नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित हों।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि "प्लेस एंड ट्रेन" को अपनाने की आवश्यकता का उल्लेख 2015 में योजना के दिशानिर्देशों में किया गया था, इसे जुलाई 2022 से ही लागू किया गया। इस प्रकार, प्लेस एंड ट्रेन मॉडल के विलंबित कार्यान्वयन (जुलाई 2022 तक) के कारण प्रमाणित अभ्यर्थी प्लेसमेंट सहायता से वंचित रह गए, जिससे योजना का अपेक्षित प्रभाव सीमित हो गया।

ii. इसके अलावा, दिशानिर्देशों<sup>27</sup> में यह निर्धारित किया गया था कि प्रशिक्षण साझेदारों (टी पी) को प्लेसमेंट के लिए उद्योगों से आशय पत्र (एल ओ आई) प्राप्त करना और प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों (के आई ए) के माध्यम से परियोजना प्रबंधन इकाई (पी एम यू) को प्रस्तुत करना आवश्यक था। पी एम यू द्वारा इन एल ओ आई की समीक्षा और चयन किया जाना था, फिर समन्वय समिति द्वारा सिफारिश की जानी थी, और अंत में विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित करके संबंधित के आई ए को सूचित किया जाना था। योजना के दिशानिर्देशों में संपूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया के लिए 15 दिन की

<sup>25</sup> के आई ए की जिम्मेदारी, पैरा 5 (f) (6)।

<sup>26</sup> कुल 4,88,388 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 1,20,474 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राप्त हुई (योजना I और II को मिलाकर, जैसा कि तालिका 5.1 में संदर्भित है)।

<sup>27</sup> के आई ए की जिम्मेदारी, पैरा 5।

समय-सीमा निर्धारित की गई थी, जिसकी गणना एल ओ आई जमा करने की तारीख से की गई थी। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, संबंधित के आई ए / टी पी को बैच आरंभ करने के लिए अगले 15 दिनों के भीतर बैच विवरण अपलोड करना आवश्यक था, ऐसा न करने पर सीटें मुख्य रिक्ति पूल में वापस सरेंडर / विलय हो जाएंगी।

हमने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद (ई एस एस सी आई) में पाया कि के आई ए द्वारा प्रस्तुत 300 एल ओ आई में से 111 एल ओ आई में अनुमोदन प्राप्त करने में 120 से 491 दिनों तक की देरी हुई, जिसके कारण इस मॉडल के समय पर कार्यान्वयन में और अधिक देरी हुई।

एम ई आई टी वाई ने (जुलाई 2024) बताया कि इस मॉडल में उद्योगों से प्राप्त एल ओ आई के मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिनमें दस्तावेज़ सत्यापन और संबंधित कंपनियों से पुष्टिकरण ई-मेल शामिल हैं। एल ओ आई प्रक्रिया में देरी आंशिक रूप से कोविड-19 के प्रभाव के कारण भी देखी गई, जिसके कारण प्रशिक्षण रुक गया और उद्योग बंद हो गए तथा अनुबंध रद्द हो गए। कुछ मामलों में, उद्योगों द्वारा जारी करने की तिथि के अनुसार, के आई ए द्वारा देरी के कारण पी एम यू को एल ओ आई देर से प्राप्त हुए।

लेखापरीक्षा स्वीकार करती है कि प्रमाणन निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है (जून 2025 तक 69.70 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत), लेकिन प्लेसमेंट निष्पादन निम्न स्तर पर बना हुआ है; अर्थात् 28 प्रतिशत। मंत्रालय को योजना में परिकल्पित प्लेसमेंट / रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक उचित उपाय करने की आवश्यकता है।

#### 5.1.7.5 ई एस डी एम योजना में प्रशिक्षुओं की ट्रेकिंग

भारत सरकार द्वारा अगस्त 2015 में घोषित कौशल विकास योजनाओं के सामान्य मानदंडों<sup>28</sup> के अनुसार, प्रशिक्षित सभी प्रशिक्षुओं को, नए प्रवेशकों के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पुनः कौशलीकरण और कौशल उन्नयन के मामले में प्रशिक्षण पूरा होने / प्रमाणन की तिथि से 14 महीने की अवधि के लिए उनके कैरियर की प्रगति, प्रतिधारण और अन्य मापदंडों के संबंध में ट्रैक किया जाएगा।

हालाँकि, हमने पाया कि योजनाओं ने सामान्य मानदंडों का उल्लंघन करते हुए केवल तीन महीने तक ही रोजगार के इस प्रमुख मानदंड पर नज़र रखी।

एम ई आई टी वाई ने (मई 2025) में कहा कि ई एस डी एम क्षेत्र योजनाएँ (योजना-I और योजना-II) अगस्त 2015 में सामान्य मानदंडों की अधिसूचना से पहले मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थीं।

<sup>28</sup> सामान्य मानदंड कौशल विकास से संबंधित संपूर्ण प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य रखते हैं, जिनमें इनपुट, आउटपुट, वित्तपोषण / लागत मानदंड, तृतीय-पक्ष प्रमाणन और मूल्यांकन, निगरानी / ट्रैकिंग तंत्र तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं को सूचीबद्ध करना शामिल हैं।

यद्यपि मंत्रालय ने सामान्य मानदंडों के अनुरूप ई एस डी एम योजनाओं की संरचना में संशोधन किया था (जून 2016), फिर भी अभ्यर्थियों के लिए ट्रेकिंग अवधि को तदनुसार नहीं बढ़ाया गया था। इससे रोजगार क्षमता की दृष्टि से योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है। मंत्रालय योजना के इच्छित प्रभाव को बढ़ाने तथा प्लेसमेंट प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रशिक्षुओं की ट्रेकिंग के संबंध में सामान्य मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

#### 5.1.7.6 प्रशिक्षण भागीदारों को पंजीकरण सह प्रमाणन शुल्क (आर सी सी एफ) और पाठ्यक्रम शुल्क (सी एफ) की प्रतिपूर्ति

इनवॉइस डेटाबेस की जाँच से पता चला कि कोर्स शुल्क (सी एफ) और आर सी सी एफ की प्रतिपूर्ति के लिए ₹8.93 करोड़ की राशि 42 महीनों<sup>29</sup> तक लंबित थी। मार्च 2024 तक, दोनों योजनाओं के 1,040 बैचों के लिए, जहाँ मूल्यांकन और प्रमाणन पूरे हो चुके थे, टी पी को धनराशि जारी की जानी थी।

एम ई आई टी वाई ने कहा (जुलाई 2024) कि अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और अनुपालन के लिए दस्तावेजों को आगे प्रस्तुत करना (गलतियों / गलत दस्तावेजों के मामले में) समय लेने वाला था और इसके परिणामस्वरूप संबंधित टी पी को सी एफ / आर सी सी एफ राशि के प्रसंस्करण और प्रतिपूर्ति में देरी हुई। 1,040 बैचों में से केवल 787 बैचों के इनवॉइस की हार्ड कॉपी पी एम यू द्वारा प्राप्त की गई है और 253 इनवॉइस संबंधित के आई ए में लंबित हैं। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त 787 बैचों में से 417 बैचों को संसाधित किया गया था और 370 बैच के आई ए / टी पी से आगे की आवश्यकता वाले दस्तावेजों / कार्रवाई के कारण लंबित हैं। अप्रैल 2024 के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सभी लंबित प्रतिपूर्तियाँ 31 दिसंबर 2024 तक पूरी की जा सकती हैं।

यद्यपि प्रसंस्करण में देरी के कारणों को स्वीकार किया गया है, परन्तु लंबित प्रतिपूर्ति राशि का निपटान नहीं किया जा सका और (27 जून 2025 तक) ₹4.79 करोड़ पर बनी रही।

प्रतिपूर्ति दावों के लंबे समय तक लंबित रहने तथा मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकार किए जाने से प्रभावी निगरानी में कमियाँ परिलक्षित होती हैं, तथा टी पी पर वित्तीय दबाव को रोकने के लिए समय पर समाधान तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है।

#### 5.1.7.7 निधि प्रबंधन और योजना

**क) धनराशि जारी करने में विलंब:** जी एफ आर-232 (vi) के अनुसार, वर्ष के अंत में बड़ी मात्रा में धनराशि जारी होने से रोकने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। हमने 19 ऐसे मामले देखे

<sup>29</sup> ₹0.99 करोड़ वर्ष 2020-21 से, ₹0.62 करोड़ वर्ष 2021-22 से, ₹1.59 करोड़ वर्ष 2022-23 से तथा ₹4.64 करोड़ वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त ₹1.09 करोड़ उन प्रविष्टियों से संबंधित है जिनमें भौतिक इनवॉइस प्राप्ति की तिथि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनवॉइस के वर्ष का निर्धारण नहीं किया जा सका।

हैं जहाँ 2014-15 से 2021-22 के दौरान दोनों योजनाओं (ई एस डी एम I और ई एस डी एम II) के तहत वर्ष के अंत में ₹37.21 करोड़ की धनराशि जारी की गई।

मई 2025 तक इस संबंध में मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

वित्तीय वर्ष के अंत में बड़ी मात्रा में धनराशि जारी किए जाने से धनराशि के प्रभावी उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है या जल्दबाज़ी में व्यय किए जाने का जोखिम बढ़ जाता है।

**ख) उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण:** नियम 238 के अनुसार, संबंधित संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह माह के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हमने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी देखी, जो ई एस डी एम I में एक से तीन वर्ष तक तथा ई एस डी एम II में एक से दो वर्ष तक थी।

एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (मई 2025) कि के आई ए द्वारा नियुक्त तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थियों के मूल्यांकन / प्रमाणन में किसी भी प्रकार की देरी के परिणामस्वरूप दावों / इनवॉइस के प्रसंस्करण में कुछ देरी हुई। इसलिए, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में एक व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्नत निगरानी तंत्रों के माध्यम से उपयोगिता प्रमाणपत्रों के आगे प्रस्तुतीकरण का समाधान किया जा रहा है, जिससे योजना की वित्तीय और परिचालनात्मक सुदृढ़ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकेगा।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के विलंबित प्रस्तुतीकरण से वित्तीय निगरानी कमजोर होती है और धनराशि के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।

**5.1.8 आकांक्षी जिलों में सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी (आई ई सी टी) के क्षेत्र में युवाओं [अनुसूचित जाति (एस सी), अनुसूचित जनजाति (एस टी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस) (महिलाएं)] का कौशल विकास, जिससे रोजगार क्षमता में वृद्धि हो (एस डी वाई ए डी)**

नीति आयोग ने सामाजिक-आर्थिक विषयों<sup>30</sup> के आधार पर 112 आकांक्षी जिलों की पहचान की थी। एम ई आई टी वाई ने शुरुआत में फरवरी 2020 में 60 आकांक्षी जिलों में इस योजना को शुरू किया, जिसका उद्देश्य चार<sup>31</sup> प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से आई ई सी टी क्षेत्र में युवाओं [अनुसूचित जाति (एस सी) / अनुसूचित जनजाति (एस टी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस) (महिलाएं)] के कौशल में सुधार कर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना था, जिसे बाद में (जून 2023) में 81 जिलों तक

<sup>30</sup> स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा अवसंरचना।

<sup>31</sup> प्रमाणित डेटा एंट्री एवं कार्यालय सहायक (अपस्किलिंग), प्रमाणित कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग एवं पब्लिशिंग सहायक, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की स्थापना एवं मरम्मत में डिप्लोमा तथा सोलर एलईडी लाइटिंग उत्पाद (डिज़ाइन एवं विनिर्माण)।

विस्तारित किया गया। यह योजना फरवरी 2023 में समाप्त होनी थी, लेकिन इसे चरणों<sup>32</sup> में अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया।

एन आई ई एल आई टी मुख्यालय में परियोजना समन्वय इकाई (पी सी यू) प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों (टी पी) को नियुक्त करती है तथा समग्र प्रबंधन का कार्य संभालती है, जबकि लखनऊ, गुवाहाटी और औरंगाबाद स्थित तीन क्षेत्रीय पी सी यू क्षेत्रीय कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन की पद्धति तथा प्रक्रिया प्रवाह को **अनुलग्नक 5.2** में दर्शाया गया है।

## लेखापरीक्षा अवलोकन

### 5.1.8.1 एस डी वाई ए डी योजना में शून्य पंजीकरण वाले जिले

प्रशिक्षण भागीदार लाभार्थी / अभ्यर्थी का चयन करने, अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण आयोजित करने तथा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन संबंधी मामलों में उनकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार थे।

हालाँकि, 21 जिलों में (मार्च 2024 तक) एन आई ई एल आई टी द्वारा किसी भी टी पी का चयन नहीं किया जा सका। इसके अलावा, 21 में से 18 जिलों में, हालाँकि इन्हें जून 2023 में जोड़ा गया था, क्षेत्रीय एन आई ई एल आई टी केंद्रों द्वारा नौ महीने बीत जाने के बाद भी टी पी की पहचान नहीं की जा सकी, जिसके कारण इन 18 में से 17 जिलों में शून्य पंजीकरण हुआ।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा (मई 2025) कि प्रमुख चुनौती इस क्षेत्र में संभावित टी पी की अनुपलब्धता थी।

इस प्रकार, यह जिलावार टी पी उपलब्धता के योजना-निर्माण और आकलन में अंतराल को उजागर करता है।

### 5.1.8.2 डेटा में सत्यापन और प्रामाणिकता का अभाव

योजना की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस ओ पी) के अनुसार, प्रशिक्षण भागीदार (टी पी) प्रत्येक बैच के प्रत्येक छात्र के आवश्यक दस्तावेजों<sup>33</sup> की गहन जाँच के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर उन्हें अपलोड करेंगे और उसके पश्चात अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण में सहायता करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के प्रवेश के बाद पोर्टल पर अपलोड किए गए लाभार्थी के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो प्रशिक्षण भागीदार (टी पी) को प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी। एस ओ पी में यह भी प्रावधान है कि एक छात्र इस योजना का लाभ केवल एक बार ही ले सकता है।

<sup>32</sup> इसे जून 2023 में फरवरी 2024 तक, फरवरी 2024 में फरवरी 2025 तक तथा मार्च 2025 में अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया।

<sup>33</sup> जैसे जाति प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (10वीं / 12वीं / आई टी आई), पहचान प्रमाण तथा ई डब्ल्यू एस प्रमाणपत्र।

हमने एन आई ई एल आई टी मुख्यालय (<http://student.NIELIT.gov.in>) के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की समीक्षा की और पाया कि पोर्टल पर केवल फोटो, हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करने के विकल्प उपलब्ध थे, लेकिन जाति प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, आई डी प्रमाण, ई डब्ल्यू एस प्रमाणपत्र आदि जैसे अन्य दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार, पोर्टल में छात्रों के रिकॉर्ड की दोहरेपन की जाँच के लिए पर्याप्त जाँच का अभाव था।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) पोर्टल पर उपलब्ध पंजीकृत अभ्यर्थियों के डेटाबेस (दिनांक 23 फरवरी 2023 तक 12,840 अभिलेख) की समीक्षा से निम्नलिखित अनियमितताएँ उजागर हुईं:

**क) एकाधिक नामांकन द्वारा:**

- i. एक ही पाठ्यक्रम में एक ही अभ्यर्थी (14 एन आई ई एल आई टी केन्द्रों के 256 अभिलेख)
- ii. एक ही अभ्यर्थी एक से अधिक पाठ्यक्रमों में (10 एन आई ई एल आई टी केन्द्रों के 154 अभिलेख)
- iii. एक ही अभ्यर्थी का एक ही पाठ्यक्रम में भिन्न एन आई ई एल आई टी केंद्र (एक मामला)

**ख) कार्यक्षमता का अस्तित्व:** हालाँकि यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) के अभ्यर्थियों के लिए थी, लेकिन डेटाबेस से चार ऐसे उदाहरण सामने आए जहाँ एक ही अभ्यर्थी ने एक साथ एक से अधिक श्रेणियों का चयन किया। पोर्टल एकाधिक श्रेणियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बीच) का चयन करने की अनुमति देता है और एक बार श्रेणी चुन लेने के बाद अन्य विकल्पों को अक्षम नहीं करता। एक ही समय में कई नामांकन / श्रेणी चयन की ऐसी कार्यक्षमता योजना की रिपोर्टिंग को विकृत कर सकती है और इसके परिणामस्वरूप अयोग्य अभ्यर्थी का चयन हो सकता है।

**ग) अमान्य मोबाइल नंबरों के साथ पंजीकरण:** अमान्य मोबाइल नंबरों (50 रिकॉर्ड) जैसे नौ और चार अंकों वाले मोबाइल नंबर, तीन अंक से शुरू होने वाले मोबाइल नंबर आदि पाए गए, जिससे पोर्टल के डेटा सत्यापन नियंत्रण तंत्र में कमी का संकेत मिलता है।

एन आई ई एल आई टी मुख्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि एम आई एस पोर्टल में टी पी द्वारा गलती से रिकॉर्ड दो बार दर्ज कर दिए गए थे, हालाँकि इन अभ्यर्थियों की पंजीकरण आई डी विशिष्ट है और अभ्यर्थियों को केवल पंजीकरण संख्या के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है और कोई दोहरा लाभ नहीं दिया गया। हालाँकि, एम आई एस डेटाबेस से दोहराव को जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। एन आई ई एल आई टी मुख्यालय ने पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने की किसी सुविधा के अभाव और टी पी स्तर पर दस्तावेजों की जाँच के लिए मैनुअल तंत्र की विद्यमानता को स्वीकार किया। पोर्टल में इन सुविधाओं के विकास न होने का कारण धन की कमी बताया गया।

एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (मई 2025) और कहा कि एन आई ई एल आई टी ने डेटा सटीकता में सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

### 5.1.8.3 कम प्लेसमेंट पहल

इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिलाएँ) के युवाओं को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के अनुसार, एन आई ई एल आई टी केंद्र संबंधित जिले की क्षेत्रीय परियोजना समन्वय इकाई (आर पी सी यू) और टी पी के माध्यम से एन आई ई एल आई टी केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन करेगा / उद्योग के साथ संबंध स्थापित करेगा / यदि संभव हो तो ऑनलाइन दूरस्थ साक्षात्कार आयोजित करेगा और प्रमाणित अभ्यर्थियों को उपयुक्त नौकरी पाने में सहायता करेगा। दूसरे पी आर एस जी (फरवरी 2022) ने अभ्यर्थियों को नियोजित करने या उन्हें संभावित उद्योगों से जोड़ने की अनुशंसा की। चौथे पी आर एस जी (जून 2023) ने के आई ए को एक विशेष प्लेसमेंट कक्ष स्थापित करने, अधिक अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट दिलाने के लिए आधारभूत कार्य करने तथा प्लेसमेंट के लिए अन्य मंत्रालयों की समकालीन योजनाओं / कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का निर्देश दिया।

योजना के कार्यान्वयन में पर्याप्त संख्या में लाभार्थियों की कमी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण प्रथम दृष्टया मूल लक्ष्य में कमी आई और योजना को अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया। जैसा कि तालिका 5.1 में दर्शाया गया है, मार्च 2024 तक कुल प्रमाणित अभ्यर्थियों में से केवल 14 प्रतिशत को ही प्लेसमेंट मिला, जो कमजोर रोजगार परिणाम को दर्शाता है।

एम ई आई टी वाई ने उत्तर दिया (मई 2025) कि प्लेसमेंट योजना / परियोजना का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तथापि, आर पी सी यू और मॉडल कैरियर सेंटर (एम सी सी) के सहयोग से एन आई ई एल आई टी 1,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट दिलाने में सक्षम रहा।

यद्यपि लेखापरीक्षा योजना दिशानिर्देशों, एस ओ पी तथा पी आर एस जी के निर्देशों के अनुरूप प्लेसमेंट को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करती है, फिर भी योजना के अपेक्षित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए प्लेसमेंट से संबंधित संबंधों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

### 5.1.8.4 प्रशिक्षण भागीदार (टी पी) द्वारा मैनुअल इनवाइस जारी करना

मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस ओ पी) के अनुसार, प्रशिक्षण और बैच के प्रमाणन के पूरा होने के बाद, टी पी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से प्रशिक्षण शुल्क के लिए इनवाइस तैयार किया जाएगा और एन आई ई एल आई टी के नोडल अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा।

हालाँकि हमने देखा (मार्च 2024) कि इन प्रावधानों के विपरीत, पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज<sup>34</sup> अपलोड किए बिना, मैन्युअल इनवॉइस के आधार पर टी पी को भुगतान किया गया था।

एन आई ई एल आई टी मुख्यालय ने बताया (अप्रैल 2024) कि यद्यपि बिलों की ऑनलाइन निगरानी और सत्यापन का प्रावधान है, लेकिन निधि की अनुपलब्धता के कारण यह सुविधा क्रियान्वित नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, एम ई आई टी वाई ने बताया (मई 2025) कि एन आई ई एल आई टी पोर्टल में ऑनलाइन इनवॉइस जनरेशन सुविधा अंतिम चरण में है।

ऑनलाइन इनवॉइस जनरेशन और मॉनिटरिंग सुविधा के क्रियान्वयन में देरी मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के प्रावधानों से विचलन तथा कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र की उपस्थिति को दर्शाती है। इसके अलावा, निधि की अनुपलब्धता संबंधी प्रतिक्रिया तथ्यों से पुष्ट नहीं होती है, क्योंकि अप्रयुक्त राशि सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त ₹1.76 करोड़ (प्रथम वर्ष) और ₹1.28 करोड़ (द्वितीय वर्ष) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वापस कर दी गई, जिसका एक हिस्सा योजना के प्रावधानों के अनुरूप पोर्टल विकास के लिए उपयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपकरणों पर स्वीकृत ₹8 लाख के जी आई ए के विरुद्ध ₹3 लाख की राशि अव्ययित रही (अगस्त 2025)।

#### 5.1.8.5 वर्ष के अंत में धनराशि जारी करना

जी एफ आर नियम 232 (vi) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में बड़ी मात्रा में धनराशि जारी होने से रोकने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

हमने देखा (मई 2024) कि जारी किए गए ₹19.17 करोड़ के जी आई ए में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹6 करोड़ की राशि जी एफ आर प्रावधानों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जारी की गई थी।

तालिका 5.3: जी आई ए जारी किये, उपयोग किये और अप्रयुक्त रहे

जी आई ए जारी किये	जी आई ए का उपयोग किया गया	अप्रयुक्त जी आई ए
₹6.00 करोड़ 30 मार्च 2022 को जारी	₹4.71 करोड़ 2022-23 के दौरान	₹1.28 करोड़ 10 जुलाई 2023 को धन वापसी

एम ई आई टी वाई ने बताया (मई 2025) कि यह योजना 2019-20 के दौरान प्रारंभ की गई थी और उसके बाद कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन के कारण उत्पन्न व्यवधानों से उबरने में लगभग दो वर्ष लग गए, जिसके कारण एन आई ई एल आई टी को आकांक्षी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित

<sup>34</sup> उपस्थिति की प्रति, जाति प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण तथा शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र।

करना पड़ा। इस देरी का जारी किए गए जी आई ए के उपयोग, उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यू सी) के प्रस्तुतिकरण तथा अप्रयुक्त जी आई ए की वापसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंततः 30 मार्च 2022 को एन आई ई एल आई टी को निधि जारी की गई और उपयोगिता प्रमाणपत्रों का निपटान कर दिया गया।

लेखापरीक्षा मंत्रालय के उत्तर को संज्ञान में लेती है तथा उल्लिखित बाधाओं को स्वीकार करती है। तथापि, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का जारी किया जाना जी एफ आर के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और इससे निधियों के प्रभावी उपयोग तथा निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम उत्पन्न हुआ।

### 5.1.9 भविष्य कौशल प्राइम - रोजगार के लिए आईटी जनशक्ति के पुनः कौशल / कौशल उन्नयन के लिए कार्यक्रम (एफ एस पी)

दिसंबर 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में पुनः कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था। यह योजना आई टी पेशेवरों, गैर-आई टी पेशेवरों, सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और नए भर्ती हुए अभ्यर्थियों पर केन्द्रित है। इस कार्यक्रम में 10 उभरती प्रौद्योगिकियों<sup>35</sup> के अंतर्गत पाँच प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल हैं: फाउंडेशन कोर्स, ब्रिज कोर्स, डीप स्किलिंग (डी एस) पाथवे (निःशुल्क व सदस्यता आधारित, दोनों), सरकारी अधिकारी प्रशिक्षण (जी ओ टी) और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी)। ये प्रशिक्षण भविष्य कौशल प्राइम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और मिश्रित रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का संचालन कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी एम यू) द्वारा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ (एन ए एस एस सी ओ एम), उन्नत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) और एन आई ई एल आई टी संसाधन केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। यह योजना दिसंबर 2022 को समाप्त होनी थी, लेकिन इसे चरणों<sup>36</sup> में मार्च 2027 तक आगे बढ़ा दिया गया।

प्रत्येक योजना के लिये परियोजना समीक्षा एवं संचालन समूह (पी आर एस जी)<sup>37</sup> का गठन किया गया, ताकि योजना की प्रगति की समीक्षा की जा सके, योजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके तथा निधि जारी करने की सिफारिश की जा सके।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन की पद्धति तथा प्रक्रिया प्रवाह को **अनुलग्नक 5.2** में दर्शाया गया है।

<sup>35</sup> आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी एवं वर्चुअल रियलिटी, 3डी प्रिंटिंग एवं मैनुफैक्चरिंग, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई ओ टी), रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आर पी ए) तथा सोशल एंड मोबाइल।

<sup>36</sup> इसे मई 2022 में दिसंबर 2023 तक तथा मार्च 2024 में मार्च 2027 तक बढ़ाया गया।

<sup>37</sup> पी आर एस जी की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (एम ई आई टी वाई) / वैज्ञानिक-जी तथा समूह समन्वयक द्वारा की जाती थी।

## लेखापरीक्षा अवलोकन

### 5.1.9.1 एफ एस पी योजना में गहन कौशल (डी एस) पाठ्यक्रम

हमने पाया कि डी एस सब्सक्रिप्शन-आधारित पाथवे में लक्ष्य का केवल 12 प्रतिशत नामांकन ही हो पाया, जो सशुल्क पाठ्यक्रमों के प्रति कम रुचि / वरीयता दर्शाता है, जबकि डी एस निःशुल्क पाथवे (एक अवैतनिक पाठ्यक्रम) में लक्ष्य का 687 प्रतिशत नामांकन हुआ। हमने यह भी पाया<sup>38</sup> कि डी एस निःशुल्क पाथवे (एक अवैतनिक पाठ्यक्रम) की तुलना में गहन कौशल (डी एस) सब्सक्रिप्शन पाथवे (एक सशुल्क पाठ्यक्रम) की पूर्णता दर अधिक (77 प्रतिशत) थी, जबकि डी एस निःशुल्क पाथवे की पूर्णता दर कम (43 प्रतिशत) थी। ये पाठ्यक्रम क्षेत्र कौशल परिषद (एस एस सी)-नैसकॉम द्वारा संचालित किए जाते हैं।

प्रारंभिक चार वर्षों में डीप स्किलिंग के लिए समग्र एफ एस पी कार्यान्वयन केवल निःशुल्क पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षार्थियों को आकर्षित कर सका, न कि सशुल्क पाठ्यक्रमों के लिए, हालांकि सशुल्क पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों ने पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिक प्रतिबद्धता दिखाई।

तीसरे पी आर एस जी (दिसंबर 2023) ने उल्लेख किया कि उद्योग प्रमाणन पूरा करने वाले शिक्षार्थियों को कोई अतिरिक्त मान्यता प्रदान नहीं करता, जिससे उनमें प्रेरणा की कमी होती है। इस प्रकार, क्षेत्र कौशल परिषद (एस एस सी)-नैसकॉम प्रमाणन को उद्योग जगत में कम मान्यता मिलने तथा योजना के लाभार्थियों के कार्यरत पेशेवर होने के कारण माँग-आधारित दृष्टिकोण का अभाव रहा, जिसके परिणामस्वरूप इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों की संख्या में कमी आई।

मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) ने (मई 2025 में) बताया कि एस एस सी नैसकॉम ने डिजिटल विज्ञापनों, जागरूकता अभियानों, सोशल मीडिया विपणन तथा देश भर के शैक्षणिक एवं औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जमीनी स्तर पर सहभागिता के माध्यम से गहन कौशल के लिए अपने विपणन और जागरूकता अभियानों को सुदृढ़ किया है। एस एस सी नैसकॉम द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 2024-25 तक गहन कौशल में कुल मिलाकर 84,000 से अधिक पाठ्यक्रम पूर्ण किए गए।

हालाँकि विपणन और आउटरीच को बढ़ाने में मंत्रालय के प्रयासों को स्वीकार किया जाता है, फिर भी मंत्रालय को पी आर एस जी द्वारा इंगित उद्योग मान्यता की कमी तथा माँग-आधारित दृष्टिकोण के अभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है।

<sup>38</sup> तालिका-5.1 में दिए गए आँकड़े।

### 5.1.10 सिफारिशें

- i. मंत्रालय लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण / ई-के वाई सी प्रक्रिया / पोर्टल की कार्यक्षमता को मजबूत कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे।
- ii. मूल्यांकन और प्रमाणन में देरी को दूर करने के लिए मंत्रालय प्रशिक्षण भागीदारों और प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों (के आई ए) की अधिक सक्रिय निगरानी सुनिश्चित कर सकता है।
- iii. मंत्रालय प्रशिक्षुओं की ट्रेकिंग के संबंध में सामान्य मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।
- iv. मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रशिक्षण भागीदार (टी पी) प्रशिक्षण शुल्क के लिए इनवॉइस ऑनलाइन पोर्टल से तैयार करने संबंधी योजना दिशानिर्देशों का पालन करें।
- v. मंत्रालय योजनाओं में परिकल्पित रोजगार-योग्यता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकता है।

## 5.2 सामान्य सेवा केंद्र (सी एस सी) 2.0 परियोजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा

### 5.2.1 परिचय

सामान्य सेवा केन्द्र (सी एस सी) योजना को भारत सरकार ने पहली बार सितंबर 2006 में मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य एक लाख सेवा वितरण केंद्र बनाना था, अर्थात् लगभग हर छह ग्रामों के लिये एक केंद्र। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर नागरिकों को विभिन्न प्रकार की ई-सेवाओं की सुगमता प्रदान करना था, जिससे डिजिटल अंतर को समाप्त किया जा सके और शासन व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

प्रारंभिक रूपरेखा के आधार पर, सरकार ने अगस्त 2015 में ₹475.11 करोड़ के समग्र परिव्यय के साथ सी एस सी 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। इस पहल को लागू करने व इसकी देखरेख करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्यों में ई-सेवाओं को गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से उपलब्ध कराना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आत्मनिर्भर सी एस सी नेटवर्क का विस्तार करना, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन के तहत जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटियों को सशक्त बनाना और परियोजना प्रबंधन का समर्थन करने के लिये और ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वी एल ई) को सहायता प्रदान करने के लिए एक मजबूत संस्थागत रूपरेखा तैयार करना शामिल था। परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सी एस सी स्थापित करके डिजिटल सेवा वितरण का विस्तार करना था, जिसके

तहत चार वर्षों के भीतर देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर किया जाना था। इस विस्तार रणनीति में पहले चरण में पहले से संचालित एक लाख सी एस सी को सुदृढ़ व एकीकृत करना तथा 1.5 लाख अतिरिक्त केन्द्र जोड़ना भी शामिल था।

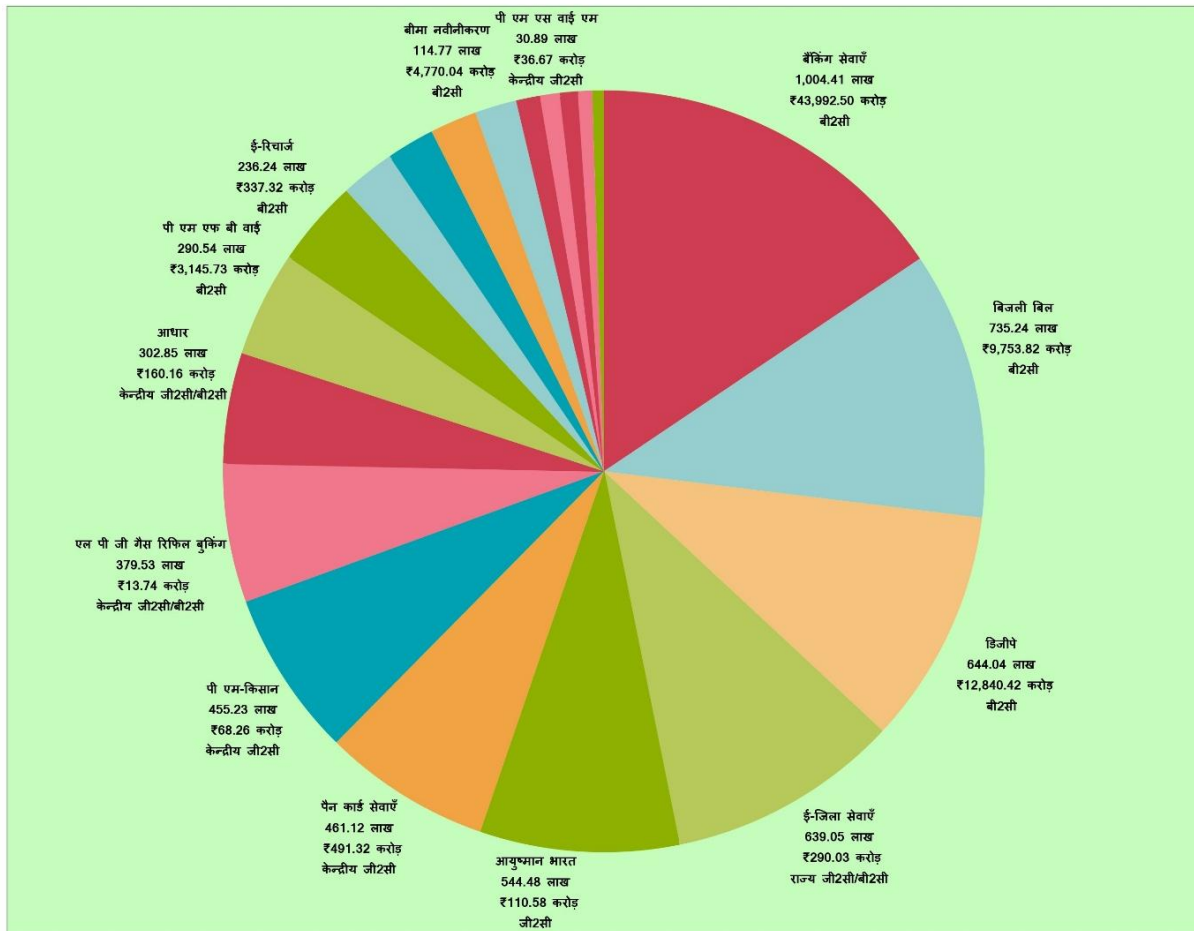
सी एस सी 2.0 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संगठन की स्थापना इस प्रकार है:

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है। यह परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत सहायता प्रदान करता है और परियोजना समीक्षा एवं संचालन समूह (पी आर एस जी)<sup>39</sup> के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। सी एस सी-एस पी वी द्वारा नियोजित राष्ट्रीय स्तर के संसाधन (एन एल आर) मंत्रालय को कार्यक्रम प्रबंधन (प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन और हितधारकों के साथ समन्वय सहित) के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
- सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सी एस सी-एस पी वी) कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक गैर सरकारी कम्पनी जिसे जुलाई 2009 में बनाया गया था, इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी थी। इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय स्तर का वैश्विक सी एस सी तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित करना और प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं के विकास, सक्षमता, ऑन-बोर्डिंग और वितरण के लिए एक समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करना है ताकि सभी सी एस सी में सेवाओं की एक मानक सूची की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसको सभी मौजूदा और नए वी एल ई को शामिल करने के लिए क्षमता निर्माण और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है।
- राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के नोडल विभाग के अंतर्गत राज्य निर्दिष्ट एजेंसी (एस डी ए) राज्य स्तरीय संसाधनों (एस एल आर), जिन्हें राज्य परियोजना प्रबंधक भी कहा जाता है, के माध्यम से राज्य में परियोजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन की जिम्मेदार थी।
- जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर के अधीन जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (डी ई जी एस) वी एल ई के चयन, सी एस सी नेटवर्क के संचालन, जिला स्तर पर निगरानी और जिला प्रबंधकों नामक जिला स्तरीय संसाधनों (डी एल आर) के माध्यम से जिले के भीतर वी एल ई की सहायता के लिए जिम्मेदार थी।
- ग्राम स्तरीय उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो सामान्य सेवा केन्द्र (सी एस सी) का संचालन एवं प्रबंधन करता है तथा सम्पूर्ण पूंजीगत एवं प्रचालन व्यय को वहन करने के लिए जिम्मेदार होता है।

<sup>39</sup> इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें सी एस सी-एस पी वी के सी ई ओ, नीति आयोग, दूरसंचार विभाग, व्यय विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा तीन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सी एस सी 2.0 परियोजना की परिकल्पना न केवल संख्या में विस्तार के रूप में की गई थी, बल्कि इसे सेवा और लेन-देन-उन्मुख मॉडल में बदलाव के रूप में भी देखा गया था, जिसमें ग्रामीण नागरिकों को उनके स्थानीय केंद्रों के माध्यम से सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई जाएगी।

चित्र 5.1 तथा तालिका 5.4 : ग्रामीण क्षेत्र में सी एस सी नेटवर्क के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं<sup>40</sup> की कुल लेनदेन मात्रा और लेनदेन मूल्य (वर्ष 2018-19 से 2022-23)



स्रोत: सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

<sup>40</sup> चित्र में वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए डी एस पी पर लेनदेन और केवल वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के लेनदेन का डेटा शामिल है।

तालिका 5.4

सेवा की श्रेणी	लेनदेन की संख्या (लाख में)	लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	लेनदेन का प्रतिशत	लेनदेन मूल्य का प्रतिशत
बैंकिंग सेवाएँ	1,004.41	43,992.50	15.26	54.34
बिजली बिल	735.24	9,753.82	11.17	12.05
डिजीपे	644.04	12,840.42	9.79	15.86
ई-जिला सेवाएँ	639.05	290.03	9.71	0.36
आयुष्मान भारत	544.48	110.58	8.27	0.14
पैन कार्ड सेवाएँ	461.12	491.32	7.01	0.61
पी एम-किसान	455.23	68.26	6.92	0.08
एल पी जी गैस रिफिल बुकिंग	379.53	13.74	5.77	0.02
आधार	302.85	160.16	4.60	0.20
पी एम एफ बी वाई	290.54	3,145.73	4.42	3.89
ई-रिचार्ज	236.24	337.32	3.59	0.42
राज्य सरकार (जी2सी)	149.45	54.37	2.27	0.07
बी बी पी एस	132.12	1,025.00	2.01	1.27
पर्यटन और यात्राएँ	128.06	1,770.86	1.95	2.19
बीमा नवीनीकरण	114.77	4,770.04	1.74	5.89
कृषि	66.20	21.83	1.01	0.03
श्रम सेवाएँ	53.15	23.39	0.81	0.03
बीमा बिक्री-जी आई	50.01	918.75	0.76	1.13
ई-स्टाम्प	37.76	219.53	0.57	0.27
पी एम एस वाई एम	30.89	36.67	0.47	0.05

सी एस सी पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में ग्राम स्तरीय उद्यमी (वी एल ई) हैं। प्रत्येक वी एल ई एक व्यक्ति होता है जो सी एस सी के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, और पूंजी निवेश और आवर्ती प्रचालन व्यय दोनों वहन करता है। उनकी वित्तीय स्थिरता एक कमीशन-आधारित राजस्व-साझाकरण मॉडल पर निर्भर करती है, जिसके तहत प्रत्येक सफल लेनदेन पर अर्जित कमीशन का 80 प्रतिशत सीधे वी एल ई को जाता है, जबकि शेष 20 प्रतिशत कार्यान्वयन एजेंसी, सी एस सी-एस पी वी द्वारा रखा जाता है।

प्रत्येक वी एल ई की एक विशिष्ट सी एस सी आई डी और प्रीपेड वॉलेट होता है, जो उनकी सी एस सी आई डी से जुड़ा होता है। वी एल ई प्रीपेड वॉलेट को रिचार्ज करता है और डिजिटल सेवा पोर्टल (डी एस पी) के माध्यम से लेनदेन करता है। लेनदेन के सफल होने पर, वी एल ई के हिस्से को छोड़कर, लेनदेन की राशि वॉलेट से काट ली जाती है। इस प्रकार, वास्तविक समय में, वी एल ई को

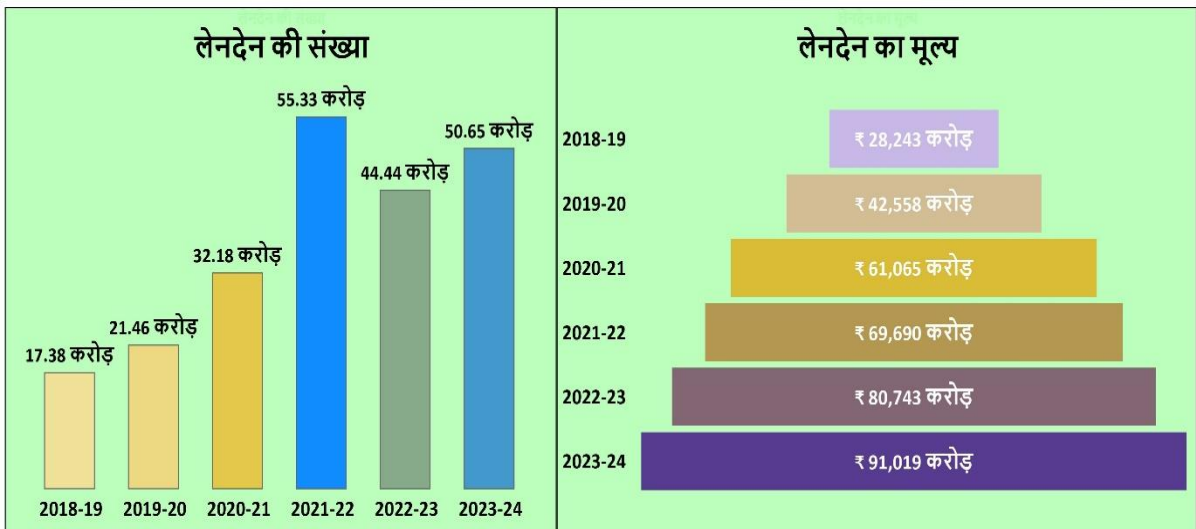
उनका क्रेडिट मिल जाता है। हालाँकि, बीमा, डिजी-पे, बैंकिंग, ई-श्रम, छात्रवृत्ति सत्यापन जैसी कुछ सेवाओं में, सी एस सी-एस पी वी समय-समय पर वी एल ई के खाते में कमीशन हस्तांतरित करता है। सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और एकीकृत मंच बनाने के लिए, सी एस सी-एस पी वी ने फरवरी 2017 में डिजिटल सेवा पोर्टल शुरू किया। इस तकनीकी आधार को एक वैश्विक इंटरफेस के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसके माध्यम से सभी सेवा प्रदाताओं से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी सेवाओं को एकीकृत करें, जिससे पूरे सी एस सी नेटवर्क में स्थिरता, सुगमता और मापनीयता सुनिश्चित हो सके।

इस परियोजना का उद्देश्य सेवा वितरण को एक ही तकनीकी मंच पर समेकित करना था, जिससे जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो सके। ऐसा करते हुए, इसका उद्देश्य निष्पक्ष कमीशन-साझाकरण संरचना के माध्यम से वी एल ई की स्थिरता को बढ़ाना था, साथ ही सी एस सी पारिस्थितिकी तंत्र में महिला उद्यमियों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

पोर्टल के माध्यम से, सी एस सी 60 सेवाओं के अंतर्गत कुल 848 उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनमें जी2सी (केंद्र / राज्य सरकार से नागरिक) सेवाएँ शामिल हैं। इनमें आधार, चुनाव आयोग, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि सेवाएँ शामिल हैं। वे अन्य व्यवसाय से नागरिक (बी2सी) सेवाएँ भी प्रदान करते हैं, जैसे टिकट बुकिंग, उपयोगिता बिल भुगतान, ई-कॉमर्स, ई-रिचार्ज आदि। सी एस सी केंद्रों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची अनुलग्नक 5.3 में दी गई है।

सी एस सी द्वारा किए गए लेन-देन का वर्षवार विवरण और उनका मूल्य नीचे चित्र-5.2 में दर्शाया गया है:

चित्र 5.2: वर्षवार लेनदेन की संख्या और लेनदेन का मूल्य



स्रोत: सी एस सी-एस पी वी की राष्ट्रीय मासिक रिपोर्ट: मार्च-2019, मार्च-2020, मार्च-2021, मार्च-2022, मार्च-2023 और मार्च-2024

हमने देखा कि वर्ष 2018-2024 के दौरान इस योजना की पहुँच में विस्तार हुआ, जिसमें लेन-देन की संख्या (291 प्रतिशत) और लेन-देन के मूल्य (322 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अनौपचारिक कार्यबल के लिए 16.57 करोड़ ई-श्रम पंजीकरण के कारण लेन-देन की संख्या वर्ष 2021-22 में चरम पर थी।

31 मार्च 2024 तक, परियोजना ने ग्राम पंचायत स्तर पर सी एस सी स्थापित करने के अपने लक्ष्य को मोटे तौर पर पूरा कर लिया था। हालाँकि, ग्राम स्तर पर निष्पादन अपेक्षाकृत कम रहा। जबकि 81.78 प्रतिशत गाँव सी एस सी नेटवर्क के अंतर्गत आते थे, वहीं इनमें से केवल 72.79 प्रतिशत ग्रामों में ही कम से कम एक सी एस सी सक्रिय था। कवरेज और सक्रिय सेवा वितरण के बीच यह अंतर सी एस सी 2.0 के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में न केवल भौतिक उपस्थिति, बल्कि केंद्रों की कार्यशीलता और स्थिरता के महत्व को भी उजागर करता है।

चित्र 5.3: 31 मार्च 2024 तक ग्राम पंचायतों (जी पी) और गांवों की कवरेज की स्थिति

	ग्राम पंचायतों की कवरेज	गांवों की कवरेज
लक्ष्य	2,59,760	6,50,328
कवरड	2,57,228 (99.03%)	5,31,825 (81.78%)
सक्रिय	2,46,418 (95.80%)	3,87,089 (72.79%)

स्रोत: जी पी के लिए सी एस सी-एस पी वी की राष्ट्रीय मासिक प्रगति रिपोर्ट: मार्च 2024 और गांव के लिए सी एस सी-एस पी वी से डेटा

## 5.2.2 लेखापरीक्षा का दायरा, कार्यप्रणाली और लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक की गई थी और इसमें वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि शामिल थी। आवश्यकतानुसार अभिलेखों की संवीक्षा पहले की अवधि तक बढ़ा दी गई थी। लेखापरीक्षा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (कॉर्पोरेट कार्यालय और 10 चयनित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य कार्यालयों) में की गई।

लेखापरीक्षा 27 सितंबर 2023 को मंत्रालय के साथ प्रारम्भिक सम्मेलन के साथ शुरू हुई। हमने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के नमूने लिए और दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के दौरान संयुक्त भौतिक सत्यापन (लेखापरीक्षा दल और सी एस सी-एस पी वी प्रतिनिधि) के लिए 315 सी एस सी<sup>41</sup> का चयन किया। नमूने का विवरण **अनुलग्नक-5.4** में दिया गया है। हमने मई 2024

<sup>41</sup> चयनित 315 सी एस सी में से 231 का भौतिक सत्यापन किया जा सका। भौतिक सत्यापन के दौरान 81 सी एस सी बंद पाए गए तथा तीन सी एस सी को स्थानांतरित / लेखापरीक्षा अवधि के बाद पंजीकृत / एक ही सी एस सी दो ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ पाया गया।

में एक लाभार्थी सर्वेक्षण<sup>42</sup> भी किया। लेखापरीक्षा 13 जनवरी 2025 को समापन सम्मेलन के साथ संपन्न हुई।

लेखापरीक्षा निम्न उद्देश्यों के साथ की गयी थी:

- यह जांचने के लिए कि क्या परियोजना का डिजाइन वी एल ई के लिए स्थायी है, जो गांव वालों को विभिन्न श्रेणियों में बिना किसी परेशानी के ई-सेवाएं देने के लिए तैयार है।
- यह जांचने के लिए कि क्या प्रशिक्षण और प्रोत्साहन ने वी एल ई को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है।
- यह जांचने के लिए कि क्या सी एस सी की सफलता की समीक्षा करने और समय-समय पर हस्तक्षेप करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र मौजूद है।

### 5.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष - परियोजना कार्यान्वयन

#### 5.2.3.1 स्थिरता

सी एस सी 2.0 दिशानिर्देशों (पैरा 8.2.2) के अनुसार, प्रत्येक केंद्र को कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइस और पावर बैकअप जैसी बुनियादी आई सी टी सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए। इस निवेश की जिम्मेदारी पूरी तरह से ग्राम स्तरीय उद्यमी (वी एल ई) की है। आई सी टी सुविधाओं की रुढ़िवादी (संतुलित) अनुमानित लागत<sup>43</sup> लगभग ₹50,000 है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान वी एल ई<sup>44</sup> की कमाई के आंकड़ों<sup>45</sup> के विश्लेषण से पता चला है कि ज्यादातर ऑपरेटरों को इस मामूली निवेश की भी भरपाई करने में मुश्किल हुई। लगभग 86 प्रतिशत ग्रामीण वी एल ई की कमाई ₹500 प्रति माह से कम थी, अर्थात् भरपाई के लिए उन्हें आठ वर्षों से ज्यादा समय लगा। 7.5 से 18.5 प्रतिशत ग्रामीण वी एल ई ने कोई कमाई नहीं की, जबकि तीन प्रतिशत से भी कम वी एल ई की कमाई ₹3,000 प्रति माह से ज्यादा रही।

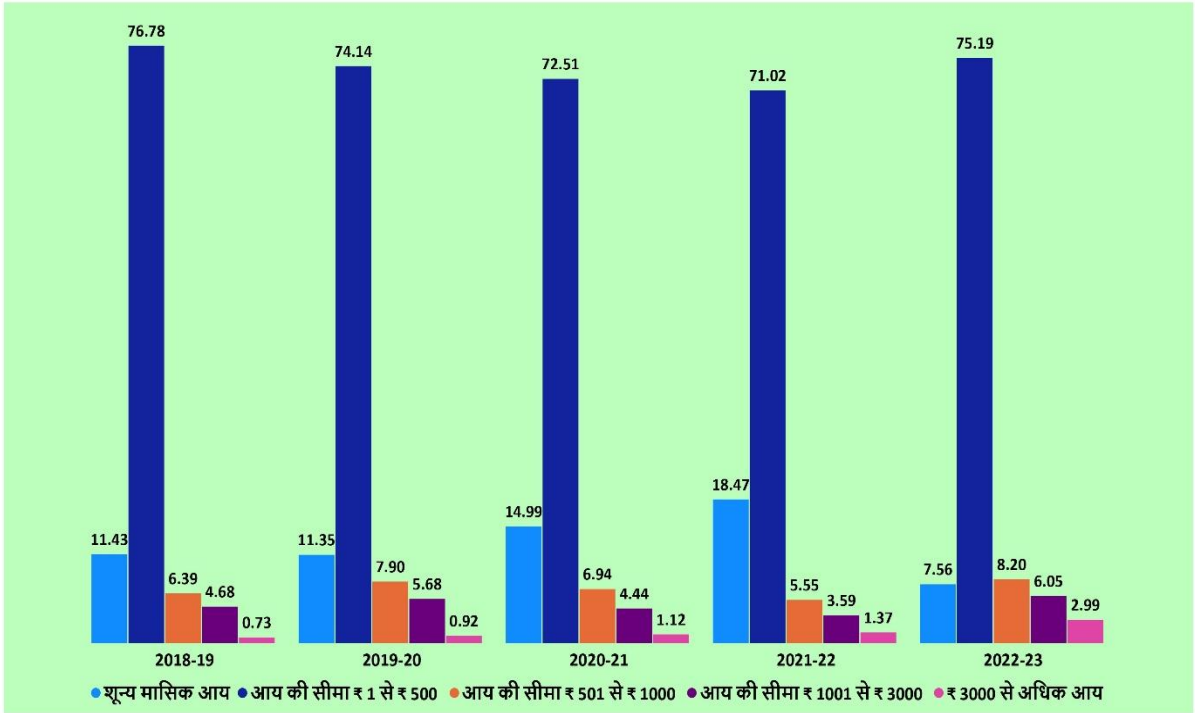
<sup>42</sup> लाभार्थी सर्वेक्षण 210 सी एस सी में किया गया क्योंकि 21 सी एस सी निष्क्रिय पाए गए।

<sup>43</sup> लेखापरीक्षा ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर उपलब्ध आई सी टी उत्पादों के आधार पर यह अनुमान लगाया है।

<sup>44</sup> 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान सक्रिय ग्रामीण वी एल ई की संख्या क्रमशः 2,47,128, 3,07,530, 4,01,430, 4,99,647 और 5,99,800 थी।

<sup>45</sup> सी एस सी-एस पी वी द्वारा व्यापारी-वार लेनदेन डेटा डंप (अप्रैल 2018 से मार्च 2024)।

चित्र 5.4: ग्रामीण वी एल ई की औसत मासिक आय (वर्ष 2018-19 से 2022-23) (प्रतिशत में)



इस अवधि के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औसत मासिक आय केवल ₹76 और ₹499 के बीच थी।

चित्र 5.5 : राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औसत मासिक आय



वर्ष 2022-23 में 4,913 वी एल ई के एक छोटे से वर्ग ने ₹10,000 से अधिक की मासिक आय हासिल की। उनकी सफलता काफी हद तक प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार से जुड़ी थी: 80 प्रतिशत से ज्यादा आवर्ती व्यवसाय-से-नागरिक (बी2सी) सेवाओं जो कि मुख्यतः बैंकिंग लेनदेन पर केंद्रित थे, जबकि केवल चार प्रतिशत सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाओं पर केंद्रित थे। लगभग 13 प्रतिशत ने उच्च आय प्राप्त करने के लिए विविध सेवाएं प्रदान की।

### केस स्टडी - उत्तर प्रदेश में एक सफल वी एल ई

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक ग्राम पंचायत के एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वी एल ई) वर्ष 2012 से सी एस सी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए हैं। शिक्षा में स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ, उन्होंने एक किराए की दुकान से केंद्र का संचालन करके अपनी यात्रा शुरू की, जो कि समय के साथ एक स्व-स्वामित्व वाली स्थापना में विकसित हुई - यह उनकी निरंतर प्रगति और दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है।

कार्यशालाओं और नियमित बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, वी एल ई ने अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाया और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का आत्मविश्वास हासिल किया। उनका केंद्र आज बैंकिंग, आधार अद्यतनीकरण, बीमा, बिजली बिल भुगतान, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ए ई पी एस) लेनदेन, डिजी-पे, मोबाइल रिचार्ज, आयकर रिटर्न, रेलवे और हवाई टिकट बुकिंग, साथ ही पी एम-किसान और पेंशन संबंधी सेवाओं जैसी योजनाओं सहित नागरिक-उन्मुख सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। एक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए एक व्यवसाय संवाददाता के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें आर्थिक स्थिरता और आय का एक निरंतर स्रोत प्रदान किया।

वी एल ई वर्तमान में ₹30,000 से ₹35,000 प्रति माह कमाता है, जो दर्शाता है कि सी एस सी मॉडल के अंतर्गत उद्यमिता कैसे सेवाओं और ग्राहक तक पहुँच के सही तालमेल के साथ वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। हालाँकि, कई ग्रामीण सेवा प्रदाताओं की तरह, उन्हें ग्राहकों की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके अधिकांश ग्राहक तत्काल समाधान की अपेक्षा रखते हैं, भले ही उनके नियंत्रण से परे तकनीकी समस्याओं के कारण देरी हो रही हो।

अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और दृश्यता को बेहतर बनाने के लिए, वह व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से तत्पर रहता है और उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल माय बिजनेस जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त, वह प्रिंट मीडिया और पैम्फलेट वितरण के माध्यम से स्थानीय विज्ञापन में निवेश करता है और प्रचार गतिविधियों के लिए प्रति माह लगभग ₹2,000 अलग रखता है। उनका दीर्घकालिक लक्ष्य केवल व्यवसाय विकास तक ही सीमित नहीं है; वह अपने गाँव में वित्तीय साक्षरता

को बढ़ावा देने और नागरिकों को बैंकिंग, बीमा और डिजिटल सेवाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

यह उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रचालन चुनौतियों के बावजूद, एक सक्रिय और अभिनव दृष्टिकोण वी एल ई को सी एस सी को जमीनी स्तर पर व्यवहार्य और प्रभावशाली उद्यमों में बदलने के लिए सक्षम बना सकता है।

कम लेनदेन की मात्रा ने कमजोर व्यावसायिक व्यवहार्यता को प्रतिबिंबित किया, लगभग आधे वी एल ई (वर्ष 2022-23 में 46.49 प्रतिशत) ने पूरे वर्ष में एक से 100 लेनदेन दर्ज किए (अनुलग्नक-5.5)।

सी एस सी-एस पी वी (सितंबर 2024) ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और वी एल ई के उद्यमशीलता कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं, और सी एस सी में दी जाने वाली सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण नागरिकों के लिए जागरूकता अभियान जैसे अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मई 2025) ने सी एस सी नेटवर्क के समग्र विकास पर महत्व दिया, जो वर्ष 2014 में 85,000 केंद्रों से बढ़कर फरवरी 2025 तक 5.7 लाख हो गया।

सी एस सी नेटवर्क का विस्तार और उनके द्वारा सृजित उद्यमशीलता के अवसर उल्लेखनीय हैं। हालाँकि, वी एल ई के एक बड़े हिस्से की लगातार कम आय उन संरचनात्मक समस्याओं की ओर इशारा करती है जिनका समाधान केवल प्रशिक्षण और जागरूकता से नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सी एस सी वी एल ई के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बने रहें और दीर्घकालिक रूप से वास्तव में टिकाऊ हों, लक्षित उपायों की आवश्यकता है।

सी एस सी-एस पी वी सफल 4,913 वी एल ई से सबक सीखने पर विचार करे तथा इन वी एल ई को उनके जिलों तथा उसके आसपास में, प्रशिक्षण / जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़े।

### 5.2.3.2 निष्क्रिय सी एस सी

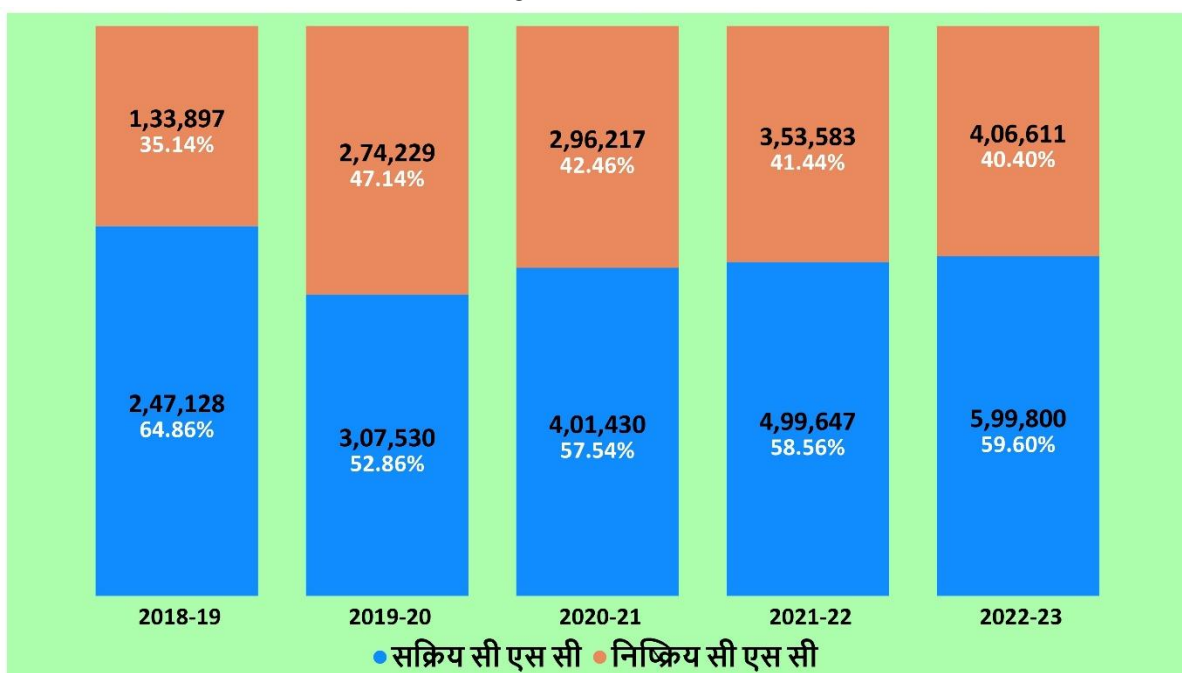
योजना के दिशानिर्देशों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सी एस सी और प्रत्येक गांव<sup>46</sup> में एक सी एस सी स्थापित करने की परिकल्पना की गई।

आंकड़ों के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि जहां वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच सी एस सी की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर इस अवधि के दौरान निष्क्रिय<sup>47</sup> सी एस सी 35 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच रहे।

<sup>46</sup> सातवें परियोजना समीक्षा एवं संचालन समूह द्वारा।

<sup>47</sup> हमने किसी वी एल ई को निष्क्रिय माना यदि उसने 365 दिनों तक लगातार कोई लेनदेन नहीं किया। सी एस सी-एस पी वी ने अपने सी एस सी पंजीकरण मैनुअल के परिशिष्ट में भी यही दृष्टिकोण अपनाया है।

चित्र 5.6 : लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल सक्रिय ग्रामीण और निष्क्रिय ग्रामीण सी एस सी



315 चयनित सी एस सी के भौतिक सत्यापन से पता चला कि इनमें से 81 सी एस सी बंद थे, जिससे संभावित अंतिम-मील उपयोगकर्ताओं को आवश्यक जी2सी / बी2सी ई-सेवाओं की उपलब्धता से वंचित होना पड़ा (अनुलग्नक-5.6)।

आगे के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2021-22 में सक्रिय 10.07 प्रतिशत वी एल ई (50,340) वर्ष 2022-23 में निष्क्रिय हो गए। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत ने वर्ष 2021-22 में 12 से कम लेनदेन (अर्थात, प्रति माह एक) और 88.31 प्रतिशत ने 24 से कम लेनदेन (अर्थात, प्रति माह दो) किए, जो कम सेवा गतिविधि और अंततः निष्क्रियता के बीच एक स्पष्ट संबंध दर्शाता है।

मंत्रालय ने (मई 2025) कहा कि सक्रिय / निष्क्रिय स्थिति वी एल ई की इच्छा और आत्मनिर्भर व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह सी एस सी नेटवर्क की समग्र स्थिरता को प्रभावित नहीं करती है।

नेटवर्क के विस्तार को स्वीकार करते हुए, लेखापरीक्षा का मानना है कि सक्रिय निगरानी आवश्यक है। सी एस सी-एस पी वी को लेनदेन की घटती मात्रा के आधार पर निष्क्रियता के जोखिम वाले वी एल ई की पहचान करनी चाहिए, अंतर्निहित समस्याओं का समाधान करना चाहिए और बंद होने से बचाने तथा अंतिम छोर तक निरंतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए समय पर सहायता प्रदान करनी चाहिए।

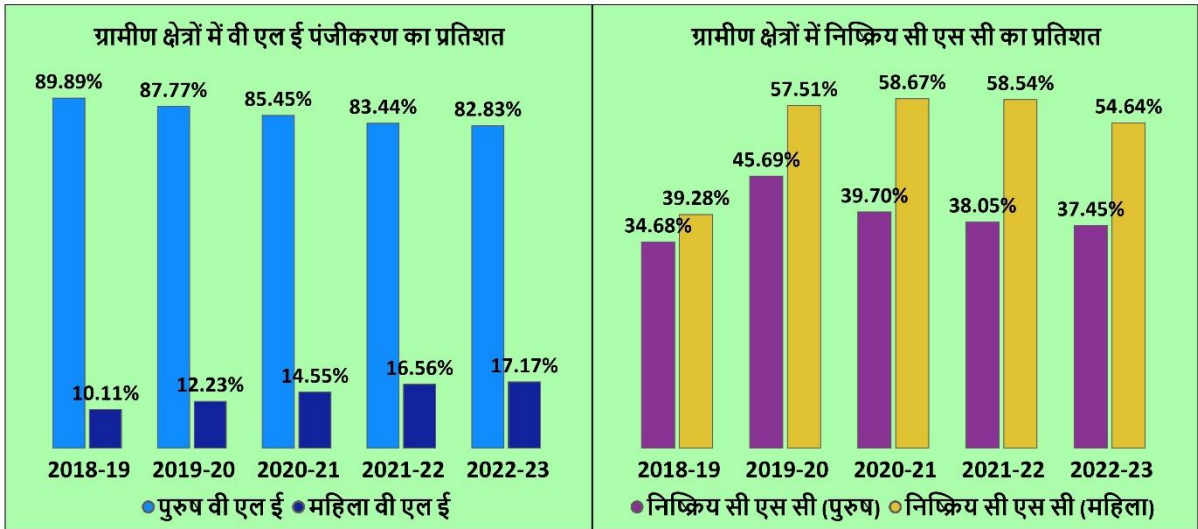
### 5.2.3.3 महिलाओं की भागीदारी

यद्यपि सी एस सी 2.0 दिशानिर्देशों (पैरा 9.2) में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमियों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई थी, न तो राज्यों

/ केंद्र शासित प्रदेशों (जो शुरू में चयन के लिए जिम्मेदार थे) और न ही सी एस सी-एस पी वी (वी एल ई के पंजीकरण की भूमिका संभालने के बाद) ने इस संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए। परिणामस्वरूप, सी एस सी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा नहीं हो पाया।

वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच सी एस सी डेटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि ग्रामीण सी एस सी में महिला वी एल ई का अनुपात लगातार कम रहा है, जो केवल 10.11 प्रतिशत से 17.17 प्रतिशत के बीच है। इसके अलावा, महिलाओं द्वारा संचालित सी एस सी में निष्क्रियता काफी अधिक थी, और वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान आधे से ज्यादा सी एस सी निष्क्रिय रहे। मार्च 2023 तक, महिलाओं द्वारा संचालित 1,72,810 सी एस सी में से 94,419 (54.64 प्रतिशत) निष्क्रिय थे, जो अस्थिरता की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चित्र 5.7: पुरुष वी एल ई की तुलना में महिला वी एल ई की स्थिति



सी एस सी-एस पी वी ने अपने उत्तर (सितंबर 2024 / मई 2025) में जागरूकता कार्यशालाओं व डिजी-पे सखी योजना जैसी पहलों पर प्रकाश डाला, जिसके माध्यम से 34,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) महिला सदस्य सेवाएँ प्रदान करने में संलग्न थीं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्थिति का समर्थन करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी सी एस सी-एस पी वी की है।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि इन उपायों के बावजूद, महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ाने के लिए कोई संरचित अनुवर्ती योजना या विशिष्ट निर्देश नहीं थे। सी एस सी में अधिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का इच्छित लक्ष्य अधूरा रह गया।

मंत्रालय सी एस सी पारिस्थितिकी तंत्र में महिला वी एल ई की भागीदारी और स्थिरता दोनों में सुधार के लिए परिभाषित समयसीमा के साथ एक स्पष्ट, लक्ष्य-आधारित रणनीति अपनाने पर विचार करे।

#### 5.2.3.4 सी एस सी पर सेवा वितरण

सी एस सी 2.0 का एक प्रमुख उद्देश्य ई-सेवाओं तक बिना किसी भेदभाव के पहुँच प्रदान करना और ग्रामीण नागरिकों को सरकारी, निजी और सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यापक सेवा वितरण केंद्रों के रूप में सी एस सी की स्थापना करना था। मार्च 2023 तक, डिजिटल सेवा पोर्टल (डी एस पी) पर 60 श्रेणियों में 848 उत्पाद उपलब्ध थे।

231 (315 में से) नमूना सी एस सी<sup>48</sup> के भौतिक सत्यापन से पता चला कि आधार<sup>49</sup>, ई-जिला सेवाएँ<sup>50</sup>, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाई<sup>51</sup>) और बैंकिंग<sup>52</sup> जैसी प्रमुख सेवाएँ क्रमशः 88.31 प्रतिशत, 63.64 प्रतिशत, 48.48 प्रतिशत और 47.19 प्रतिशत केंद्रों पर प्रदान नहीं की गयी थीं (अनुलग्नक-5.7)। लाभार्थी सर्वेक्षण में, इन सी एस सी के 1,121 लाभार्थियों में से 608 (54.23 प्रतिशत) ने बताया कि उन्हें आधार सेवाओं / ई-जिला / बैंकिंग की आवश्यकता थी, लेकिन ये केंद्रों पर उपलब्ध नहीं (अनुलग्नक-5.8) थी।

जवाब में, सी एस सी-एस पी वी (सितंबर 2024) ने दावा किया कि नागरिकों को अधिकांश ई-सेवाएं अपेक्षित रूप से प्राप्त हो रही हैं, जबकि एम ई आई टी वाई (मई 2025) ने आधार और बैंकिंग सेवाओं में अंतराल के लिए नियामक प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कवरेज का विस्तार करने के प्रयास चल रहे हैं।

लेखापरीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि सी एस सी-एस पी वी डिजिटल सेवा पोर्टल पर आधार, ई-जिला सेवाएं, पी एम एफ बी वाई और बैंकिंग जैसी प्रमुख सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए और परियोजना के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी सी एस सी में उनका निरंतर वितरण सुनिश्चित करे।

#### 5.2.3.5 डिजिटल सेवा पोर्टल में राज्य से संबंधित सेवाओं का एकीकरण

दिशानिर्देश (पैरा 8.3.3.1) ई-सेवाओं के समेकित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य ई-सेवाओं, उपयोगिता सेवाओं के पोर्टलों और अन्य सरकारी विभागों के पोर्टलों को डिजिटल सेवा पोर्टल (डी एस पी) के साथ एकीकृत करने का आदेश देते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2024) कि ऐसा एकीकरण केवल 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ही पूरा हुआ (मार्च 2024), जो कि इस प्रक्रिया के लिए

<sup>48</sup> 10 राज्यों में: बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

<sup>49</sup> आधार सेवाएँ अखिल भारतीय स्तर पर सी एस सी के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की कुल लेनदेन मात्रा का 4.6 प्रतिशत है।

<sup>50</sup> ई-जिला सेवाएँ अखिल भारतीय स्तर पर सी एस सी के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की कुल लेनदेन मात्रा का 9.71 प्रतिशत है।

<sup>51</sup> पी एम एफ बी वाई अखिल भारतीय स्तर पर सी एस सी के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की कुल लेनदेन मात्रा का 4.42 प्रतिशत है।

<sup>52</sup> अखिल भारतीय स्तर पर सी एस सी के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के कुल लेनदेन की मात्रा में बैंकिंग सेवाओं का योगदान 15.26 प्रतिशत तथा कुल लेनदेन मूल्य का 54.34 प्रतिशत है।

जिम्मेदार राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रालय और सी एस सी-एस पी वी द्वारा अपर्याप्त समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, परियोजना का कार्यान्वयन अपूर्ण रहा है, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हुई है और राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-सेवाओं तक नागरिकों की पहुँच सीमित हुई है।

मंत्रालय ने (मई 2025) अंतराल को स्वीकार किया और कहा कि सी एस सी-एस पी वी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय कर रहा है और 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत चल रही है।

जबकि ये प्रयास उल्लेखनीय हैं, लेकिन नौ वर्षों से भी अधिक समय बाद भी पूर्ण एकीकरण का अभाव, उन्नयन तंत्र की कमजोरियों और राज्य प्राधिकरणों के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई की कमी को उजागर करता है। इसके विपरीत, केरल में अक्षय केंद्रों<sup>53</sup> और तेलंगाना में मीसेवा<sup>54</sup> जैसे राज्य-विशिष्ट ई-सेवा वितरण मॉडलों ने लेन-देन और ग्राहकों की संख्या के मामले में काफी बेहतर कार्य किया है, और परिणामस्वरूप, सी एस सी की तुलना में उनकी औसत मासिक आय ज्यादा रही है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.5: सामान्य सेवा केंद्रों की अक्षय और मीसेवा केंद्रों से तुलना

	मार्च 2023 के अंत में केंद्रों की संख्या	वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक के लेन-देन (लाख में)	प्रति केंद्र प्रति माह औसत आय (₹ में)
मीसेवा, तेलंगाना	5,242	912	3,000 से 10,000
सी एस सी तेलंगाना	11,558	72	261
अक्षय केंद्र, केरल	2,868	2,173	1.39 लाख
सी एस सी केरल	10,060	84	234

राज्य ई-सेवाओं की व्यापक श्रृंखला की उपलब्धता तथा तुलनात्मक रूप से कम संख्या में केन्द्रों की उपस्थिति इन मॉडलों के बेहतर निष्पादन में योगदान देने वाले कारक थे, जिससे सी एस सी की व्यावसायिक क्षमता और प्रासंगिकता पर और अधिक प्रभाव पड़ा।

<sup>53</sup> ई-साक्षरता को बढ़ावा देने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ वर्ष 2002 में केरल में अक्षय केंद्रों की स्थापना की गई थी और बाद में इन केंद्रों ने विभिन्न ई-सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया। अक्षय केंद्र सभी राज्य सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाओं, जैसे ई-ज़िला सेवाएँ और राशन कार्ड सेवाएँ आदि, को संभालने के लिए सुसज्जित हैं। सामान्य सेवा केंद्र (सी एस सी) राज्य जी2सी सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरूप, लोग अपनी सेवा आवश्यकताओं के लिए अक्षय केंद्रों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सामान्य सेवा केंद्रों की व्यावसायिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

<sup>54</sup> मीसेवा केंद्र वर्ष 1999 में तेलंगाना में शुरू किए गए थे। मीसेवा सभी राज्य सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाएँ प्रदान करता है।

### 5.2.3.6 स्पेक्टा डैशबोर्ड में अधूरा डेटा

दिशानिर्देशों के पैरा 13.1.1 में स्वचालित एम आई एस रिपोर्ट के माध्यम से सी एस सी नेटवर्क की निगरानी की परिकल्पना की गई है। इसके लिये स्पेक्टा टूल विकसित किया गया। पंजीकरण नियमावली के अनुसार, प्रत्येक वी एल ई को पंजीकरण के समय व्यक्तिगत, आवासीय और बैंकिंग विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10,469 वी एल ई के संबंध में वी एल ई का नाम, स्थान और कोड जैसे प्रमुख विवरण गायब थे, जिन्होंने फिर भी मार्च 2024 तक ₹87.71 करोड़ मूल्य के लेनदेन किए थे।

सी एस सी-एस पी वी ने कहा (मई 2024) कि डेटाबेस को अद्यतन किया जा रहा है और प्रभावित वी एल ई को प्रविष्टियों की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा, जबकि एम आई आई टी वाई ने (मई 2025) सी एस सी-एस पी वी को डेटाबेस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

उत्तर से प्रणालीगत कमी का पता चलता है, क्योंकि वी एल ई को पूर्ण अनिवार्य विवरण प्रस्तुत किए बिना लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी, जिससे प्रभावी निगरानी के लिए स्पेक्टा की विश्वसनीयता कम हो गई।

### 5.2.3.7 सी एस सी-एस पी वी द्वारा सी एस सी का भौतिक सत्यापन न किया जाना

दिशानिर्देशों के पैरा 13.2.1 में सी एस सी के स्थान, अवसंरचना और कार्यशीलता की पुष्टि के लिए जियो-टैग्ड एप्लिकेशन के माध्यम से समय-समय पर क्षेत्र-स्तरीय सत्यापन की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी एस सी-एस पी वी ने सत्यापन के अपने वार्षिक लक्ष्य हासिल नहीं किए, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है:

**तालिका 5.6: सी एस सी-एस पी वी द्वारा सी एस सी के भौतिक सत्यापन का लक्ष्य और उपलब्धि**

तक	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
मार्च 2020	5,16,869	70,338	13.61
मार्च 2021	7,97,117	2,93,985	36.88
मार्च 2022	9,22,746	4,41,643	47.86
मार्च 2023	5,19,652	2,92,510	56.29

इसके अलावा, चयनित सी एस सी के भौतिक सत्यापन से 81 बंद सी एस सी और 231 कार्यरत सी एस सी में कमियां सामने आईं, जैसे प्रिंटर (2.6 प्रतिशत), स्कैनर (5.2 प्रतिशत), वेबकैम (19 प्रतिशत), पावर बैकअप (24.24 प्रतिशत), और दर सूची का प्रदर्शन (74.9 प्रतिशत) (अनुलग्नक-5.9) की कमी। इन कमियों के कारण उपयोगकर्ता आवश्यक जी2सी / बी2सी सेवाओं तक विश्वसनीय पहुंच से वंचित रहे।

एम ई आई टी वाई (मई 2025) ने देरी के लिए कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराया और इस बात पर जोर दिया कि सी एस सी-एस पी वी संसाधनों के उपयोग और सी एस सी 2.0 के बाद सत्यापन जारी रखने के लिए जवाबदेह बना रहेगा।

लेखापरीक्षा मानता है कि अपूर्ण सत्यापन के कारण सी एस सी अपर्याप्त अवसंरचना, बिना मानचित्रित स्थानों से कार्य करने, अधिक शुल्क लेने, या पंजीकृत वी एल ई के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा संचालन के प्रति संवेदनशील रहे।

#### सिफारिश:

मंत्रालय / सी एस सी-एस पी वी

- i. सफल 4,913 वी एल ई से सीख लेने पर विचार करे तथा इन वी एल ई को उनके जिलों व उसके आसपास में, प्रशिक्षण / जागरूकता कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध करे।
- ii. राजस्व साझेदारी मॉडल की समीक्षा करे तथा सफल वी एल ई को आदर्श मॉडल के रूप में बढ़ावा देने के साथ-साथ वी एल ई की स्थिरता को मजबूत करने के लिये नियमित प्रशिक्षण प्रदान करे।
- iii. सक्रिय रूप से निष्क्रिय सी एस सी की पहचान करे और उनकी कार्यशीलता बहाल करने में सहयोग करे।
- iv. वी एल ई के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाये।
- v. सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की ई-सेवाओं का डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ एकीकरण सुनिश्चित करे।
- vi. निगरानी तथा सेवा वितरण में सुधार के लिये सी एस सी का भौतिक सत्यापन समय पर पूर्ण करे।

#### 5.2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष - शासन

##### 5.2.4.1 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों की भागीदारी

परियोजना दिशानिर्देशों में एक निर्दिष्ट नोडल विभाग, राज्य निर्दिष्ट एजेंसियों (एस डी ए) और जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटियों (डी ई जी एस) के माध्यम से राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई थी। ये एजेंसियां परियोजना कार्यान्वयन, वी एल ई के चयन और समर्थन और स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए जिम्मेदार थीं। दिसंबर 2015 और जनवरी 2016 में मंत्रालय द्वारा पत्राचार के बावजूद, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और डी ई जी एस ने वी एल ई चयन में भाग नहीं लिया, बल्कि यह प्रक्रिया सीधे सी एस सी-एस पी वी द्वारा एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की गई।

राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों की इस सीमित भागीदारी के कारण कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतराल हुए, जैसे कि डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ राज्य ई-सेवाओं का अपूर्ण एकीकरण, महिला वी एल ई को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों का अभाव, निष्क्रिय सी एस सी की बड़ी संख्या, तथा इच्छुक वी एल ई के लिए अनियमित प्रशिक्षण आवश्यकताएं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2025) में सी एस सी-एस पी वी को पूरी जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि राज्य सरकारें निगरानी व संचालन तंत्र में शामिल थीं।

लेखापरीक्षा का मानना है कि मंत्रालय को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय कदम उठाने और प्रभावी परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समन्वय तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। केरल में अक्षय केंद्र और तेलंगाना में मीसेवा जैसे सफल राज्य-प्रधान मॉडल दर्शाते हैं कि जब राज्य स्वामित्व लेते हैं, तो सेवा वितरण अधिक प्रभावी होता है, नागरिकों की पहुँच में सुधार होता है और ग्रामीण उद्यमियों की आय का स्तर ऊँचा होता है।

#### 5.2.4.2 सी एस सी पर सामान्य ब्रांडिंग

परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सी एस सी को एक मानकीकृत राष्ट्रव्यापी पहचान सुनिश्चित करने के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की सह-ब्रांडिंग के साथ समान राष्ट्रीय ब्रांडिंग अपनानी होगी। इसे सुगम बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मार्च 2016 में समान ब्रांडिंग लोगो को मंजूरी दी और बाद में (अप्रैल 2019) सी एस सी-एस पी वी ने सभी सत्यापित सी एस सी को एक समान रंग में रंगने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2023 तक, ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकृत 2.54 लाख केंद्रों में से केवल 1.45 लाख सी एस सी (57 प्रतिशत) पर ही सामान्य ब्रांडिंग प्रदर्शित की गई थी। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन से पता चला कि 231 सी एस सी में से 226 में सरकारी खर्च पर ब्रांडिंग नहीं की गई थी।

एम ई आई टी वाई (मई 2025) ने कहा कि मार्च 2024 तक 2.97 लाख सी एस सी पर ब्रांडिंग प्रदर्शित की गई थी और कहा कि निधि के पुनःआंबटन और टूट-फूट के कारण लागत वी एल ई द्वारा वहन की गई थी।

इससे वी एल ई पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा, एक समान ब्रांडिंग समर्थन का उद्देश्य कमजोर हुआ तथा सी एस सी की वित्तीय स्थिरता पर और अधिक प्रभाव पड़ा।

#### 5.2.4.3 प्रशिक्षण शुल्क लगाना

दिशानिर्देशों में वी एल ई के लिए परियोजना लागत पर अनिवार्य उद्यमिता प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया था ताकि उनकी स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। मई 2018 में, सी एस सी-एस पी वी ने एक प्रमाणन कार्यक्रम के रूप में टेली-सेंटर उद्यमी पाठ्यक्रम (टी ई सी) शुरू किया। हालाँकि, वर्ष 2020-21 में, सी एस सी-एस पी वी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वीकृति के बिना इच्छुक

वी एल ई के लिए टी ई सी पाठ्यक्रम को अनिवार्य पात्रता शर्त बना दिया और वर्ष 2020-23 के दौरान पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में ₹108.89 करोड़ एकत्र किए। इस बीच, प्रशिक्षण के लिए मूल रूप से आवंटित ₹21.40 करोड़ में से, ₹7.26 करोड़ अगस्त 2022 में अन्य मदों में पुर्नविनियोग कर दिए गए।

सी एस सी-एस पी वी ने बताया कि टी ई सी प्रमाणन कार्यक्रम का प्रबंधन सी एस सी अकादमी जो सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वतंत्र संस्था है, द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आई एस बी) के सहयोग से किया जाता है। सी एस सी अकादमी, टी ई सी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यान्वयन और प्रबंधन सहित प्रशिक्षण से एकत्रित शुल्क के उपयोग के लिए जिम्मेदार है। सी एस सी-एस पी वी इन निधियों का सीधे आवंटन या प्रबंधन नहीं करता है। सी एस सी-एस पी वी ने इस कार्यक्रम को इसलिए स्वीकृत किया क्योंकि इसका उद्देश्य वी एल ई के कौशल को बढ़ाना है ताकि वे सी एस सी को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें। हालाँकि, सी एस सी-एस पी वी की इस कार्यक्रम में कोई वित्तीय भागीदारी नहीं है।

एम ई आई टी वाई ने पुष्टि की (सितंबर 2024) कि टी ई सी को इसकी मंजूरी नहीं थी, लेकिन बाद में कहा (मई 2025) कि इसे आवेदकों के लिए पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण के रूप में शुरू किया गया था, न कि मौजूदा वी एल ई के लिए।

यह जवाब लेखापरीक्षा की टिप्पणी की पुष्टि करता है, क्योंकि दिशानिर्देशों में उम्मीदवारों के खर्च पर पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं था। वी एल ई की कम आय के बावजूद, आवेदकों पर अनिवार्य शुल्क लगाने से उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा और उनकी स्थिरता को नुकसान पहुँचा।

#### 5.2.4.4 सी एस सी 2.0 परियोजना की निगरानी

परियोजना समीक्षा एवं संचालन समूह (पी आर एस जी<sup>55</sup>), जिसे जनवरी 2016 में बनाया गया, को सी एस सी 2.0 कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तिमाही बैठक करनी थी। हालाँकि, पहली बैठक अप्रैल 2018 में ही हुई, और उसके बाद नौवीं बैठक तक की बैठकें निर्धारित समय-सीमा के विपरीत, एक महीने से लेकर 11 महीने से भी अधिक की देरी से हुईं। इस अनियमित निगरानी के कारण दूरदराज के इलाकों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति, और डिजिटल सेवा पोर्टल पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की ई-सेवाओं का सीमित एकीकरण जैसी समस्याएँ लगातार बनी रहीं।

उल्लेखनीय रूप से, वी एल ई स्थिरता के मुद्दे पर परियोजना शुरू होने के छह वर्षों बाद, केवल आठवें पी आर एस जी (मार्च 2022) में ही चर्चा हुई, जिसमें नीति आयोग ने कम आबादी वाले गांवों में

<sup>55</sup> इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें सी एस सी-एस पी वी के सी ई ओ, नीति आयोग, दूरसंचार विभाग, व्यय विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा तीन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

वित्तीय व्यवहार्यता की चुनौती पर प्रकाश डाला। हालाँकि, सी एस सी विस्तार के साथ-साथ स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप तैयार नहीं किया गया।

एम ई आई टी वाई ने स्वीकार किया कि त्रैमासिक बैठकें आयोजित नहीं की गईं, लेकिन यह स्पष्ट करते हुए कि 10 पी आर एस जी बैठकें आयोजित की गईं, स्पेक्टा और मासिक रिपोर्ट जैसे वैकल्पिक निगरानी तंत्रों का हवाला दिया।

यद्यपि सी एस सी-एस पी वी ने 2.5 लाख ग्रामीण सी एस सी स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन समय पर और नियमित पी आर एस जी निगरानी के अभाव के कारण महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान सीमित रहा और वी एल ई स्थिरता पर ध्यान देने में देरी हुई, जो कि परियोजना की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

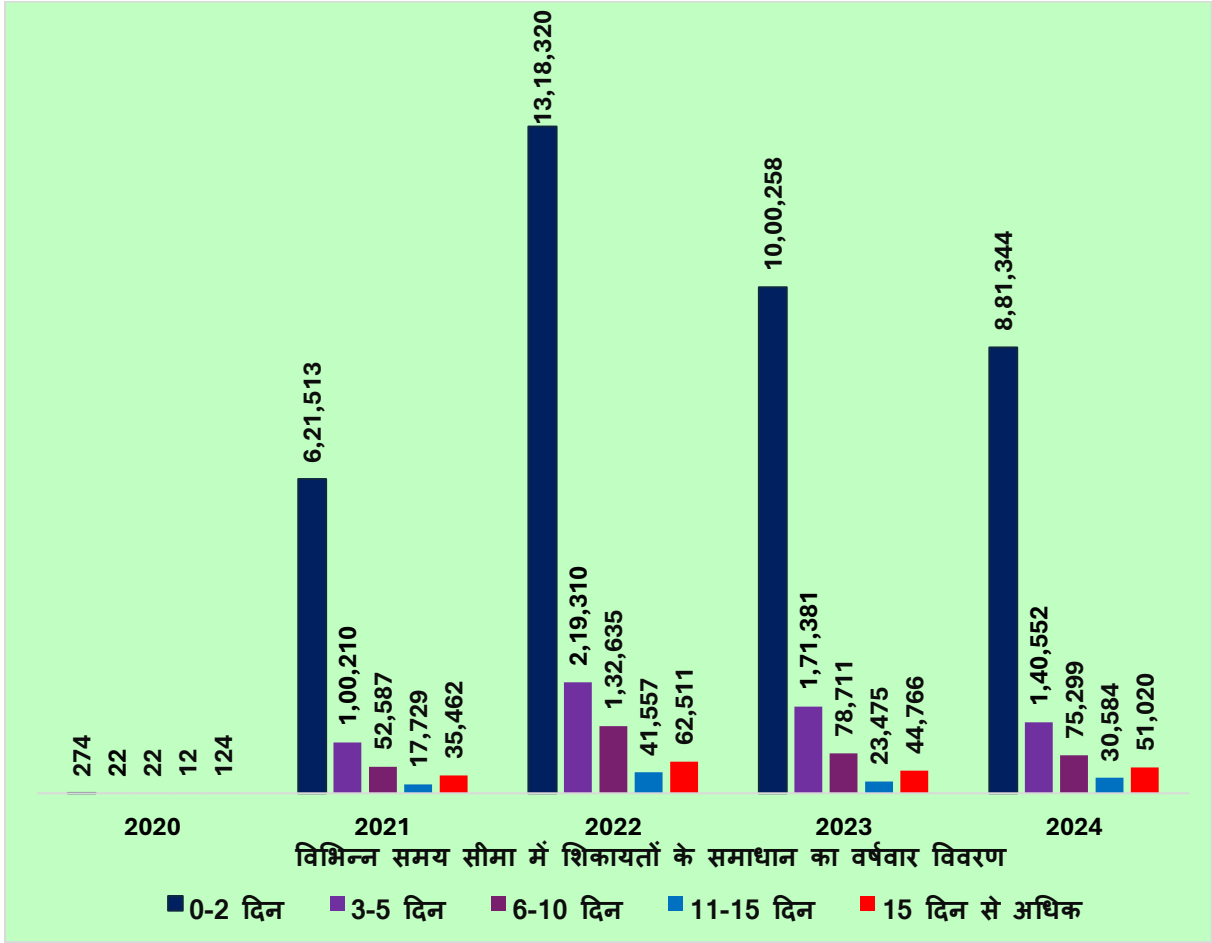
#### 5.2.4.5 सी एस सी-एस पी वी में शिकायत निवारण तंत्र और हेल्पडेस्क

सी एस सी-एस पी वी ने एक एस्केलेशन मैट्रिक्स तथा एक हेल्पलाइन नंबर और डिजिटल सेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा के साथ वी एल ई के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। शिकायतों को एक दिन के भीतर दर्ज किया जाता है और उन्हें एक टिकट नंबर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य 24 घंटों के भीतर पहली प्रतिक्रिया और दो कार्यदिवसों के भीतर समाधान प्रदान करना है। वी एल ई द्वारा शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया निम्नलिखित उदाहरण में दी गई है:

ग्राहक पैन कार्ड आवेदन या रेलवे टिकट बुकिंग जैसी सेवाओं के लिए वी एल ई से संपर्क करता है। वी एल ई इन अनुरोधों को डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से संसाधित करता है, जोकि संबंधित प्रणालियों (पैन के लिए एन एस डी एल / यू टी आई टी एस एल और रेलवे बुकिंग के लिए आई आर सी टी सी) के साथ एकीकृत है। कभी-कभी, आवेदन या बुकिंग विफल हो सकती है या सेवा के सफलतापूर्वक पूरा हुए बिना वी एल ई के वॉलेट से डेबिट हो जाता है। ऐसे मामलों में, डेबिट की गई राशि आमतौर पर 24 घंटे के भीतर स्वचालित रूप से वापस आ जाती है। यदि धनवापसी संसाधित नहीं होती है, तो वी एल ई डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध सी एस सी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। विफल लेनदेन के मामलों में, वी एल ई के पास सेवा के लिए फिर से आवेदन करने का विकल्प भी होता है। ऐसी शिकायतों का समाधान सेवा सक्रियण, सेवा बहाली या वॉलेट निपटान तक सीमित है। इस प्रकार वी एल ई द्वारा की गई शिकायतें मुख्य रूप से डिजिटल सेवा पोर्टल के द्वारा सेवा प्रदान करने में उनकी असमर्थता से सम्बन्धित होती हैं।

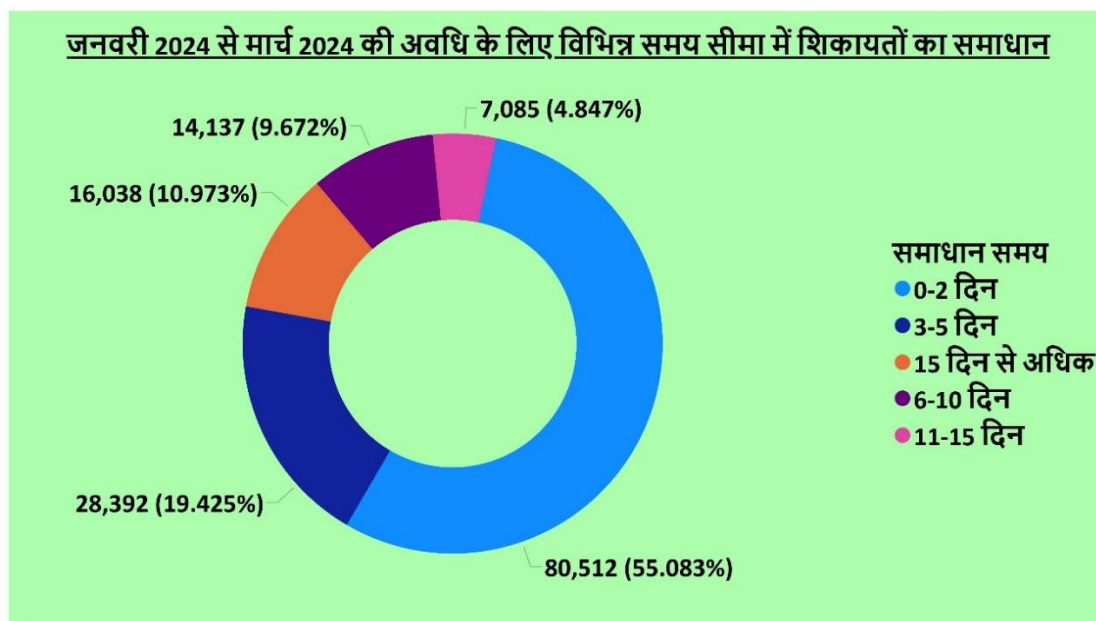
वर्ष 2020-24 के दौरान, लगभग 51 लाख शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश सरकारी सेवाओं, दूरसंचार, यात्रा, बिजली और शिक्षा से संबंधित थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वी एल ई द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान में देरी हुई, जैसा कि नीचे चित्र 5.8 में दर्शाया गया है।

चित्र 5.8: वर्ष 2020 से 2024 की अवधि के दौरान वी एल ई द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान समय का वर्षवार विवरण



जनवरी 2024 से मार्च 2024 की अवधि के लिए शिकायत डेटा (वी एल ई द्वारा निर्दिष्ट कारण सहित) के लेखापरीक्षा विश्लेषण से भी समाधान में देरी का पता चला, जिसमें 44.9 प्रतिशत मामलों में दो दिनों से अधिक समय लगा और 11 प्रतिशत मामलों में समाधान के लिए 15 दिनों से अधिक समय लगा, जैसा कि नीचे चित्र 5.9 में दर्शाया गया है।

चित्र 5.9: जनवरी 2024 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान वी एल ई द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान समय का विवरण



हमने पाया कि पैन सेवा, आई आर सी टी सी पंजीकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना<sup>56</sup> (पी एम एफ बी वाई) और आयुष्मान भारत योजना<sup>57</sup> के अंतर्गत कई शिकायतें 15 दिनों से अधिक समय तक अनसुलझी रहीं।

एम ई आई टी वाई ने उत्तर दिया (मई 2025) कि सी एस सी-एस पी वी की शिकायत निवारण प्रणाली, वी एल ई और सी एस सी सेवाओं का उपयोग करने वाले नागरिकों की शिकायतों का समय पर और कुशल समाधान सुनिश्चित करती है।

लगातार देरी से सेवा वितरण और नागरिक संतुष्टि प्रभावित होती है। यह त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण की कड़ी निगरानी और सुव्यवस्थीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

#### सिफारिश:

##### मंत्रालय / सी एस सी-एस पी वी

- वी एल ई चयन, सी एस सी के स्थान निर्धारण और अवसंरचना समर्थन में जिला ई-गवर्नेन्स सासायटी तथा स्थानीय प्रशासन को शामिल करे।
- वी एल ई पर पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण शुल्क की समीक्षा करे और इसे बंद करे।

<sup>56</sup> समस्या तब उत्पन्न होती है जब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत फसल बीमा आवेदन बीमाकर्ता की प्रणाली में स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

<sup>57</sup> वी एल ई ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में सक्षम बनाते हैं।

- iii. स्पेक्टा तथा सेवा वितरण की नियमित निगरानी के माध्यम से सी एस सी निगरानी को मजबूत करे।

#### 5.2.5 निष्कर्ष

सी एस सी 2.0 परियोजना ने ग्रामीण भारत में केंद्रों और लेन-देन का विस्तार करके डिजिटल समावेशन को उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ाया है। हालाँकि, राज्य ई-सेवाओं के अपूर्ण एकीकरण, ग्राम स्तरीय उद्यमियों की कमजोर वित्तीय स्थिरता, निष्क्रिय सी एस सी की अधिक घटनाएं और बिना अनुमोदन के प्रशिक्षण शुल्क लगाए जाने के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित है। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सीमित भागीदारी, निगरानी और भौतिक सत्यापन में कमियां, असंगत ब्रांडिंग, महिलाओं की कम भागीदारी और शिकायत निवारण में देरी सेवा वितरण को और कमजोर करती है। राज्य की भागीदारी को मजबूत करना, वी एल ई की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना, निगरानी में सुधार करना और शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करना सी एस सी के लिए सुलभ और टिकाऊ अंतिम-मील ई-गवर्नेंस के अपने वादे को पूरा करने के लिए आवश्यक है।



---

खंड - ख

---



## अध्याय

## VI

## संचार मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

## 6.1 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा

## 6.1.1 परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग के एक नए मॉडल के रूप में पेमेंट्स बैंकों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को जमा और भुगतान जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। पारंपरिक बैंकों के विपरीत, पेमेंट्स बैंकों को ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। इन्हें लेनदेन को सुगम बनाने, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने, जमा (एक निर्धारित सीमा तक) स्वीकार करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और बैंकिंग तक आसान पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई पी पी बी) डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की एक पहल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2016 में ₹800 करोड़ के बजट के साथ इसकी स्थापना को मंजूरी दी थी, जिसमें ₹400 करोड़ इक्विटी और ₹400 करोड़ पाँच वर्षों के लिए अनुदान के रूप में शामिल थे। आई पी पी बी की स्थापना अगस्त 2016 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। शुरुआत में, इसे सितंबर 2017 तक ज़िला मुख्यालयों पर 650 शाखाएँ खोलनी थीं और उप-ज़िला स्तर पर सभी डाकघरों के साथ एकीकृत होकर एसेस पॉइंट के रूप में कार्य करना था।

अगस्त 2018 में, कैबिनेट ने परियोजना लागत<sup>58</sup> को संशोधित कर ₹1,435 करोड़ कर दिया और सभी 1.55 लाख डाकघरों को आई पी पी बी से जोड़ने की समय सीमा दिसंबर 2018 तक बढ़ा<sup>59</sup> दी। अप्रैल 2022 में कुल परिव्यय को और बढ़ाकर ₹2,255 करोड़ कर दिया गया।

## आई पी पी बी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- भारत में बैंकिंग सुविधा से वंचित, कम बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले तथा कम सुविधा प्राप्त समाज के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय बैंक का निर्माण करना तथा सहायक घर-घर बैंकिंग के माध्यम से कम बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए अवसर लागत को कम करना।

<sup>58</sup> प्रौद्योगिकी लागत में वृद्धि और त्वरित रोलआउट से मानव संसाधन लागत में वृद्धि।

<sup>59</sup> भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निवल मूल्य और लाभ अनुपात की विनियामक आवश्यकता को बनाए रखना तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन करना।

- iii. सामाजिक क्षेत्र के लाभार्थियों, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम एस एम ई), पंचायत, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कम आय वाले परिवारों को सेवा प्रदान करना।

#### 6.1.1.1 प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

अक्टूबर 2021 तक, आई पी पी बी छोटे व्यापारियों और व्यवसाय मालिकों के लिए चालू खाता सुविधाएँ प्रदान करता था। वर्तमान में, यह चार प्रकार के बचत खाते प्रदान करता है:

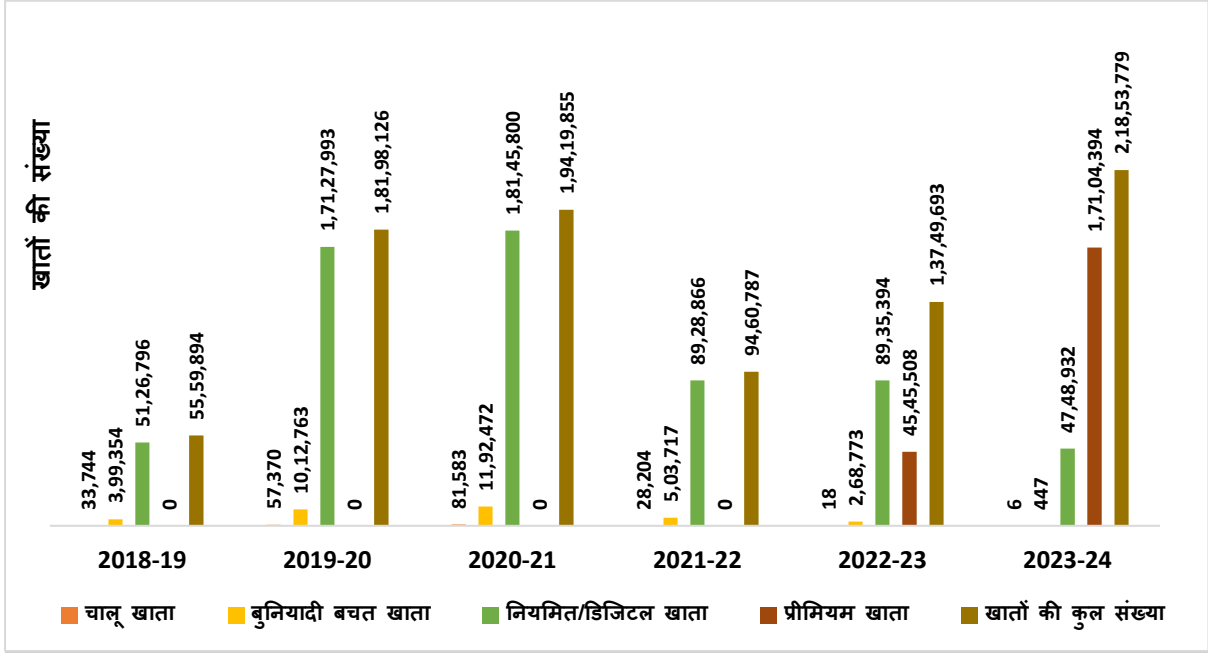
- नियमित बचत खाता: असीमित जमा, आहरण और धन प्रेषण की अनुमति।
- डिजिटल बचत खाता: आधार और पैन का उपयोग करके मोबाइल ऐप के माध्यम से खोला जाता है, जिसकी वैधता एक वर्ष होती है; के वाई सी पूरा होने के बाद इसे नियमित खाते में अपग्रेड किया जाता है।
- बेसिक बचत खाता: एक शून्य-शेष खाता जो प्रति माह सीमित (चार) निःशुल्क डेबिट लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।
- प्रीमियम बचत खाता: वर्चुअल डेबिट कार्ड और उपयोगिता बिल भुगतान के माध्यम से किए गए पात्र लेनदेन पर कैशबैक जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं के साथ 2022 में शुरू किया गया।

बचत खातों में अधिकतम ₹2 लाख तक की राशि जमा की जा सकती है। इस सीमा से अधिक राशि को लिंकड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (पी ओ एस ए) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, बशर्ते खाताधारक का पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में बचत खाता हो। ₹1 लाख तक की राशि पर दो प्रतिशत प्रतिवर्ष और ₹1-2 लाख के बीच की राशि पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। अन्य सेवाओं में घरेलू धन अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी बी टी), उपयोगिता बिल भुगतान और ऋण, बीमा और निवेश योजनाओं जैसे तृतीय-पक्ष उत्पादों का वितरण शामिल हैं।

#### 6.1.1.2 बचत खातों का विवरण और एसेस पॉइंट्स की रोल आउट स्थिति

मार्च 2024 के अंत तक, आई पी पी बी में 8.82 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। चालू खाता और बचत खाते की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत खातों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है:

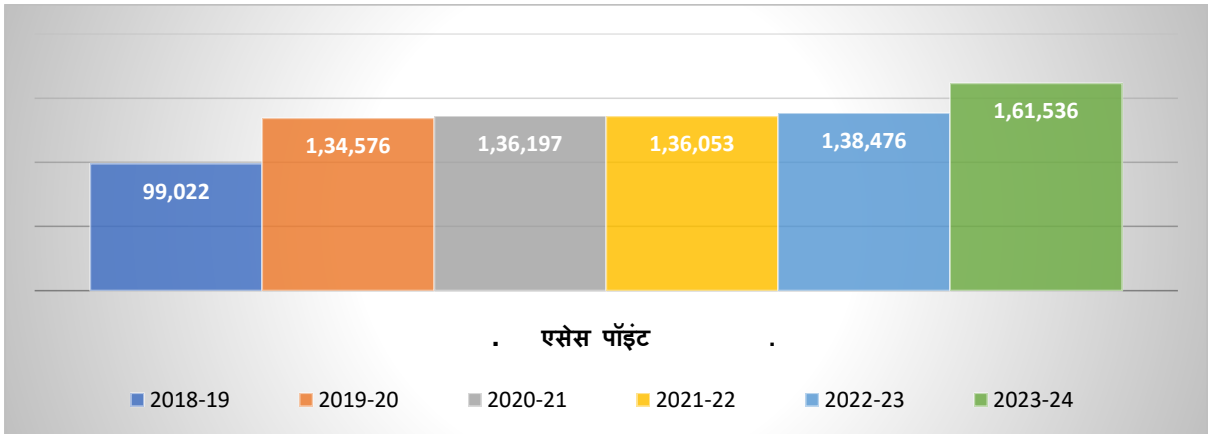
चित्र 6.1: वर्ष-वार खोले गए आई पी बी खातों की संख्या



स्रोत: आई पी बी से प्राप्त डेटा

कैबिनेट नोट (मई 2016) के अनुसार, सभी डाकघरों को आई पी बी एसेस पॉइंट के रूप में कार्य करना था। मार्च 2024 तक, 1,61,536 सक्रिय एसेस पॉइंट थे, जिनमें से 83 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 6.2: लाइव एसेस पॉइंट की वर्षवार संख्या



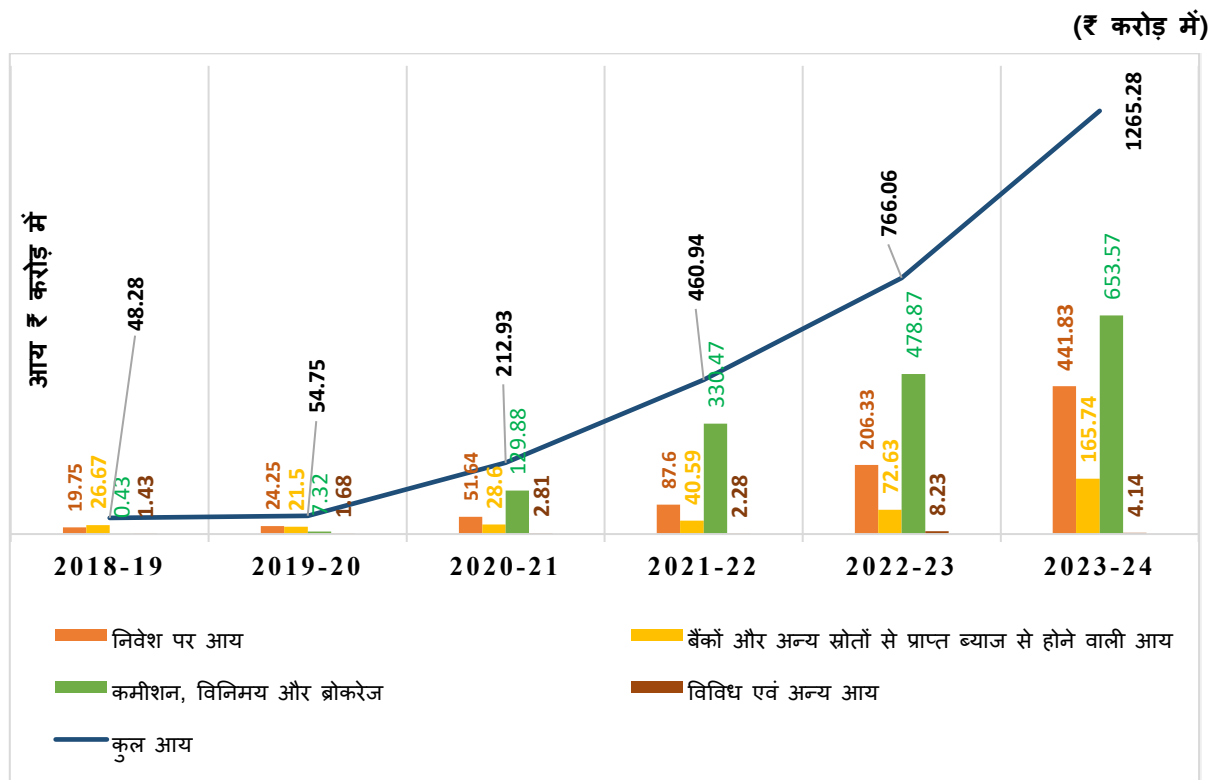
### 6.1.2 वित्तीय निष्पादन

सी ए एस ए (चालू और बचत खाता) राशि 2018 में ₹93.07 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 तक ₹3,764.30 करोड़ हो गई, जो पर्याप्त विस्तार को दर्शाता है। आई पी बी की कुल आय में शुरुआती वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई और नए उत्पादों<sup>60</sup>, की शुरुआत के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21

<sup>60</sup> वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्यक्ष धन अंतरण, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, भारत बिल भुगतान सेवा, डाकपे-यू पी आई, यू पी आई और रुपे के साथ आई पी बी मोबाइल बैंकिंग ऐप, वर्चुअल डेबिट कार्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन बीमा जैसे नए उत्पाद और सेवाएं शुरू की गईं।

से इसमें तेज़ी आई। आई पी पी बी परिचालन वित्तीय वर्ष 2022-23 में संतुलित स्तर पर पहुँच गया, जहाँ उसने ₹20.16 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर ₹34.24 करोड़ हो गया।

चित्र 6.3: बैंक की आय का वर्षवार विवरण



स्रोत: आई पी पी बी की वार्षिक रिपोर्ट

### 6.1.3 संगठनात्मक व्यवस्था

नई दिल्ली में आई पी पी बी मुख्यालय का नेतृत्व एक प्रबंध निदेशक और सी ई ओ करते हैं, जबकि डाक विभाग के सचिव इसके गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसका परिचालन नेटवर्क भारत के डाक ढांचे का प्रतिबिम्ब है, जो 23 परिमंडलो में विभाजित है, जिनमें 650 शाखा कार्यालय और सामान्य, प्रधान, उप और शाखा डाकघरों में 1.61 लाख से अधिक एसेस पॉइंट हैं।

उप-डाकघर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित होते हैं, जबकि शाखा डाकघर मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करते हैं। डाक कर्मचारी, जिनमें डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक (जी डी एस) शामिल हैं, आई पी पी बी के लिए अग्र-पंक्ति प्रतिनिधि (आई पी पी बी के अंतिम उपयोगकर्ता) के रूप में कार्य करते हैं और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए कमीशन प्राप्त करते हैं।

### 6.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जाँच करना है कि क्या आई पी पी बी द्वारा सेवाओं की योजना और कार्यान्वयन वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। यह लेखापरीक्षा सितंबर

2023 से मार्च 2024 के दौरान की गई, जिसमें 2016-17 से 2022-23 तक की अवधि शामिल थी। ग्राहकों की संख्या के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए आठ डाक परिमंडलो<sup>61</sup> का चयन किया गया, जिनमें 42 आई पी पी बी शाखाएँ (प्रत्येक चयनित डाक सर्किल में आकांक्षी जिलों<sup>62</sup> से दो) शामिल थीं।

लेखापरीक्षा ने आई पी पी बी कॉर्पोरेट कार्यालय के अभिलेखों की जांच की, जिसमें आई पी पी बी के कार्यान्वयन के अनुपालन, आई पी पी बी और डाक विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, मंत्रिमंडल का अनुमोदन, आर बी आई के दिशानिर्देश और डाक निदेशालय के निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऑडिट के दौरान, मंत्रालय और आई पी पी बी के साथ बातचीत के अलावा, सर्विस चाहने वालों के तौर पर कस्टमर्स और फ्रंट-एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर ग्रामीण डाक सेवकों से भी बातचीत की गई।

## 6.1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 6.1.5.1 एसेस पॉइंट्स का रोल आउट

#### 6.1.5.1(क) व्यक्तिगत व्यवसाय अभिकर्ता की अपर्याप्त तैनाती से ग्रामीण पहुँच में बाधा उत्पन्न हुई

वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, आर बी आई के दिशानिर्देश (अक्टूबर 2016) बैंकों (आई पी पी बी जैसे पेमेंट्स बैंकों सहित) को बुनियादी वित्तीय सेवाएँ जैसे खाता खोलना, बिजली बिलों का भुगतान और धन हस्तांतरण, आदि प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय अभिकर्ताओं<sup>63</sup> (आई बी सी) को नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। हालाँकि आई बी सी को नकद लेनदेन या आधार-संबंधी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति नहीं है, फिर भी वे कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में आई पी पी बी की पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अक्टूबर 2021 की मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के अनुसार, प्रत्येक आई पी पी बी एसेस पॉइंट द्वारा दो से पांच आई बी सी नियुक्त करने की अपेक्षा की गई थी, जिनमें से कम से कम एक बैंकिंग सुविधा से वंचित या कम बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाली ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करेगा। सर्किल स्तरीय समितियाँ आई बी सी डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता वाले गाँवों की पहचान करने और आई पी पी बी शाखाओं के माध्यम से नियुक्तियाँ सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार थीं।

मार्च 2024 तक की लेखापरीक्षा जाँच से चयनित परिमंडलो में आई बी सी परिनियोजन में कमी का पता चला, जहाँ औसत आई बी सी परिनियोजन प्रति एसेस पॉइंट केवल 0.20 आई बी सी था, जो निर्धारित न्यूनतम दो से काफी कम था (अनुलग्नक-6.1)। लेखापरीक्षा ने चयनित परिमंडलो में 2022-23

<sup>61</sup> बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर-पूर्व, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

<sup>62</sup> नीति आयोग द्वारा परिभाषित आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में पिछड़े रहे हैं। नीति आयोग ने वित्तीय समावेशन और अन्य सरकारी योजनाओं के उद्देश्य से देश में आकांक्षी जिलों की सूची तैयार की है।

<sup>63</sup> एक व्यक्ति या संस्था, जो बैंक की ओर से गैर-नकद बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है

में आई बी सी परिनियोजन की नमूना जाँच की और पाया कि आई पी पी बी ने स्वयं द्वारा निर्धारित परिनियोजन लक्ष्य का केवल 16.27 प्रतिशत ही प्राप्त किया, और नियोजित 2,415 में से केवल 393 आई बी सी को सक्रिय किया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 6.1: आई बी सी के सक्रियकरण में लक्ष्य के प्रति उपलब्धि

सर्किल का नाम <sup>64</sup>	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (प्रतिशत)
मध्य प्रदेश	341	88	25.81
महाराष्ट्र	312	51	16.35
पूर्वोत्तर	203	04	1.97
राजस्थान	425	79	18.59
तमिलनाडु	475	92	19.37
उत्तर प्रदेश	659	79	11.99
<b>कुल</b>	<b>2,415</b>	<b>393</b>	<b>16.27</b>

पूर्वोत्तर में प्रदर्शन विशेष रूप से खराब रहा, जहां केवल चार आई बी सी तैनात किए गए थे। प्रबंधन (मई 2024) ने कहा कि सेवा सीमाएँ जैसा कि पूर्ण खाता संचालन पर प्रतिबंध और उत्पाद विविधता की कमी ने संभावित आई बी सी को हतोत्साहित किया, और सेवाओं का एक व्यापक समूह उपलब्ध होने के बाद भविष्य में इनकी तैनाती में सुधार होगा। पूर्वोत्तर जैसे कुछ क्षेत्रों में, दुर्गम भूभाग को भी एक बाधा के रूप में उद्धृत किया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में (अगस्त 2025) कहा कि आई बी सी के लिए निर्दिष्ट आई पी पी बी एसेस पॉइंटों पर स्थित होना अनिवार्य नहीं है, और उन्हें वहाँ नियुक्त किया जाता है जहाँ डी ओ पी नेटवर्क की अनुपस्थिति या किसी सेवा-संबंधी समस्या के कारण ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करना चुनौतीपूर्ण होता है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि ये उत्तर अपर्याप्त ग्रामीण पहुँच के मूल मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं। 2021 की एस ओ पी में सभी एसेस पॉइंटों पर, विशेष रूप से बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में, आई बी सी की तैनाती की परिकल्पना की गई थी, न कि केवल उन क्षेत्रों में जहाँ डाक विभाग की सेवाएँ अनुपस्थित थीं।

<sup>64</sup> बिहार और हरियाणा को छोड़कर

**सिफारिश:**

आई पी पी बी को आई बी सी की तैनाती की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र स्थापित किया जाए तथा कठिन या कम संभावनाओं वाले क्षेत्रों में आई बी सी को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन संरचना लागू की जाए।

**6.1.5.1(ख) आई पी पी बी ग्राहक खातों में व्यापक सुप्तता और निष्क्रियता**

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई पी पी बी) का एक प्रमुख उद्देश्य व्यापक पहुँच और सक्रिय ग्राहक जुड़ाव के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। हालाँकि, लेखापरीक्षा निष्कर्षों से पता चलता है कि खाता खोलने और निरंतर उपयोग के बीच एक बड़ा अंतर है।

आर बी आई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक द्वारा शुरू किए गए किसी भी लेनदेन को न करने के एक साल बाद खातों को सुप्त और दो साल बाद निष्क्रिय माना जाता है। मार्च 2022 तक आई पी पी बी द्वारा खोले गए 5.13 करोड़ बचत खातों में से, लगभग 2.98 करोड़ खाते (58 प्रतिशत) मार्च 2024 तक सुप्त हो गए थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

**तालिका 6.2: कुल खातों की संख्या की तुलना में सुप्त खातों की संख्या (करोड़ में)**

वर्ष	शाखा में खातों की कुल संख्या	शाखा में सुप्त खातों की कुल संख्या	शाखा में सुप्त खातों की संचयी संख्या
2018-19	0.55	0.39	0.39
2019-20	1.79	1.25	1.64
2020-21	1.89	1.08	2.72
2021-22	0.90	0.26	2.98
<b>कुल</b>	<b>5.13</b>	<b>2.98</b>	

आकांक्षी जिलों (ए डी) में, जो वित्तीय समावेशन के मुख्य केंद्रित क्षेत्र होने चाहिए, आई पी पी बी ने 2021-22 तक 63.57 लाख खाते खोले, जिनमें से 31.30 लाख खाते (49.24 प्रतिशत) मार्च 2024 तक सुप्त हो चुके हैं।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मार्च 2023 तक स्थापित किए गए 7.5 प्रतिशत (1,38,476 में से 10,373) एसेस पॉइंट्स में दस या उससे कम खाते थे, जो न्यूनतम ग्राहक पहुँच को दर्शाता है। इनमें से 1,564 एसेस पॉइंट्स में कोई खाता नहीं था, जो शून्य ग्राहक जुड़ाव को दर्शाता है। इन गैर-कार्यात्मक केंद्रों में से 1,165 (74.5 प्रतिशत) में प्रशिक्षित अंतिम उपयोगकर्ताओं का अभाव था, जिससे वे आई

पी पी बी सेवाएँ (अनुलग्नक-6.2) प्रदान करने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त, 4,743 एसेस पॉइंट्स (3.4 प्रतिशत) में, कुल 8,675 खाते थे, जिनमें से सभी निष्क्रिय थे, जिसके कारण वे प्रभावी रूप से गैर-परिचालनात्मक हो गए।

इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान खोले गए 1.37 करोड़ खातों में से, 20.85 लाख (15.16 प्रतिशत) खाते निष्क्रिय हो गए हैं क्योंकि पिछले एक वर्ष से इन खातों में कोई लेनदेन नहीं हुआ है और इनके सुप्त खाते होने की संभावना है।

प्रबंधन (मई 2024) ने सुप्तता के लिए स्टाफिंग, कनेक्टिविटी और प्रशिक्षण की कमी को जिम्मेदार ठहराया, और कहा कि कई निष्क्रिय खाते पुराने डी बी टी-लिंकड खाते थे, जो यू पी आई कार्यन्वयन से पहले खोले गए थे। इसमें आगे कहा गया है कि अप्रैल 2023 में शुरू की गई पुनरुद्धार योजना, जिसे आर बी आई के संशोधित दिशानिर्देशों (जनवरी 2024) से सहायता मिली, सुप्तता को कम करने में मदद कर रही है। मंत्रालय (अगस्त 2025) ने आगे बताया कि ग्राहकों से एस एम एस, डाक चौपालों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है, और प्रीमियम योजनाओं में खातों का उन्नयन केवल ग्राहकों की सहमति से, सुविधाओं और संबंधित शुल्कों के बारे में बताने के बाद किया जा रहा है। इसने 2024-25 की अंतिम दो तिमाहियों के दौरान 51.94 लाख खातों के सक्रिय होने की भी सूचना दी।

लेखापरीक्षा स्वीकार करती है कि ये पहल सही दिशा में उठाए गए कदम तो हैं, लेकिन पुनरुद्धार योजना देर से शुरू की गई थी, और खातों का पुनः सक्रियण मुख्यतः ग्राहकों द्वारा पुनः-के वाई सी के बाद प्रीमियम बचत खातों में उन्नयन करने पर निर्भर था, जिससे कम आय वाले उपयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त आवर्ती लागत आती थी। पुनः-के वाई सी और वैकल्पिक सशुल्क अपग्रेड की आवश्यकता, भले ही ग्राहक की सहमति से की गई हो, कम मूल्य वाले खाताधारकों को पुनः सक्रियण से हतोत्साहित कर सकती है। पुनरुद्धार रणनीति में सरलीकृत पुनः सक्रियण प्रक्रियाओं या निष्क्रिय खंडों के डेटा-आधारित लक्ष्यीकरण जैसे निरंतर जुड़ाव उपायों का अभाव है।

#### **सिफारिश:**

**आई पी पी बी को निष्क्रिय खातों के वास्तविक समय में निगरानी, आकांक्षी जिलों में लक्षित पुनर्सक्रियण तथा ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना सरल पुनर्सक्रियण की व्यवस्था के साथ एक सक्रिय निष्क्रियता प्रबंधन ढाँचा अपनाया जाए।**

### 6.1.5.2 सेवा की गुणवत्ता

#### 6.1.5.2(क) खराब सेवा गुणवत्ता और अस्वीकृत यू पी आई लेनदेन की उच्च दर ने ग्राहक विश्वास को कमजोर किया

आई पी पी बी ने डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और नकदी पर निर्भरता कम करने के लिए आई पी पी बी मोबाइल बैंकिंग ऐप, डाक पे और माइक्रो ए टी एम जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से दिसंबर 2020 में यू पी आई सेवाएं शुरू कीं।

हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों से पता चला है कि यू पी आई लेनदेन के लिए आई पी पी बी की तकनीकी गिरावट (टी डी<sup>65</sup>) दर काफी अधिक थी - वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3.29 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.82 प्रतिशत - जोकि आर बी आई के 1 प्रतिशत से कम के लक्ष्य से कहीं अधिक है और समकक्ष पेमेंट्स बैंकों<sup>66</sup> (अनुलग्नक-6.3) की तुलना में खराब निष्पादन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, आई पी पी बी की यू पी आई सेवाओं में 97 रुकावटें आईं, कुल मिलाकर 362 घंटे (अनुलग्नक-6.4), जोकि फिनो (19 घंटे), एयरटेल (52 घंटे) और पेटीएम पेमेंट्स बैंक (0 घंटे) से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा, डेबिट रिवर्सल सफलता<sup>67</sup> दर में खराब प्रदर्शन के कारण ग्राहकों में असंतोष और शिकायतें बढ़ीं, जिससे आई पी पी बी की डिजिटल सेवाओं में विश्वास कम हुआ। 2021-22 में डेबिट रिवर्सल सफलता दर 35.43 प्रतिशत थी, जोकि 2022-23 में थोड़ा सुधरकर 51.97 प्रतिशत हो गई, जबकि इन दो वर्षों के दौरान चारों भुगतान बैंकों का औसत लगभग 80 प्रतिशत था (अनुलग्नक-6.3)।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि अवसंरचना के उन्नयन सहित बैंडविड्थ वृद्धि और डेटाबेस प्रबंधन ने तकनीकी गिरावट दरों को कम कर दिया है, और मंत्रालय ने (अगस्त 2025) नेटवर्क शुरू करने, एच एस एम उन्नयन और लेनदेन पृथक्करण जैसे सुधारों का हवाला देते हुए इन उपायों का समर्थन किया।

हालाँकि, उत्तर में लंबे समय तक डाउनटाइम, डेबिट रिवर्सल की कम सफलता और उच्च व्यावसायिक गिरावट जैसी लगातार समस्याओं को संबोधित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा का मानना है कि ये निरंतर कमियाँ अपर्याप्त प्रणालीगत लचीलेपन, निगरानी और लेनदेन विफलताओं के मूल कारण विश्लेषण को दर्शाती हैं।

<sup>65</sup> तकनीकी गिरावट (टी डी) - तकनीकी कारणों से लेनदेन में गिरावट, जैसे सिस्टम की अनुपलब्धता और बैंक या एन पी सी आई की ओर से नेटवर्क संबंधी समस्याएं।

<sup>66</sup> 2021-22 में, पे टी एम पी बी, एयरटेल पी बी और फिनो पी बी के मामले में तकनीकी गिरावट क्रमशः 0.15 प्रतिशत, 1.56 प्रतिशत और 2.83 प्रतिशत थी। 2022-23 में, पे टी एम पी बी, एयरटेल पी बी और फिनो पी बी के मामले में तकनीकी गिरावट क्रमशः 0.08 प्रतिशत, 1.96 प्रतिशत और 4.11 प्रतिशत थी।

<sup>67</sup> डेबिट रिवर्सल सफलता प्रतिशत उन कुल मामलों का प्रतिशत दर्शाता है, जहाँ किसी ग्राहक के खाते से डेबिट किया जा सकता है, और उनका बैंक ऐसे डेबिट के रिवर्सल की स्थिति की तुरंत पुष्टि करने में असमर्थ होता है। जब रिवर्सल / क्रेडिट तुरंत संसाधित नहीं होता है, तो इसे आर बी आई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा मैन्युअल रूप से संसाधित किया जाता है।

**सिफारिश:**

**आई पी पी बी को ग्राहकों के विश्वास की रक्षा के लिए यू पी आई लेन-देन से संबंधित निर्धारित मानकों को निरंतर पूरा करने हेतु सुदृढ़ निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र लागू किया जाए।**

**6.1.5.2(ख) असत्यापित मोबाइल नंबरों से खाते खोलना और एक ही मोबाइल नंबर से कई सी आई एफ<sup>68</sup> को जोड़ना**

हालाँकि RBI के दिशानिर्देश "एक मोबाइल, एक सी आई एफ" नियम को अनिवार्य नहीं करते हैं, लेकिन वे खाते की सुरक्षा और परिचालन अखंडता के लिए जिम्मेदारी से मोबाइल नंबर के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करते हैं। आई पी पी बी ने सितंबर 2020 में "एक मोबाइल, एक सी आई एफ" नीति शुरू की, जिसने प्रति मोबाइल नंबर पाँच सी आई एफ तक की अनुमति देने की अपनी पूर्व प्रवृत्ति को बदला। इस नीति के तहत, एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े कई सी आई एफ ग्राहकों को अपना नंबर अद्यतन करने के लिए 15 दिन का एस एम एस नोटिस प्राप्त होता था, अन्यथा मोबाइल बैंकिंग की सुविधा बंद कर दी जाती थी।

मार्च 2024 तक, 8.61 करोड़ मामलों में से लगभग 1.22 करोड़ मामलों में, आई पी पी बी की नीति का उल्लंघन करते हुए एक मोबाइल नंबर से कई सी आई एफ जुड़े हुए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

एक मोबाइल से जुड़े एक नंबर के मामले (एक्स)	7,39,10,520
एक मोबाइल नंबर से जुड़े दो से पाँच सी आई एफ के मामले (क)	1,21,70,402
एक मोबाइल नंबर से जुड़े पाँच से अधिक, अधिकतम दस सी आई एफ के मामले (ख)	71,048
एक मोबाइल नंबर से जुड़े दस से अधिक सी आई एफ के मामले (ग)	1,136
<b>एक मोबाइल नंबर से जुड़े कई सी आई एफ के कुल मामले (घ=क+ख+ग)</b>	<b>1,22,42,586</b>
<b>कुल सी आई एफ (एक्स+घ)</b>	<b>8,61,53,106</b>

इसके अलावा, आई पी पी बी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सी आई एफ एक ही मोबाइल नंबर से जुड़ा हो, जिसे खाता खोलने के दौरान ओ टी पी के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। आई पी पी बी की फिनेकल<sup>69</sup> प्रणाली की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 2019-20 के दौरान, कई खाते स्पष्ट

<sup>68</sup> ग्राहक सूचना फ़ाइलें

<sup>69</sup> फिनेकल एक वेब-आधारित, एकीकृत कोर बैंकिंग समाधान है जो विभिन्न वित्तीय और परिचालन कार्यों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है और किसी भी समय, कहीं भी बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

रूप से अमान्य मोबाइल नंबरों (जैसे, 9999999999, 7777777777) के साथ खोले गए थे, जो अक्सर विभिन्न शाखाओं में कई सी आई एफ से जुड़े होते थे (अनुलग्नक-6.5)। ये प्रविष्टियाँ खाता खोलने की प्रक्रिया में गंभीर नियंत्रण चूक की ओर संकेत करती हैं।

प्रबंधन ने बताया (मई 2024) कि ज्यादातर मल्टीपल-लिंगेज मामले 2020 की नीति से पहले खोले गए पुराने खातों से संबंधित थे और मोबाइल विवरण अद्यतन करने के लिए जागरूकता शिविर के ज़रिए प्रयास किए जा रहे थे। मंत्रालय ने (अगस्त 2025) यह भी बताया कि ग्रामीण कनेक्टिविटी की सीमाओं के कारण पहले प्रति मोबाइल पाँच-सी आई एफ वाला तरीका अपनाया गया था और वर्तमान में केवल 1,565 अवांछित नंबर मौजूद हैं, जबकि 2021 के बाद के छह खातों में विसंगतियों की समीक्षा की जा रही है।

लेखापरीक्षा को ये उत्तर आंशिक रूप से ही विश्वसनीय लगते हैं, क्योंकि असत्यापित या प्रतिरूप मोबाइल लिंगेज का बने रहना, विरासत डेटा में अपर्याप्त शोधन और बैंकिंग प्रणाली में कमजोर सत्यापन को दर्शाता है।

#### सिफारिश:

**आई पी पी बी को चाहिये कि वह अवैध या डुप्लीकेट लिंक को समाप्त करने तथा खाता खोलने के दौरान सत्यापन में मौजूद कमियों की पहचान करने के लिए व्यापक डेटा शुद्धिकरण किया जाए, जिससे आई टी प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सके।**

#### 6.1.5.2(ग) घर-घर बैंकिंग की अपर्याप्त पहुंच और सेवा गुणवत्ता

आई पी पी बी "आपका बैंक आपके द्वार" के नाम से घर-घर बैंकिंग<sup>70</sup> की सुविधा प्रदान करता है, जो अपने व्यापक डाक नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्राहकों को खाता खोलने, धन हस्तांतरण, नकदी जमा और आहरण, बिल भुगतान, बीमा खरीद और अन्य बैंकों से नकदी आहरण के लिए आधार से जुड़े खातों तक पहुंच जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

घर-घर बैंकिंग में सीमित रुचि देखी गई और पाँच वर्षों (2018-2023) में 6.51 करोड़ ग्राहकों से केवल 47,204 अनुरोध प्राप्त हुए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इनमें से 57.46 प्रतिशत अनुरोधों पर या तो ध्यान नहीं दिया गया या दो दिन से अधिक की देरी हुई। इसके अलावा, बैंक द्वारा सेवा प्रदान करने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

<sup>70</sup> ग्राहक कॉल सेंटर के माध्यम से या जी डी एस, डाकियों या डाकघरों के माध्यम से तदर्थ अनुरोध करके सेवाओं का अनुरोध कर सकते हैं। हालाँकि, ये सेवाएँ आई पी पी बी मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से उपलब्ध नहीं हैं। घर-घर बैंकिंग के लिए सेवा शुल्क को 01-09-2021 से संशोधित कर प्रति ग्राहक सेवा जी एस टी सहित ₹20 प्रति डोरस्टेप विज़िट कर दिया गया था, जिसे बाद में 25-08-2023 से समाप्त कर दिया गया।

ग्राहक घर-घर अनुरोध प्रबंधन (सी डी आर एम) के डेटा (अक्टूबर-दिसंबर 2022) की एक नमूना जाँच से पता चला कि 3,812 ग्राहकों के अनुरोधों में से 1,477 (38.77 प्रतिशत) को आगे सौंपा नहीं गया। इसके अलावा, मिले कुल अनुरोधों में से 3,503 अनुरोध के वाई सी-आधारित खाता रूपांतरण के लिए थे, जिनमें से 1,314 (37.51 प्रतिशत) पूरे नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप खाते बंद हो गए। उपरोक्त आँकड़ों के आगे विश्लेषण से पता चला कि 3,812 ग्राहक अनुरोधों में से 564 आकांक्षी ज़िलों से संबंधित थे जिसमें से 229 का निपटान नहीं किया गया। के वाई सी आधारित खाता रूपांतरण के 3,503 अनुरोधों में से 524 आकांक्षी ज़िलों से संबंधित थे जिसमें से 210 अनुरोध पूरे नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप खाते बंद हो गए।

लेखापरीक्षा में अस्पष्ट अनुरोध लॉग, रिपोर्ट की गई और वास्तविक सेवाओं के बीच विसंगतियाँ, और कुछ क्षेत्रों में अंतिम उपयोगकर्ताओं की कमी के कारण सेवा से इनकार भी देखा गया। यहाँ तक कि प्रीमियम खाताधारकों, जो निःशुल्क घर-घर बैंकिंग सेवाओं के हकदार थे, को भी अक्सर डाकघर जाने की सलाह दी जाती थी।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि सेवा में देरी, इनकार और ₹25 के शुल्क (सितंबर 2021-अगस्त 2023) ने घर-घर बैंकिंग के उपयोग को हतोत्साहित किया, खासकर डी बी टी लाभार्थियों द्वारा। अगस्त 2023 में इसका उपयोग बढ़ाने के लिए शुल्क को हटा दिया गया। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन(अगस्त 2025) किया।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि न केवल सेवा शुल्क बल्कि अपर्याप्त जन शक्ति और कमज़ोर अनुरोध-ट्रैकिंग भी प्रमुख बाधाएँ थीं। सेवा की गुणवत्ता, निगरानी या प्रतिनिधि की उपलब्धता में उचित सुधार के बिना सेवा शुल्क वापस लेना, घर-घर बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने में अप्रभावी होगा। इसके अलावा, एक संरचित अनुरोध-ट्रैकिंग प्रणाली का अभाव और अस्पष्ट समापन टिप्पणियों का उपयोग प्रभावी समाधान और निगरानी में बाधा डालता है।

#### **सिफारिश:**

**आई पी पी बी को ग्राहक घर-घर अनुरोध प्रबंधन प्रणाली में ट्रैकिंग तंत्र को सुदृढ़ किया जाए तथा सेवा प्रदाय में सुधार करते हुए घर-घर बैंकिंग सेवाओं की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।**

#### **6.1.5.3 व्यवसाय के छूटे हुये अवसर**

##### **6.1.5.3(क) आई पी पी बी खातों को डाकघर बचत बैंक खातों से न जोड़ने के कारण विफल लेनदेन**

आई पी पी बी ग्राहकों को अपने बचत खातों को डाकघर बचत खातों (पी ओ एस ए) से जोड़ने की अनुमति देता है ताकि वे ₹2 लाख से अधिक की राशि का प्रबंधन कर सकें, लेनदेन अस्वीकृति से बच सकें, और स्वीप-इन / आउट सुविधा व उच्च ब्याज का लाभ प्राप्त कर सकें। डाक विभाग ने अगस्त 2021 में राजस्व लाभ के लिए आई पी पी बी-पी ओ एस ए को जोड़ने को प्राथमिकता देने का निर्देश

दिया था क्योंकि डाक विभाग में पी ओ एस ए से जुड़े खातों की औसत राशि, गैर जुड़े खातों<sup>71</sup> की तुलना में अधिक थी। इन लाभों और डाक विभाग के निर्देशों के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक 6.51 करोड़ खातों में से केवल 32.7 लाख (5.02 प्रतिशत) ही पी ओ एस ए से जुड़े थे।

गैर-जोड़ के कारण, सभी लेन-देन, जहाँ ₹2 लाख की सीमा का उल्लंघन हुआ, अस्वीकृत कर दिए गए। 2019-20 से जनवरी 2024 के दौरान, ऐसी 55,479 अस्वीकृतियाँ (54,412 ए पी बी एस<sup>72</sup> के माध्यम से और 1,067 एन ए सी एच<sup>73</sup> के माध्यम से) हुईं, जिनमें ₹1,301.79 करोड़ शामिल थे। आकांक्षी जिलों के संबंध में, अस्वीकृति का आंकड़ा 4,288 (4,134 ए पी बी एस के माध्यम से और 154 एन ए सी एच के माध्यम से) था, जिसमें ₹93.25 करोड़ शामिल थे। एकाधिक असफल क्रेडिट प्रयासों के कारण वास्तविक अस्वीकृत राशि अधिक हो सकती है।

प्रबंधन ने बताया (मई 2024) कि पी ओ एस ए को जोड़ना वैकल्पिक था और लेन-देन विफल होने के बाद जोड़ने की सुविधा के लिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2025) कि तब से 45 लाख खाते (ग्राहकों का लगभग 4 प्रतिशत) जोड़ दिए गए हैं, और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 25 लाख अतिरिक्त खाते जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

इन उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ग्राहकों की कम जागरूकता, पूर्व-निवारक संपर्क अभियान के अभाव और आई पी पी बी तथा डाक विभाग के बीच सीमित समन्वय के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। विफलताओं के बाद ग्राहकों से संपर्क करने का प्रतिक्रियात्मक तरीका अपर्याप्त निवारक नियंत्रण को दर्शाता है।

#### **सिफारिश:**

**बैंक को विशेष रूप से उच्च शेष राशि तथा डी बी टी से जुड़े खातों के लिए डाकघर बचत खातों के साथ सक्रिय लिंकिंग को बढ़ावा देने हेतु लक्षित अभियान और प्रणालीगत संकेत प्रारंभ किए जाएँ।**

#### **6.1.5.3 (ख) वित्तीय साक्षरता शिविरों (एफ एल सी) के लिए नाबार्ड की ₹4.30 करोड़ की सहायता का गैर उपयोग**

नाबार्ड का लक्ष्य अपने वित्तीय समावेशन निधि (एफ आई एफ) के माध्यम से, अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे पिछड़े जिलों में वित्तीय समावेशन की कमी को पूरा करना है,

<sup>71</sup> 25 लाख पी ओ एस ए से संबद्ध खातों के लिए औसत राशि ₹1960 थी, जबकि 430 लाख गैर-पी ओ एस ए से संबद्ध खातों के लिए औसत राशि केवल ₹517 थी।

<sup>72</sup> ए पी बी एस - आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली सरकार और सरकारी एजेंसियों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने में मदद कर रही है।

<sup>73</sup> एन ए सी एच - राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एन ए सी एच), बल्क पुश और पुल लेनदेन के लिए एक ऑफलाइन वेब-आधारित प्रणाली है। एन ए सी एच, जनादेशों को पंजीकृत करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक जनादेश प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे निगमों और बैंकों के लिए कागज रहित संग्रह प्रक्रिया सुगम हो जाती है। यह खाता-आधारित और आधार-आधारित, दोनों प्रकार के लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।

जिन्हें मुख्य केंद्रित जिलों (एस एफ डी) का नाम दिया गया है। एफ आई एफ से अनुदान, आई पी पी बी जैसे पेमेंट्स बैंकों सहित, वित्तीय साक्षरता पहल को लागू करने वाले बैंकों के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। "वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविर" योजना में, आई पी पी बी ग्रामीण आबादी के लिए विभिन्न विषयों पर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु एस एफ डी में प्रति शिविर ₹6,000 और अन्य जिलों में ₹5,000 के लिए पात्र था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई पी पी बी 2019-20 और 2022-23 के बीच कम सेवा वाले क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और सेवाओं का विस्तार करने के लिए नाबार्ड की सहायता का लाभ उठाने में विफल रहा। आठ लेखापरीक्षित सर्किल में 11,654 शिविरों के लिए नाबार्ड द्वारा धनराशि स्वीकृत करने के बावजूद, आई पी पी बी ने केवल 5,173 शिविर आयोजित किए, जो लक्ष्य का मात्र 44.39 था, और कुल स्वीकृत राशि ₹5.59 करोड़ में से केवल ₹1.30 करोड़ (23.26 प्रतिशत) खर्च किए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर सर्किल जैसे क्षेत्रों ने अपनी उपलब्ध धनराशि का 25 प्रतिशत से भी कम उपयोग किया, यहाँ तक कि शीर्ष निष्पादन करने वाले मध्य प्रदेश सर्किल ने भी केवल 62.41 प्रतिशत का ही उपयोग किया (अनुलग्नक- 6.6)।

प्रबंधन (मई 2024) ने इस कमी के लिए जनशक्ति की कमी और कोविड-19 महामारी को ज़िम्मेदार ठहराया। मंत्रालय ने आगे कहा कि उपयोग नाबार्ड की राज्य-स्तरीय मंजूरीयों पर निर्भर करता है और आई पी पी बी ने व्यय कम करने के लिए प्रति शिविर लागत ₹1,500 तक सीमित कर दी, साथ ही अन्य सहयोगों के माध्यम से साक्षरता गतिविधियाँ भी की।

ये उत्तर कम उपयोग को पर्याप्त रूप से उचित नहीं ठहराते, क्योंकि यह कमी महामारी की अवधि के बाद भी बनी रही, और आई पी पी बी की आंतरिक सीमा नीति ने नाबार्ड के वित्तपोषण समर्थन के उद्देश्य को कमजोर कर दिया। नाबार्ड के साथ सीमित समन्वय और कमजोर निगरानी के कारण वित्तीय रूप से वंचित क्षेत्रों में पहुँच के अवसर चूक गए।

#### **सिफारिश:**

**आई पी पी बी सर्किलों और नाबार्ड के राज्य कार्यालयों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाए, स्वीकृत और आयोजित शिविरों की निगरानी को बेहतर बनाया जाए तथा निधियों के उपयोग को सीमित करने वाली मनमानी आंतरिक सीमाओं को समाप्त किया जाए।**

#### **6.1.5.4 प्रणाली सुरक्षा समस्याएँ : माइक्रो - ए टी एम उपकरणों में कमजोर सुरक्षा नियंत्रण**

आर बी आई के सूचना सुरक्षा दिशानिर्देश जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत उपयोगकर्ता पहचान और प्रमाणीकरण पर ज़ोर देते हैं। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्रामीण डाक सेवकों (बैंकिंग परिचालन के लिए अंतिम उपयोगकर्ता) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आई पी पी बी के माइक्रो-ए टी एम उपकरणों में तकनीकी क्षमता होने के बावजूद बायोमेट्रिक या बहु-कारक प्रमाणीकरण

का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके बजाय, उपयोगकर्ता केवल लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से प्रणाली तक पहुँच सकते थे, जिससे असुरक्षा की स्थिति पैदा हो रही थी।

कमज़ोर प्रमाणीकरण तंत्र लेन-देन सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं और आई पी पी बी उपकरणों के दुरुपयोग होने देते हैं। एक मामले में (जनवरी 2024, दौसा शाखा), एक दूरस्थ शाखा कार्यालय में एक जी डी एस को सौंपे गए माइक्रो-ए टी एम का दुरुपयोग एक कार्यालय सहायक द्वारा शाखा के भीतर लेनदेन करने के लिए किया गया, जो अनधिकृत पहुँच और संभावित धोखाधड़ी के जोखिम को उजागर करता है।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2025) कि बैंक ने उपकरणों की जियो-टैगिंग शुरू कर दी है और कई प्रमाणीकरण परतें लागू की हैं, जिनमें सिम सत्यापन, पासवर्ड लॉगिन और मोबाइल डिवाइस प्रबंधन (एम डी एम) के माध्यम से नियंत्रण शामिल है, जिसके लिए अनिवार्य पासवर्ड पहुँच की आवश्यकता होती है।

आई पी पी बी बायोमेट्रिक या ओ टी पी-आधारित द्वितीय-कारक सत्यापन को अनिवार्य करके, डिवाइस स्थान का पता लगाने के लिए वास्तविक समय जियो-फेंसिंग को एकीकृत करके, और उपयोगकर्ता एसेस लॉग की आवधिक समीक्षा करके प्रमाणीकरण तंत्र को और मजबूत कर सकता है।

### 6.1.6 निष्कर्ष

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई पी पी बी) की परिकल्पना विशाल डाक नेटवर्क का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले के रूप में की गई थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा से पता चला है कि आई पी पी बी की पहुँच और सेवा वितरण परिचालन संबंधी अक्षमताओं, अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और उपलब्ध संसाधनों के कम उपयोग के कारण लगातार बाधित हो रहा है। यह इस बात से साफ़ है कि मार्च 2022 तक खोले गए बैंक अकाउंट में से लगभग 58 प्रतिशत अकाउंट खुलने के दो साल के अंदर ही सुप्त हो गए। जबकि यह आई बी सी के डिप्लॉयमेंट के लिए अपने तय किए गए टारगेट को सिर्फ़ 16.27 प्रतिशत ही हासिल कर सका, इसकी डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज़ को भी बहुत कम लोग अपना रहे थे, जिससे ग्रामीण इलाकों में बैंक की पहुँच कम हुई। इसके अलावा, टेक्निकल कमियाँ जैसे कि बार-बार यू पी आई लेनदेन विफलताएँ जो 7.82 प्रतिशत तक था, डेबिट रिवर्सल दरों की कम सफलता दर (प्राइवेट सेक्टर पेमेंट्स बैंकों के लगभग 80 प्रतिशत की तुलना में आई पी पी बी का 52 प्रतिशत) और माइक्रो-ए टी एम उपकरणों पर अपर्याप्त प्रमाणीकरण नियंत्रण से ग्राहक का भरोसा कम हुआ और आई पी पी बी के परिचालन की सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर चिंताएँ पैदा की हैं।

वित्तीय और परिचालन संबंधों से बैंक और डाक विभाग दोनों का निष्पादन बेहतर हो सकता था। डाकघर बचत खातों के साथ आई पी पी बी प्रणाली का एकीकरण ठीक से लागू नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन विफल रहा और ग्राहकों को असुविधा हुई। इसके अलावा, आई पी पी बी ने वित्तीय साक्षरता पहल के लिए नाबार्ड की ₹4.30 करोड़ की सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं

किया, जिससे कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में जागरूकता और समावेशन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर चूक गया।

बैंक को अपनी पहुँच बेहतर करने के लिए परिचालन प्रबंधन के लिए डेटा-आधारित और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने, तकनीकी लचीलापन बढ़ाने और डाक विभाग तथा नाबार्ड जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय को मज़बूत करने की आवश्यकता है। ग्रामीण भारत में सुलभ, विश्वसनीय और समावेशी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के अपने दायित्व को साकार करने के लिए आई पी पी बी के लिए ग्राहक सहभागिता, सेवा गुणवत्ता निगरानी और सूचना सुरक्षा के लिए एक मज़बूत ढाँचा आवश्यक है।

## 6.2 भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) में टावर संपत्तियों के प्रबंधन पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा

### 6.2.1 परिचय

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल), दूरसंचार विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, 1 अक्टूबर 2000 को स्थापित हुआ और अक्टूबर 2002 में मोबाइल सेवाएं शुरू की, पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग (डी टी एस) और दूरसंचार संचालन विभाग (डी टी ओ) से परिचालन का कार्यभार संभाला। दूरसंचार टावर मोबाइल नेटवर्क का आधार हैं और मार्च 2025 तक, बी एस एन एल सभी दूरसंचार सर्किलों<sup>74</sup> में 66,200 टावरों की एक बड़ी अवसंरचना का स्वामित्व और संचालन करता है। स्वामित्व और किराए पर ली गई दोनों जगहों पर स्थित इन टावरों का बही मूल्य ₹3,766.10 करोड़ था।

राजस्व बढ़ाने के लिए, बी एस एन एल अपने टावर अवसंरचना को एयरटेल, वोडाफोन आईडीया और रिलायंस जियो जैसे निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) के साथ साझा कर रहा है। मार्च 2025 तक, 11,994 टावर साझा किए गए थे। नीचे दी गई तालिका 2018-19 से 2024-25 तक बी एस एन एल के टावर अवसंरचना<sup>75</sup>, साझाकरण व्यवस्था और अवसंरचना प्रावधान राजस्व का सारांश प्रस्तुत करती है।

<sup>74</sup> दिल्ली और मुंबई को छोड़कर जो एम टी एन एल के अंतर्गत आते हैं।

<sup>75</sup> टावर अवसंरचना में निष्क्रिय अवसंरचना शामिल होती है, जैसे भवन, टावर, तथा विद्युत उपकरण जिसमें बैटरी और पावर प्लांट, डार्क फाइबर, डक्ट स्पेस, राइट ऑफ वे आदि शामिल हैं।

तालिका 6.3: बी एस एन एल के टावर स्वामित्व का विवरण

वर्ष (वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक)	बी एस एन एल के पास टावरों की कुल संख्या	अन्य टी एस पी के साथ साझा किए गए टावरों की संख्या	राजस्व (अवसंरचना प्रावधान शुल्क <sup>76</sup> ) (₹ करोड़ में)
2018-19	68,029	13,567	659.64
2019-20	68,050	13,490	661.25
2020-21	67,470	13,469	621.57
2021-22	67,436	13,399	643.07
2022-23	67,464	12,684	637.19
2023-24	67,340	12,502	673.07
2024-25	66,200	11,994	698.68

### 6.2.2 लेखापरीक्षा का दायरा, उद्देश्य और मानदंड

यह लेखापरीक्षा 2018-19 से 2022-23<sup>77</sup> तक सात वर्षों की अवधि को शामिल करती है और बी एस एन एल निगमित कार्यालय में की गई। इसके अतिरिक्त, 10 चयनित बी एस एन एल सर्किलों (अनुलग्नक 6.7) के 30 व्यावसायिक क्षेत्रों (बी ए) के अभिलेखों की जाँच की गई। जहाँ आवश्यक हुआ, टावर अवसंरचना से संबंधित विरासत संबंधी समस्याओं की पुष्टि के लिए जाँच को पहले की अवधि तक भी बढ़ाया गया।

यह लेखापरीक्षा विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) के रूप में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ की गई:

- बी एस एन एल के वित्तीय और परिचालन हितों की सुरक्षा के लिए टावर साइटों के संपदा अभिलेख की पर्याप्तता और पूर्णता का आकलन करना;
- यह आकलन करना कि क्या दूरसंचार सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए टावर अवसंरचना का इष्टतम उपयोग किया गया था; और
- टावर अवसंरचना की वित्तीय व्यवहार्यता की जांच करना, चाहे वह निर्मित हो या पट्टे पर दी गई हो।

<sup>76</sup> बी एस एन एल और टी एस पी के बीच मास्टर सेवा समझौते (एम एस ए) की अनुसूची 3 के तहत उप-खंड 1.1 के अनुसार मासिक आधार किराया निष्क्रिय अवसंरचना प्रावधान शुल्क के रूप में जाना जाता है।

<sup>77</sup> जहां भी प्रासंगिक समझा गया, वहां 2024-25 तक अद्यतन किया गया।

लेखापरीक्षा में बी एस एन एल निगमित कार्यालय द्वारा जारी प्रासंगिक फाइलों, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं की जांच; टावर अवसंरचना से संबंधित बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त और एजेंडा नोट्स; तथा टावर साझा करने के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ हस्ताक्षरित मास्टर सेवा समझौतों की जांच शामिल थी।

बी एस एन एल प्रबंधन के साथ प्रवेश बैठक 14 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई, और निकास बैठक 6 जून 2024 को आयोजित की गई।

### 6.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 6.2.3.1 संपत्ति अभिलेखों की पर्याप्तता और पूर्णता

##### 6.2.3.1(क) बी एस एन एल को भूमि स्वामित्व का हस्तांतरण न करना

बी एस एन एल की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी, जो सितंबर 2000 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दूरसंचार सेवा विभाग (डी टी एस) और दूरसंचार परिचालन विभाग (डी टी ओ) के निगमीकरण के निर्णय के परिणामस्वरूप हुई थी। तदनुसार, डी टी ओ और डी टी एस की सभी संबद्ध परिसंपत्तियां और देनदारियां, जिनमें भूमि के टुकड़े भी शामिल हैं, बी एस एन एल को हस्तांतरित की जानी थी।

चयनित सर्किलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 1,680 भूखंडों में से 599 भूखंडों (36 प्रतिशत) के स्वामित्व-पत्र, जिन पर दूरसंचार टावर लगाए गए थे, बी एस एन एल के नाम पर पंजीकृत नहीं थे (अनुलग्नक 6.8)। स्वामित्व-पत्रों के हस्तांतरण न होने के मुख्य कारणों में भूमि के दस्तावेजों का गायब होना, राज्य प्राधिकरणों के पास लंबित उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) और अन्य संस्थाओं के साथ संयुक्त स्वामित्व शामिल थे।

बी एस एन एल ने बताया (जून 2024) कि हालाँकि कंपनी का गठन 2000 में हुआ था, लेकिन 7,585 साइटों के लिए म्यूटेशन शुरू करने की अनुमति 2012-13 में ही मिली। तब से, यह प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभिलेख की कमी और कुछ राज्यों द्वारा म्यूटेशन से इनकार करने के कारण इसमें देरी हो रही है। मंत्रालय ने (जून 2025) बी एस एन एल के जवाब का समर्थन किया।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 लेखापरीक्षा किए गए व्यावसायिक क्षेत्रों में से केवल तीन (अयोध्या, जमशेदपुर और धनबाद) ने ही उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के लक्ष्य निर्धारित किए थे। 20 वर्षों से अधिक समय से ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बावजूद, बी एस एन एल ने उचित पंजीकरण सुनिश्चित नहीं किया है। स्पष्ट भूमि स्वामित्व के बिना, बी एस एन एल को कानूनी और वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर वह इन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने की कोशिश करता है। कंपनी को सभी व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए और उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) पूरा करने के लिए राज्य प्राधिकरणों के साथ सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।

### 6.2.3.1(ख) टावर साइटों के लिए पट्टा समझौतों का नवीनीकरण न करना

पट्टे पर ली गई ज़मीन के लिए, कानूनी और वित्तीय जोखिमों से बचने के लिए एक वैध पट्टा समझौता ज़रूरी है। अपनी ज़मीन के अलावा, बी एस एन एल विभिन्न सर्किलों में पट्टे पर ली गई संपत्तियों पर टावर भी संचालित करता है।

चयनित सर्किलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 7,242 पट्टे पर दिए गए टावर साइटों में से 1,981 साइटों (27 प्रतिशत) के पट्टा समझौते जुलाई 1997 और फरवरी 2024 के बीच समाप्त हो गए थे। ये साइटें विस्तारित अवधि के लिए बिना वैध समझौतों के काम कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि इन समाप्त हो चुके पट्टे में से 40 प्रतिशत पाँच वर्षों से अधिक समय से नवीनीकृत नहीं हुए हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

**तालिका 6.4: उन स्थलों की संख्या का आयु-वार वर्गीकरण जहां पट्टा समझौता समाप्त हो गया है**

आयु (वर्ष)	महाराष्ट्र	बिहार	झारखंड	ओडिशा	उ प्र (पू)	उ प्र (प)	म प्र	छत्तीसगढ़	राजस्थान	तमिलनाडु	कुल
5 वर्ष से कम	21	145	88	76	145	137	24	72	341	133	1182
5-10 वर्ष	29	176	43	16	69	31	4	41	47	29	485
10-15 वर्ष	8	61	36	4	27	19	8	35	10	13	221
15 वर्ष और उससे अधिक	3	19	18	0	3	6	3	4	35	2	93
कुल	61	401	187	96	244	193	39	152	433	177	1981

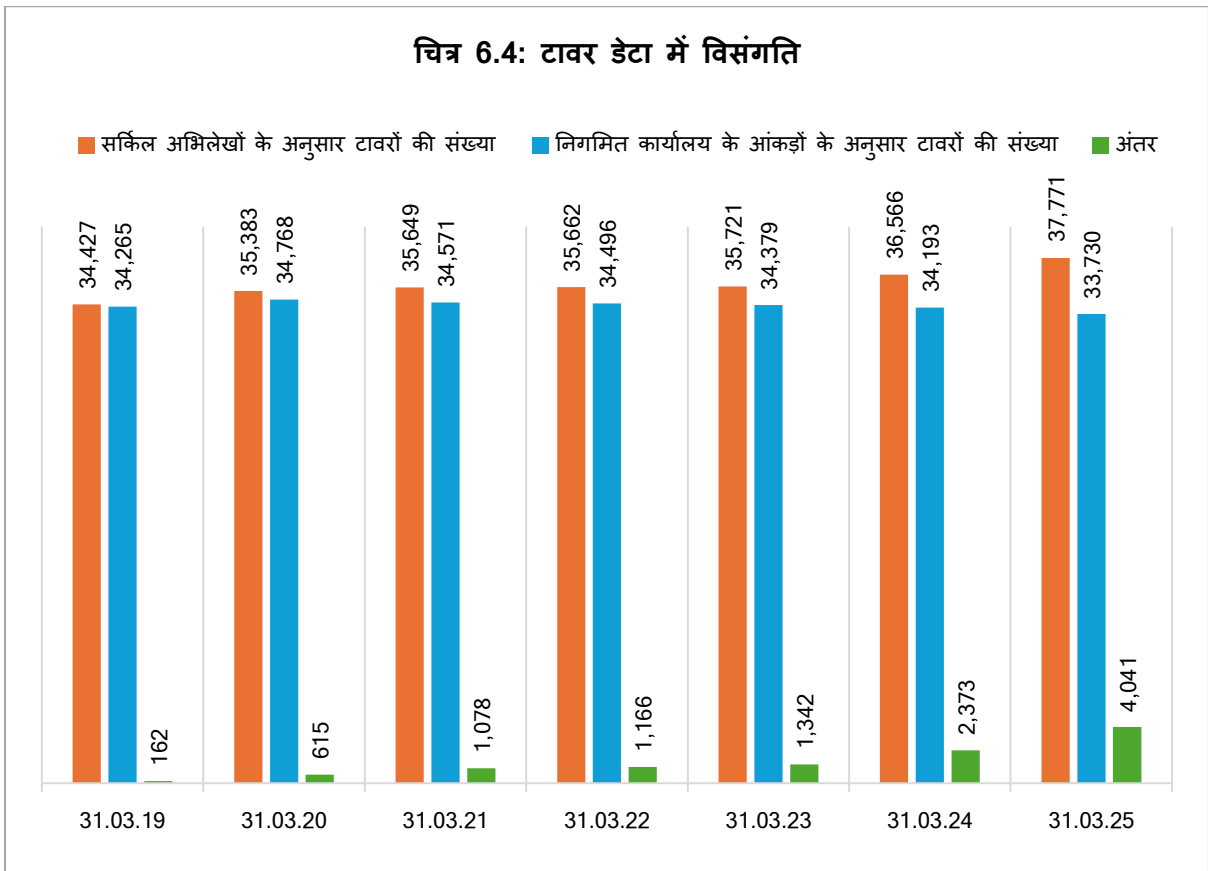
नवीनीकरण न कराने के लिए सर्किलों द्वारा बताए गए कारणों में पट्टा विलेखों का गायब होना, मकान मालिकों के साथ विवाद तथा उच्च किराए की मांग शामिल थी।

बी एस एन एल प्रबंधन (जून 2024) ने बताया कि पट्टा नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है और भूस्वामियों, जो ज़्यादातर निजी व्यक्ति हैं, के साथ बातचीत चल रही है। सर्किलों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर नवीनीकरण में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने (जून 2025) इस जवाब का समर्थन किया।

हालाँकि, समाप्त हो चुके पट्टों पर परिचालन जारी रखने से बी एस एन एल को कानूनी जोखिमों और संभावित वित्तीय देनदारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें बकाया किराया या बेदखली का खतरा भी शामिल है। कंपनी के परिचालन और वित्तीय हितों की रक्षा के लिए सभी पट्टा समझौतों का समय पर नवीनीकरण आवश्यक है।

### 6.2.3.1(ग) गलत और असंगत टावर डेटा प्रबंधन

दूरसंचार परिचालन में प्रभावी योजना, उपयोग और लागत नियंत्रण के लिए सटीक डेटा आवश्यक है। हालाँकि, निगमित कार्यालय द्वारा बनाए गए टावर डेटा और 10 चयनित सर्किलों<sup>78</sup> द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा के बीच तुलना से पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती हुई विसंगतियों का पता चला है, जैसा कि नीचे चार्ट<sup>79</sup> में दर्शाया गया है:



यह बढ़ता अंतर, सर्किलों और निगमित कार्यालय के बीच अपर्याप्त समन्वय और नियमित डेटा समाधान की कमी को दर्शाता है।

<sup>78</sup> बिहार, झारखंड, उ प्र (पूर्व), उ प्र (पश्चिम), मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र

<sup>79</sup> चूंकि मध्य प्रदेश सर्कल के संबंध में 31-3-2024 और 31-3-2025 तक टावर साइटों का डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए समाधान के उद्देश्य से 31-3-2023 तक का डेटा लिया गया।

एक विशिष्ट मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ओडिशा सर्किल में, सात टावर (अनुलग्नक 6.9) निजी विक्रेताओं (मैसर्स ए टी सी लिमिटेड, मैसर्स एसेन्ड लिमिटेड और मैसर्स भारती इंफ्रा लिमिटेड<sup>80</sup>) से किराए पर लिए गए थे, जबकि उन स्थानों पर बी एस एन एल के स्वामित्व वाले टावर (यू एस ओ निधि सब्सिडी योजना<sup>81</sup> के तहत वित्त पोषित) पहले से ही मौजूद थे। इस दोहराव और यू एस ओ एफ साइटों को तैयार करने में बी एस एन एल की असमर्थता के कारण, ब्राह्मणबिल में अप्रैल 2017 से और बालीपट्टा में अगस्त 2014 से साइटों को किराए पर लेने पर उसे किराया खर्च करना पड़ा।

बी एस एन एल प्रबंधन (जून 2024) ने बताया कि सभी सर्किलों को नई अवसंरचना के लिए मंजूरी लेने से पहले प्रस्तावित स्थलों के आस-पास निष्क्रिय या कम उपयोग वाले टावरों की अनुपस्थिति प्रमाणित करने का निर्देश दिया गया है। ओडिशा सर्किल को भी निष्क्रिय यू एस ओ टावरों को हटाने और किराए पर ली गई अनावश्यक जगहों को वापस करने के लिए कहा गया है। आगे बताया गया कि टावर डेटा के लिए एक केंद्रीकृत सी एन एम सी<sup>82</sup> पोर्टल मौजूद था, और नियमित अद्यतन के लिए सर्किल जिम्मेदार थे। मंत्रालय ने (जून 2025) इस प्रतिक्रिया का समर्थन किया और सर्किलों को नए निर्देशों के माध्यम से वास्तविक-समय डेटा सटीकता में सुधार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

सी एन एम सी पोर्टल और डेटा सत्यापन के निर्देशों के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में लगातार और बढ़ती हुई विसंगतियां, निगमित कार्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच अपर्याप्त निगरानी और अप्रभावी डेटा समन्वय का संकेत देती हैं। इससे परिचालन योजना कमजोर होती है और अनावश्यक व्यय होता है, जैसा कि ओडिशा सर्किल में देखा गया है।

### 6.2.3.2 टावर अवसंरचना का उपयोग

#### 6.2.3.2(क) खराब उपयोग के कारण ₹59.77 करोड़ मूल्य की टावर सामग्री का निष्क्रिय रहना

बी एस एन एल के खरीद दिशानिर्देशों (जून 2001) के अनुसार, दूरसंचार भंडार की आवश्यकताओं का आकलन मौजूदा भण्डार, प्रक्रियाधीन में मौजूद आपूर्ति और पिछले उपभोग स्वरूप के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रबंधन का यह भी दायित्व है कि वह खरीदी गई सामग्री का शीघ्र और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करे, साथ ही भण्डार को अनुकूलित करने के लिए धीमी / अचल वस्तुओं की समय-समय पर पहचान भी करे।

<sup>80</sup> मैसर्स भारती इंफ्रा लिमिटेड को अब मैसर्स इंडस टावर्स लिमिटेड (मैसर्स आई टी एल) के नाम से जाना जाता है।

<sup>81</sup> बी एस एन एल ने जून 2007 से प्रभावी सब्सिडी योजना के तहत यू एस ओ निधि से वित्तपोषण की व्यवस्था करके 330 टावर लगाए थे और यह योजना साढ़े छह साल के लिए वैध थी। दूरसंचार विभाग और बी एस एन एल के बीच हुए समझौते के अनुसार, नवंबर 2013 में परियोजना की सब्सिडी अवधि समाप्त होने पर, ये टावर बी एस एन एल की संपत्ति बन जाएंगे।

<sup>82</sup> केंद्रीकृत नेटवर्क प्रबंधन केंद्र (सी एन एम सी) बी एस एन एल द्वारा अपने मोबाइल नेटवर्क की वास्तविक-समय निगरानी और प्रबंधन के लिए विकसित एक प्रणाली है।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 2005-06 और 2012-13 के बीच खरीदी गई ₹59.77 करोड़ मूल्य की टावर सामग्री<sup>83</sup>, मार्च 2025<sup>84</sup> तक चयनित सर्किलों में अप्रयुक्त रही। इसका एक बड़ा हिस्सा (46 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल में केंद्रित था, उसके बाद तमिलनाडु (12.72 प्रतिशत) और झारखंड (12.30 प्रतिशत) का स्थान था, जो भण्डार और परियोजना नियोजन में भारी अक्षमताओं को दर्शाता है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसंरचना के घटकों के लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के परिणामस्वरूप धन अवरुद्ध हुआ और सामग्री की खराबी स्पष्ट देखी गई, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों से स्पष्ट है:



झारखंड सर्किल



ओडिशा सर्किल

जवाब में, बी एस एन एल प्रबंधन ने इस अवलोकन को स्वीकार कर लिया और धन की कमी और बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बी टी एस) के सीमित आवंटन को इसका कारण बताया, जिसके कारण मोबाइल परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि भंडार के समयबद्ध उपयोग, निपटान या स्क्रेपिंग की योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं, और आश्वासन दिया कि सामग्री का उपयोग भविष्य की परियोजनाओं में किया जाएगा। मंत्रालय ने (जून 2025) इस बात को दोहराया और कहा कि अधिकांश सामग्री का उपयोग या निपटान हो चुका है, जबकि शेष सामग्री को आगामी विस्तार कार्यों के लिए नियोजित किया जा रहा है।

हालाँकि, प्रबंधन के जवाब से यह पुष्टि होती है कि कई वर्षों तक समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण सामग्री लंबे समय तक बेकार पड़ी रही और खराब होती रही। भविष्य में उपयोग का आश्वासन अनिश्चित बना हुआ है, और यह चूक खरीद योजना और सामग्री उपयोग में व्यवस्थागत कमजोरी को दर्शाती है।

<sup>83</sup> टावर सामग्री को ऊंचाई के संदर्भ में दर्ज किया जाता है, जैसे 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर और 100 मीटर आदि, इसमें एंटीना माउंटिंग फिक्सचर भी शामिल है।

<sup>84</sup> उ प्र (पश्चिम) सर्किल में टावर सामग्री की निष्क्रियता की स्थिति मार्च 2024 तक है।

**6.2.3.2(ख) निर्मित टावरों का उपयोग न होना और देरी से उपयोग होना, जिसके परिणामस्वरूप पूंजी अवरुद्ध हुई और राजस्व की हानि हुई**

कुशल पूंजी उपयोग और समय पर राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए टावरों के निर्माण के तुरंत बाद अवसंरचना चालू की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 10 बी एस एन एल सर्किलों में से तीन<sup>85</sup> में स्थापित टावर लंबे समय तक अप्रयुक्त या निष्क्रिय रहे:

- ओडिशा (51), उत्तर प्रदेश (पूर्व) (15) और महाराष्ट्र (15) में 81 टावर, जिनकी कीमत ₹11.13 करोड़ है, स्थापना के बाद से तीन से सात वर्षों तक<sup>86</sup> निष्क्रिय पड़े रहे।
- ओडिशा सर्किल में 84 टावरों के निर्माण और बी टी एस स्थापना के बीच 3 से 74 महीने की देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप विलंबित उपयोग के कारण ₹6.22 करोड़<sup>87</sup> की अनुमानित राजस्व की हानि हुई (अनुलग्नक 6.10)।

ओडिशा सर्किल में फापंदा छक और पासासिंह (महादिया) में टावर के निष्क्रिय होने के उदाहरणात्मक चित्र नीचे दिए गए हैं:



फापंदा छक



पासासिंह (महादिया)

<sup>85</sup> ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (पूर्व)।

<sup>86</sup> ओडिशा में वर्ष 2017-18 से 2022-23 में, महाराष्ट्र में वर्ष 2018-19 से 2022-23 में (डेटा केवल कोल्हापुर बी ए से संबंधित है) और उ प्र (पूर्व) में मार्च 2018 से अप्रैल 2022 के दौरान स्थापित किया गया।

<sup>87</sup> लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व हानि की गणना परियोजना अनुमान में राजस्व के आंकलन को ध्यान में रखते हुए की गई। प्रति बी टी एस 875 लाइनें और प्रति लाइन प्रीपेड राजस्व ₹44 प्रति माह को राजस्व हानि की गणना के लिए माना गया है।

सर्किलों ने उपकरणों और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता को टावरों के उपयोग न होने का कारण बताया। बी एस एन एल निगमित कार्यालय (जून 2024) ने बताया कि टावरों का उपयोग आगामी चरण IX.2 मोबाइल नेटवर्क विस्तार में किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि सर्किलों को निष्क्रिय टावरों के लिए उपयोग योजनाएँ तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें 4जी विस्तार में उपयोग, लॉक-इन-पीरियड समाप्त हो चुके आई पी साइटों को स्थानांतरित करना और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पट्टे पर देना शामिल है। मंत्रालय ने (जून 2025) इस उत्तर का समर्थन करते हुए कहा कि टावर भविष्य की परियोजनाओं में चालू करने के लिए तैयार हैं।

बी एस एन एल द्वारा बताए गए कारण अवसंरचना के निर्माण व सेवा परिनियोजन के बीच अपर्याप्त योजना और खराब समन्वय को दर्शाते हैं। मार्च 2025 तक इन स्थापित टावरों के उपयोग की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। भविष्य में उपयोग के बारे में प्रबंधन का आश्वासन लंबी देरी (कुछ मामलों में 74 महीने तक), ₹11.13 करोड़ मूल्य की संपत्तियों के निष्क्रिय रहने और ₹6.22 करोड़ के अनुमानित राजस्व नुकसान के मुद्दों का समाधान नहीं करता है।

#### 6.2.3.2(ग) टी एस पी को टावर साइटों के प्रावधान में देरी के कारण ₹10.87 करोड़ के राजस्व की हानि

बी एस एन एल और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) के बीच हस्ताक्षरित मास्टर सेवा समझौते (एम एस ए) की अनुसूची 2 के अनुसार, बी एस एन एल को पुष्टिकृत सेवा आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर या टी एस पी की रोलआउट योजना के अनुरूप पारस्परिक रूप से सहमत समय-सीमा के भीतर साइट सौंपनी थी। 30 दिनों से अधिक की देरी की सूचना बी एस एन एल निगमित कार्यालय को दी जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और झारखंड सर्किलों में, बी एस एन एल ने 2011-12 और 2024-25 के बीच रिलायंस जियो (आर जे आई एल), भारती एयरटेल (बी ए एल) और वोडाफोन आइडिया (वी आई) को आवंटित 1,092 साइटों के लिए इन समय सीमाओं का पालन नहीं किया। 92 प्रतिशत मामलों में, देरी छह महीने तक बढ़ गई, एक मामले में तो यह 933 दिनों तक चली। इससे ₹10.87 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। देरी का आयु-वार वितरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 6.5: आयु-वार विश्लेषण

आयु	साइटों की संख्या				
	महाराष्ट्र	बिहार	झारखंड	ओडिशा	कुल
6 महीने तक	729	66	74	134	1003
6 महीने से 1 वर्ष तक	27	3	9	44	83
1 से 2 वर्ष	2	0	0	3	5
2 वर्ष से अधिक	0	0	1	0	1
<b>साइटों की कुल संख्या</b>	<b>758</b>	<b>69</b>	<b>84</b>	<b>181</b>	<b>1092</b>
<b>देरी के कारण किराये की आय की संभावित हानि (₹ करोड़ में)</b>	<b>6.55</b>	<b>0.66</b>	<b>1.00</b>	<b>2.66</b>	<b>10.87</b>

बी एस एन एल (जून 2024) ने देरी का कारण दो अलग-अलग गतिविधियों - टावर स्थापना और संबंधित अवसंरचना की स्थापना - के बीच तालमेल न होना बताया और कहा कि ये दोनों हमेशा एक साथ नहीं किए जा सकते। क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे भविष्य में राजस्व हानि से बचने के लिए पट्टे पर दी गई साइटों के लिए अवसंरचना के प्रावधान को प्राथमिकता दें। मंत्रालय ने (जून 2025) उत्तर का समर्थन किया।

बी एस एन एल का जवाब देरी की तीव्रता और आवृत्ति को उचित नहीं ठहराता। बी एस एन एल की जिम्मेदारी थी कि वह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से सेवा आदेश स्वीकार करने से पहले टावर निर्माण और अवसंरचना की तैयारी का समन्वय करे। लंबे समय तक और बार-बार होने वाली देरी प्रणालीगत अक्षमताओं, कमजोर परियोजना समन्वय और अनुबंधों के पालन में कमी को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई है और ग्राहकों का विश्वास कम हुआ है।

#### 6.2.3.2(घ) गैर-कार्यात्मक / विकिरण रहित<sup>88</sup> टावर साइटें

प्रचालन आवश्यकताओं के अनुसार, बी एस एन एल को मोबाइल टावर अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव पर महत्वपूर्ण पूंजीगत और आवर्ती व्यय करना पड़ता है, जिसमें किराया (यदि पट्टे पर दिया गया हो), ऊर्जा शुल्क और सुरक्षा व्यय शामिल हैं। निर्बाध सेवा वितरण और सुरक्षित राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए इन टावरों के चालू रहने की उम्मीद है।

<sup>88</sup> विकिरण रहित टावरों का अर्थ है कि बेस ट्रांसमीटर स्टेशन (बी टी एस) कार्यात्मक नहीं है और टावर से जुड़ा एंटीना विकिरण उत्सर्जित नहीं कर रहा है।

10 चयनित बी एस एन एल सर्किलों में अभिलेख की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कुछ महीनों से लेकर 16 वर्षों (2009 से 2025) तक की लंबी अवधि तक 1,740 टावर साइट निष्क्रिय या विकिरण रहित रहे (अनुलग्नक 6.11)। इसके कारणों में दोषपूर्ण या अनुपलब्ध उपकरण और ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) में व्यवधान शामिल थे। 10 में से सात सर्किलों<sup>89</sup> में, 404 निष्क्रिय टावरों का आयु-वार विश्लेषण किया गया, और 338 टावर (83.6 प्रतिशत) दो वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पाए गए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 6.6: टावरों की निष्क्रियता की अवधि

निष्क्रियता की अवधि	महाराष्ट्र <sup>90</sup>	बिहार	झारखंड	ओडिशा <sup>91</sup>	उ प्र (पू)	उ प्र (प)	राजस्थान	कुल
6 महीने तक	0	9	0	0	0	0	0	9
6 महीने से एक वर्ष तक	0	10	0	5	0	0	4	19
1-2 वर्ष	4	33	0	1	0	0	0	38
2 वर्ष से अधिक	16	81	55	71	29	9	77	338
<b>कुल</b>	<b>20</b>	<b>133</b>	<b>55</b>	<b>77</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>81</b>	<b>404</b>

इसके अतिरिक्त, तीन सर्किलों - मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु - ने 1,324 टावर साइटों के निष्क्रिय रहने की अवधि के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, जो कमजोर आंतरिक निगरानी का संकेत देता है।

जवाब में (जून 2024), बी एस एन एल प्रबंधन ने बताया कि सर्किलों को निर्देश दिया गया था कि वे निष्क्रिय साइटों की समीक्षा करें और आई पी साइटों को स्थानांतरित करके, 4जी रोलआउट को सक्षम करके, या उन्हें अन्य टी एस पी को पट्टे पर देकर उनका उपयोग करें। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि नए अवसंरचना के प्रावधान आदेश जारी करने से पहले वे प्रमाणित करें कि आसपास कोई निष्क्रिय टावर मौजूद नहीं है। इस जवाब को मंत्रालय ने जून 2025 में अनुमोदित किया।

हालाँकि, बी एस एन एल निगमित कार्यालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद, बड़ी संख्या में निष्क्रिय टावरों का बने रहना, कार्यान्वयन में खामियों और सर्किल स्तर पर अप्रभावी निगरानी का संकेत देता है। ये निष्क्रिय संपत्तियां न केवल डूबी हुई लागतों को दर्शाती हैं, बल्कि पट्टे या पुनर्नियोजन के माध्यम से राजस्व सृजन के छूटे हुए अवसरों को भी दर्शाती हैं।

<sup>89</sup> तीन सर्किलों - मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु - के लिए निष्क्रियता संबंधी डेटा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं था।

<sup>90</sup> महाराष्ट्र सर्किल के संबंध में, 08 टावरों के निष्क्रिय रहने की अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

<sup>91</sup> ओडिशा सर्किल के संबंध में, 04 टावरों के निष्क्रिय रहने की अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

### 6.2.3.3 वित्तीय मुद्दे

#### 6.2.3.3(क) कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण के कारण बिल न बनाना और राजस्व हानि

बी एस एन एल और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) के बीच हस्ताक्षरित मास्टर सेवा समझौते (एम एस ए) की अनुसूची 3 में अवसंरचना प्रावधान शुल्क (आई पी एफ)<sup>92</sup> के विभिन्न घटकों के भुगतान की शर्तें निर्धारित की गई थीं। इसमें समय पर बिलिंग, विलंबित भुगतानों पर ब्याज वसूलने और अतिरिक्त भूमि किराये की वसूली के प्रावधान शामिल थे। लेखापरीक्षा में ऐसे कई उदाहरण पाए गए जहाँ बी एस एन एल इन शर्तों को लागू नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई और खराब वित्तीय प्रबंधन का संकेत मिला, जैसा कि नीचे वर्णित है:

#### क. विलंबित भुगतान शुल्क न लगाया जाना

अनुसूची 3 के खंड 4 में अवसंरचना शुल्क अग्रिम रूप से वसूलने का आदेश दिया गया है, जिसके लिए 15 दिन की छूट अवधि दी गई है, जिसके बाद अतिदेय राशि पर ब्याज<sup>93</sup> लागू होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बी एस एन एल ने लेखापरीक्षित 10 में से पाँच<sup>94</sup> सर्किलों में जुलाई 2018 और मार्च 2025 के बीच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) पर ₹7.24 करोड़ का विलंब भुगतान शुल्क नहीं लगाया था (अनुलग्नक 6.12)।

बी एस एन एल निगमित कार्यालय (जून 2024) ने कहा कि दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के लिए, संचालकों के बीच आपसी सहमति से ब्याज न लगाने पर सहमति बनी थी। मंत्रालय (जून 2025) ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। हालाँकि, इस तरह की छूट या इसके वित्तीय औचित्य का कोई औपचारिक दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

#### ख. किराये के शुल्क का बिल न बनाना

अनुसूची 3 के खंड 1.1(ए) और 1.2(ए) में ₹38,700 (जी बी टी साइट) और ₹24,900 (आर टी टी साइट) के मासिक आधार किराये के साथ-साथ प्रति साइट ₹5,000 से अधिक भूमि किराये की आनुपातिक वसूली का प्रावधान है। ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार सर्किलों<sup>95</sup> में, बी ए एल, वी आई एल और आर जे आई एल को पट्टे पर दी गई 244 साइटों के लिए ₹2.33 करोड़ के किराये और भूमि शुल्क का नवंबर 2011 और मार्च 2025 के बीच बिल नहीं भेजा गया (अनुलग्नक 6.13)।

<sup>92</sup> आई पी एफ, एम एस ए की अनुसूची 3 के अनुसार मासिक सेवा शुल्क है जिसमें किराया और ऊर्जा शुल्क शामिल हैं।

<sup>93</sup> बी ए एल और वी आई एल के मामले में भुगतान की देय तिथि को प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान उधार दर से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक तथा आर जे आई एल के मामले में 18 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक।

<sup>94</sup> ओडिशा, बिहार, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु।

<sup>95</sup> शॉर्ट बिलिंग की अवधि ओडिशा में अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2024 के बीच, तमिलनाडु में नवंबर 2011 से मार्च 2025 के बीच, महाराष्ट्र में फरवरी 2012 से दिसंबर 2023 के बीच तथा बिहार में अप्रैल 2017 से दिसंबर 2023 के बीच रही।

हालांकि प्रबंधन ने कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन उसने आश्वासन दिया (जून 2024) कि सर्किलों को बकाया राशि का तुरंत बिल जारी करने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र और बिहार सर्किलों ने क्रमशः फरवरी और अप्रैल 2025 में लेखापरीक्षा द्वारा चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद ही कार्रवाई की और बिल जारी किए।

#### ग. अवसंरचना प्रावधान शुल्क (आई पी एफ) का बिल न बनाना

ओडिशा और तमिलनाडु सर्किलों में, बी ए एल, आर जे आई एल और वी आई एल को पट्टे पर दी गई आठ साइटों के लिए 2021-2025 के दौरान 27-35 बिलिंग चक्रों के लिए आई पी एफ का बिल नहीं भेजा गया, जिससे ₹0.55 करोड़ की राजस्व हानि हुई। तमिलनाडु सर्किल ने कहा कि बिल अनुमोदन के लिए लंबित था, जबकि ओडिशा सर्किल ने लेखापरीक्षा हस्तक्षेप के बाद अप्रैल 2024 में ₹0.51 करोड़ का बिल भेजा और वसूल किया।

ये उदाहरण सर्किल स्तर पर आंतरिक नियंत्रण और राजस्व आश्वासन प्रक्रियाओं में प्रणालीगत खामियों की ओर इशारा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, सहमत अनुबंध शर्तों के उल्लंघन में बकाया राशि की कम वसूली हुई और बिल तैयार करने में देरी हुई।

#### 6.2.4 निष्कर्ष

दूरसंचार संचालकों के लिए सेवा विश्वसनीयता, लागत दक्षता और डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से राजस्व को अधिकतम करने हेतु प्रभावी टावर प्रबंधन आवश्यक है। हालांकि, बी एस एन एल के टावर अवसंरचना की लेखापरीक्षा में टावर स्वामित्व और पट्टा दस्तावेज़ीकरण पर कमज़ोर नियंत्रण, ₹59.77 करोड़ मूल्य की बेकार पड़ी टावर सामग्री, लंबे समय से निष्क्रिय टावर, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) को टावर स्थल उपलब्ध कराने में देरी के कारण ₹10.87 करोड़ के राजस्व की हानि, और टी एस पी को विभिन्न शुल्क न लगाने और बिल न भेजने के कारण राजस्व की हानि जैसी महत्वपूर्ण कमियां सामने आईं। ये मुद्दे प्रचालन अक्षमताओं और कमज़ोर निगरानी के साथ-साथ परिसंपत्ति उपयोग और राजस्व प्राप्ति में कमियों को दर्शाते हैं। ये मुद्दे वित्तीय और प्रचालन निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए मज़बूत आंतरिक नियंत्रण, समय पर निर्णय लेने और बेहतर जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को भी उजागर करते हैं।

#### 6.2.5 सिफारिशें

##### बी एस एन एल

- i. सभी टावर-संबंधी डेटा की निगरानी, सत्यापन और प्रबंधन के लिए एक मजबूत, वास्तविक-समय प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करे, जिसमें कार्यक्षमता की स्थिति, साइट का उपयोग, पट्टे की व्यवस्था और बिलिंग चक्र शामिल हों।

- ii. परिचालन निरंतरता में बाधा उत्पन्न करने वाली संभावित कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए भूमि स्वामित्व से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करे तथा समाप्त हो चुके पट्टे समझौतों का नवीनीकरण करे।
- iii. निष्क्रिय और गैर-कार्यशील टावरों के उपयोग को अनुकूल बनाने के लिए उनकी नियमित समीक्षा करे तथा पुनः उपयोग एवं पुनर्स्थापन या पट्टे पर देने के संबंध में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे।
- iv. मास्टर सेवा समझौतों के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से राजस्व की सटीक और समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत बिलिंग और वसूली तंत्र लागू करे।

नई दिल्ली

दिनांक: 17 मार्च 2026



(खालिद बिन जमाल)

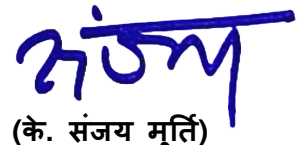
महानिदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 19 मार्च 2026



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



---

## परिशिष्ट और अनुलग्नक

---



परिशिष्ट I

{पैराग्राफ 1.4.1.1, 1.4.1.2 ग, 1.4.2.1 और 1.4.3 का सन्दर्भ ले}

31 मार्च 2024 तक संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) और वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

क्र. सं.	सी पी एस यू का नाम	प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार के निवेश का प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूंजी निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)
<b>संचार मंत्रालय</b>					
<b>दूरसंचार विभाग</b>					
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	100	85,266.82	21,302.38	(5,370.73)
2	बी एस एन एल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बी एस एन एल की सहायक कंपनी		14.39	3.21
3	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	56.25	354.38	1,301.48	(3,302.19)
4	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल)	एम टी एन एल की सहायक कंपनी		0.38	0.25
5	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)	100	60.00	571.37	2.14
6	आई टी आई लिमिटेड	97.80	1,391.45	1,308.13	(569.06)
7	तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (टी टी एल)	टी सी आई एल की सहायक कंपनी		0.03	(14.62)
8	टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)	100	59.20	2,603.46	73.37

क्र. सं.	सी पी एस यू का नाम	प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार के निवेश का प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूंजी निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)
9	टी सी आई एल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड	टी सी आई एल की सहायक कंपनी		2.81	(0.63)
10	टी सी आई एल बीना टोल रोड लिमिटेड	टी सी आई एल की सहायक कंपनी		4.37	(2.79)
<b>कुल</b>			<b>87,131.85</b>	<b>27,108.8</b>	<b>(9,181.05)</b>
<b>डाक विभाग</b>					
11	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक	100	2,105.00	1,265.29	34.24
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>					
12	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	100	2.00	2,357.86	196.82
13	सी एस सी ई -गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	*(भारत सरकार का केवल 1 शेयर है)		1,753.56	131.67
14	सी एस सी वाई-फाई चौपाल	सी एस सी की सहायक कंपनी		10.99	0.33
15	सी एस सी ग्रामीण ई स्टोर	सी एस सी की सहायक कंपनी		6.21	0.92
16	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	कोई शेयर पूंजी नहीं		417.36	11.76
<b>कुल</b>			<b>2.00</b>	<b>4,545.98</b>	<b>341.5</b>
<b>वित्त मंत्रालय</b>					
<b>आर्थिक कार्य विभाग</b>					
17	सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल)	99.99	987.50	5,078.88	911.04

क्र. सं.	सी पी एस यू का नाम	प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार के निवेश का प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूंजी निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)
18	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल)	एस पी एम सी आई एल और बी आर बी एन एम पी एल का संयुक्त उद्यम	800.00	1,250.35	231.79
19	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)	आर बी आई की सहायक कंपनी	1,800.00	3,085.99	566.40
20	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल)	100	0.02	0.32	0.13
<b>कुल</b>			<b>3,587.52</b>	<b>9,415.54</b>	<b>1,709.36</b>

\*भारत सरकार के पास केवल एक शेयर है, जो कुल पेड-अप कैपिटल का 0.000001 प्रतिशत है।

#बी एन पी एम आई पी एल और बी आर बी एन एम पी एल निजी लिमिटेड कंपनियाँ हैं, तथापि भारत सरकार इन पर नियंत्रण रखती है।

परिशिष्ट II

{पैराग्राफ 1.4.1.1, 1.4.1.2 ग, 1.4.2.1 और 1.4.3 का सन्दर्भ ले}

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) से सम्बद्ध कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) की संक्षिप्त रूपरेखा

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), संचार मंत्रालय (एम ओ सी):		
1	आई टी आई लिमिटेड (पी एस यू)	आई टी आई लिमिटेड, जो 1948 में एक विभागीय कारखाने के रूप में शुरू हुई थी, दूरसंचार उपकरण बनाने वाली एक दूरसंचार तकनीकी पी एस यू है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के नैनी, रायबरेली और मनकापुर और केरल के पलक्कड़ में इसके विनिर्माण संयंत्र के अलावा बेंगलुरु में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी है। 31 मार्च 2024 तक सरकार के पास कंपनी की 97.80 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत ₹1,391.45 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल राजस्व और हानि क्रमशः ₹1,308.13 करोड़ और ₹569.06 करोड़ थी।
2	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) (पी एस यू)	भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल), की स्थापना 1978 में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करने, उचित विपणन रणनीतियों को विकसित करके विदेशी और घरेलू बाजारों में अपने संचालन में उत्कृष्टता हासिल करने और अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। मार्च 2024 के अंत में कंपनी में सरकार का निवेश ₹59.20 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व और लाभ क्रमशः ₹2,603.46 करोड़ और ₹73.37 करोड़ था।
3	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल) (पी एस यू)	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी) कंपनी है, का गठन वर्ष 2012 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारतनेट परियोजना, पूर्व में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) के क्रियान्वयन हेतु किया गया था। 31 मार्च 2024 तक कंपनी में भारत सरकार का कुल निवेश ₹60.00 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने ₹571.37 करोड़ का राजस्व अर्जित किया तथा ₹2.14 करोड़ का लाभ प्राप्त किया। 27 जुलाई 2022 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विलय को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो प्रक्रियाधीन है।
4	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) (पी एस यू)	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी पी एस ई) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) की पूर्ण स्वामित्व वाली असूचीबद्ध सहायक कंपनी है। एम टी एल की स्थापना फरवरी 2000 में हुई थी और इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। एम टी एल द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में क्लाउड सेवाएं, वाई-फाई समाधान,

		ई-गवर्नेंस पर परियोजना, प्रबंधित सेवाएं, आरंभ से अंत तक सम्पूर्ण आई सी टी समाधान, जी आई एस आधारित सेवाएं, क्षमता निर्माण और कौशल विकास आदि शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹0.38 करोड़ था और इसने ₹0.25 करोड़ का लाभ अर्जित किया ।
5	बी एस एन एल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी टी सी एल) (पी एस यू)	बी एस एन एल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी टी सी एल) को 04.01.2018 को भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। बी टी सी एल ने गैर-दूरसंचार गतिविधियों को करने के लिए अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है, जैसे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भाग लेना, सभी ई बी कार्य / व्यवसाय / ई ओ आई / निविदा / बोलियां / आर एफ पी जहां एस आई / साझेदार / बाहरी / गैर दूरसंचार घटक पर्याप्त है; सिविल / बी डब्ल्यू विंग - राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, स्वायत्त निकायों जैसे ग्राहकों के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में बाहरी कार्यों का क्रियान्वयन, सी एफ ए वर्टिकल के तहत समाधान प्रदाता का इम्पेनलमेंट आदि। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने परिचालन से ₹12.89 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है और इस अवधि के लिए लाभ ₹3.21 करोड़ है।
6	तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड (टी टी एल) (पी एस यू)	तमिलनाडु टेलीकॉम लिमिटेड (टी टी एल) को टेलीकॉम केबल के निर्माण के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टी आई डी सी ओ) और जापान के मेसर्स फुजिकुरा के सहयोग से वर्ष 1988 में शामिल किया गया था। टीटीएल में टीसीआईएल की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है। ऑर्डर की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का प्रदर्शन गिर रहा है। वर्तमान मांग ज्यादातर रिबन-टाइप केबलों की है, जिसके लिए टी टी एल के पास अपेक्षित विनिर्माण मशीनरी नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, टी टी एल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए टी टी एल भूमि के मुद्रीकरण के विकल्प तलाशने की कोशिश कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का परिचालन कारोबार शून्य था और वर्ष के दौरान, कर के बाद हानि ₹14.62 करोड़ थी।
7	टी सी आई एल बीना टोल रोड लिमिटेड (टी बी टी आर एल) (पी एस यू)	टी सी आई एल बीना टोल रोड लिमिटेड (टी बी टी आर एल) को 11.07.2012 को टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डी बी एफ ओ टी) आधार पर बीना-कुरवाई सराज टोल रोड परियोजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से शामिल किया गया था। परियोजना 2014 में पूरी हुई और टोल संग्रह अप्रैल 2014 में शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का परिचालन कारोबार ₹4.32 करोड़ था और कर के बाद हानि ₹2.79 करोड़ थी।

8	टी सी आई एल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टी एल टी आर एल) (पी एस यू)	टी सी आई एल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टी एल टी आर एल) को 21.08.2013 को टी सी आई एल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निर्माण, संचालन एवं स्थानांतरण बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (बी ओ टी) मॉडल पर लखनाडोन-घंसोर रोड परियोजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से शामिल किया गया था। परियोजना 29.06.2016 को पूरी हो गई और टोल संग्रहण 06.07.2016 से शुरू हो गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का परिचालन कारोबार ₹2.81 करोड़ था और वर्ष के दौरान, कर के बाद हानि ₹0.63 करोड़ थी।
<b>डाक विभाग (डी ओ पी), संचार मंत्रालय (एम ओ सी):</b>		
1	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई पी पी बी) (पी एस यू)	<p>वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से, भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ, डीओपी के अंतर्गत 17 अगस्त 2016 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। आई पी पी बी संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच ₹2 लाख की शेष राशि तक बचत और चालू खातों जैसे मांग जमा, डिजिटल रूप से सक्षम भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान करता है और बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड हाउस, पेंशन प्रदाताओं, बैंकों, अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण संगठनों आदि के साथ साझेदारी में बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन, क्रेडिट उत्पादों और विदेशी मुद्रा जैसी तीसरे पक्ष की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान करता है।</p> <p>31 मार्च 2024 तक सरकार का कुल पूंजी निवेश ₹2,105.00 करोड़ था। कंपनी का कुल राजस्व ₹1,265.29 करोड़ था और इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹34.24 करोड़ का लाभ अर्जित किया।</p>
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई):</b>		
1	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) (संलग्न कार्यालय)	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क बेकबोन और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। यह (क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, (ख) राज्य क्षेत्र और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं और (ग) जिला प्रशासन-प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
2	मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी) (संलग्न कार्यालय)	एस टी क्यू सी, 1980 में स्थापित, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आश्वासन सेवा प्रदाता है, जो अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करता है और आई टी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एम ई आई टी वाई के जनादेश के साथ संरेखित है।
3	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू)	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को एम ई आई टी वाई के अंतर्गत आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम,

	<p>आई डी ए आई (सांविधिक प्राधिकरण)</p>	<p>2016 ("आधार अधिनियम 2016") के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है।</p> <p>यू आई डी ए आई को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या, "आधार" नामक एक विशिष्ट पहचान जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत है और (ख) आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है।</p> <p>यू आई डी ए आई को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹800 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई और इसने ₹800 करोड़ व्यय किए, जिससे उपयोग किए गए अनुदान के रूप में शून्य शेष रह गया। यू आई डी ए आई प्रमाणीकरण और नामांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त शुल्क के माध्यम से भी राजस्व अर्जित करता है। मार्च 2019 से प्रभावी सभी प्राप्तियां सरकार द्वारा बनाए गए यू आई डी ए आई निधि में जमा की जाती हैं।</p>
<p>4</p>	<p>डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी) (पी एस यू)</p>	<p>डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एक 'गैर-लाभकारी' कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना है। कंपनी के अनुप्रयोग क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका और विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए आई सी टी का उपयोग शामिल है। कंपनी गारंटी द्वारा सीमित है और उसके पास कोई शेयर पूंजी नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत इस कंपनी की लेखापरीक्षा सी ए जी को सौंपी गयी थी कंपनी विकास कार्य करने के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ काम करती है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान इसकी कुल आय ₹417.36 करोड़ (मुख्य रूप से अनुदान सहायता के कारण) थी।</p>
<p>5</p>	<p>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक. (एन आई सी एस आई) (पी एस यू)</p>	<p>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एन आई सी एस आई) की स्थापना 1995 में सरकारी संगठनों को संपूर्ण आई टी समाधान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अंतर्गत धारा -25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के रूप में की गई थी। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत का आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹2,357.86 करोड़ था और इसने ₹196.82 करोड़ का लाभ अर्जित किया।</p>
<p>6</p>	<p>सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (पी एस यू)</p>	<p>सामान्य सेवा केंद्र (सी एस सी) योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन-मोड परियोजनाओं में से एक है। सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल, सी एस सी योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एम ई आई टी वाई द्वारा स्थापित किया गया है। सी एस सी एस पी वी योजना की प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा, सी एस सी के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं के वितरण के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी ढांचा प्रदान करता है।</p>

		वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल राजस्व ₹1,753.56 करोड़ था और इसने ₹131.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया।
7	सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पी एस यू)	2016 की शुरुआत में, सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और विश्वसनीय आई सी टी समाधानों के विकास के लिए की गई थी। वाई-फाई चौपाल सभी ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, फाइबर रखरखाव, पेशेवर टीमों के साथ गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जी पी ओ एन) अवसंरचना, वाई-फाई ऑडियो / वीडियो कॉलिंग समाधान और विभिन्न सरकारी संस्थानों को अनुप्रयोग विकास और समर्थन आदि की सुविधा प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹10.99 करोड़ था और इसने ₹0.33 करोड़ का लाभ अर्जित किया।
8	सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पी एस यू)	सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 31 जुलाई 2020 को भारत के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शीर्ष उद्यम, सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वी एल ई) के अपने नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण ई-कॉमर्स को सक्षम करने, स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी), किसानों, एम एस एम ई आदि जैसे स्थानीय निर्माताओं के साथ साझेदारी करके वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹6.21 करोड़ था और इसने ₹0.92 करोड़ का लाभ अर्जित किया।
<b>आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए), वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ):</b>		
1	सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल) (पी एस यू)	सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची 'ए' मिनीरत्न श्रेणी- I कंपनी है, जिसे 2006 में सिक्का और मुद्रा प्रभाग, डी ई ए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नौ उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्रण, रखरखाव और संचालन के लिए शामिल किया गया था। एस पी एम सी आई एल मुद्रा और बैंक नोट, सुरक्षा कागज, गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर, डाक टिकट और स्टेशनरी, यात्रा दस्तावेज विनिर्माण / उत्पादन जैसे पासपोर्ट और वीजा, सुरक्षा प्रमाणपत्र, चेक, बांड, वारंट, सुरक्षा सुविधाओं वाले विशेष प्रमाणपत्र, सुरक्षा स्याही, प्रचलन और स्मारक सिक्के, पदक, सोने और चांदी के परिष्करण तथा बहुमूल्य धातुओं का परीक्षण के निर्माण / उत्पादन में लगी हुई है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹987.50 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹5,078.88 करोड़ था और इसने ₹911.04 करोड़ का लाभ अर्जित किया।
2	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड 1995 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है। यह भारतीय बैंकनोट बनाता है। बी आर बी एन एम पी एल देश में बैंक नोट की आवश्यकता के एक बड़े हिस्से की

		<p>आपूर्ति करता है, शेष आवश्यकताएं एस पी एम सी आई एल के माध्यम से पूरी की जाती हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹1,800 करोड़ था और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹3,085.99 करोड़ था और इसने ₹566.40 करोड़ का लाभ कमाया।</p>
3	<p>बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल)</p>	<p>बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 13 अक्टूबर 2010 को एस पी एम सी आई एल और बी आर बी एन एम पी एल के बीच बैंक नोट पेपर बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम के तौर पर निगमित और पंजीकृत किया गया था। 31 मार्च 2024 तक कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹800 करोड़ था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,250.35 करोड़ था और इसने ₹231.79 करोड़ का लाभ कमाया।</p>
4	<p>राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एन आई आई एफ टी एल) (पी एस यू)</p>	<p>राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि भारत का पहला अवसंरचना-विशिष्ट निवेश निधि या एक संप्रभु धन निधि है जिसे भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में स्थापित किया गया था। इस निधि को बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से अवसंरचना के निवेश के माध्यम से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार की व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना था।</p> <p>एन आई आई एफ टी एल तीन निधियों का प्रबंधन करता है: मास्टर निधि , निधियों की निधि और रणनीतिक निधि। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाकर भारत में अवसंरचना निवेश करने के लिए इन निधि की स्थापना की गई थी। कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹0.02 करोड़ है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹0.32 करोड़ था और इसने ₹0.13 करोड़ का लाभ कमाया।</p>

परिशिष्ट III

{पैराग्राफ 1.5.3(क) का सन्दर्भ ले}

31 अगस्त 2025 तक मंत्रालयों / विभागों से प्रतीक्षित एक्शन टेकन नोट्स की संक्षिप्त स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या और वर्ष		ए टी एन देय	बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के अंतर्गत
<b>संचार मंत्रालय</b>				
<b>डाक विभाग</b>				
1	2025 की 01	3	1	2
	<b>कुल</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>दूरसंचार विभाग</b>				
1	2025 की 01	1	0	1
	<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>				
1	2025 की 01	2	0	2
	<b>कुल</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>वित्त मंत्रालय</b>				
<b>व्यय विभाग</b>				
1	2019 की 02	1	1	0
2	2020 की 04	1	0	1
3	2021 की 07	5	0	5
4	2022 की 31	35	32	3
5	2023 की 21	28	17	11
6	2025 की 04	64	64	0
	<b>कुल</b>	<b>134</b>	<b>114</b>	<b>20</b>
<b>आर्थिक कार्य विभाग</b>				
1	2024 की 01	1	-	1
2	2025 की 03	2	2	0
3	2025 की 19	2	2	0
	<b>कुल</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>145</b>	<b>119</b>	<b>26</b>

परिशिष्ट IV  
{पैराग्राफ 1.5.3(ख) का सन्दर्भ ले}

31 अगस्त 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतीक्षित एक्शन टेकन नोट्स की संक्षिप्त स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या और वर्ष	ए टी एन देय	बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के अंतर्गत	
संचार मंत्रालय				
भारत संचार निगम लिमिटेड				
1	2000 की 6	2	शून्य	2
2	2001 की 6	2	शून्य	2
3	2002 की 6	1	शून्य	1
4	2003 की 5	5	शून्य	5
5	2004 की 5	2	शून्य	2
6	2005 की 5	2	शून्य	2
7	2006 की 9 (पी ए)	2	शून्य	2
8	2006 की 13	4	शून्य	4
9	2007 की 10 (पीए)	1	शून्य	1
10	2007 की 12	6	शून्य	6
11	2008 की 9 (पी ए)	1	शून्य	1
12	सी ए 2008 की 10	1	शून्य	1
13	सी ए 2008 की 12	5	शून्य	5
14	2009-10 की 09	1	शून्य	1
15	सी ए 2009 की 25	4	शून्य	4
16	2011- 12 की 3	2	शून्य	2
17	2012 - 13 की 8	1	शून्य	1
19	2016 की 29	1	शून्य	1
20	2021 की 03	1	शून्य	1
21	2023 की 16	3	शून्य	3
22	2025 की 01	1	शून्य	1
<b>कुल</b>		<b>48</b>	<b>शून्य</b>	<b>48</b>

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या और वर्ष	ए टी एन देय	बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के अंतर्गत	
<b>महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड</b>				
1	2004 की 5	1	शून्य	1
2	2007 की 10 (पी ए)	1	शून्य	1
3	2007 की 12	1	शून्य	1
4	सी ए 2008 की 12	1	शून्य	1
<b>कुल</b>		<b>4</b>	<b>शून्य</b>	<b>4</b>
<b>आई टी आई लिमिटेड</b>				
1	2007 की 10	1	शून्य	1
2	2007 की 12	1	शून्य	1
3	2008 की 12	1	शून्य	1
4	2021 की 03	1	शून्य	1
<b>कुल</b>		<b>4</b>	<b>शून्य</b>	<b>4</b>
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>				
<b>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.</b>				
1	2015 की 55	1	शून्य	1
2	2017 की 21	1	शून्य	1
3	2021 की 03	1	1	शून्य
4	2022 की 15	1	1	शून्य
<b>कुल</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>वित्त मंत्रालय</b>				
<b>भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)</b>				
1	2022 की 15	1	1	शून्य
<b>कुल</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>शून्य</b>
<b>कुल योग</b>		<b>61</b>	<b>3</b>	<b>58</b>

परिशिष्ट V

{पैराग्राफ 1.5.4 सन्दर्भ ले}

वर्ष 2023-24 के लिए केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (ए बी) के सम्बन्ध में लेखों का प्रमाणीकरण और प्रस्तुतिकरण

क्रम संख्या	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	प्रमाणन की तिथि	संसद में रखे जाने की तिथि
1	यू आई डी ए आई	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2024	01-07-2024	07-11-2024	लो.स.:12-03-2025 रा.स.:21-03-2025
2	ट्राई	संचार	30-06-2024	05-07-2024	10-12-2024	लो.स.:12-03-2025 रा.स.:20-03-2025
3	ट्राई-सी पी एफ	संचार	30-06-2024	11-07-2024	13-11-2024	लो.स.:12-03-2025 रा.स.:20-03-2025
4	आई एफ एस सी ए	वित्त मंत्रालय	30-06-2024	05-07-2024	30-10-2024	लो.स.: 10-02-2025 रा.स.: 11-02-2025
5	सेबी	वित्त मंत्रालय	30-06-2024	27-06-2024	02-12-2024	लो.स.: 03-02-2025 रा.स.: 04-02-2025

वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के सम्बन्ध में लेखों के प्रमाणीकरण और प्रस्तुतिकरण का विवरण

क्रम संख्या	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	प्रमाणन की तिथि
1	बी एस एन एल	संचार	30-06-2024	30-05-2024	12-09-2024
2	बी टी सी एल	संचार	30-06-2024	11-07-2024	04-09-2024
3	एम टी एन एल	संचार	30-06-2024	31-05-2024	04-09-2024
4	एम टी एल	संचार	30-06-2024	12-06-2024	22-08-2024
5	सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2024	11-09-2024	10-12-2024
6	सी एस सी वाई-फाई चौपाल	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2024	30-07-2024	09-10-2024
7	आईटीआई	संचार	30-06-2024	24-06-2024	11-09-2024
8	टी सी आई एल	संचार	30-06-2024	27-05-2024	16-08-2024
9	टी सी आई एल- एल टी आर एल	संचार	30-06-2024	29-05-2024	19-07-2024

क्रम संख्या	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	प्रमाणन की तिथि
10	टी सी आई एल- बी टी आर एल	संचार	30-06-2024	29-05-2024	26-07-2024
11	टी टी एल	संचार	30-06-2024	30-05-2024	12-08-2024
12	आई पी पी बी	संचार	30-06-2024	28-06-2024	09-10-2024
13	एन आई सी एस आई	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2024	31-07-2024	27-09-2024
14	बी बी एन एल	संचार	30-06-2024	04-09-2024	14-11-2024
15	डी आई सी	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2024	13-11-2024	11-03-2025
16	एस पी एम सी आई एल	वित्त	30-06-2024	19-07-2024	27-09-2024
17	बी आर बी एन एम पी एल	वित्त	30-06-2024	22-07-2024	27-09-2024
18	बी एन पी एम आई पी एल	वित्त	30-06-2024	04-07-2024	25-09-2024
19	एन आई आई एफ टी एल	वित्त	30-06-2024	30-07-2024	14-08-2024
20	सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2024	16-08-2024	17-09-2024

परिशिष्ट VI

{पैराग्राफ 1.5.5 सन्दर्भ ले}

क. वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के खातों पर महत्वपूर्ण अवलोकन

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
1	आई टी आई लिमिटेड.	<p><b>लाभ और हानि</b></p> <p><b>व्यय</b></p> <p><b>अन्य व्यय - ₹167.14 करोड़ (नोट 30)</b></p> <p>वर्ष 2023-24 से सम्बंधित व्यय का प्रावधान न करने के कारण से उपरोक्त शीर्ष में ₹ 2.42 करोड़ की रकम कम बताई गई है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप हानि को भी उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है।</p>
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<p><b>बैलेंस शीट</b></p> <p><b>परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>वर्तमान परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>व्यापार प्राप्य: ₹496.45 करोड़ (नोट संख्या 15)</b></p> <p>बेतार(वायरलेस) सेवाओं से व्यापार प्राप्तियों का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹15.27 करोड़ की राशि अधिक बताई गई है। यह वायरलेस सेवाओं के लिए कंपनी की लेखांकन नीति का उल्लंघन है जो 180 दिनों से अधिक के बकाया देनदारों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान प्रदान करती है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप नुकसान को भी उतनी ही राशि से कम करके दिखाया गया है।</p> <p><b>वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए स्टैंडअलोन कैश फ्लो विवरण</b></p> <p><b>निवेश गतिविधियों में उपयोग की गई शुद्ध नकदी: ₹100.11 करोड़</b></p> <p>निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह में ₹0.92 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल है। यह भारतीय लेखांकन मानक 07 के अनुच्छेद 43 का उल्लंघन है। नकदी प्रवाह विवरण इस सीमा तक अपर्याप्त है।</p> <p><b>लेखाओं के नोट्स पर टिप्पणियाँ</b></p> <p><b>आकस्मिक देनदारियों, लंबित मुकदमों और अन्य मामलों का विवरण</b></p> <p><b>बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, नगर निगम कर की मांगें विवादित हैं और अपील के अधीन हैं: ₹529.71 करोड़ - नोट 50(b)</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹9.73 करोड़ की राशि कम बताई गई है क्योंकि श्रम उपकर के कारण वैधानिक देय राशि को शामिल नहीं किया गया है।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p><b>प्रतिबद्धताएं (नोट संख्या 51)</b></p> <p><b>अन्य प्रतिबद्धताएं: शून्य</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹8.10 करोड़ की राशि कम बताई गई है क्योंकि कॉपर नेटवर्कपर विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के व्यापक रखरखाव और प्रावधान के लिए अनुबंध के प्रति प्रतिबद्धताओं का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।</p> <p><b>प्रकटीकरण पर टिप्पणी</b></p> <p>कंपनी ने 31 मार्च 2024 के बाद हुई एक महत्वपूर्ण घटना का प्रकटीकरण नहीं किया है एवं दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में ₹450 करोड़ (लगभग) के मध्यस्थता पुरस्कार के बराबर राशि जमा करने के बदले ₹1,258.26 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख जमा करने के लिए आवेदन किया है। यह भी भारतीय लेखांकन मानक 10 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।</p> <p><b>वैधानिक लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ</b></p> <p>वैधानिक लेखा परीक्षक ने सी ए आर ओ 2020 के निर्देशों का पालन नहीं किया है, जैसे कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>जिन अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं, उनकी जानकारी नहीं दी गई है।</li> <li>आयकर विभाग को दी गई विवादित राशि में, उस पर लगे ब्याज की राशि शामिल नहीं है।</li> </ol>
3	भारत संचार निगम लिमिटेड	<p><b>लाभ और हानि लेखा पर टिप्पणियाँ</b></p> <p><b>परिचालन से राजस्व: ₹ 19,330.71 करोड़ (नोट संख्या 32)</b></p> <p><b>अन्य परिचालन राजस्व: ₹ 3,522.18 करोड़</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में राशि ₹69.11 करोड़ ज़्यादा दिखाई गई है, क्योंकि एल डब्ल्यू ई प्रोजेक्ट के संबंध में 30.04.2023 के बाद की अवधि के लिए राजस्व बुक किया गया है, जो इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय के 14.03.2024 के निर्देशों का उल्लंघन है। इससे हानि की राशि भी उतनी ही कम दिखाई गई है।</p> <p><b>व्यय</b></p> <p><b>अन्य व्यय- ₹ 9,401.73 करोड़ (नोट 37)</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹420.98 करोड़ की राशि कम दिखाई गई है, क्योंकि दूरसंचार विभाग के टर्म सेल ने उपभोक्ता आवेदन प्रपत्र (सी ए एफ) और ई एम एफ जुर्माने के लिए जो दण्ड लगाया था, उसे इसमें शामिल नहीं</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>किया गया है। इस वजह से हानि की राशि भी उतनी ही कम दिखाई गई है। इस मामले पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गयी थी।</p> <p><b>बैलेंस शीट पर टिप्पणियाँ</b></p> <p><b>अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ - ₹3,644.30 करोड़ (नोट संख्या 11)</b></p> <p><b>पूंजी अग्रिम - ₹3,083.44 करोड़</b></p> <p>खरीदी गई संपत्ति की कुल लागत के घटक होने के कारण पूंजीगत व्यय के रूप में बुक करने के बजाय विक्रेता को अग्रिम के रूप में देय सीमा शुल्क को शामिल करने से उपरोक्त शीर्ष में ₹2.03 करोड़ की राशि अधिक बताई गई है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप पी पी ई की राशि भी उतनी ही कम बताई गई और उस पर मूल्यहास हुआ।</p> <p><b>अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ ₹ 9,553.62 करोड़ (नोट संख्या 17)</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में निम्नलिखित को शामिल करने के कारण ₹4.44 करोड़ की राशि अधिक बताई गई है-</p> <p>(i) एल डब्ल्यू ई साइटों के ओ एंड एम से संबंधित यू एस ओ निधि से प्राप्त के रूप में ₹2.94 करोड़ की राशि दिखाई गई है। इसे यू एस ओ निधि द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>(ii) 9 से 19 वर्षों से लंबित विविध वसूली को शामिल करने के कारण ₹1.50 करोड़।</p> <p>इन राशियों का प्रावधान न करने से, वर्ष की हानि को भी उस सीमा तक कम दिखाया गया है ।</p> <p><b>वर्तमान देनदारियां</b></p> <p><b>प्रावधान- ₹ 212.69 करोड़ (नोट संख्या 31)</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में अरुणाचल सरकार के ऊर्जा विभाग को दिए जाने वाले बिजली के बिल के बकाए के तौर पर ₹ 4.46 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। बीएसएनएल ने इस शीर्ष के अंतर्गत बुक किए गए खर्चों को इस आधार पर वापस कर दिया है कि ब्याज और जुर्माना माफ करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को इसकी जानकारी दी गई थी। इससे नुकसान भी उतनी ही राशि से कम दिखाया गया।</p> <p><b>नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ</b></p> <p><b>कार्यशील पूंजी में शुद्ध परिवर्तन</b></p> <p>कंपनी ने कार्यशील पूंजी में बदलाव का आकलन करने के लिए गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों में बदलाव को शामिल किया है, बजाय</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		इसके कि इसे निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह के अंतर्गत दिखाया जाए। इसे दर्शाना भारतीय लेखांकन मानक 7 के अनुरूप नहीं है। इसलिए, नकद प्रवाह विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। इस प्रकरण पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गयी थी।
4	सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	<p><b>क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ</b></p> <p><b>1. परिचालन से राजस्व: (नोट संख्या 27) यू आई डी से सेवाओं की बिक्री: ₹ 186.82 करोड़</b></p> <p>(i) ऊपर दी गई आय में जी एस टी स्वरूप मिले ₹ 2.17 करोड़ और बिक्री राजस्व शामिल हैं, जिसे देनदारी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था क्योंकि यह सरकार को देना है। इस वजह से आय को इस सीमा तक ज्यादा और देनदारी को कम दिखाया गया।</p> <p>(ii) उपरोक्त शीर्ष में ₹ 2.09 करोड़ कम दिखाए गए हैं, क्योंकि अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के महीनों के लिए जमा हुई आय का हिसाब नहीं दिया गया, जिनकी बिक्री की पुष्टि वर्ष 2023-24 की बैलेंस शीट बंद होने की तारीख से पहले मैनेजमेंट को कर दी गई थी। इसके कारण चालू परिसंपत्तियों (विविध देनदार) को भी इस राशि से कम दिखाया गया। इस समय के लिए यू आई डी ए आई द्वारा इस बिक्री राजस्व पर लगाई गई ₹ 5.49 करोड़ के जुर्माने को अकाउंट्स के नोट्स में बताया जा सकता है।</p> <p><b>ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ</b></p> <p><b>अन्य संपत्तियां: ₹ 274.17 करोड़ (नोट-15)</b></p> <p><b>अन्य देनदारियाँ: ₹ 673.80 करोड़ (नोट-25)</b></p> <p>परियोजनाओं के अंतर्गत अनुदानों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को क्रमशः ₹ 199.81 करोड़ और ₹ 12.34 करोड़ से घटाकर दिखाने की वजह से अन्य परिसंपत्तियों और अन्य देनदारियों को ₹ 4.46 करोड़ कम दिखाया गया है। यह 'वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण' से जुड़े भारतीय लेखांकन मानक -1 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।</p> <p>कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा जारी उप-निर्देशों पर वैधानिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन भी इस सीमा तक अपूर्ण है क्योंकि वे अतिरिक्त व्यय पर टिप्पणी देने और संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग से आवश्यक अनुमोदन लेने में विफल रहे हैं।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
5	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड.	<p><b>1. लाभ और हानि लेखा</b></p> <p><b>व्यय</b></p> <p><b>कर्मचारी लाभ व्यय- ₹439.64 करोड़ (नोट 34)</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹3.07 करोड़ ज़्यादा बताए गए हैं, क्योंकि कंपनी ने उन कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा सुविधा का प्रावधान किया है, जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक न तो इस सुविधा का लाभ उठाया है और न ही एल टी एफ लेने के लिए कोई आवेदन / दावा प्रस्तुत किया है।</p> <p>इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का लाभ भी उतना ही कम दिखाया गया। यह टिप्पणी वर्ष 2022-23 में भी उठाई गयी थी।</p> <p><b>2. वित्तीय विवरण का भाग बनने वाले लेखों के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी (नोट नंबर 46 सी)</b></p> <p>यह नोट सी एफ ओ सह सी एस के वेतन, भत्तों और दूसरे लाभों के विवरण की जानकारी नहीं देता है, जो कंपनी के बोर्ड के मुख्य प्रबंधक कार्मिक में से एक हैं।</p>
6	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	<p><b>1. बैलेंस शीट- परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>अन्य परिसंपत्तियां: ₹732.63 करोड़ (अनुसूची-11)</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹26.89 करोड़ की राशि ज़्यादा दिखाई गई है, क्योंकि एक वर्ष से अधिक समय से प्राप्तियों के लिए बनाए गए प्रावधान को समायोजित नहीं किया गया है। डाक विभाग से प्राप्तियों को ₹26.89 करोड़ कम करने के बजाय, बैंक ने खातों में ₹26.89 करोड़ का प्रावधान बनाया है। इसे अन्य देनदारियों और प्रावधानों में भी उतनी ही राशि से ज़्यादा दिखाया गया है।</p> <p><b>2. बैलेंस शीट-परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>अन्य परिसंपत्तियां: ₹732.63 करोड़ (अनुसूची-11)</b></p> <p><b>स्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध): ₹152.43 करोड़</b></p> <p>अस्थगित कर आकलित करते समय ग्रेच्युटी और संदेहात्मक ऋण के लिए किए गए प्रावधान को शामिल न करने की वजह से उपरोक्त शीर्ष में ₹10.94 करोड़ की राशि कम दिखाई गई है।</p> <p>इसका परिणाम यह हुआ कि शुद्ध लाभ भी उतना ही कम दिखाया गया।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p><b>3. आय और व्यय-आय</b>  <b>अन्य परिसंपत्तियां: ₹657.72 करोड़ (अनुसूची-14)</b>  उपरोक्त शीर्ष में ₹23.62 करोड़ की राशि ज़्यादा बताई गई है, क्योंकि ग्राहकों को भेजे गए एस एम एस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के तय दर से ज़्यादा शुल्क लगाया गया है।  इसका परिणाम यह हुआ है कि देनदारियां और प्रावधान भी उसी राशि से कम बताए गए हैं।</p> <p><b>4. नकद प्रवाह विवरण</b>  नकद प्रवाह विवरण में निम्न सीमा तक कमियां पायी गयी हैं :</p> <p>i) आई पी पी बी ने लेखांकन मानक 3 के अनुच्छेद 42 के अनुसार नकद और नकद तुल्यांक का मिलान विवरण पेश नहीं किया है।  ii) आई पी पी बी ने परिचालन से होने वाले नकद प्रवाह में जमा ब्याज को शामिल किया है, जो एक गैर-नकद मद है। इस वजह से लेखांकन मानक 3 का पालन नहीं हुआ है।</p> <p><b>5. आकस्मिक देयताएं: ₹64.30 करोड़ (अनुसूची-12)</b>  उपरोक्त शीर्ष में ₹203.03 करोड़ की राशि कम बताई गई है, क्योंकि मैसर्स ई आई टी सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एकल मध्यस्थ के सामने दावे का खुलासा नहीं किया।</p>
7	टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	<p><b>अन्य चालू संपत्तियां: - ₹1,181.25 करोड़ (नोट 17)</b>  सब-कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए पुराने बकाया एडवांस को शामिल करने की वजह से ऊपर दिए गए हेड में ₹4.87 करोड़ ज़्यादा बताए गए हैं। कंपनी ने इन एडवांस के लिए प्रावधान नहीं किया है, जबकि मध्यस्थता अवॉर्ड सब-कॉन्ट्रैक्टर्स के पक्ष में दिया गया है।  इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू परिसंपत्तियों को भी अधिक बताया गया है, प्रावधानों को कम बताया गया है और वर्ष के लाभ को ₹4.87 करोड़ अधिक बताया गया है।</p>
8	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	<p><b>गैर-वर्तमान परिसंपत्ति</b>  <b>अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां (नोट 4)- ₹30.95 लाख</b>  (i) वर्ष 2007-08 के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत आयकर परिसंपत्तियों के लिए ज़्यादा प्रावधान की वजह से ऊपर दिए गए हेड में ₹9.42 लाख की रकम कम दिखाई गई है।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>इसका परिणाम यह हुआ कि प्रावधानों को भी उतना ही ज्यादा बताया गया। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी कमेंट किया गया था।</p> <p>(ii) आयकर परिसंपत्तियों के कम प्रावधानों के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹40.36 लाख की राशि ज्यादा दिखाई गई है। इसकी वजह से लाभ भी उतनी ही राशि से ज्यादा दिखाया गया है।</p> <p><b>आकस्मिक देनदारियों पर टिप्पणी (नोट नंबर 26)</b></p> <p>पेमेंट ऑफ़ वेजेज़ एक्ट 1936 के अंतर्गत जिला श्रम न्यायालय गाजियाबाद द्वारा की गई मांग का खुलासा न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹59.13 लाख की राशि कम दिखाई गई है। वैधानिक लेखापरीक्षकों ने भी अपने प्रतिवेदन में इसे प्रतिवेदित नहीं किया है।</p> <p><b>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना पर टिप्पणी (नोट 27)</b></p> <p>लाभांश भुगतान का तरीका डी आई पी ए एम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹15.87 लाख की राशि कम लाभांश का भुगतान हुआ। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में इसका खुलासा नहीं किया है और वैधानिक लेखापरीक्षकों ने भी अपने प्रतिवेदन में इसे प्रतिवेदित नहीं किया है।</p> <p><b>नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणी</b></p> <p><b>नकद और नकद तुल्यांक का बैलेंस तुल्यांक के साथ मिलान: ₹6 करोड़</b></p> <p>तीन महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशि को शामिल करने के कारण उपरोक्त मद में ₹5.83 करोड़ की राशि अधिक बताई गई है।</p>
9	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	<p><b>बैलेंस शीट</b></p> <p><b>परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (नोट संख्या 9)</b></p> <p><b>पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम- ₹14.50 करोड़</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹4.53 करोड़ ज्यादा बताए गए हैं, क्योंकि इसमें मैनपावर सेवा के आपूर्तिकर्ता को तीन वर्ष से ज्यादा समय से बकाया अग्रिम भी शामिल है। इन अग्रिम का प्रावधान नहीं करना कंपनी की लेखांकन नीति का उल्लंघन है।</p> <p>इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष के लिए व्यय को कम दिखाया गया और लाभ को इस राशि से ज्यादा दिखाया गया।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p><b>वैधानिक लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन पर टिप्पणी</b></p> <p>कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर प्रतिवेदन</p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत जारी भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के निर्देशों पर वैधानिक लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया बिंदु संख्या 3 (विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि) तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कंपनी को वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से विशिष्ट योजनाओं के लिए ₹961.02 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जबकि वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को किसी भी केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से ऐसी कोई धनराशि प्राप्त / प्राप्य नहीं हुई थी।</p>
10	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	<p><b>क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी</b></p> <p><b>1. बैलेंस शीट</b></p> <p><b>चालू देनदारियां</b></p> <p><b>अन्य चालू देनदारियाँ: ₹12,999.77 करोड़ (नोट संख्या 9)</b></p> <p>बी बी एन एल ने जी एस टी एक्ट के अनुसार जमा राजस्व पर जी एस टी के लिए ₹86.94 लाख का प्रावधान नहीं किया है और जी एस टी के विलम्ब से भुगतान के कारण उस पर ₹21.20 लाख का ब्याज देय है। इसके कारण अन्य चालू देनदारियों को ₹1.08 करोड़ कम दिखाया गया है और व्यय को भी उतनी ही राशि से कम दिखाया गया है।</p> <p><b>2 परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>गैर चालू परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹11,105.31 करोड़ (नोट संख्या 11)</b></p> <p>ऊपर दी गई राशि में बी बी एन एल द्वारा 13.03.2024 को स्वीकृत किए गए कैपेक्स राशि के रूप में ₹240.17 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिसका भुगतान तमिलनाडु राज्य में भारतनेट फेज़-II को लागू करने के लिए चौथा चरण पूरा होने पर मैसर्स तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टी ए एन एफ आई एन ई टी) को किया जाना था।</p> <p>इसके कारण चल रहे पूंजीगत कार्य और चालू देनदारी को ₹240.17 करोड़ कम दिखाया गया और पूंजी प्रतिबद्धता को उतनी ही राशि ज़्यादा दिखाया गया।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ:</p> <p>3. स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन</p> <p>स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक क</p> <p>स्वतंत्र लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के अनुलग्नक क का पैराग्राफ संख्या i (सी), जिसमें उन सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख से जुड़ी जानकारी दी गई थी जो कंपनी के नाम पर नहीं थीं, वह पूरी नहीं है क्योंकि इसे सी ए आर ओ 2020 के द्वारा निर्धारित प्रारूप और विवरण के अनुसार नहीं बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप सी ए आर ओ 2020 की अनुपालना नहीं हुई।</p>
11	सी एस सी वाई- फाई चौपाल	<p><b>बैलेंस शीट</b></p> <p><b>चालू परिसंपत्तियाँ- वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b></p> <p><b>उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक बैलेंस: ₹2.36 करोड़ (नोट संख्या 19)</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹2.15 करोड़ की राशि ज़्यादा बताई गयी है , क्योंकि इसमें सावधि जमा को चालू परिसंपत्ति के तौर पर शामिल किया गया है, जो भारतीय लेखांकन मानक -I का उल्लंघन है।</p> <p>इसका परिणाम यह हुआ कि गैर-चालू परिसंपत्तियां को भी उसी राशि से कम दिखाया गया।</p>

**ख. वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण अवलोकन**

क्रमांक	सी ए बी का नाम	अवलोकन
1	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	<p><b>क. बैलेंस शीट</b></p> <p><b>1. अचल परिसंपत्तियाँ: ₹1,610.07 करोड़ (अनुसूची 6)</b></p> <p><b>कंप्यूटर / परिधीय-सॉफ्टवेयर: ₹17.52 करोड़</b></p> <p>उपरोक्त में ₹5.75 करोड़ का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (स्कोर्स बी 2.0) शामिल नहीं है, जिसे 13.03.2024 से परियोजना गो लाइव के रूप में स्वीकृति दी गई थी। सॉफ्टवेयर का पूंजीकरण न करने की वजह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ₹5.75 करोड़ कम दिखाया गया, छोटे बकायेदारों को ₹3.69 करोड़ कम दिखाया गया, सी डब्ल्यू आई पी को ₹2.06 करोड़ ज़्यादा दिखाया गया। पूंजीकरण न करने की वजह से मूल्यहास और अधिशेष को ₹9.94 लाख कम दिखाया गया। इस सन्दर्भ में सेबी की अपनी लेखांकन नीति का भी उल्लंघन हुआ।</p> <p><b>2. निर्धारित निधि से निवेश: ₹2,332.15 करोड़ (अनुसूची 7)</b></p> <p><b>सावधि जमा में रखे गए ए ओ जुर्माने का निवेश: ₹100.84 करोड़</b></p> <p>उपरोक्त में ₹1.73 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। यह ए ओ जुर्माने की वसूली से वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश किए गए ₹25.00 करोड़ के</p>

क्रमांक	सी ए बी का नाम	अवलोकन
		<p>सावधि जमा पर मिला ब्याज है। इसकी वजह से ए ओ जुर्माना जमा खाता (परिसंपत्ति) और ए ओ जुर्माना रिटेन्ड अकाउंट (देनदारी) में ₹1.73 करोड़ की कमी आई है।</p> <p><b>ख. सामान्य टिप्पणियाँ</b></p> <p><b>3. मौजूदा देनदारियों और प्रावधानों में ₹2.58 करोड़ की राशि शामिल है,</b> जो ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं से अलग-अलग कामों के लिए ई एम डी, प्रतिभूति जमा और रिटेंशन धन के रूप में है, जो 3 से 15 वर्ष से बिना किसी उचित कारण के बकाया है।</p> <p><b>ग. सहायता अनुदान</b></p> <p>वर्ष के दौरान भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी एजेंसी से कोई सहायता अनुदान नहीं मिला।</p>
3	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	<p><b>क. बैलेंस शीट</b></p> <p><b>1. अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-8)</b></p> <p><b>प्रगतिरत पूंजीगत कार्य-शून्य</b></p> <p>दूरसंचार विभाग से मिले अनुदान से नौरोजी नगर, दिल्ली में कार्यालय स्थल खरीदने के लिए एम ओ एच यू ए और एन एस एल को प्रदान गयी राशि को सम्मिलित न करने के कारण प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹454.53 करोड़ की राशि से कम दिखाया गया है। इस वजह से कुल संचित कोष / पूंजी को भी उतनी ही राशि से कम दिखाया गया है।</p> <p>यह उपार्जन आधारित लेखांकन का उल्लंघन है।</p> <p><b>2. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11)</b></p> <p><b>पूर्व भुगतान: ₹12,13,618/-</b></p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹7.52 करोड़ की राशि कम दिखाई गई है, क्योंकि इसमें दूरसंचार विभाग से दो वर्ष के लिए मिले अनुदान से नौरोजी नगर, दिल्ली में खरीदे गए कार्यालय स्थल के रखरखाव के लिए किया गया अग्रिम भुगतान शामिल नहीं है। इससे कुल संचित कोष / पूंजी भी उतनी ही राशि कम दिखाई गई।</p> <p><b>3. मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान (अनुसूची 7)</b></p> <p><b>प्रावधान: ₹44,55,33,235/-</b></p> <p>वर्ष 2023-24 से संबंधित अलग-अलग शीर्षों में खर्च का प्रावधान न होने की वजह से उपरोक्त शीर्ष में ₹5.51 करोड़ की राशि कम बताई गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि आय भी उतनी ही ज़्यादा बताई गई।</p>

क्रमांक	सी ए बी का नाम	अवलोकन
		<p><b>ख. आकस्मिक देनदारियों और लेखाओं पर नोट्स (अनुसूची 25)</b>  <b>पूंजी प्रतिबद्धता</b>  उपरोक्त शीर्ष में ₹28.76 करोड़ की राशि कम दिखाई गई है, क्योंकि नौरोजी नगर, दिल्ली में नए खरीदे गए कार्यालय स्थल में आंतरिक कार्य के विकास के लिए देने वाली राशि की जानकारी नहीं दी गई।</p> <p><b>ग. अनुदान सहायता</b>  <b>(ए) राजस्व अनुदान:</b>  वर्ष के दौरान मिले ₹126.74 करोड़ के सहायता अनुदान (पिछले वर्ष के ₹14.74 करोड़ की अव्ययित शेष सहित) में से, 31 मार्च 2024 तक ट्राई ने ₹105.34 करोड़ का प्रयोग किया, जिसमें से ₹21.40 करोड़ का अनुदान अप्रयुक्त रह गया।  <b>(बी) पूंजी अनुदान:</b>  वर्ष के दौरान मिले ₹248.26 करोड़ के सहायता अनुदान (जिसमें पिछले वर्ष का ₹46.71 करोड़ का अव्ययित शेष और बिल्डिंग अकाउंट के सावधि जमा राशि पर ब्याज के तौर पर मिले ₹1.65 करोड़ की राशि शामिल है) में से, ट्राई ने 31 मार्च 2024 तक ₹145.05 करोड़ की राशि प्रयोग किया, जिसमें से ₹103.17 करोड़ का शेष अप्रयुक्त अनुदान के तौर पर रह गया।</p>
4	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण	<p><b>क. आय और व्यय लेखा</b>  <b>1. आय-शुल्क / सब्सक्रिप्शन्स ₹62.66 करोड़ (अनु. XIII)</b>  उपरोक्त शीर्ष में ₹56.05 लाख की राशि अधिक दिखाई गई है, क्योंकि इसमें वर्ष के दौरान अलग-अलग एजेंसियों से अग्रिम में मिले पंजीकरण शुल्क को शामिल किया गया था, जो उपार्जन आधारित लेखांकन का उल्लंघन है। इससे मौजूदा देनदारियों में भी उतनी ही कमी दिखाई गई।  <b>2. व्यय-अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (अनु. XIX)</b>  उपरोक्त शीर्ष में ₹20 लाख की राशि कम दिखाई गई है, क्योंकि जी एस टी विभाग ने जिन दावों को अस्वीकार कर दिया है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके कारण अधिशेष के साथ-साथ वर्ष के चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम को भी उतनी ही राशि से अधिक दिखाया गया।  <b>ख. प्राप्ति और भुगतान लेखा</b>  <b>प्राप्ति</b>  3. बैंक सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज को शामिल करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹61.94 लाख की राशि अधिक बताई गई है। प्राप्ति</p>

क्रमांक	सी ए बी का नाम	अवलोकन
		<p>और भुगतान लेखा के प्रारंभिक और अंतिम शेष में गैर-नकद वस्तुओं को शामिल करना बुनियादी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।</p> <p><b>ग. सामान्य टिप्पणियाँ</b></p> <p>4. सहायता अनुदान पर प्राप्त एवं भारत सरकार को भुगतान किए गए ब्याज का लेखांकन न करना स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के सामान्य प्रारूप के अनुरूप नहीं है।</p> <p><b>घ. अनुदान सहायता</b></p> <p>वर्ष के दौरान सामान्य, वेतन, और पूंजी शीर्ष के लिए ₹64.64 करोड़ का सहायता अनुदान मिला और पिछले वित्तीय वर्ष का ₹41.38 करोड़ का अनुदान अप्रयुक्त रह गया। आई एफ एस सी ए ने वर्ष के दौरान ₹100.35 करोड़ का उपयोग किया तथा 31 मार्च 2024 तक ₹5.67 करोड़ अप्रयुक्त अनुदान शेष रहा।</p>
5	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि	<p><b>क. बैलेंस शीट</b></p> <p><b>चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11) बैंक शेष जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित): ₹ 23,05,00,000</b></p> <p>ट्राई-सी पी एफ ने ₹1.90 करोड़ का ब्याज अर्जित किया, जिसे बैंकों द्वारा ब्याज राशि के पुनर्निवेश के रूप में संचयी सावधि जमा में जोड़ा गया। हालाँकि, ट्राई-सी पी एफ द्वारा इस राशि को सावधि जमा राशि के स्थान पर उपार्जित ब्याज के रूप में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप सावधि जमा को कम दिखाया गया और उपार्जित ब्याज को उसी राशि से अधिक दिखाया गया।</p> <p><b>ख. प्राप्ति और भुगतान लेखा</b></p> <p>जमा लेखाओं का प्रारंभिक और अंतिम शेष प्राप्ति और भुगतान लेखा में नहीं दिखाया गया था। यह प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करने के लिए स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखा के एकसमान प्रारूप के विरुद्ध है।</p> <p><b>ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची-24)</b></p> <p>ट्रस्ट के वित्तीय विवरण निवेश से संबंधित लेखांकन नीति के गैर-प्रकटीकरण की सीमा तक अपर्याप्त हैं। यह लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित लेखांकन मानक 1 का उल्लंघन है।</p>

अनुलग्नक 2.1

{पैराग्राफ- 2.1 देखें}

जुलाई 2017 से दिसंबर 2023 तक पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसीधारकों से एकत्रित डिफॉल्ट शुल्क पर लगने वाले जी एस टी का सर्किल-वार विवरण (₹ में)

क्र. सं.	डाक सर्किल का नाम	पी एल आई / आर पी एल आई में वसूल की गई विलंब शुल्क की कुल राशि	पी एल आई / आर पी एल आई की 18 प्रतिशत की दर से देय जी एस टी राशि	डाक विभाग द्वारा जीएसटी का भुगतान
1	आंध्र प्रदेश	34,13,63,487	6,14,45,428	7,80,99,096
2	असम	7,91,44,046	1,42,45,928	1,44,33,904
3	बिहार	17,62,49,193	3,17,24,855	3,05,03,664
4	छत्तीसगढ़	6,92,13,686	1,24,58,463	1,24,58,409
5	दिल्ली	23,83,34,557	4,29,00,220	4,38,89,052
6	गुजरात	44,27,27,772	7,96,90,999	7,88,29,278
7	हरियाणा	7,80,87,363	1,40,55,725	1,40,57,284
8	हिमाचल प्रदेश	2,40,67,427	43,32,137	43,32,133
9	जम्मू और कश्मीर	4,41,59,390	79,48,690	40,36,379
10	झारखंड	2,12,93,633	38,32,854	38,32,855
11	कर्नाटक	49,67,76,160	8,94,19,709	8,95,78,762
12	केरल	17,55,35,193	3,15,96,335	3,15,67,941
13	मध्य प्रदेश	11,28,30,973	2,03,09,575	2,12,63,407
14	महाराष्ट्र	43,06,57,365	7,75,18,326	7,75,33,788
15	पूर्वोत्तर	3,07,90,396	55,42,271	55,42,272
16	ओडिशा	21,29,66,970	3,83,34,055	3,83,33,657
17	पंजाब	6,70,45,986	1,20,68,277	1,21,11,203
18	राजस्थान	20,16,48,406	3,62,96,713	2,25,93,458
19	तेलंगाना	18,15,64,809	3,26,81,666	4,66,29,551
20	तमिलनाडु	42,25,12,450	7,60,52,241	7,78,01,483
21	उत्तर प्रदेश	29,05,38,604	5,22,96,949	4,74,28,748
22	उत्तराखंड	7,04,86,072	1,26,87,493	1,27,69,420
23	पश्चिम बंगाल	17,63,23,541	3,17,38,237	3,31,50,032
	कुल	438,43,17,479	78,91,77,144	80,07,75,776

अनुलग्नक 4.1

{पैराग्राफ 4.1.2 देखें}

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बचत निधि पर लेखापरीक्षा द्वारा ब्याज की गणना (तिमाही संयोजित) (₹ में)

माह (2023-24)	मंत्रालय द्वारा साधारण ब्याज दर पर ब्याज की गणना						लेखापरीक्षा द्वारा निकाला गया ब्याज (संयोजित तिमाही)				
	अथ शेष	वर्ष के दौरान निवल	अंत शेष	तिमाही प्रगति	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज (तिमाही प्रगति पर)	वास्तविक ब्याज (तिमाही प्रगति का कुल योग/12)	अंत शेष (तिमाही ब्याज सहित)	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज	वास्तविक ब्याज (तिमाही प्रगति का कुल योग/12)	अंतर	
अप्रैल	40765422454.89	-191014779.70	40574407675.19				40574407675.19				
मई	40574407675.19	-397461161.30	40176946513.89				40176946513.89				
जून	40176946513.89	-565118788.80	39611827725.09	120363181914.17	8545785915.91	712148826.33	39611827725.09	8545785915.91	712148826.33	0.00	
जुलाई	39611827725.09	-552566343.30	39059261381.79				39771410208.12				
अगस्त	39059261381.79	-75283532.30	38983977849.49				39696126675.82				
सितम्बर	38983977849.49	-362134701.40	38621843148.09	116665082379.37	8283220848.94	690268404.08	39333991974.42	8434908548.94	702909045.75	12640641.67	
अक्टूबर	38621843148.09	-730254084.40	37891589063.69				39306646935.76				
नवंबर	37891589063.69	-341025664.10	37550563399.59				38965621271.66				
दिसंबर	37550563399.59	-379539310.60	37171024088.99	112613176552.27	7995535535.21	666294627.93	38586081961.06	8296942861.96	691411905.16	25117277.23	
जनवरी	37171024088.99	-460174750.20	36710849338.79				38817319116.02				
फरवरी	36710849338.79	-445760678.90	36265088659.89				38371558437.12				
मार्च	36265088659.89	226733421.40	36491822081.29	109467760079.97	7772210965.68	647684247.14	38598291858.52	8220889028.23	685074085.69	37389838.55	
कुल 2023-24	463382801299.38	-4273600373.60	459109200925.78		वर्ष के दौरान ब्याज	2716396105.48			2791543862.93	75147757.44	
₹ करोड़ में							271.64		279.15		7.51

**अनुलग्नक-4.2**

{पैराग्राफ 4.1.3 देखें}

वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के यू जी एफ ए के विवरण संख्या 14 के अनुसार सी जी ई जी आई एस के तहत अथशेष, वृद्धि, संवितरण तथा अंतशेष का विवरण

(₹ हज़ारों में)

वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल को राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च को राशि
2016-17	4,408,87,55	538,21,53	518,03,87	4,429,05,21
2017-18	4,429,05,21	533,35,97	551,64,45	4,410,76,73
2018-19	4,411,00,37	511,29,64	562,67,45	4,359,62,56
2019-20	4,359,62,56	633,99,19	664,69,01	4,328,92,74
2020-21	4,328,92,74	490,18,53	539,40,52	4,279,70,75
2021-22	4,279,70,75	450,40,79	647,37,25	4,082,74,29
2022-23	4,082,74,29	341,71,66	551,78,75	3,872,67,20
2023-24	3,872,67,20	430,30,86	528,05,02	3,774,93,04

अनुलग्नक 5.1

(संदर्भ - अनुच्छेद 5.1.2)

मार्च तक 2024 ई एस डी एम I और ई एस डी एम II योजना की शीर्षवार बजट और व्यय स्थिति (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	योजना I	योजना II	कुल	योजना I	योजना II	कुल
		जी आई ए	जी आई ए	कुल जी आई ए	व्यय	व्यय	व्यय
1	पाठ्यक्रम शुल्क (कौशल सहायता)	78.04	278.47	356.51	55.36	157.24	212.60
2	ओवरहेड + प्लेसमेंट	7.80	28.44	36.24		0.84	0.84
3	आर सी सी एफ	10.80	39.36	50.16	6.80	25.03	31.83
4	पी एम यू / एम आई एस* (उप-शीर्षकों का विवरण नीचे दिया गया है)						
क)	जागरूकता और प्रचार	0.40	1.60	2.00	0.04	0.09	0.13
ख)	एम आई एस	0.35	0.35	0.70	0.07	0.15	0.22
ग)	जनशक्ति	1.39	2.37	3.76	3.67	4.33	8.00
घ)	यात्रा / परिवहन	0.36	1.92	2.28	0.08	0.08	0.16
च)	प्रभाव आकलन	0.25	1.00	1.25	0.18	0.38	0.56
छ)	उपकरण, फर्नीचर, फिक्स्चर, नवीनीकरण	0.19	0.21	0.40	0.07	0.14	0.21
ज)	कार्यालय व्यय	0.07	0.21	0.28	0.05	0.13	0.18
झ)	आकस्मिकता / विविध	0.05	0.14	0.19	0.01	0.03	0.04
ट)	संस्थागत ओवरहेड्स	0.30	0.78	1.08	0.38	0.57	0.95
	कुल पी एम यू	3.36	8.58	11.94	4.37	5.90	10.27
	<b>कुल</b>	<b>100.00</b>	<b>354.85</b>	<b>454.85</b>	<b>66.71</b>	<b>189.01</b>	<b>255.72</b>

मार्च 2024 तक एफ एस पी का शीर्षवार बजट और व्यय स्थिति (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	जी आई ए	कुल व्यय
1	मिश्रित शिक्षण संसाधन केंद्र की लागत	72.7	71.09
2	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	9.04	8.63
3	प्लेटफॉर्म डिजाइन, परिचालन और प्रबंधन लागत	78.8	61.32
4	वकालत और जागरूकता	9.22	8.23
5	मूल्यांकन और प्रमाणन	24.73	0.67
6	प्रोत्साहन	235	0
7	प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करना / सरकारी आधिकारिक लागत	7	6.56
8	प्रभाव आकलन	0.38	0
	<b>कुल</b>	<b>436.87</b>	<b>156.5</b>

मार्च 2024 तक एस डी वाई ए डी में शीर्षवार बजट और व्यय की स्थिति (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	जीआईए	व्यय किया
1	अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए आवश्यक धनराशि (जी एस टी सहित)	24.86	13.53
2	पी सी यू और आर पी सी यू के लिए जनशक्ति	1.17	1.00
3	यात्रा / परिवहन	0.15	0.47
4	पी सी यू और आर पी सी यू में उपकरण (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)	0.08	0.05
5	फर्नीचर, फिक्सचर, नवीनीकरण	0.04	0.01
6	विज्ञापन, जागरूकता, प्रचार और केंद्र पहचान	0.60	0.15
7	एम आई एस और प्लेसमेंट पोर्टल	0.15	0.13
8	प्रभाव आकलन	0.05	0.00
9	आकस्मिकताएं / विविध 1, 2 और 3 को 5 प्रतिशत पर	1.35	0.00
10	संस्थागत ओवरहेड / निधि प्रबंधन शुल्क 1, 2 और 3 को 5 प्रतिशत पर	1.36	0.78
	<b>कुल</b>	<b>29.81</b>	<b>16.12</b>

अनुलग्नक- 5.2

{संदर्भ पैराग्राफ 5.1.7, 5.1.8 तथा 5.1.9}

ई एस डी एम-I और ई एस डी एम-II, एस डी वाई ए डी और एफ एस पी का कार्यान्वयन ढांचा और प्रक्रिया प्रवाह

विवरण	ई एस डी एम-I	ई एस डी एम-II	एस डी वाई ए डी	एफ एस पी
टी पी का चयन	प्रशिक्षण भागीदार (टी पी), के आई ए के संबद्धता मानदंड के आधार पर प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों (के आई ए, एन आई ई एल आई टी, ई एस एस सी आई या टी एस एस सी) के साथ संबद्धता प्राप्त करते हैं।		एन आई ई एल आई टी मुख्यालय से केंद्र प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति निर्धारित मानदंडों के आधार पर टी पी की सूची बनाएगी।	सी-डैक और एन आई ई एल आई टी के संसाधन केंद्र ब्रिज कोर्स, सरकारी अधिकारी प्रशिक्षण (जी ओ टी) और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी) पाठ्यक्रम श्रेणियों का संचालन करते हैं। सेक्टर स्किल्स काउंसिल (एस एस सी) नैसकॉम फाउंडेशन गहन कौशल डीपस्किंग (सदस्यता और निःशुल्क) पाठ्यक्रम श्रेणियों का संचालन करता है।
अभ्यर्थियों को संगठित करना	टी पी + के आई ए / एस आई ए योजना का प्रचार करते हैं और प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को संगठित करते हैं।		आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। क्षेत्रीय या स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों / वेबसाइट / शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्यक्ष परामर्श के माध्यम से प्रचार किया जाएगा या उम्मीदवारों / अभ्यर्थियों के नाम / सूची या डेटा को संबंधित राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग / एस सी / एस टी विकास विभाग / महिला एवं बाल विकास विभाग / स्थानीय रोजगार कार्यालय आदि द्वारा उपलब्ध / अपलोड किया जा सकता है।	एस एस सी नैसकॉम विपणन और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अभ्यर्थियों को संगठित करता है और उन्हें शिक्षण ढांचे से जोड़ता है।
नामांकन	टी पी आवेदकों की स्क्रीनिंग करते हैं, पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं, और उम्मीदवारों / अभ्यर्थियों		किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रारंभिक पंजीकरण अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा और टी पी	संबंधित पाठ्यक्रम के संबंध में पंजीकरण के समय से लेकर प्रमाणन तक सही

विवरण	ई एस डी एम-I	ई एस डी एम-II	एस डी वाई ए डी	एफ एस पी
	के अंडरटेकिंग वचन पत्र एकत्र करते हैं। टी पी नामांकित उम्मीदवारों / अभ्यर्थियों को बैच बनाने के लिए ई एस डी एम पोर्टल पर अपलोड करते हैं (बैच गठन के आई ए अनुमोदन के अधीन है)।		पंजीकरण में अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करेगा। टी पी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि इस योजना के अंतर्गत कोई भी छात्र एक ही पाठ्यक्रम में या एक से अधिक पाठ्यक्रमों में बार बार नामांकित न-हो।	विवरण प्रदान करना तथा दी गई जानकारी की एकरूपता और वैधता सुनिश्चित करना लाभार्थी की जिम्मेदारी है।
<b>मानदंड</b>	लक्षित लाभार्थियों में 8वीं / 10वीं पास अभ्यर्थी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) डिग्री धारक, पॉलिटेक्निक, पूर्वस्नातक और स्नातक शामिल हैं। 60 प्रतिशत सामान्य / 40 प्रतिशत आरक्षित (एस सी 15 प्रतिशत , एस टी 7.5 प्रतिशत , ई डब्ल्यू एस 17.5 प्रतिशत )		18 राज्यों के 60 आकांक्षी जिलों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ई डब्ल्यू एस (महिलाएँ) युवा। जनवरी 2023 में 19 राज्यों के 81 आकांक्षी जिलों के 18,209 एस सी / एस टी / ई डब्ल्यू एस (महिलाएँ) युवाओं के लिए संशोधित। - न्यूनतम पात्रता मानदंड: 10 वीं कक्षा / 12 वीं कक्षा / आई टी आई	- आई टी गैर-आई टी फर्मों/ में आई टी कर्मचारी। - नए भर्ती हुए लोग (जिन्हें रोजगार की पेशकश की गई है) लेकिन अभी तक नौकरी नहीं की है, साथ ही वे लोग जो आई टी / आई टी ई एस में इंटरशिप और अप्रेंटिसशिप भूमिकाओं के लिए चयनित हैं।
<b>आर सी सी एफ पाठ्यक्रम शुल्क का संग्रह</b>	टी पी नामांकन के समय सभी अभ्यर्थियों से 500 रुपये से 1,905 रुपये प्रति अभ्यर्थी के बीच पंजीकरण सह प्रमाणन शुल्क (आर सी सी एफ) वसूलता है (राशि पाठ्यक्रम स्तर पर निर्भर करती है) और भुगतान रिकॉर्ड करता है। टी पी बैच शुरू होने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर संचयी आर सी सी एफ को संबंधित के आई ए में स्थानांतरित करता है और पोर्टल को एन ई एफ टी / लेनदेन विवरण के साथ अद्यतन करता है। पाठ्यक्रम शुल्क प्रति अभ्यर्थी 5,000 रुपये से 19,600 रुपये के बीच होता है, जिसकी प्रतिपूर्ति टी पी को की जाती है।		पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति पाठ्यक्रम पूरा होने और इनवॉइस जारी होने पर टी पी को कर दी जाती है। पाठ्यक्रम शुल्क सामान्य मानदंडों के अनुरूप होता है।	पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में 68 रुपये (अधिकतम छूट लागू होने के बाद) से लेकर 2,53,390 रुपये तक का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

विवरण	ई एस डी एम-I	ई एस डी एम-II	एस डी वाई ए डी	एफ एस पी
<b>प्रशिक्षण</b>	टी पी प्रशिक्षकों को संगठित / नियुक्त करता है तथा एन एस क्यू एफ-संरेखित पाठ्यक्रम सामग्री, सामग्री और आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध कराता है। टी पी दिन-वार उपस्थिति (इलेक्ट्रॉनिक / बायोमेट्रिक) बनाए रखता है - मूल्यांकन के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।		प्रशिक्षण चार एन एस क्यू एफ-संरेखित पाठ्यक्रमों में आयोजित किया जाएगा, जैसे डेटा प्रविष्टि और कार्यालय स्वचालन में प्रमाणन पाठ्यक्रम, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की स्थापना और मरम्मत में डिप्लोमा, कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग और पब्लिशिंग में एडवांस डिप्लोमा, सोलर-एल ई डी लाइटिंग उत्पाद (डिज़ाइन और विनिर्माण)।	एन एस क्यू एफ-संरेखित पाठ्यक्रम एफ एस पी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन / मिश्रित मोड में प्रस्तुत किए जाते हैं।
<b>आकलन</b>	प्रशिक्षण पूरा होने पर टी पी के आई ए को सूचित करता है; के आई ए प्रशिक्षण पूरा होने के दो सप्ताह के भीतर मूल्यांकन निर्धारित करता है और मूल्यांकनकर्ता (ओं) को आवंटित करता है।		परीक्षा अनुभाग, एन आई ई एल आई टी मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी।	पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, अभ्यर्थी को ₹600/- (मूल्यांकन शुल्क) का भुगतान करके भविष्य कौशल प्राइम पोर्टल पर मूल्यांकन से गुजरना होगा।
<b>प्रमाणन</b>	के आई ए परिणाम के पाँच दिनों के भीतर पोर्टल पर प्रमाणपत्र अपलोड करता है; टी पी प्रमाणपत्र डाउनलोड करता है और अभ्यर्थी को वितरित करता है (प्रमाणपत्र एक सामान्य के आई ए टेम्पलेट / सीरियल नंबर का पालन करते हैं)।		सभी सफल प्रतिभागियों को एन आई ई एल आई टी मुख्यालय द्वारा डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।	सफल मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी को नैसकॉम प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
<b>टी पी / अभ्यर्थी को दावों की प्रतिपूर्ति</b>	टी पी प्रतिपूर्ति दावे (पाठ्यक्रम शुल्क + आर सी सी एफ) पोर्टल के माध्यम से के आई ए को प्रस्तुत करता है; के आई ए दावे की समीक्षा करता है और दावे की अनुशंसा / अग्रगण्य (एस आई ए / एन आई ई एल आई टी-पी एम यू को) 10 कार्यदिवसों के भीतर करता है। यदि दावा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सही है, तो भुगतान पूरा हो जाता है। आर सी सी एफ के लिए ई एस डी एम-		किसी बैच के प्रशिक्षण और प्रमाणन के पूरा होने के बाद, टी पी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से इनवॉइस तैयार किया जाएगा। टी पी इनवॉइस का ऑनलाइन सत्यापन करेगा, उस बैच के छात्रों की उपस्थिति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को उचित सत्यापन के बाद अपलोड करेगा और उसे संबंधित राज्य में एन आई ई एल आई टी केंद्र के नोडल अधिकारी को	सफलतापूर्वक प्रमाणित अभ्यर्थियों के लिए, प्रोत्साहन राशि (मूल्यांकन शुल्क और पाठ्यक्रम शुल्क का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹12,000) का भुगतान अभ्यर्थी को आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

विवरण	ई एस डी एम-I	ई एस डी एम-II	एस डी वाई ए डी	एफ एस पी
	<p>I के तहत सभी श्रेणियों के लिए प्रतिपूर्ति 100 प्रतिशत है, और ई एस डी एम-II के तहत आरक्षित श्रेणी के लिए 100 प्रतिशत और सामान्य श्रेणी के लिए 75 प्रतिशत है।</p> <p>आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है और सामान्य अभ्यर्थी के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।</p> <p>प्रथम किस्त = 70 प्रतिशत (सफल प्रमाणन पर देय); दूसरी किस्त = 30 प्रतिशत (प्लेसमेंट-लिंकड)।</p> <p>बैच प्लेसमेंट के 70 प्रतिशत पर 100 प्रतिशत प्लेसमेंट-लिंकड प्रोत्साहन राशि जारी की जाती है, अन्यथा यह राशि केस-टू-केस आधार पर दी जाती है।</p>		<p>भेजेगा। नोडल अधिकारी एन आई) ई एल आई टी केंद्र) इन विवरणों का आगे सत्यापन करेंगे, निदेशक का अनुमोदन लेंगे और केंद्र द्वारा टी पी को भुगतान किया जाएगा।</p>	

अनुलग्नक - 5.3

(पैराग्राफ 5.2.1 देखें)

31 मार्च 2023 तक डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से सी एस सी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची

क्रम सं.	सेवा श्रेणी	सेवा का प्रकार	उत्पादों की संख्या
1	आधार	केंद्रीय (जी2सी) / बी2सी	9
2	कृषि	केंद्रीय (जी2सी) / बी2सी	19
3	आयुष्मान भारत	केंद्रीय (जी2सी) / राज्य (जी2सी)	3
4	बैंकिंग सेवाएँ	बैंकिंग / बी2सी	32
5	भारत बिल भुगतान प्रणाली (बी बी पी एस)	बी2सी	15
6	केंद्रीय जी2सी	केंद्रीय (जी2सी)	1
7	क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सी आई बी आई एल)	बी2सी	1
8	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस)	केंद्रीय (जी2सी)	1
9	डिजीनेम.इन	बी2सी	3
10	डिजीपे	बी2सी	1
11	ई-कॉमर्स	बी2सी	6
12	ई-कोर्ट	केंद्रीय (जी2सी)	4
13	ई-जिला सेवाएँ	राज्य (जी2सी) / बी2सी	74
14	शिक्षा	केंद्रीय (जी2सी) / बी2सी	91
15	चुनाव	केंद्रीय (जी2सी) / बी2सी	14
16	बिजली बिल	बी2सी	57
17	ई-मॉबिलिटी	बी2सी	2
18	रोजगार सेवा	केंद्रीय (जी2सी) / बी2सी / बैंकिंग	3
19	ई-रिचार्ज	बी2सी	19
20	ई-श्रम	केंद्रीय (जी2सी)	2
21	ई-स्टाम्प	केंद्रीय (जी2सी)	1
22	ई-वाहन	बी2सी	2
23	ई-विग्यापन	बी2सी	1

क्रम सं.	सेवा श्रेणी	सेवा का प्रकार	उत्पादों की संख्या
24	फास्टैग सेवा	बी2सी	13
25	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई)	केंद्रीय (जी2सी)	2
26	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ	बी2सी	33
27	स्वास्थ्य बीमा	बी2सी	4
28	बीमा नवीनीकरण	बी2सी	20
29	बीमा बिक्री- सामान्य बीमा (जी आई)	बी2सी	101
30	बीमा बिक्री- जीवन बीमा (एल आई)	बी2सी	124
31	आई टी रिटर्न फाइलिंग	बी2सी	6
32	श्रम सेवाएँ	राज्य (जी2सी) / बी2सी	21
33	ऋण सेवा	राज्य (जी2सी) / बी2सी / बैंकिंग	14
34	एल पी जी गैस रिफिल बुकिंग	केंद्रीय (जी2सी) / बी2सी	6
35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई)	केंद्रीय (जी2सी) / बी2सी	3
36	नगरपालिका सेवाएँ	राज्य (जी2सी)	1
37	अन्य	बी2सी	7
38	पैन कार्ड सेवाएँ	केंद्रीय (जी2सी)	5
39	पासपोर्ट	केंद्रीय (जी2सी)	1
40	पेंशन सेवाएँ	केंद्रीय (जी2सी) / राज्य (जी2सी)	6
41	पी एम केयर्स	केंद्रीय (जी2सी)	2
42	पी एम स्ट्रीट वेंडर का आत्मनिर्भर	केंद्रीय (जी2सी)	2
43	प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई)	केंद्रीय (जी2सी)	1
44	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाई)	बी2सी	17
45	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी एम-किसान)	केंद्रीय (जी2सी)	1
46	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी एम-के एम वाई)	केंद्रीय (जी2सी)	2
47	प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान- धन योजना (पी एम-एल वी एम)	केंद्रीय (जी2सी)	1

क्रम सं.	सेवा श्रेणी	सेवा का प्रकार	उत्पादों की संख्या
48	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान- धन (पी एम एस वाई एम)	केंद्रीय (जी2सी)	3
49	प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना' (पी एम-उदय)	राज्य (जी2सी)	1
50	डाकघर	केंद्रीय (जी2सी)	1
51	भर्ती सेवा	केंद्रीय (जी2सी) / राज्य (जी2सी) / बी2सी	6
52	सड़क एवं परिवहन	केंद्रीय (जी2सी) / बी2सी	4
53	कौशल विकास	बी2सी	18
54	राज्य सरकार (जी2सी)	केंद्रीय (जी2सी) / राज्य (जी2सी) / बी2सी	32
55	स्वच्छ भारत अभियान	केंद्रीय (जी2सी)	1
56	टेली-कानून	केंद्रीय (जी2सी)	1
57	पर्यटन और यात्राएँ	केंद्रीय (जी2सी) / बी2सी	22
58	उद्यम परिचय	केंद्रीय (जी2सी)	1
59	जल बिल भुगतान	बी2सी	3
60	वाईफाई चौपाल	बी2सी	1
<b>कुल योग</b>			<b>848</b>

जी2सी: सरकार से नागरिक

बी2सी: व्यवसाय से नागरिक

अनुलग्नक - 5.4

{पैराग्राफ 5.2.2 देखें}

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा, सी एस सी के भौतिक सत्यापन और लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए नमूना डेटा का विवरण

क्रम सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	जिलों की कुल संख्या	कुल जिलों की संख्या का प्रतिशत नमूना (न्यूनतम 2 और अधिकतम 10 के बीच)	25 नमूना जिलों की संख्या (प्रति जिले में दो ब्लॉक / उप-जिले)	नमूना लिए गए ब्लॉक / उप-जिले की संख्या	नमूना लिए गए ग्राम संख्या (प्रति जिला 5 ग्राम पंचायत)	वी एल ई सर्वेक्षण के दौरान कवर ग्राम संख्या	लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान कवर ग्राम पंचायतों की संख्या	लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान कवर ग्राम पंचायतों की संख्या
1	बिहार	38	10	20	50	47	47	247	
2	जम्मू और कश्मीर	20	5	10	25	21	20	129	
3	केरल	14	4	8	20	18	16	86	
4	पंजाब	23	6	12	30	21	21	109	
5	सिक्किम	6	2	4	10	3	2	10	
6	तमिलनाडु	37	10	20	50	34	28	140	
7	तेलंगाना	33	8	16	40	23	22	115	
8	त्रिपुरा	8	2	4	10	6	6	30	
9	उत्तर प्रदेश	75	10	20	50	34	31	170	
10	पश्चिम बंगाल	22	6	12	30	24	17	85	
	<b>कुल</b>	<b>276</b>	<b>63</b>	<b>126</b>	<b>315</b>	<b>231</b>	<b>210</b>	<b>1121</b>	

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों और भौतिक सत्यापन के लिए सी एस सी (ग्राम पंचायत में स्थित) के नमूने के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति को अपनाया गया। सी एस सी नेटवर्क द्वारा राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम ग्राम पंचायत कवरेज के दो समूहों में विभाजित करके और दोनों समूहों से कुल 30 प्रतिशत राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों का नमूना लेकर 10 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया।

प्रत्येक चयनित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के अंतर्गत 25 प्रतिशत जिलों का नमूना न्यूनतम दो और अधिकतम 10 जिलों के मानदंड के साथ तथा चयनित जिलों में दो ब्लॉक / उप जिलों और अंत में, इन दो ब्लॉक / उप-जिलों की ग्राम पंचायतों में स्थित पांच सक्रिय सी एस सी का नमूना लेकर, 315 सी एस सी (प्रति ग्राम पंचायत एक सी एस सी) का चयन किया गया।

अनुलग्नक - 5.5

{पैराग्राफ 5.2.3.1 देखें}

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण सी एस सी में लेनदेन का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	सक्रिय सी एस सी की कुल संख्या (ग्रामीण)	1,001 और उससे अधिक लेनदेन करने वाले सक्रिय सी एस सी की संख्या	501 से 1,000 लेनदेन करने वाले सक्रिय सी एस सी की संख्या	101 से 500 लेनदेन करने वाले सक्रिय सी एस सी की संख्या	1 से 100 लेनदेन करने वाले सक्रिय सी एस सी की संख्या	1,001 और उससे अधिक लेनदेन करने वाले सक्रिय सी एस सी का प्रतिशत	501 से 1,000 लेनदेन करने वाले सक्रिय सी एस सी का प्रतिशत	101 से 500 लेनदेन करने वाले सक्रिय सी एस सी का प्रतिशत	1 से 100 लेनदेन करने वाले सक्रिय सी एस सी का प्रतिशत
1	2018-19	2,47,128	9,164	14,573	61,189	1,62,202	3.71%	5.90%	24.76%	65.63%
2	2019-20	3,07,530	15,671	23,928	85,619	1,82,312	5.10%	7.78%	27.84%	59.28%
3	2020-21	4,01,430	14,740	25,389	1,09,685	2,51,616	3.67%	6.32%	27.32%	62.68%
4	2021-22	4,99,647	23,155	32,665	1,34,234	3,09,593	4.63%	6.54%	26.87%	61.96%
5	2022-23	5,99,800	72,445	60,200	1,88,309	2,78,846	12.08%	10.04%	31.40%	46.49%

डेटा स्रोत: सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया डैश बोर्ड

नोट: तालिका में वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए डी एस पी पर लेनदेन और केवल वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए बैंकिंग और डिजीपी के लेनदेन के आंकड़े शामिल हैं।

अनुलग्नक - 5.6

{पैराग्राफ 5.2.3.2 देखें}

भौतिक सत्यापन के लिए चयनित सी एस सी की स्थिति

क्रम सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	नमूना सी एस सी की संख्या	सक्रिय / उपलब्ध सी एस सी की संख्या	निष्क्रिय / अनुपलब्ध सी एस सी की संख्या	निष्क्रिय सी एस सी का प्रतिशत
1	उत्तर प्रदेश	50	34	16	32
2	तमिलनाडु	50	34	16	32
3	तेलंगाना	40	23	15	37.5
4	केरल	20	18	2	10
5	पश्चिम बंगाल	30	24	6	20
6	त्रिपुरा	10	6	3	30
7	सिक्किम	10	3	7	70
8	पंजाब	30	21	9	30
9	जम्मू और कश्मीर	25	21	4	16
10	बिहार	50	47	3	6
<b>कुल</b>		<b>315</b>	<b>231</b>	<b>81</b>	<b>25.7</b>

चयनित 315 सी एस सी में से 231 का भौतिक सत्यापन किया जा सका। भौतिक सत्यापन के दौरान 81 सी एस सी बंद पाए गए तथा तीन सी एस सी को स्थानांतरित / लेखापरीक्षा अवधि के बाद पंजीकृत / एक ही सी एस सी दो ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ पाया गया।

अनुलग्नक- 5.7

{पैराग्राफ 5.2.3.4 देखें}

ग्रामीण सी एस सी पर लोकप्रिय सेवाओं का प्रावधान न होना

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	बिहार	जम्मू और कश्मीर	केरल	सिक्किम	तेलंगाना	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	तमिलनाडु	पंजाब	कुल मिलाकर	उन सी एस सी का प्रतिशत जहां सेवाएं प्रदान नहीं की गईं / वितरित नहीं की गईं
	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-50	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-25	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-20	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-10	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-40	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-10	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-50	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-30	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-50	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-30	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-315	
	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 47	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 21	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 18	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 3	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 23	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 6	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 34	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 24	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 34	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 21	वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या-231	
सेवा का नाम	सी एस सी की संख्या जहां सेवा प्रदान की जाती है											
आधार	5	0	0	1	7	1	7	1	2	3	27	88.31
कृषि	42	21	1	1	19	6	32	2	32	20	176	23.81
आयुष्मान भारत	40	21	0	1	22	6	13	0	26	21	150	35.06
बैंकिंग सेवाएँ	25	21	0	1	16	2	18	3	16	20	122	47.19
भारत बिल भुगतान प्रणाली	37	21	17	2	22	6	33	22	34	21	215	6.93
डिजीपे	41	21	9	1	23	6	33	7	33	21	195	15.58
ई-जिला सेवाएँ	11	21	0	0	1	6	12	14	19	0	84	63.64
बिजली बिल	45	0	16	1	2	6	33	18	33	21	175	24.24
ई-रिचार्ज	39	21	14	2	15	6	32	19	32	21	201	12.99
ई-स्टाम्प	5	0	0	0	0	3	4	1	2	0	15	93.51

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	बिहार	जम्मू और कश्मीर	केरल	सिक्किम	तेलंगाना	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	तमिलनाडु	पंजाब	कुल मिलाकर	उन सी एस सी का प्रतिशत जहां सेवाएं प्रदान नहीं की गईं / वितरित नहीं की गईं
	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-50 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 47	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-25 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 21	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-20 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 18	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-10 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 3	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-40 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 23	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-10 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 6	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-50 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 34	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-30 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 24	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-50 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 34	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-30 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या - 21	नमूनाकृत सी एस सी की कुल संख्या-315 वास्तव में देखे गए सी एस सी की संख्या-231	कुल सी एस सी की संख्या जहां सेवा प्रदान की जाती है
सेवा का नाम	सी एस सी की संख्या जहां सेवा प्रदान की जाती है											
बीमा नवीनीकरण	32	20	8	2	12	6	27	12	30	21	170	26.41
बीमा बिक्री-जी आई	26	20	6	1	14	6	24	5	26	21	149	35.50
श्रम सेवाएँ	29	0	0	0	2	6	32	0	24	6	99	57.14
एल पी जी गैस रिफिल बुकिंग	30	20	1	0	13	0	27	11	28	21	151	34.63
पैन कार्ड सेवाएँ	43	20	16	2	21	6	34	22	33	21	218	5.63
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	20	20	4	0	1	6	31	0	31	6	119	48.48
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	39	20	17	2	19	6	31	18	32	21	205	11.26
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान- धन	19	20	0	0	9	6	23	4	32	18	131	43.29
राज्य सरकार (जी2सी)	29	20	0	0	4	6	21	0	33	1	114	50.65
पर्यटन और यात्राएँ	26	20	9	1	14	6	26	13	21	18	154	33.33

**अनुलग्नक - 5.8**  
**{पैराग्राफ 5.2.3.4 देखें}**

**सी एस सी पर उपलब्ध नहीं होने वाली लोकप्रिय सेवाएँ**

क्रम सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों की संख्या	सी एस सी पर सेवा की आवश्यकता होने पर भी उपलब्ध न होने / प्रदान न किये जाने की सूचना देने वाले लाभार्थियों की संख्या			
			आधार सेवा	ई-जिला	बैंकिंग	कुल
1	बिहार	247	127	60	14	201
2	जम्मू और कश्मीर	129	97	4	0	101
3	केरल	86	25	17	1	43
4	पंजाब	109	20	19	0	39
5	सिक्किम	10	0	0	0	0
6	तमिलनाडु	140	0	0	0	0
7	तेलंगाना	115	32	13	2	47
8	त्रिपुरा	30	13	1	3	17
9	उत्तर प्रदेश	170	123	5	4	132
10	पश्चिम बंगाल	85	8	0	20	28
	<b>कुल</b>	<b>1121</b>	<b>445</b>	<b>119</b>	<b>44</b>	<b>608</b>

अनुलग्नक - 5.9

{पैराग्राफ 5.2.3.7 देखें}

भौतिक सत्यापन के दौरान सी एस सी में अपर्याप्त अवसंरचना (प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और पावर बैकअप)

क्रम सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	भौतिक रूप से देखे गए सी एस सी की संख्या	प्रिंटर रहित सी एस सी की संख्या	स्कैनर रहित सी एस सी की संख्या	वेबकैम रहित सी एस सी की संख्या	पावर बैकअप रहित सी एस सी की संख्या	सी एस सी की संख्या जहां दर-सूची प्रदर्शित नहीं की गई
1	बिहार	47	1	1	20	6	45
2	जम्मू और कश्मीर	21	0	0	0	2	0
3	केरल	18	0	0	2	4	18
4	पंजाब	21	0	1	2	4	21
5	तेलंगाना	23	0	4	4	7	21
6	तमिलनाडु	34	0	0	3	10	31
7	त्रिपुरा	6	1	2	1	4	6
8	सिक्किम	3	0	0	0	3	3
9	पश्चिम बंगाल	24	2	2	10	15	24
10	उत्तर प्रदेश	34	2	2	2	1	4
कुल		231	6	12	44	56	173

सी एस सी दिशानिर्देशों (पैरा 8.2.2) के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और पावर बैकअप की आवश्यकता है।

अनुलग्नक- 6.1

{पैराग्राफ-6.1.5.1(क) देखें}

एसेस पॉइंट्स (ए पी) के प्रति आई बी सी का परिनियोजन

सर्किल का नाम	एसेस पॉइंट्स की संख्या	परिनियोजित आई बी सी की संख्या	प्रति ए पी परिनियोजित आई बी सी की औसत संख्या
बिहार	8,835	1,404	0.16
हरियाणा	डेटा उपलब्ध नहीं		
मध्य प्रदेश	10,273	2,767	0.27
महाराष्ट्र	13,787	2,500	0.18
पूर्वोत्तर	2,394	154	0.06
राजस्थान	11,067	1,875	0.17
तमिलनाडु	11,805	3,706	0.31
उत्तर प्रदेश	17,915	2,447	0.14
कुल	<b>76,076</b>	<b>14,853</b>	<b>0.20</b>

अनुलग्नक - 6.2

{पैराग्राफ-6.1.5.1(ख) देखें}

अनुलग्नक में एसेस पॉइंट्स में खोले गए खारों की संख्या दिखाई गई है

एसेस पॉइंट्स में खारों की संख्या	एसेस पॉइंट्स की संख्या	एसेस पॉइंट्स की संचयी कुल संख्या
0	1,564	1,564 (1.13%)
1	3,190	4,754 (3.43%)
2	1,354	6,108 (4.41%)
3	835	6,943 (5.01%)
4	650	7,593 (5.48%)
5	519	8,112 (5.86%)
06 से 10	2,261	10,373 (7.49%)
11 से 50	12,823	23,196 (16.75%)
51 से 100	13,962	37,158 (26.83%)
101 से 200	24,316	61,474 (44.39%)
201 से 300	18,173	79,647 (57.52%)
301 से 400	13,031	92,678 (66.93%)
401 से 500	9,630	1,02,308 (73.88%)
501 से 1,000	21,643	1,23,951 (89.51%)
1,001 से 5,000	13,646	1,37,597 (99.37%)
5,001 से 10,000	696	1,38,293 (99.87%)
10,001 से 15,000	128	1,38,421 (99.96%)
15,001 से 20,000	21	1,38,442 (99.98%)
20,001 से 25,000	20	1,38,462 (99.99%)
25,001 से 50,000	13	1,38,475 (99.99%)
>=50,000	1	1,38,476 (100%)
<b>कुल</b>	<b>1,38,476</b>	

**अनुलग्नक - 6.3**  
**{पैराग्राफ-6.1.5.2(क) देखें}**

**2021-22 और 2022-23 के दौरान चार पेमेंट बैंकों का निष्पादन दर्शाता अनुलग्नक**

**(करोड़ में)**

वर्ष	यूपीआई प्रेषक बैंक (पेमेंट्स बैंक-पीबी)	लेन-देन की कुल मात्रा	लेन-देन (लेन-देन)			प्रतिशत में लेनदेन			डेबिट रिवर्सल (डीआर)		
			स्वीकृत लेनदेन	बीडी * लेन-देन	टीडी ** लेन-देन	स्वीकृत %	बीडी %	टीडी %	कुल डीआर गणना	डीआर सफल लेनदेन	डीआर सफलता % में
2021-22	पेटीएम पीबी	268.59	253.99	14.19	0.41	94.56%	5.28%	0.15%	1.39	1.28	92.13%
	एयरटेल पीबी	59.04	50.83	7.29	0.92	86.09%	12.35%	1.56%	0.52	0.41	79.25%
	आईपीपीबी	34.77	27.79	5.83	1.15	79.93%	16.78%	3.29%	0.69	0.24	35.43%
	फिनो पीबी	15.88	12.63	2.79	0.45	79.57%	17.60%	2.83%	0.15	0.13	91.43%
	<b>कुल</b>	<b>378.28</b>	<b>345.24</b>	<b>30.11</b>	<b>2.92</b>	<b>91.27%</b>	<b>7.96%</b>	<b>0.77%</b>	<b>2.59</b>	<b>2.06</b>	<b>79.62%</b>
	<b>औसत</b>	<b>94.57</b>	<b>86.31</b>	<b>7.53</b>	<b>0.73</b>	<b>91.27%</b>	<b>7.96%</b>	<b>0.77%</b>	<b>0.65</b>	<b>0.52</b>	<b>79.62%</b>
2022-23	पेटीएम पीबी	419.40	402.07	17.00	0.33	95.87%	4.05%	0.08%	1.30	1.18	91.01%
	एयरटेल पीबी	157.30	132.24	21.98	3.08	84.07%	13.97%	1.96%	1.33	0.94	71.29%
	आईपीपीबी	139.11	100.18	28.04	10.88	72.02%	20.16%	7.82%	1.83	0.95	51.97%
	फिनो पीबी	61.86	48.93	10.39	2.54	79.09%	16.79%	4.11%	0.80	0.48	60.43%
	<b>कुल</b>	<b>777.67</b>	<b>683.42</b>	<b>77.41</b>	<b>16.83</b>	<b>87.88%</b>	<b>9.95%</b>	<b>2.16%</b>	<b>4.45</b>	<b>3.56</b>	<b>79.92%</b>
	<b>औसत</b>	<b>194.42</b>	<b>170.85</b>	<b>19.35</b>	<b>4.21</b>	<b>87.88%</b>	<b>9.95%</b>	<b>2.16%</b>	<b>1.11</b>	<b>0.89</b>	<b>79.92%</b>

\*-व्यावसायिक गिरावट

\*\* -तकनीकी गिरावट

लॉन्च की तारीख: एयरटेल पी बी- जनवरी 2017, फिनो पी बी- अप्रैल 2017, आई पी पी बी- सितंबर 2018 और पेटीएम पी बी- नवंबर 2017

**अनुलग्नक - 6.4**  
**{पैराग्राफ-6.1.5.2(क) देखें}**

चार पेमेंट बैंकों के यू पी आई डाउनटाइम पर सांख्यिकीय जानकारी

पेमेंट्स बैंक का नाम =>	एयरटेल पेमेंट बैंक		फिनो पेमेंट्स बैंक		इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड		पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	
	घटना संख्या	डाउनटाइम (घंटों में)	घटना संख्या	डाउनटाइम (घंटों में)	घटना संख्या	डाउनटाइम (घंटों में)	घटना संख्या	डाउनटाइम (घंटों में)
अप्रैल-2023	1	8:33:00	0	0:00	27	109:31:00	0	0:00
मई-2023	0	0:00	0	0:00	0	0:00	0	0:00
जून-2023	2	8:08:00	0	0:00	11	64:23:00	0	0:00
जुलाई-2023	3	8:08:00	4	9:43:00	7	25:24:00	0	0:00
अगस्त-2023	2	3:38:00	1	2:43:00	4	10:10:00	0	0:00
सितंबर-2023	0	0:00	1	0:51:00	4	12:00:00	0	0:00
अक्टूबर-2023	0	0:00	2	3:09:00	2	14:02:00	0	0:00
नवंबर-2023	1	1:21:00	1	1:06:00	2	3:23:00	0	0:00
दिसंबर-2023	4	10:55:00	0	0:00	10	28:56:00	0	0:00
जनवरी-2024	4	12:55:00	1	1:06:00	6	25:31:00	0	0:00
फरवरी-2024	0	0:00	0	0:00	7	19:39:00	0	0:00
मार्च-2024	0	0:00	2	2:10:00	17	48:52:00	0	0:00
<b>कुल</b>	<b>17</b>	<b>52:38:00</b>	<b>12</b>	<b>19:48:00</b>	<b>97</b>	<b>361:51:00</b>	<b>0</b>	<b>0:00:00</b>

(स्रोत: <https://www.npci.org.in/statistics/bd-td-and-uptime>)

अनुलग्नक- 6.5

{पैराग्राफ-6.1.5.2(ख) देखें}

गैर - सत्यापित नंबरों से खोले गए खातों का नमूना दर्शाता विवरण

मोबाइल संख्या	सी आई एफ की संख्या	सी आई एफ नंबर	स्थिति	खाता खोलने की तिथि
9999999999	10	052610041748	सुप्त	01-08-2019
		052610041707	सुप्त	01-08-2019
		052610042021	सुप्त	03-08-2019
		052610041774	सुप्त	01-08-2019
		052610040628	सुप्त	20-07-2019
		100000011377	सुप्त	27-07-2018
		001610010186	सुप्त	22-07-2019
		052610041781	सुप्त	01-08-2019
		052610041776	सुप्त	01-08-2019
9111111111	5	046910001573	सुप्त	15-06-2019
		049410019610	सक्रिय	20-02-2020
		047410016107	सक्रिय	25-09-2019
		048410016649	सुप्त	21-11-2019
		041410016214	सुप्त	19-02-2020
9898989898	5	048410013045	सुप्त	30-09-2019
		048410013063	सक्रिय	30-09-2019
		048410013083	सक्रिय	30-09-2019
		048410013069	सक्रिय	30-09-2019
		048410013041	सक्रिय	30-09-2019
9222222222	5	054110081028	सुप्त	22-06-2020
		034810027183	सुप्त	10-01-2020
		048410016370	सक्रिय	19-11-2020
		054110053790	सुप्त	15-02-2020
		048410016460	सक्रिय	20-11-2020
9000000000	5	001410031412	सुप्त	18-10-2019
		048510009338	सक्रिय	26-09-2019
		048510009353	सुप्त	26-09-2019
		025710018816	सुप्त	29-11-2019
		025710018789	सुप्त	29-11-2019
9000000001	4	048410008249	सक्रिय	18-09-2019
		048410015141	सुप्त	22-10-2019
		024510011346	सुप्त	22-08-2019
		048410015965	सुप्त	11-11-2019
9000000002	4	048410016373	सुप्त	19-11-2019

मोबाइल संख्या	सी आई एफ की संख्या	सी आई एफ नंबर	स्थिति	खाता खोलने की तिथि
		048410016375	सुप्त	19-11-2019
		024510013769	सुप्त	31-10-2019
		048410004479	सक्रिय	05-06-2019
9000000003	3	048410005228	सक्रिय	02-07-2019
		048410016378	सुप्त	19-11-2019
		048410016382	सक्रिय	19-11-2019
9000000005	5	048410016403	सुप्त	19-11-2019
		048410016404	सुप्त	19-11-2019
		048410015094	सुप्त	22-10-2019
		048410016413	सुप्त	19-11-2019
		048410005233	सक्रिय	02-02-2019
99999888888	3	034710009189	सुप्त	08-07-2019
		001410155437	सक्रिय	11-03-2020
		024510015604	सुप्त	07-12-2019
9900000000	4	009210131696	सुप्त	20-07-2020
		009210131680	सुप्त	20-07-2020
		009210131677	सुप्त	20-07-2020
		009210131695	सक्रिय	11-03-2020
9800000000	3	010110146257	सुप्त	23-05-2020
		010110093643	सुप्त	24-04-2020
		008410065385	सक्रिय	26-06-2019
9600000000	3	048410005196	सक्रिय	02-07-2019
		057210022223	निष्क्रिय	09-01-2020
		057210022233	सक्रिय	09-01-2020
9400000000	5	025710009179	सुप्त	03-08-2019
		025710009180	सुप्त	03-08-2019
		025710009183	सुप्त	03-08-2019
		025710009184	सुप्त	03-08-2019
		025710009182	सुप्त	03-08-2019
9100000000	5	049410011615	सुप्त	15-11-2019
		048510012287	सुप्त	31-10-2019
		049410011355	सक्रिय	07-11-2019
		049410014858	सुप्त	07-01-2020
		008010099548	सक्रिय	08-07-2020
9876543210	3	048510009529	सुप्त	27-09-2019
		048510009164	सुप्त	26-09-2019
		048510009585	सुप्त	27-09-2019

मोबाइल संख्या	सी आई एफ की संख्या	सी आई एफ नंबर	स्थिति	खाता खोलने की तिथि
8888888888	5	011210007826	सुप्त	15-06-2019
		011210007823	सक्रिय	15-06-2019
		056410014458	सुप्त	03-12-2019
		041410012938	सुप्त	03-02-2020
		011210007856	सुप्त	15-06-2019
8000000000	4	048510010280	सुप्त	01-10-2019
		048510010275	सुप्त	01-10-2019
		001410031257	सुप्त	18-10-2019
		048510009862	सक्रिय	27-09-2019
8585858585	5	002710159449	सुप्त	19-02-2020
		029810016661	सुप्त	12-12-2019
		029810016658	सुप्त	12-12-2019
		029810016659	सुप्त	12-12-2019
		029810017382	सुप्त	30-12-2019
7000000000	4	052610063539	सुप्त	24-02-2020
		024610080785	सुप्त	12-02-2020
		024610112545	सुप्त	10-03-2020
		052610063500	सुप्त	24-02-2023
7777777777	5	011210007897	सुप्त	15-06-2019
		034810026026	सुप्त	07-01-2020
		034810019580	सक्रिय	05-12-2019
		011210007819	सक्रिय	15-06-2019
		041410012939	सुप्त	03-02-2020
7000000001	5	046210036793	सुप्त	08-03-2020
		046210039697	सुप्त	11-03-2020
		046210036045	सुप्त	08-03-2020
		046210036039	सुप्त	08-03-2020
		046210036392	सुप्त	08-03-2020
7000000002	3	046210039378	सुप्त	07-02-2020
		046210039377	सुप्त	11-03-2020
		046210039537	सुप्त	11-03-2020
6000000000	3	041410013312	सुप्त	07-02-2020
		041410013314	सुप्त	07-02-2020
		041410013333	सुप्त	07-02-2020
6000000001	3	048410016155	सुप्त	16-11-2019
		048410017868	सक्रिय	03-12-2019
		048410016320	सक्रिय	18-11-2019

**अनुलग्नक - 6.6**  
**{पैराग्राफ-6.1.5.3(ख) देखें}**

वित्तीय समावेशन निधि (एफ आई एफ) का सर्किल वार गैर-उपयोग

(राशि करोड़ में)

राज्यों के नाम	आयोजित किए जाने वाले शिविरों की संख्या	स्वीकृत राशि	आयोजित शिविरों की संख्या	आयोजित शिविरों में कमी	उपयोग की गई राशि	अप्रयुक्त राशि	
						राशि	प्रतिशत में
बिहार	795	0.40	267	528	0.12	0.28	71.11
हरियाणा	854	0.23	555	299	0.11	0.12	49.52
मध्य प्रदेश	2,050	0.92	1,802	248	0.57	0.35	37.59
महाराष्ट्र	1,597	0.32	629	968	0.09	0.23	72.30
पूर्वोत्तर	1,237	0.74	264	973	0.16	0.58	78.76
राजस्थान	1,584	1.52	455	1,129	0.04	1.48	97.68
तमिलनाडु	2,149	0.76	643	1,506	0.1	0.66	86.29
उत्तर प्रदेश	1,388	0.71	558	830	0.11	0.60	84.60
<b>कुल</b>	<b>11,654</b>	<b>5.60</b>	<b>5,173</b>	<b>6,481</b>	<b>1.30</b>	<b>4.30</b>	<b>76.79</b>

अनुलग्नक - 6.7  
{पैराग्राफ 6.2.2 देखें}

लेखापरीक्षा के लिए चुने गए दस बी एस एन एल सर्किल के बिज़नेस एरिया की लिस्ट

क्रम संख्या	वृत्त का नाम	बी ए / ओ ए का नाम
1	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	बी ए आगरा
		बी ए बरेली
		बी ए गाजियाबाद
2	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बी ए सुल्तानपुर
		बी ए अयोध्या
		बी ए गोरखपुर
3	तमिलनाडु	बी ए मदुरई
		बी ए तिरुनेलवेली
		बी ए तंजावुर
4	बिहार	बी ए दरभंगा
		बी ए मुजफ्फरपुर
		बी ए भागलपुर
5	छत्तीसगढ़	बी ए रायपुर
		बी ए बिलासपुर
		बी ए बस्तर
6	मध्य प्रदेश	बी ए इंदौर
		बी ए सागर
		बी ए ग्वालियर
7	झारखंड	बी ए जमशेदपुर
		बी ए रांची
		बी ए धनबाद
8	महाराष्ट्र	बी ए पुणे
		बी ए चंद्रपुर
		बी ए कोल्हापुर
9	ओडिशा	बी ए ढेंकानाल
		बी ए बालासोर
		बी ए कटक
10	राजस्थान	बी ए जयपुर
		बी ए बीकानेर
		बी ए जोधपुर

अनुलग्नक - 6.8

{पैराग्राफ 6.2.3.1(क) देखें}

बी एस एन एल के नाम पर टावर स्थापना वाली भूमि का गैर-म्यूटेशन दर्शाने वाला विवरण

सर्किल का नाम	चयनित व्यावसायिक क्षेत्र / परिचालन क्षेत्र	बी एस एन एल के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित टावरों की संख्या	बी एस एन एल की भूमि पर टावरों की संख्या जिसके लिए भूमि अभिलेख उपलब्ध हैं या बी एस एन एल के नाम पर भूमि का म्यूटेशन किया गया है	बी एस एन एल के नाम पर बी एस एन एल भूमि पर म्यूटेशन के लिए बाकी टावरों की संख्या
उ प्र (पश्चिम)	बी ए आगरा	#	#	#
	बी ए बरेली	44	27	17
	बी ए गाजियाबाद	39	23	16
उ प्र (पूर्व)	ओ ए सुल्तानपुर	12	2	10
	ओ ए अयोध्या	18	1	17
	बी ए गोरखपुर	87	37	50
तमिलनाडु	बी ए मदुरई	99	85	14
	बी ए तिरुनेलवेली	100	95	5
	बी ए तंजावुर	64	46	18
बिहार	बी ए दरभंगा	62	11	51
	बी ए मुजफ्फरपुर	76	8	68
	बी ए भागलपुर	66	5	61
छत्तीसगढ़	बी ए रायपुर	56	41	15
	बी ए बिलासपुर	#	#	#
	बी ए बस्तर	#	#	#
म प्र सर्किल	ओ ए इंदौर	42	24	18
	बी ए सागर	92	63	29
	ओ ए ग्वालियर	22	10	12
झारखंड	बी ए जमशेदपुर	24	11	13
	बी ए रांची	#	#	#
	बी ए धनबाद	46	16	30
महाराष्ट्र	बी ए पुणे	9	7	2
	बी ए चंद्रपुर	4	0	4
	बी ए कोल्हापुर	15	7	8
ओडिशा	बी ए ढेंकानाल	45	23	22
	बी ए बालासोर	49	4	45
	बी ए कटक	35	15	20

सर्किल का नाम	चयनित व्यावसायिक क्षेत्र / परिचालन क्षेत्र	बी एस एन एल के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित टावरों की संख्या	बी एस एन एल की भूमि पर टावरों की संख्या जिसके लिए भूमि अभिलेख उपलब्ध हैं या बी एस एन एल के नाम पर भूमि का म्यूटेशन किया गया है	बी एस एन एल के नाम पर बी एस एन एल भूमि पर म्यूटेशन के लिए बाकी टावरों की संख्या
राजस्थान	बी ए जयपुर	172	155	17
	बी ए बीकानेर	106	94	12
	बी ए जोधपुर	296	271	25
	<b>कुल</b>	<b>1680</b>	<b>1081</b>	<b>599</b>

# बी एस एन एल द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई

**अनुलग्नक - 6.9**  
**पैराग्राफ 6.2.3.1(ग) देखें**

उन किराए पर ली गयी आई पी साइटों को दर्शाने वाला विवरण जहाँ यू एस ओ टावर उपलब्ध थे

क्रम सं.	ओडिशा के यू एस ओ साइट विवरण के अनुसार डेटा				बी एस एन एल ओडिशा द्वारा किराए पर ली गई आई पी साइटों के सी एन एम सी पोर्टल के अनुसार डेटा				दोनों साइटों के बीच की दूरी कि मी में (निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित)
	जिले का नाम	उस गाँव का नाम जहाँ टावर स्थित है	अक्षांश (डिग्री उत्तर में)	देशांतर (डिग्री पूर्व में)	एस एस ए नाम	साइट का नाम	अक्षांश (डिग्री उत्तर में)	देशांतर (डिग्री पूर्व में)	
1	अंगुल	बालिपाटा	20.98745	84.85535	अंगुल	बालिपाटा	20.98465	84.85472	0
2	अंगुल	सीपुर	21.17508	85.15601	अंगुल	सीपुर	21.16505	85.15446	1
3	बारागढ़	ब्राह्मणबिल (ए जी एल)	21.04509	84.93266	अंगुल	ब्राह्मणबिल (ए जी एल)	21.05278	84.93228	1
4	मयूरभंज	बड़ा दलिमा	22.45789	86.07539	मयूरभंज	बड़ा दलिमा	22.44460	86.07530	1
5	गजपति	अलीगंडा	19.53873	84.16933	गजपति	अलीगंडा	19.54452	84.17099	1
6	सुंदरगढ़	तलसारा	22.37296	84.09630	सुंदरगढ़	तलसारा	22.36109	84.09978	1
7	बारागढ़	बिजेपुर खरमुंडा	21.13584	83.48904	बारागढ़	बिजेपुर खरमुंडा	21.13591	83.48911	0

**अनुलग्नक - 6.10**  
**{पैराग्राफ 6.2.3.2(ख) देखें}**

बी एस एन एल ओडिशा सर्किल में स्थापित टावर के उपयोग में देरी के कारण संभावित राजस्व की हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	एस एस ए	साइट का प्रकार	साइट का नाम	टावर स्थापना तिथि	बी टी एस बनाया गया	टावर की स्थापना की तिथि से उपयोग की तिथि तक महीने में देरी (बी टी एस निर्मित)	देरी के कारण राजस्व की हानि ₹44 (प्रोपेड) प्रति माह प्रति लाइन (कुल लाइन 875 प्रति बी टी एस)* (₹ करोड़ में)
1	बालेश्वर	जी बी टी	भोइसाही	18-12-17	12-09-19	21	0.08
2	बालेश्वर	आर टी पी	सिनेमा-बाजार-बी एल एस	30-04-17	27-02-18	10	0.04
3	बालेश्वर	जी बी टी	मोतीगंज	10-02-18	15-03-19	13	0.05
4	बालेश्वर	जी बी टी	पडाबडागांव	15-12-18	06-06-19	6	0.02
5	बालेश्वर	जी बी टी	एफ एम यूनिवर्सिटी-एन बी	01-09-16	27-07-18	23	0.09
6	बारीपदा	जी बी टी	दहिकोटी	25-11-17	15-04-19	17	0.07
7	बारीपदा	जी बी टी	संकुचा	12-07-17	08-04-19	21	0.08
8	बारीपदा	जी बी टी	बेटनोटी-3	25-11-17	12-04-19	17	0.06
9	बरहमपुर	जी बी टी	निमिना	11-09-17	29-12-22	65	0.25
10	बरहमपुर	जी बी टी	गोपालपुर बंदरगाह	22-01-17	30-08-17	7	0.03
11	बरहमपुर	जी बी टी	भटनई ते	07-03-17	14-12-17	9	0.04
12	बरहमपुर	जी बी टी	सुरमणि-बी एस	07-03-17	14-01-23	71	0.27
13	बरहमपुर	जी बी टी	धोबाबाड़ी	30-03-16	29-08-17	17	0.07

क्रम संख्या	एस एस ए	साइट का प्रकार	साइट का नाम	टावर स्थापना तिथि	बी टी एस बनाया गया	टावर की स्थापना की तिथि से उपयोग की तिथि तक महीने में देरी (बी टी एस निर्मित)	देरी के कारण राजस्व की हानि ₹44 (प्रीपेड) प्रति माह प्रति लाइन (कुल लाइन 875 प्रति बी टी एस)* (₹ करोड़ में)
14	बरहमपुर	जी बी टी	तारातारिनी जंक्शन	24-04-17	16-11-17	7	0.03
15	बरहमपुर	जी बी टी	मथुरा (पोलासरा)	20-03-16	28-08-17	18	0.07
16	बरहमपुर	जी बी टी	तुरुबुराई	11-09-17	18-10-19	26	0.10
17	बरहमपुर	आर टी टी	के एम आर प्लाजा बेर	23-12-16	30-08-17	8	0.03
18	बरहमपुर	जी बी टी	फासी / दानापुर	20-03-16	29-08-17	18	0.07
19	बरहमपुर	जी बी टी	कुलागाडा	27-04-17	28-06-18	14	0.05
20	बरहमपुर	जी बी टी	देवी नगर, छत्रपुर	21-01-17	28-08-17	7	0.03
21	बरहमपुर	जी बी टी	लांजिया (दखिनापुर एक्स जी ई)	30-01-17	29-08-17	7	0.03
22	बरहमपुर	जी बी टी	चिकारदा	30-03-16	28-06-16	3	0.01
23	बरहमपुर	जी बी टी	सुबरनपुर	07-03-17	24-08-17	6	0.02
24	भुवनेश्वर	जी बी टी	सत्य विहार_1	21-08-16	21-09-17	13	0.05
25	भुवनेश्वर	जी बी टी	एनआईएसईआर	20-01-16	23-03-18	26	0.10
26	भुवनेश्वर	जी बी टी	लिंगीपुर-3	13-03-18	26-03-19	13	0.05
27	भुवनेश्वर	जी बी टी	राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज	06-09-17	17-02-18	5	0.02
28	भुवनेश्वर	जी बी टी	आई एन एस चिल्डिका	10-07-16	30-11-19	41	0.16

क्रम संख्या	एस एस ए	साइट का प्रकार	साइट का नाम	टावर स्थापना तिथि	बी टी एस बनाया गया	टावर की स्थापना की तिथि से उपयोग की तिथि तक महीने में देरी (बी टी एस निर्मित)	देरी के कारण राजस्व की हानि ₹44 (प्रीपेड) प्रति माह प्रति लाइन (कुल लाइन 875 प्रति बी टी एस)* (₹ करोड़ में)
29	भुवनेश्वर	जी बी टी	एमएस सिजुआ-2_2	05-09-17	20-03-18	7	0.03
30	भुवनेश्वर	जी बी टी	संचुरियन विश्वविद्यालय	05-09-17	10-06-19	21	0.08
31	भुवनेश्वर	आर टी पी	उत्तरी ऊंचाई	25-04-17	20-09-17	5	0.02
32	भुवनेश्वर	जी बी टी	धौली चौक	05-09-17	17-02-18	6	0.02
33	भुवनेश्वर	जी बी टी	नबीनबाँग	25-11-17	19-07-22	57	0.22
34	भुवनेश्वर	जी बी टी	नानपुट	31-10-17	13-06-19	20	0.08
35	भुवनेश्वर	आर टी पी	जेड एस्टेट	19-05-17	30-12-17	8	0.03
36	भुवनेश्वर	जी बी टी	जामुसाही	10-08-17	30-11-19	28	0.11
37	भुवनेश्वर	जी बी टी	बलिहारचंडी	20-08-16	20-09-17	13	0.05
38	भुवनेश्वर	जी बी टी	कृष्णप्रसाद	25-12-17	25-10-19	22	0.09
39	भुवनेश्वर	जी बी टी	लोकनाथ घाट	30-11-17	15-11-18	12	0.04
40	कटक	जी बी टी	सारपद	20-12-16	11-01-18	13	0.05
41	कटक	जी बी टी	सिरलो नुआगांव	10-08-16	31-08-22	74	0.28
42	कटक	जी बी टी	खपुरिया	21-12-16	19-01-18	13	0.05
43	कटक	जी बी टी	ओ एस ए पी 6-बटालियन	21-03-17	10-01-18	10	0.04

क्रम संख्या	एस एस ए	साइट का प्रकार	साइट का नाम	टावर स्थापना तिथि	बी टी एस बनाया गया	टावर की स्थापना की तिथि से उपयोग की तिथि तक महीने में देरी (बी टी एस निर्मित)	देरी के कारण राजस्व की हानि ₹44 (प्रीपेड) प्रति माह प्रति लाइन (कुल लाइन 875 प्रति बी टी एस)* (₹ करोड़ में)
44	कटक	जी बी टी	दैतारी-2	10-10-16	26-05-17	8	0.03
45	कटक	जी बी टी	मंगराजपुर	10-10-16	29-07-17	10	0.04
46	कटक	जी बी टी	प्रहराजपुर	02-06-16	29-07-17	14	0.05
47	कटक	जी बी टी	लोकपद	02-10-17	19-03-19	18	0.07
48	कटक	जी बी टी	जगुलेइपाड़ा	25-04-16	16-09-17	17	0.07
49	ढेंकनाल	जी बी टी	सौभाग्य नगर	21-04-17	20-11-17	7	0.03
50	ढेंकनाल	जी बी टी	चिरुलेई	25-04-17	21-11-19	31	0.12
51	ढेंकनाल	जी बी टी	धुरपद	24-01-17	17-01-18	12	0.05
52	ढेंकनाल	जी बी टी	कुमुदी	27-04-17	11-12-17	8	0.03
53	ढेंकनाल	जी बी टी	कंदरापोसी	24-01-17	23-10-19	33	0.13
54	कोरापुट	जी बी टी	प्रशासनिक भवन, जयपुर	25-10-16	14-10-19	36	0.14
55	कोरापुट	जी बी टी	नाल्को स्टोर (पंचपुटमाली)	15-10-16	31-05-18	20	0.08
56	कोरापुट	जी बी टी	अर्ध मोबाइल कोल्हू (एस एम सी पी)	02-01-17	01-09-17	8	0.03
57	फूलबाणी	जी बी टी	धलापुर (पीएचयू)	30-06-16	01-10-19	40	0.15
58	फूलबाणी	जी बी टी	सारासारा	25-03-17	28-09-17	6	0.02

क्रम संख्या	एस एस ए	साइट का प्रकार	साइट का नाम	टावर स्थापना तिथि	बी टी एस बनाया गया	टावर की स्थापना की तिथि से उपयोग की तिथि तक महीने में देरी (बी टी एस निर्मित)	देरी के कारण राजस्व की हानि ₹44 (प्रीपेड) प्रति माह प्रति लाइन (कुल लाइन 875 प्रति बी टी एस)* (₹ करोड़ में)
59	फूलबाणी	जी बी टी	चहाली	31-03-17	17-02-18	11	0.04
60	फूलबाणी	जी बी टी	गुमागढ़	31-10-16	17-02-18	16	0.06
61	फूलबाणी	जी बी टी	ताजुंगिया	15-11-16	27-09-17	11	0.04
62	फूलबाणी	जी बी टी	अरबाका	27-03-17	27-03-18	12	0.05
63	फूलबाणी	जी बी टी	टुडिपाजू	15-09-16	28-09-17	13	0.05
64	फूलबाणी	जी बी टी	रुंतुंगिया	15-03-16	15-02-18	23	0.09
65	फूलबाणी	जी बी टी	किरिकुटी	27-12-17	21-01-21	37	0.14
66	फूलबाणी	जी बी टी	कुदुतुली	20-02-18	19-10-19	20	0.08
67	फूलबाणी	जी बी टी	फूलबानी टाउन पी एस-एन बी	23-08-16	06-08-18	24	0.09
68	फूलबाणी	जी बी टी	पीताबरी	21-06-16	26-09-17	15	0.06
69	फूलबाणी	जी बी टी	अदासिकुपा	15-10-16	13-09-19	35	0.14
70	फूलबाणी	जी बी टी	आर नुआगांव	27-03-17	26-03-18	12	0.05
71	फूलबाणी	जी बी टी	सिर्दिगुडा	31-12-17	17-02-23	62	0.24
72	फूलबाणी	जी बी टी	केलापाड़ा	07-02-17	26-09-17	8	0.03
73	फूलबाणी	जी बी टी	गांधी चौक-एनबी	12-06-16	26-09-17	16	0.06

क्रम संख्या	एस एस ए	साइट का प्रकार	साइट का नाम	टावर स्थापना तिथि	बी टी एस बनाया गया	टावर की स्थापना की तिथि से उपयोग की तिथि तक महीने में देरी (बी टी एस निर्मित)	देरी के कारण राजस्व की हानि ₹44 (प्रीपेड) प्रति माह प्रति लाइन (कुल लाइन 875 प्रति बी टी एस)* (₹ करोड़ में)
74	फूलबाणी	जी बी टी	दासिगबाड़ी	14-02-18	13-05-19	15	0.06
75	फूलबाणी	जी बी टी	बिसिपाडा	25-02-16	25-09-17	19	0.07
76	फूलबाणी	जी बी टी	गदापुर	31-12-16	25-09-17	9	0.03
77	फूलबाणी	जी बी टी	दारिगबाड़ी-II	14-02-18	13-09-19	19	0.07
78	फूलबाणी	जी बी टी	राटिगिया	31-03-17	26-10-19	31	0.12
79	फूलबाणी	जी बी टी	कैंडर	05-02-17	26-09-17	8	0.03
80	संबलपुर	जी बी टी	गुडरपाली	15-07-17	25-03-21	45	0.17
81	संबलपुर	जी बी टी	कुडोपल्ली	05-08-17	16-11-19	28	0.11
82	संबलपुर	जी बी टी	लिमचोड	10-08-17	19-10-19	27	0.10
83	संबलपुर	जी बी टी	बीटीआई गोसाला	27-09-17	28-02-18	5	0.02
84	सुंदरगढ़	जी बी टी	मोहंती पोडा	10-11-16	06-09-17	10	0.04
<b>कुल</b>							<b>6.23</b>

\* लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व हानि की गणना परियोजना अनुमान में राजस्व के आंकलन को ध्यान में रखते हुए की गई। प्रति बी टी एस 875 लाइनें और प्रति लाइन प्रीपेड राजस्व ₹44 प्रति माह को राजस्व हानि की गणना के लिए माना गया है।

अनुलग्नक - 6.11

{पैराग्राफ 6.2.3.2(घ) देखें}

बी एस एन एल में निष्क्रिय टावरों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

सर्किल	बी ए / ओ ए	निष्क्रिय / विकिरण रहित टावरों की संख्या	निष्क्रियता के बाद की अवधि
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	11	2016-17
	पुणे	#	#
	चंद्रपुर	17	2014-15
उ प्र (पूर्व)	अयोध्या	15	2020
	सुल्तानपुर	10	2016
	गोरखपुर	4	2013
उ प्र (पश्चिम)	बरेली	#	#
	गाजियाबाद	8	2019
	आगरा	1	2014
ओडिशा	सर्किल	81	#
बिहार	दरभंगा	25	2015
	भागलपुर	76	2017
	मुजफ्फरपुर	32	2017
झारखंड	सर्किल	55	2021
छत्तीसगढ़	सर्किल	214	2009
म प्र	सर्किल	1095	#
तमिलनाडु	तंजावुर	0	#
	मदुरई	15	#
	तिरुनेलवेली	#	#
राजस्थान	सर्किल	81	#
	<b>कुल</b>	<b>1740</b>	

# बी एस एन एल द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई

अनुलग्नक - 6.12

{पैराग्राफ 6.2.3.3(क) क देखें}

विलंब शुल्क का बिल न भेजे जाने का बयौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	सर्किल का नाम	टी एस पी का नाम जिसे बिल दिया गया	बिलों के भुगतान में विलंब की अवधि	विलंब शुल्क का बिल न देना (₹ करोड़ में)
1	ओडिशा	मैसर्स बी ए एल	अप्रैल 2019 से जनवरी 2025 तक	0.0242
		मैसर्स वी आई एल	जनवरी 2019 से फरवरी 2025 तक	1.8286
		मैसर्स आर जे आई एल	मई 2019 से मई 2021 तक	0.2807
2	बिहार	मैसर्स बी ए एल	जुलाई 2018 से मार्च 2025 तक	0.8631
		मैसर्स आर जे आई एल	जुलाई 2018 से मार्च 2025 तक	0.8245
3	झारखंड	मैसर्स बी ए एल	जनवरी 2022 से मार्च 2025 तक	0.0137
		मैसर्स वी आई एल	फरवरी 2024 से मार्च 2025 तक	0.0002
		मैसर्स आर जे आई एल	अप्रैल 2019 से मार्च 2025 तक	0.5002
4	राजस्थान	मैसर्स आर जे आई एल	अगस्त 2020 से मार्च 2025 तक	1.3698
5	तमिलनाडु	मैसर्स बी ए एल	अक्टूबर 2020 से मार्च 2025 तक	0.6872
		मैसर्स आर जे आई एल	नवंबर 2022 से मार्च 2025 तक	0.6346
<b>कुल</b>				<b>7.24</b>

अनुलग्नक - 6.13

{पैराग्राफ 6.2.3.3(क) ख देखें}

अतिरिक्त किराये का बिल न देने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

सर्किल का नाम	साझा करने वाली टी एस पी का नाम	कम बिलिंग की अवधि	उन साइटों की संख्या जहाँ कम बिलिंग देखी गई	अतिरिक्त किराये का बिल न देना (₹ करोड़ में)
ओडिशा	आर जे आई एल, बी ए एल, वी आई एल	अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2024	26	0.35
तमिलनाडु	आर जे आई एल, बी ए एल, वी आई एल	नवंबर 2011 से मार्च 2025	170	1.28
महाराष्ट्र	आर जे आई एल, बी ए एल, वी आई एल	फरवरी 2012 से दिसंबर 2023	41	0.62
बिहार	आर जे आई एल	अप्रैल 2017 से दिसंबर 2023	7	0.08
<b>कुल</b>			<b>244</b>	<b>2.33</b>

## शब्दावली

ए बी	स्वायत्त निकाय
ए डी	आकांक्षी जिले
ए ई पी एस	आधार सक्षम भुगतान प्रणाली
ए जी आर	समायोजित सकल राजस्व
ए पी बी एस	आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली
ए पी एम एस	लेखापरीक्षा पैरा निगरानी प्रणाली
ए टी एम	स्वचालित टेलर मशीन
ए टी एन	एक्शन टेकन नोट्स
ए टी आर	एक्शन टेकन रिपोर्ट
बी ए	व्यावसायिक क्षेत्र
बी बी पी एस	भारत बिल भुगतान प्रणाली
बी ए एल	भारती एयरटेल लिमिटेड
बी 2 सी	व्यवसाय से नागरिक
बी एस एन एल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बी ओ	शाखा डाकघर
बी पी सी ओ डी	बिज़नेस पार्सल - कैश ऑन डिलीवरी
बी टी एस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन
बी सी	ब्रिज कोर्स
सी ए बी एस	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सी ए एफ	ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र
सी एंड ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सी ए एस ए	चालू और बचत खाता
सी डी आर एम	ग्राहक घर अनुरोध प्रबंधन प्रणाली
केपेक्स	पूंजीगत व्यय
सी सी ए	मुख्य लेखा नियंत्रक
सी सी टी वी	क्लोर्ड सर्किट टेलीविज़न
सी - डैक	प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी एफ	पाठ्यक्रम शुल्क
सी एफ आई	भारत की संचित निधि

सी जी ए	लेखा महानियंत्रक
सी जी एस टी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सी जी ई जी आई एस	केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना
सी आई बी आई एल	क्रेडिट इनफार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
सी ई ओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी-एम ई टी	इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र
सी एन एम सी	केंद्रीकृत नेटवर्क प्रबंधन केंद्र
सी ओ डी	केश ऑन डिलीवरी
सी ओ पी यू	सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
सी पी सी	केंद्रीय वेतन आयोग
सी पी जी आर ए एम एस	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सी पी एस ई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
सी एस सी	सामान्य सेवा केंद्र
सी एस सी-एस पी वी	सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
डी ए एम ए	डेटा विश्लेषण और मासिक लेखे
डी बी एन	डिजिटल भारत निधि
डी बी टी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डी ई जी एस	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी
डी एल आर	जिला स्तरीय संसाधन
डी ओ पी	डाक विभाग
डी ओ टी	दूरसंचार विभाग
डी ई ए	आर्थिक कार्य विभाग
डी ओ ई	व्यय विभाग
डी ओ पी टी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
डी ओ आर	राजस्व विभाग
डी पी सी	कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें
डी पी एम एस	डिलीवरी पोस्टमैन प्रबंधन प्रणाली
डी पी आर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डी एस	गहन कौशल
डी एस पी	डिजिटल सेवा पोर्टल

डी टी ओ	दूरसंचार संचालन विभाग
डी टी एस	दूरसंचार सेवा विभाग
ई पी सी ओ डी	एक्सप्रेस पार्सल - कैश ऑन डिलीवरी
ई आर एन ई टी	भारतीय शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क
ई एन	व्याख्यात्मक नोट
ई एस डी एम	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्माण
ई डब्ल्यू एस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
ई एस एस सी आई	भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र कौशल परिषद
एफ सी	आधारभूत पाठ्यक्रम
एफ एल सी	वित्तीय साक्षरता शिविर
एफ आई एफ	वित्तीय समावेशन निधि
एफ वाई	वित्तीय वर्ष
एफ एस एस ए आई	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
एफ एस पी	भविष्य कौशल प्राइम
एफ टी टी एच	फाइबर टू द होम
जी 2 सी	सरकार से नागरिक
जी डी एस	ग्रामीण डाक सेवक
जी आई	सामान्य बीमा
जी आई ए	सहायता अनुदान
जी ओ आई	भारत सरकार
जी ओ टी	सरकारी अधिकारी प्रशिक्षण
जी पी	ग्राम पंचायत
जी एस एम	मोबाइल संचार वैश्विक प्रणाली
जी एस टी	वस्तु एवं सेवा कर
एच ओ	प्रधान डाकघर
एच एस एम	हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल
एच आर डी	मानव संसाधन विकास
आई सी टी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई ई सी टी	सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रौद्योगिकी
आई एफ एस सी ए	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

आई पी पी बी	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
आई पी पी बी एल	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
आई बी सी	व्यक्तिगत व्यवसाय संवाददाता
आई आर सी टी सी	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम
आई ओ टी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आई एफ	बीमा निधि
आई पी एफ	अवसंरचना प्रावधान शुल्क
आई एस बी	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस
आई टी	सूचना प्रौद्योगिकी
आई टी आई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
के आई ए	प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां
के वाई सी	नो योर कस्टमर
एल डी	परिनिर्धारित हर्जाना
एल आई	जीवन बीमा
एल ओ एल एस	आशय पत्र
एल एस ए	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
एम सी सी	आदर्श कैरियर केंद्र
एम आई एस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम डी एम	मोबाइल डिवाइस प्रबंधन
एम पी एल ए डी	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एम एस एम ई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एम जी एन आर ई जी एस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम ई आई टी वाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एम ओ सी	संचार मंत्रालय
एम ओ एफ	वित्त मंत्रालय
एम ओ एस पी आई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एम ओ यू एस	समझौता ज्ञापन
एम टी एल	मिलेनियम दूरसंचार लिमिटेड
एम टी एन एल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एम एस ए	मास्टर सेवा समझौता

एम एस डी ई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एन एस डी एल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एन ए सी एच	राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस
एन ए एस एस सी ओ एम	राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ
एन आई ई एल आई टी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एन आई सी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एन पी पी	गैर-निष्पादन जुर्माना
एन ओ एस	राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
एन एल आर	राष्ट्रीय स्तर के संसाधन
एन एस क्यू एफ	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा
ओ ए	परिचालन क्षेत्र
ओ एफ सी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओ टी पी	वन टाइम पासवर्ड
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी ए ओ-आई डी ए	वेतन एवं लेखा कार्यालय-आंतरिक ऋण एवं लेखा
पी सी यू	परियोजना समन्वय इकाई
पी एल आई	डाक जीवन बीमा
पी एम ए वाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पी एम एफ बी वाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पी एम-एल वी एम	प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना
पी एम - किसान	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
पी एम - के एम वाई	प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना
पी एम - एस वाई एम	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन
पी एम - उदय	प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना
पी एम यू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पी ओ एस ए	डाकघर बचत खाता
पी ओ एस बी	डाकघर बचत बैंक
पी आर एस जी	परियोजना समीक्षा और संचालन समूह
क्यू ओ एस	सेवा की गुणवत्ता

आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
आर सी एस	संसाधन केंद्र
आर सी सी एफ	पंजीकरण सह प्रमाणन शुल्क
आर एफ पी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर जे आई एल	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
आर पी सी यू	क्षेत्रीय परियोजना समन्वय इकाई
आर आर	प्रदर्शक दर
आर एम एस	रेल डाक सेवा
आर पी एल आई	ग्रामीण डाक जीवन बीमा
आर पी ए	रोबोटिक्स प्रक्रिया स्वचालन
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस आई ए	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां
एस सी	अनुसूचित जाति
एस डी ए	राज्य निर्दिष्ट एजेंसी
एस डी वाई ए डी	आकांक्षी जिलों में युवाओं का कौशल विकास
एस टी	अनुसूचित जनजाति
एस एफ	बचत निधि
एस ई बी आई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस एफ डी	विशेष फोकस जिले
एस आई एम	सब्सक्राइबर पहचान माँड्यूल
एस एम एस	लघु संदेश सेवा
एस ओ पी	मानक संचालन प्रक्रिया
एस ओ	उप डाकघर
एस एस सी ए	विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा
एस एस सी	क्षेत्र कौशल परिषद
एस यू सी	स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क
एस एस पी एस	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ
टी डी	तकनीकी गिरावट
टी डी एस ए टी	दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण
टी ई सी	टेली-सेंटर उद्यमी पाठ्यक्रम

टी ओ टी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टी पी एस	प्रशिक्षण भागीदार
टी आर ए आई	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
टी एस पी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
टी एस सी	तकनीकी उप-समिति
टी एस एस सी	दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद
यू ए एल	सार्वभौमिक पहुँच शुल्क
यू सी	उपयोग प्रमाणपत्र
यू जी एफ ए	संघ सरकार वित्त लेखे
यू एल	एकीकृत लाइसेंस
यू पी आई	एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
यू एस ओ एफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यू एस ओ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व
यू एस पी	सार्वभौमिक सेवा प्रदाता
यू टी	केंद्र शासित प्रदेश
यू टी आई टी एस एल	यू टी आई अवसंरचना तकनीकी एंड सर्विसेज लिमिटेड
वी आई	वोडाफोन आइडिया
वी एल ई	ग्राम स्तरीय उद्यमी









© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/pt/delhi/hi/page-pt-delhi-union-reports>

